हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

बंगाल में सियासत

पश्चिम बंगाल में सरकारी एजेंसियों से जुड़ी सियासत का फिर से तेज होना बहुत चिंताजनक है। सहज शब्दों में बयान करें, तो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी के एक बड़े रणनीतिकार के आवास व कार्यालय पर एक पुराने कथित घोटाले की वजह से छापा मारा। जवाब में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपने मातहत आला पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गईं। नतीजा यह हुआ कि दोनों पक्षों के बीच आरोपों-प्रत्यारोपों की बौछार शुरू हो गई। ईडी ने बताया कि ये छापे कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि छापा मारने के बहाने ईडी अधिकारियों द्वारा तृणमूल प्रत्याशियों की सूची और चुनावी रणनीति संबंधी दस्तावेजों को जब्त किया जा रहा है। आदर्श स्थिति यह है कि एक सरकारी एजेंसी अगर जांच-पड़ताल कर रही हो, तो दूसरी एजेंसियां सहयोग में खड़ी हो जाएं, लेकिन पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों के प्रति राज्य सरकार की शिकायत पुरानी है। ऐसे कई मौके आए हैं, जब राज्य सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को निशाना बनाया और जांच करने वाले अधिकारियों की भी मुसीबत बढ़ गई।

अपने स्वभाव के अनुरूप ममता बनर्जी के आवेश को समझा जा सकता है। उन्होंने भाजपा को ललकारा है कि वह तृणमूल कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से हराकर दिखाए। ईडी ने जिस रणनीतिकार प्रतीक जैन के आवास पर छापा मारा है, उसे ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी का आईटी प्रमुख बताया है। बहरहाल, राज्य सरकार के अधिकारियों के पहुंचने का फायदा यह हुआ है कि ममता बनर्जी ने पार्टी के कथित जरूरी दस्तावेजों और हार्ड डिस्क को वापस ले लिया है। पश्चिम बंगाल में राजनीति की यह नाटकीयता नई नहीं है। ममता बनर्जी की यह धमकी भी गौरतलब है कि ईडी के छापे के जवाब में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पार्टी कार्यालयों पर छापेमारी की जाए, तब क्या होगा? उनका कहना है कि वह संयम बरत रही हैं और यही होना चाहिए। कुल मिलाकर, ऐसी सियासत शुरू हो गई है कि ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या ईडी का व्यवहार उसके अपने नियम-कायदों के अनुरूप है? यहां अगर ईडी सही है, तो राज्य सरकार को किस हद तक और कैसे कठघरे में खड़ा किया जा सकता है? ईडी के छापे की जगह पर खुद मुख्यमंत्री का पहुंचना और खुद अपने हाथों में दस्तावेज थामे दिखना भारतीय राजनीति की ताजा स्याह तस्वीर है। निश्चित ही इससे लोगों में भ्रम की स्थिति बढ़ेगी, जिससे सरकारी एजेंसियों के प्रति लोगों का सम्मान भी प्रभावित होगा।

ईडी के छापे की जगह पर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पहुंचना और खुद अपने हाथों में दस्तावेज थामे दिखना भारतीय राजनीति की ताजा स्याह तस्वीर है।

ध्यान रहे कि कथित कोयला घोटाले में ईडी ने पश्चिम बंगाल में छह जगह और दिल्ली में चार जगह छापेमारी की है। यह मामला साल 2020 का है और इसमें तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी से भी सीबीआई पूछताछ हो चुकी है। पहला सवाल यही खड़ा होता है कि क्या केंद्रीय एजेंसियां किसी जांच में जरूरत से ज्यादा समय लेती हैं? क्या प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर छापा मारते हुए ईडी को यह ध्यान नहीं था कि इसका एक गंभीर राजनीतिक परिणाम भी हो सकता है? जिस राजनीतिक सलाहकार संस्थान आई-पैक पर छापा मारा गया, वह तृणमूल के लिए काम करता है और इसी वजह से मामला ज्यादा सियासी हो गया। अब यही उम्मीद करनी चाहिए कि केंद्रीय एजेंसियां हों या सियासी पार्टियां, बदले की मानसिकता से काम नहीं करेंगी और जो बर्ताव सबने देखा है, वह कहीं नजीर न बन जाए।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले

09 जनवरी, 1951

बाढ़ की रोकथाम

एशिया और दूरपूर्व के आर्थिक कमीशन ने बाढ़ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की है और उसकी ओर से आयोजित एक प्रादेशिक सम्मेलन भारत की राजधानी में प्रारंभ हुआ है। इस सम्मेलन में एक दर्जन देशों और आठ विशिष्ट एजेंसियों और अन्तर्राष्ट्रीय टेकनीकल संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

एशिया और दूरपूर्व के देशों के लिए बाढ़ की एक मुख्य समस्या है। जैसा कि सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए निर्माण, उत्पादन और रसद मंत्री श्री गाडगिल ने कहा है, नदियां कृत्रिम राजनीतिक सीमाओं से बंधी हुई नहीं हैं और अनेक नदियां अनेक राज्यों की सीमाओं में होकर बहती हैं, अतः बाढ़ की समस्या का मुकाबला अन्तर-राज्य अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए। यह सच है कि प्रत्येक नदी की अपनी विशेषता होती है, अतः इस संबंध में कोई समान सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता; किन्तु विभिन्न देशों में बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए जो विशिष्ट ज्ञान अर्जित किया गया है, उससे दूसरे भी लाभ उठा सकते है। मौजूदा सम्मेलन का, जिसमें अनेक देशों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं, यही सबसे उत्तम उपयोग है। इस सम्मेलन में जो सामूहिक ज्ञान उपलब्ध किया जायेगा, उससे सभी जरूरतमंद देश लाभ उठा सकेंगे।

एशिया और दूरपूर्व के अनेक विस्तृत प्रदेशों के लिए प्रकृति का यह अभिशाप है कि या तो वह पानी की रेल-पेल कर देती है या पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। दोनों ही दशाओं में लोगों को दुष्काल का सामना करना पड़ता है। किन्तु जब नदियों में बाढ़ आती है, तो मनुष्यों की विपत्ति सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। फसलों और संपत्ति को उनसे भारी नुकसान पहुंचता है। पशु बह जाते हैं और प्राण-हानि भी कम नहीं होती। बाढ़ में जो रेत बहकर आती है, वह उपजाऊ भूमि को बंजर बना देती है। चीन की पीत नदी में बहुधा बाढ़ आती रहती है और उससे जो व्यापक हानि होती है, उसके कारण 'चीन का शोक' इसका पर्यायवाची बन गया है। एशिया और दूरपूर्व के देशों में 20 करोड़ से अधिक व्यक्ति, जो यहां की कुल आबादी का एक पंचमांश है, नदी-बांधों के संरक्षण में रहते हैं। ये बांध, जो 12 हजार मील की दूरी में फैले हुए हैं, कभी कहीं और कभी कहीं टूट जाते हैं और मृत्यु तथा विनाश फैला देते हैं।

पाकिस्तान का बगलगीर बांग्लादेश

यहां स्कैन करें

संजय के भारद्वाज | प्रोफेसर, जेएनयू

पाकिस्तान की मंशा एक नए रणनीतिक गठबंधन की है, जिसमें चीन और बांग्लादेश तो होंगे ही, कतर व तुर्किये जैसे इस्लामी देशों को भी शामिल किया जा सकता है।

बांग्लादेश का पाकिस्तान की राह चलना चिंतनीय है। अगस्त, 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद तस्वीर काफी बदल गई है। 1971 के बाद जहां पहली बार दोनों देशों के बीच सीधे व्यापार की शुरुआत हुई है, वहीं आगामी 29 जनवरी से उनके बीच सीधी विमान सेवा भी शुरू होने जा रही है। इन सबके बीच सैन्य सहयोग को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और ढाका ने इस्लामाबाद से जेएफ-17 लड़ाकू विमान खरीदने की बात कही है।

परेशानी सिर्फ यही नहीं है कि बांग्लादेश के रूप में हमारे सामने सुरक्षा का एक नया मोर्चा खुल रहा है, बल्कि दिक्कत यह भी है कि 'बांग्लादेश ट्रेड ऐंड टैरिफ कमीशन' ने भारतीय कॉटन यार्न पर 20 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने की मांग की है। उधर, अमेरिका में भी राष्ट्रपति ट्रंप 'रूस प्रतिबंध विधेयक 2025' पर सहमत हो चुके हैं, जिसमें रूस के साथ-साथ उन देशों पर भी शिकंजा कसने का प्रावधान है, जो मॉस्को से तेल खरीद रहे हैं। माना जा रहा है कि इसकी जद में भारत आ सकता है और इस नई कवायद से नई दिल्ली पर 500 फीसदी तक टैरिफ लग सकता है।

बांग्लादेश ने आखिर यह रवैया क्यों अपनाया है? इसके जवाब के लिए हमें अतीत में लौटना चाहिए। दरअसल, 1947 में भारत के विभाजन के बाद बेशक पाकिस्तान का जन्म हो गया, लेकिन सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से उसका पूर्वी व पश्चिमी हिस्सा एक-दूसरे से अलग था। दोनों जगह के समुदाय अलग-अलग संस्कृति जी रहे थे। पूर्वी हिस्सा काफी हद तक समावेशी था, तो पश्चिम पाकिस्तान को 1947 के बाद अमूमन संकीर्ण बना दिया गया। यहां तक कि पश्चिम पाकिस्तान पर दबदबा रखने वाला पंजाबी समुदाय पूर्वी हिस्से के बंगाली मुस्लिमों को दोयम दर्जे का मानता था, क्योंकि उसके मुताबिक, इनके पूर्वज हिंदू थे। इतना ही नहीं, मछली व कपास के कारण कमाई पूर्वी पाकिस्तान की अधिक थी, लेकिन खर्च पश्चिमी हिस्से में होता था। इसका असर दोनों इलाकों के विकास-कार्यों पर भी पड़ा। ये तमाम तथ्य बांग्लादेश के निर्माण की वजह बने।

हालांकि, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक विभेद बढ़ने पर बांग्लादेश ने 1971 में पाकिस्तान से अलग रास्ता जरूर चुन लिया, लेकिन आजादी मिलने के बाद भी उसकी मुश्किलों का अंत नहीं हो सका था। कुछ मसले महत्वपूर्ण बने हुए थे- मसलन, मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी फौज द्वारा किए गए नरसंहार के लिए माफी की मांग करना, जिसे पाकिस्तान ने नहीं माना। दूसरा, संपत्तियों का हस्तांतरण, जिसके तहत पाकिस्तान ने कुछ पैसे बांग्लादेश को देने का वायदा किया था, लेकिन इस्लामाबाद ने यह भी नहीं दिया।

तीसरा, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से 1947 में पूर्वी पाकिस्तान में बसे मुस्लिमों की मांग के अनुरूप पाकिस्तान द्वारा उन्हें स्वीकार न किया जाना, क्योंकि वे बांग्लादेश की नागरिकता नहीं चाह रहे थे। ये वही समुदाय हैं, जो जमात-ए-इस्लामी के काडर हैं और बांग्लादेश की आजादी के खिलाफ रहे हैं।

ढाका इसलिए भी परेशान था, क्योंकि पाकिस्तान ने शर्त रखी थी कि जब तक बांग्लादेश इस्लामी देशों के संगठन का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक उसका समर्थन नहीं किया जाएगा। आखिरकार 1974 में मुजीबुर्रहमान ने इस संगठन के सम्मेलन में शिरकत की, जिसके बाद चीन ने भी बांग्लादेश को मान्यता दी और यह राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना।

अभी जो कुछ हो रहा है, उसके बीज इन्हीं घटनाक्रमों में छिपे हुए हैं। वास्तव में, बांग्लादेश में एक धड़ा ऐसा है, जो 1971 के विचार को जीता है, जबकि दूसरा 1947 के। अवामी लीग पार्टी 'मुक्ति युद्ध' की समर्थक है और भारत के साथ अच्छे रिश्तों की हिमायती, वहीं उसके विरोधी दल (बीएनपी, जमात आदि सभी) पाकिस्तान के करीब रहना चाहते हैं। दुर्भाग्य से 2024 में सत्ता-परिवर्तन के बाद से ये विरोधी ही सत्ता पर काबिज हैं। वे वही काम कर रहे हैं, जो 1971 में आजादी के साथ ढाका ने रोक दिया था- इस्लामाबाद से व्यापार, सैन्य सहयोग व हवाई सेवा। इससे बांग्लादेश की वर्तमान हुकूमत को दो फायदा हो रहा है- एक, उसे राजनीतिक स्वीकार्यता मिल रही है। दूसरी- उसे धार्मिक तौर पर लाभ मिल रहा है। इसी कारण, ढाका भारत के विकल्प के रूप में पाकिस्तान को देख रहा है। सैन्य प्रशिक्षण और सहयोग के जो कार्यक्रम पहले नई दिल्ली के साथ चला करते थे, वे अब इस्लामाबाद के साथ चलाने के प्रयास हो रहे हैं। हालांकि, इसका लाभ शायद ही ढाका को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास उसे देने के लिए इस्लामी विचारधारा, आतंकवाद और गैर-लोकतांत्रिक विचार ही हैं।

चिंता की बात यही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की मंशा एक नए सामरिक गठबंधन बनाने की है, जिसमें चीन और बांग्लादेश तो होंगे ही, कतर व तुर्किये जैसे इस्लामी देशों को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि उनकी मौजूदगी बांग्लादेश में बढ़ रही है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। इससे तीन तरह की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पहली, भारत में आतंकवाद का प्रसार बढ़ सकता है। दूसरी, बांग्लादेश व पाकिस्तान में मजहबी कट्टरता में वृद्धि हो सकती है। और तीसरी, पूर्वोत्तर भारत के अलगाववादी गुटों को ठीक 2001-06 की तरह शह दी जा सकती है। रोहिंग्या का मुद्दा भी परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि इनकी संख्या 20 से 25 लाख हैं और ये जमीन व मकान-विहीन हैं। इनको चंद रकमों का लालच देकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। यह दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए सुखद तस्वीर नहीं होगी।

ऐसे में, भारत आखिर क्या करे? उसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मदद से बांग्लादेश में लोकतांत्रिक चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। यह चुनाव ऐसा हो, जिसमें अवामी लीग सहित तमाम राजनीतिक दलों की भागीदारी हो। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पिछले 18 महीने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने नागरिकों व मीडिया की आजादी पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई हैं और अपने मुल्क को धार्मिक कट्टरता की तरफ धकेल दिया है। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव ही बांग्लादेश को बचा सकता है।

यहां 'बॉयकॉट बांग्लादेश' जैसी रणनीति कारगर नहीं हो सकती। इसके बजाय हमारी हुकूमत को ढाका में अपनी उपस्थिति और अधिक बढ़ानी चाहिए। हम जितना अधिक बांग्लादेश से जुड़ेंगे, उतना ही हमारे लिए स्थिति सुखद बन सकती है। जाहिर है, यह समय सावधानी से साथ आगे बढ़ने का है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

काश! हाथों में मोबाइल की जगह लौट आएं किताबें

यहां स्कैन करें

धनंजय चोपड़ा | मीडिया प्राध्यापक, इलाहाबाद विवि.

आगामी 10 जनवरी से दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला शुरू हो रहा है। इससे पहले देश के कई शहरों में भीड़ भरे पुस्तक मेलों के सफल आयोजन हो चुके हैं, जिनमें किताबों की बेशुमार बिक्री दर्ज की गई है। यह प्रवृत्ति दुनियाभर में देखी जा रही है। अनायास नहीं है कि स्वीडन ने अपने यहां स्कूलों में लगाए उन सारे कंप्यूटर को हटा दिया है, जो डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2009 में लगाए गए थे। वहां एक बार फिर छपी हुई किताबें रखी जा रही हैं। यही नहीं, स्वीडन की सरकार ने स्कूलों में परंपरागत शिक्षण पद्धतियों को वापस लाने के लिए बहुत बड़ा बजट निर्धारित किया है।

ऐसा ही कुछ पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, जहां की सरकार ने 16 साल से छोटे बच्चों का सोशल मीडिया उपयोग प्रतिबंधित कर दिया। नार्वे और ब्रिटेन किताबों से जुड़ी तरह-तरह की सर्जनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों को आर्थिक मदद दे रहे हैं। अमेरिकी भारतीयों ने अपनी भाषा की पुस्तकों के पाठ के लिए घर-घर 'रीडिंग सेशन' संचालित करना शुरू किया है, जो बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। यहां यह बताना जरूरी है कि यूनिसेफ ने 2022 में ही इस बात की चेतावनी दे दी थी कि किशोरों में बढ़ रहे सोशल मीडिया उपयोग से उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक सरोकार की दुनिया संकुचित होती जा रही है। बच्चों को यदि उनका बचपन लौटाना है, तो उन्हें किताबें लौटानी होंगी।

निरंतर आयोजित होने वाले पुस्तक मेलों में उमड़ने वाली भीड़ तस्दीक करती है कि हम मजबूती के साथ किताबों की ओर लौट सकते हैं।

बहरहाल अपने देश में कई जगह किताबों की घर वापसी के लिए कमाल का काम हो रहा है। तकनीक और किताबें- दोनों के साथ नातेदारी बनाने की पहल भोपाल में हुई है, जहां नगर निगम के छह पुस्तकालयों में रोज सैकड़ों युवा विद्यार्थी पहुंच रहे हैं और अपनी उपस्थिति से वे किताबों की मेज पर वापस आने के ख्वाब पाल रहे हैं। केरल में किताबों को लेकर एक अनोखी पहल हुई है। यहां के पतनमथिट्टा जिले के आयुर्वेदिक अस्पताल ने मरीजों के इलाज में 'पढ़ाई' को शामिल किया है। रोचक है कि मरीजों को किताबें औषधीय पेड़-पौधों के बीच पढ़नी होती हैं। भरपूर ऑक्सीजन की उपलब्धता और मानसिक शांति का भाव इस पहल के केंद्र में हैं। 'पुस्तक कुट्टू' (किताबों से दोस्ती) नामक इस पहल को शुरू करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि इससे मरीजों में सार्थक सुधार देखने को मिल रहे हैं। जिस ओपीडी पर्ची पर दवाई मिलती है, उसी पर्ची पर किताबें भी मिल जाती हैं। इस पहल का ही परिणाम है कि कई जिलों में आशा कार्यकर्ता घर पर इलाज करा रहे लोगों तक किताबें पहुंचा-ले जा रही हैं।

'यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स' द्वारा हाल में किए एक अध्ययन के अनुसार, मात्र 6 मिनट तक किताब पढ़ने से 68 प्रतिशत तनाव कम हो जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि किताबें पढ़ने से मन-मस्तिष्क किसी काल्पनिक दुनिया में चला जाता है, जिससे किताब पढ़ने वाले का ध्यान तरह-तरह की उलझनों से हट जाता है और उसके रक्तचाप में कमी आती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि नियमित रूप से किताब पढ़ने पर न केवल मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि मृत्यु का जोखिम 20 प्रतिशत तक कम हो जाता है। देखें तो 21वीं सदी के 25 साल गुजर जाने के बाद स्क्रीन से ऊबी दुनिया अपने लिए ऑफलाइन स्पेस की होड़ में शामिल हो चुकी है। लोगों का किस्सागोई या ऑडियो पॉडकास्ट की ओर मुड़ना इसी का नतीजा है। जगह-जगह मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए कला-साहित्य उत्सव हो रहे हैं।

दुनिया में बढ़ते वर्चुअल ऑटिज्म के खतरे से निपटने में कारगर किताबों से दोस्ती निभाने में भारत बहुतेरे देशों से आगे है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब किताब छापने वाले देशों की सूची में 10वें स्थान पर आ गया है। सबसे ऊपर ब्रिटेन है, जहां लगभग 1,88,000 किताबें प्रतिवर्ष छपती हैं। भारत में अभी हर साल 24 से अधिक भाषाओं में लगभग 90,000 किताबें प्रकाशित हो रही हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत छपे हुए शब्दों की दुनिया में तेजी से आ रहा है। छोटे-बड़े शहरों में निरंतर आयोजित होने वाले पुस्तक मेलों में उमड़ने वाली भीड़ भी इस बात की तस्दीक करती है कि हम मजबूती के साथ किताबों की दुनिया में लौट रहे हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

जात-पात पूछे नहीं कोई

जगद्गुरु रामानंदाचार्य ने भारत में जो व्यापक प्रयोग किए, इसीलिए भी यह भूमि श्रेष्ठ हुई। भक्ति और भगवद् प्रेम को ऊंची जातियों से आगे विस्तार देते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि *जात-पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।* उनके शिष्यों में हर जाति-वर्ग की विभूतियां थीं। उन्होंने पहली बार महिला संतों को शिष्या रूप में स्वीकार किया। उनके परम प्रिय बारह शिष्यों में पद्मावती और सुरसरि भी थीं। ब्राह्मण अनंतानंद भी उनके शिष्य थे और जुलाहे कबीर भी। राजा पीपा भी शिष्य थे, चर्मकार रैदास भी। शिष्यों में धन्ना जाट भी थे और सेन नाई भी। उन्होंने भारतीय समाज को ऐसे संयोजित किया कि सनातन धर्म सबको प्रेरित करने वाला धर्म बन गया।

वैदिक सनातन धर्म केवल ब्राह्मणों का नहीं है, केवल भारत वालों का नहीं है, किसी भी प्रकार के भेदभाव का नहीं है। सनातन धर्म संपूर्ण मानवता का धर्म है। भगवान ने अनादि वेदों का स्मरण किया और संसार को वेद मिले। केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों को नहीं, सबको मिले। कहना चाहिए कि जैसे राम जी की तुलना राम जी से होगी और किसी से नहीं। ठीक वैसे ही रामानंदाचार्य की तुलना और किसी आचार्य से नहीं होगी। भारतीय समाज में रामानंदाचार्य अतुलनीय हैं। उन्होंने भक्ति और प्रेम की भाषा को सहज बनाकर जन-जन तक पहुंचाया। उन्हीं की छत्रछाया में बाद में हमें *श्रीरामचरितमानस* जैसा पावन-अनुपम लोक ग्रंथ लोकभाषा में प्राप्त हुआ।

अपना देश यूं ही नहीं महान है। हमारे संतों ने अपने मन से ही कहा, रे मन मूरख। यहां हम दूसरे को मूरख क्यों कहेंगे, अपने मन को ही कहेंगे और अपनी प्रेम-भक्ति का उत्थान करेंगे। रामानंदाचार्य ने अद्भुत कार्य किए, मानव जीवन और सनातन धर्म के लिए। उन्होंने सबको मिलाकर रखने के धार्मिक अभिप्राय को समझा।

कुछ लोग कहते हैं कि हम मानव धर्म को मानते हैं। वास्तव में, वैदिक सनातन धर्म से जुड़ा मनुष्य जीवन ही प्रशस्त है। सड़क से दूर खेत में कोई गाड़ी जा फंसी हो, तो पेट्रोलिंग वाले भी उसे कुछ नहीं बोलते हैं। जो गाड़ी नेशनल हाईवे पर हो, उसकी तत्काल मदद की जा सकती है, पर जो गाड़ी मार्ग पर ही नहीं है, उसकी मदद कौन करेगा? अतः हम स्वयं को भटकने न दें, इसीलिए

जगद्गुरु रामानंदाचार्य ने अपने जीवन में अद्भुत कार्य किए, मानव जीवन और सनातन धर्म के लिए। उन्होंने सबको मिलाकर रखने के धार्मिक अभिप्राय को समझा। जयंती पर विशेष :

रामानंदाचार्य हमें निर्मल मन के लिए प्रेरित करते हैं।

भारत में तो वैदिक सनातन धर्म है, लोग सुबह उठते हैं, तो हथेली पर ही ईश्वर के दर्शन कर लेते हैं। भगवान के नाम से सुबह की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी पर पांव रखने से पहले उसे प्रणाम करते हैं। पग-पग पर भगवत्स्मरण ही सनातन जीवन है। रामानंदाचार्य के पद पवित्र *गुरुग्रंथ साहिब* में भी सुशोभित हैं, जिसका भाव है कि आप अपने मन में परमात्मा को बसा लीजिए, तो फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।

रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामनरेशाचार्य

बेंजामिन नेतन्याहू | इजरायली प्रधानमंत्री

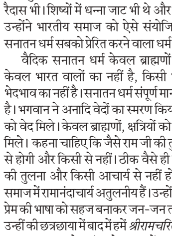

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सकारात्मक बातचीत और दोस्ती के लिए मैं भारत के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इजरायल भारत के साथ गहरी साझेदारी और आतंकवाद के खिलाफ हमारे साझा संकल्प का सम्मान करता है।

वैश्विक संस्था की लगातार बढ़ती उपेक्षा

आज की दुनिया एक गहरे नैतिक और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रही है, जहां अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है और नियम आधारित विश्व व्यवस्था केवल कागजों और भाषणों तक सिमटकर रह गई है। जिन सिद्धांतों पर यह व्यवस्था खड़ी थी, आज वही सिद्धांत सबसे अधिक उपेक्षित नजर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं होते, बल्कि उनकी व्याख्या ताकत और हितों के तराजू पर की जाती है। जब नियम शक्तिशाली देशों के हितों के अनुकूल होते हैं, तब उन्हें 'वैश्विक व्यवस्था' कहा जाता है, और जब वही नियम उनके रास्ते में बाधा बनते हैं, तब उन्हें नजरंदाज कर दिया जाता है या तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र से उम्मीद थी कि वेनेजुएला मसले पर वह सख्त रुख अपनाएगा, लेकिन वह मूक ही बना है।

हालिया उदाहरण बताते हैं कि किस तरह आर्थिक प्रतिबंध, राजनीतिक दबाव और बाहरी हस्तक्षेप को लोकतंत्र और मानवाधिकारों की आड़ में हथियार बना लिया गया है। किसी देश की सरकार की वैधता पर सवाल उठाना, समानांतर सत्ता को मान्यता देना, संसाधनों पर नियंत्रण की इच्छा और जनता को मजबूर कर देने वाले प्रतिबंध, ये सब उस व्यवस्था का चेहरा हैं, जो खुद को नियम आधारित कहती है। वेनेजुएला के संदर्भ में सत्ता-परिवर्तन की खुली बातें, तेल और प्राकृतिक संसाधनों पर पकड़ की लालसा और धमकी भरी भाषा यह बताती है कि आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता नहीं, बल्कि ताकत निर्णायक बनती जा रही है। यही प्रवृत्ति दुनिया के अन्य हिस्सों में भी दिखती है, जहां ग्रीनलैंड, क्यूबा, कोलंबिया या मेक्सिको जैसे देशों के बारे में अल्टीमेटम की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, मानो वे संप्रभु राष्ट्र नहीं हों।

अगर यही रुख जारी रहा, तो छोटे और कमजोर देशों के लिए अपनी स्वतंत्रता और पहचान बचा पाना बेहद कठिन हो जाएगा। यह स्थिति केवल किसी एक देश या क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जब नियम टूटते हैं और शक्ति ही न्याय बन जाती है, तब दुनिया अराजकता, युद्ध व हिंसा के अंधेरे में डूब जाती है। आज जरूरत इस बात की है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को फिर से नैतिक आधार दिया जाए, कानून को ताकत से ऊपर रखा जाए और यह स्वीकार किया जाए कि सच्ची वैश्विक शांति किसी एक देश के वर्चस्व से नहीं, बल्कि समानता, सम्मान और न्याय से ही संभव है। अन्यथा, इतिहास खुद को एक बार फिर विनाशकारी रूप में दोहराएगा।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

संयुक्त राष्ट्र

समय के साथ बढ़ रही उपयोगिता

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश से अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर रात के अंधेरे में हमला किया और उसके राष्ट्रपति को पत्नी सहित अपमानजनक ढंग से अपने देश ले गए। इससे विश्व व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। यह वही व्यवस्था है, जिसे संचालित करने की बड़ी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के पास है। आरोप लगाया जा रहा है कि यह संस्था अब निष्प्रभावी हो गई है। हालांकि, मैं इससे सहमत नहीं। अलबत्ता, इस घटना के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई, जिसमें महासचिव का यह कहना उचित था कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि सभी सदस्य देश इसके चार्टर का पालन करें, इसलिए यह कहना गलत होगा कि इस विश्वस्तरीय संस्था की उपादेयता समाप्त हो गई है।

वास्तव में, दोष इस संस्था में नहीं, इसके कुछ सदस्य देशों में है। वे इसके मूल्यों को मानने से इनकार करने लगे हैं। यही कारण है कि यूएन की बैठक में मतभेद भी दिखे। रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों ने अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की, जबकि दक्षिण अफ्रीका, ईरान जैसे राष्ट्रों ने खुलकर कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय कानून सब पर समान रूप से लागू नहीं होंगे, तो पूरी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी। उनकी चिंता जायज है। सवाल यह भी है कि क्या इस संस्था का कोई विकल्प आज के समय में है? गौरतलब है कि वीटो अधिकार देशों को मिला था, उनके नेताओं को नहीं, लेकिन ये नेता वीटो का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते। ऐसे में, जरूरी यह है कि इस संस्था में सुधार हो, न कि इसकी प्रासंगिकता खारिज कर दी जाए।

किसी महत्वपूर्ण कामकाजी संस्था पर आक्षेप लगा देना, उसके महत्व को निर्मूल्य कह देना बहुत आसान है, लेकिन उसकी स्थापना, उसका नियमित सुचारू संचालन कदापि सुगम नहीं होता। संस्था को दोषी सिद्ध करने से उस पर काबिज दोषी व्यक्ति का दोष कमतर या शून्य हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर उंगली उठाते समय क्या आप डोनाल्ड ट्रंप की मूढ़ता और हठधर्मिता को कम नहीं कर रहे होते हैं? संयुक्त राष्ट्र के पास अपना कोष नहीं है, उसकी निर्भरता सदस्य राष्ट्रों पर है। वास्तव में, कुछ सदस्य राष्ट्र उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। लिहाजा, इसमें दोष ढूंढ़कर इसे बदनाम करने या नष्टप्राय करने के बजाय इसे कैसे और प्रभावशाली, सक्षम व न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। बदलते भू-राजनीति के इस दौर में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक है। हमें इसमें सुधार की वकालत करनी चाहिए।

दिनेश सिंह, चिकित्सक

नमक, चीनी, मैदा कम खाएं तो अच्छा

नमक, मैदा और चीनी खाने का स्वाद तो बढ़ा देते हैं, लेकिन लंबे समय तक इनका अधिक सेवन शरीर पर बुरा असर डालता है, इसलिए इसे सफेद जहर भी कहा जाता है। खासकर, चालीस के बाद दिल, किडनी, मोटापा और डायबिटीज संबंधी समस्याओं से बचाव के लिए इनके सेवन में एहतियात बरतना जरूरी हो जाता है। बता रही हैं स्मिता

चालीस की उम्र के बाद शरीर में तेजी से बदलाव आने लगता है। शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है और शरीर छोटी-छोटी गलतियों का हिसाब मांगने लगता है। ऐसे में खानपान का खास ध्यान रखना जरूरी हो जाता है।

ऑक्सफोर्ड अकादमिक के जर्नल एनिमल फ्रंटियर में छपे हालिया शोध बताते हैं कि 40 साल से अधिक उम्र के लोगों की थाली में सफेद जहर यानी नमक, चीनी और मैदे की अधिकता शरीर को नुकसान पहुंचाती है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर की मरम्मत करने वाले सिस्टम कम असरदार हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है, हार्मोनल बदलाव आते हैं। ऐसे में नमक, चीनी और मैदे की अधिकता हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और किडनी की समस्याओं के उभार का कारण बन सकती है।

सफेद जहर को समझें

न्यूट्रिशन साइंस में व्हाइट पॉइजन यानी 'सफेद जहर' रिफाइंड और प्रोसेस्ड सफेद खाने की चीजों से जोड़कर देखा जाता है, जैसे चीनी, नमक, मैदा और कभी-कभी सफेद चावल/आलू, जिनमें प्रोसेसिंग के दौरान पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इसमें पाश्चुराइज्ड मिल्क को भी शामिल किया जाता है। हालांकि मुख्य रूप से सफेद चीनी-नमक-मैदा पर बात की जाती है, जिनका असर मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोगों पर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। यही वजह है कि ऐसे रोगों में डॉक्टर सबसे पहले इन्हें कम खाने की सलाह देते हैं।

दिल्ली के सीके बिड़ला हॉस्पिटल में डायरेक्टर (इंटरनल मेडिसिन) डॉ. मनीषा अरोड़ा के अनुसार, 'नमक, मैदा और चीनी, ये तीनों खाने का स्वाद बढ़ाते हैं। प्रोसेस्ड और रेडी-टू-ईट फूड में ज्यादातर मैदे का बेस होता है और जरूरत से कहीं ज्यादा चीनी और नमक मिलाया जाता है। स्वाद के कारण इन्हें बार-बार खाने की ललक होती है, लेकिन इनका अधिक सेवन चुपचाप कई गंभीर व पुराने रोगों का कारण बन जाता है। ये तीनों मिलकर मेटाबॉलिक रोगों की नींव डाल देते हैं।'

नमक को ना कहें

नमक शरीर के लिए जरूरी है। यह नसों व मांसपेशियों के सुचारू रूप से काम करने और शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन, ज्यादा नमक लेने से रक्तवाहिकाओं में तरल पदार्थ बढ़ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। लंबे समय तक हाईबीपी से नसों पर दबाव पड़ता है और धमनियां खराब होती हैं। जो लोग पहले से हृदय समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनका अधिक नमक खाना अटैक व स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है।

हमारे शरीर में किडनी, सोडियम का संतुलन बनाए रखती हैं, पर नमक की अधिकता होने पर किडनी के लिए उसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। धीरे-धीरे इससे किडनी की कार्यक्षमता कम हो सकती है, शरीर में पानी जमा हो सकता है, पैरों व चेहरे पर सूजन आ सकती है। पथरी का खतरा बढ़ जाता है। गंभीर मामलों में किडनी फेलियर भी हो सकता है।

कुछ हेल्थ एक्सपर्ट 'सॉल्ट बैंक' का कॉन्सेप्ट बताते हैं, जिसमें लोग जानबूझकर अपने रोज के नमक का हिसाब रखते हैं और उसे सीमित करते हैं। विदेश में डाइनिंग टेबल पर रखे नमकदानियों के छेद छोटे किए गए हैं, ताकि लोग कम नमक लें। एक साथ ज्यादा नमक खाने से बचना जरूरी है।

क्या कहते हैं शोध

1. इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबोलिज्म में छपे शोध के अनुसार, भारत दुनिया में चीनी व नमक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश है। सफेद चीनी मेटाबोलिज्म की सबसे बड़ी दुश्मन है। वहीं अधिक नमक खाने से हाइपरटेंशन, फाइब्रोसिस, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां, सूजन, पथरी व किडनी फेलियर का खतरा बढ़ सकता है।
2. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, पश्चिमी देशों की नकल पर फास्ट फूड खाने का चलन भारत में तेजी से बढ़ा है, जिसमें मुख्य रूप से मैदा मौजूद रहता है। स्वाद बढ़ाने के लिए इनमें नमक व चीनी भी अधिक होते हैं। मैदा पाचन समस्याएं बढ़ाने के साथ डायबिटीज का खतरा भी बढ़ाता देता है।
3. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जर्नल में छपे शोध के अनुसार, ज्यादा मात्रा में चीनी लिवर पर दबाव डालती है। लिवर पर चीनी का असर उसी तरह होता है, जिस तरह अल्कोहल का।

नमक से बढ़ाएं दूरी

- अपने दिनभर के भोजन में नमक 5 ग्राम से कम रखें।
- खाना बनने के बाद ऊपर से नमक न डालें।
- दही, फल व सब्जियों के सलाद में ऊपर से नमक न छिड़कें। अनाज व सब्जियों में कुदरती नमक भी होता है। ऐसे में नीबू, धनिया, अजवाइन, काली मिर्च आदि से स्वाद बढ़ाएं।
- पैकेज्ड सूप, नमकीन, बिस्किट से दूरी बनाएं।

मैदे से ऐसे बचें

- सफेद ब्रेड की जगह मल्टीग्रेन या आटा ब्रेड चुनें। वे भी सीमित मात्रा में खाएं।
- समोसे, पिज्जा, बर्गर को रोजमर्रा की थाली से हटाएं।
- रोटी के आटे में गेहूं के साथ चना, ज्वार, बाजरा, ओट्स, रागी आदि भी शामिल करें।
- मैदे से बनी चीजों में सब्जियां खूब मिलाएं। खासकर, नूडल्स, पिज्जा या सैंडविच खाते समय इसका ध्यान रखें।

ऐसे कम करें चीनी

- अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन महिलाओं के लिए रोजाना अधिक से अधिक 25 ग्राम और पुरुषों के लिए रोजाना 36 ग्राम चीनी खाने की सलाह देता है।
- चाय-कॉफी में मीठा कम लें।
- मीठे के लिए फल व कुदरती मिठास वाली चीजें खाएं। रिफाइंड व आर्टिफिशियल शुगर वाली चीजों से बचें।
- कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड जूस से पूरी तरह बचें।

मैदे से दूरी बनाएं

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड, अधिक तली-भूनी चीजें और जंक फूड में ज्यादातर मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे भोजन स्वाद और लंबे समय तक टिकने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इनमें पोषण बहुत कम होता है। मैदा बनाने की प्रक्रिया में इसके फाइबर, विटामिन व मिनरल नष्ट हो जाते हैं। मैदा आंतों से चिपक कर मेटाबॉलिज्म बिगाड़ता है और चर्बी बढ़ाता है। मैदे में मौजूद रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत तेजी से ग्लूकोज में बदल जाता है। इससे ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोतरी होती है और फिर इंसुलिन तेजी से रिलीज होता है। बार-बार ऐसा होने पर शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। कई रिसर्च यहां तक साबित कर चुके हैं कि मैदा और मैदे से बने अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाने से डिप्रेशन की समस्या भी बढ़ती है।

ज्यादा मिठास अच्छी नहीं

अक्सर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि वे कितनी ज्यादा चीनी खा रहे हैं, खासतौर पर मीठे ड्रिंक्स, मिठाइयों, पैकेज्ड स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड के जरिये। ज्यादा चीनी लिवर पर सीधा बोझ डालती है, क्योंकि लिवर अतिरिक्त शुगर को फैट में बदल देता है। युवाओं में फैटी लिवर की बढ़ती समस्या का एक बड़ा कारण चीनी का अधिक सेवन भी है। चीनी लिवर की अन्य समस्याओं के खतरे को भी बढ़ाती है।

इसके अलावा ज्यादा चीनी से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज होती है, साथ ही शरीर में सूजन बढ़ती है। ज्यादा चीनी मूड में भी उतार-चढ़ाव का कारण भी बन सकती है। कैंसर की स्थिति में डॉक्टर कम चीनी खाने की सलाह देते हैं।

खासकर चाशनी और कृत्रिम मिठास वाले शुगर सिरप मुख्य रूप से ब्लड शुगर और यूरिक एसिड बढ़ाकर ब्लड वेसेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर जब मोटापा और शरीर में पानी की कमी हो, तो चीनी का अधिक सेवन किडनी के गंभीर रोगों का खतरा बढ़ा सकता है।

एक साथ अधिक खाने से बचें

जब नमक, मैदा और चीनी एक साथ खाए जाते हैं-जैसे फास्ट फूड, बेकरी आइटम्स और डिब्बा बंद चीजें- तो ये शरीर में मेटाबॉलिक तूफान खड़ा कर देते हैं। इससे मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, किडनी डैमेज और दिल की बीमारियां होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। समय के साथ ये समस्याएं और अधिक बढ़ती हैं।

फरीदाबाद स्थित एशियन हॉस्पिटल की आहार व पोषण विशेषज्ञ कोमल मलिक कहती हैं, 'इन तीनों का अधिक सेवन दिमाग पर भी असर डालता है। ज्यादा नमक दिमाग की नसों पर दबाव बढ़ाता है। याद्दाश्त कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। मैदा आंतों की सेहत बिगाड़ता है, जिससे आंतों में मौजूद सूक्ष्म जीवों का संतुलन बिगड़ता है, जो दिमाग पर असर डालता है। चिड़चिड़ापन, थकान और फोकस की कमी दिखने लगती है। अधिक चीनी दिमाग में डोपामाइन के स्तर को असंतुलित करती है। इससे मूड स्विंग्स, बेचैनी और डिप्रेशन तक की समस्या हो सकती है।'

कुल मिलाकर 40 के बाद बेहतर है कि घर का ताजा खाना खाएं। बढ़ती उम्र के साथ मसाले कम खाएं और पौष्टिक भोजन खाएं।

सवाल-जवाब

सीढ़ियां चढ़ने पर आए पसीना तो अनदेखी न करें

डॉ. पुलिन गुप्ता
प्रोफेसर (मेडिसिन), राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, नई दिल्ली

- **सवाल : मेरी उम्र 40 साल है। मैं थोड़ा-सा भी चलता हूं या भारी सामान उठाता हूं, तो मुझे पसीना आने लगता है। क्या यह हृदय रोग की समस्या है? मुझे क्या करना चाहिए?**

जवाब : हां, यह हृदय से जुड़ी समस्या हो सकती है। अब भारत में हृदय रोग व हृदयाघात के मामले कम उम्र में भी देखने को मिल रहे हैं। चलने पर या भारी सामान उठाने पर पसीना आता है, सांस फूलती है, तो इसे हम एंजाइना इक्विवलेंट कहते हैं, जो दिल से ही जुड़ी समस्या है। इसके लिए फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। वे ट्रेडमिल टेस्ट, इको टेस्ट या अन्य किसी टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। आजकल सीटी स्कैन से भी एंजियोग्राफी होती है। थायरॉइड में भी पसीना आता है। अपनी स्थिति की अनदेखी न करें। डॉक्टर से मिलकर सही कारण जानें ताकि शुरुआत में ही स्थिति को काबू किया जा सके।

- **सवाल : मेरी उम्र 35 है। अक्सर मेरे हाथ में कंपन होता है। क्या यह पार्किन्सन है? हमारे परिवार में इस बीमारी का कोई इतिहास नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए?**

जवाब : इस उम्र में पार्किन्सन आमतौर पर नहीं होता। इसका असर 60 के बाद देखने को मिलता है। हालांकि, कुछ मरीजों में जिन्हें कई बार स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज हुआ हो या कोई ऐसा वायरल फीवर हुआ हो, जिसका असर दिमाग पर हो जाए, तो पार्किन्सन के लक्षण कम उम्र में भी देखने को भी मिल सकते हैं। हालांकि, ऐसा होता कम है। अगर इस उम्र में हाथ में कंपन हो रहा है, तो इसका कारण बहुत ज्यादा कॉफी, सिगरेट व चाय का सेवन करना हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को एंग्जाइटी की समस्या हो, मन विचलित रहता हो, उनमें भी किसी विषय का तनाव होने पर घबराहट में कंपन रहने लगता है। इसका एक अन्य कारण है असेंशियल ट्रेमर, यह तंत्रिका तंत्र से जुड़ी स्थिति है, जिसमें कंपन होता है। इन तीनों ही स्थिति का उपचार संभव है। कुछ लोगों को हाइपोथायरॉइड की समस्या होती है। इसमें थायरॉइड ग्रंथि से स्राव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में भी शरीर में कंपन होता है, इसलिए बेहतर है कि आप सबसे पहले अच्छे फिजिशियन से मिलें और सही कारण तक पहुंचकर उस के अनुरूप उपचार कराएं।

- **सवाल : मेरी उम्र 41 साल है, पिछले कई महीने से सीधा पैर सोते हुए सुन्न हो जाता है या पिंडली की तरफ चमक सी उठती है। ऐसा क्यों होता है?**

जवाब : हमारी रीढ़ की हड्डी से कुछ नसें निकलती हैं, जो पैरों तक जाती हैं। कई बार डिस्क की समस्या होती हैं या निचले हिस्से में कसाव आ जाता है, जिसे लंबर कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं, इस कारण ऐसा सुन्नपन आ जाता है। आमतौर पर ऐसा डिस्क की समस्या के कारण होता है, जिसमें नस दब जाती है। ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति को चलने में दर्द होता है, तो कुछ लेटने पर दर्द महसूस करते हैं। इसके लिए आप अच्छे हड्डीरोग विशेषज्ञ या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। आमतौर पर कुछ दवाओं और थोड़े समय लगातार फिजियोथेरेपी की मदद से आराम आ जाता है। 10 प्रतिशत मामलों में सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है।

भेजें अपने सवाल

सेहत से जुड़े सवाल **tanmanhindustan@gmail.com** पर मेल करें। आप इस पते पर भी सवाल भेज सकते हैं-

तन-मन, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301

दोपहर में भोजन के बाद नहीं सताएगी नींद

कामकाजी लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि दोपहर में भोजन के बाद थकान और नींद हावी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचें...

दोपहर के समय भोजन के बाद थकान और नींद का अहसास होना सामान्य है। यह संकेत है कि हम पौष्टिक और संतुलित भोजन नहीं कर रहे हैं। ऐसा शरीर की जैविक घड़ी के थोड़ा धीमे पड़ने के कारण भी होता है। पर हम भारतीयों में इसका बड़ा कारण है, अधिक कार्बोहाइड्रेट लेना और व्यायाम की कमी।

1. क्या खाते हैं?

दोपहर का भोजन आमतौर पर एक से तीन बजे के बीच खाया जाता है। सुबह भागदौड़ अधिक होती है और रात में देर हो जाने के कारण आमतौर पर दोपहर का भोजन ही तसल्ली से किया जाता है।

कई बार भोजन में एक साथ कई चीजें ग्लूकोज इंडेक्स बढ़ाने वाली होती हैं, मसलन चावल, गेहूं, आलू आदि। वहीं प्रोटीन और फाइबर कम होता है। इस कारण खाने के बाद शरीर में शुगर तेजी से बढ़ता है और शरीर में थकान हावी होने लगती है। आमतौर पर भोजन के एक घंटे के बाद शुगर बढ़ता है। अगर पहले से शुगर की समस्या है और भोजन में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और नसों पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा चावल, चिकन, गेहूं, आलू, चीनी और बेक्ड चीजें मस्तिष्क में मेलाटोनिन का उत्पादन बढ़ा देती हैं, जिससे नींद आती है।

2. देर से सोना, कम सोना

रात में देर से सोना और सुबह जल्दी उठना भी दोपहर में नींद आने का बड़ा कारण है। विशेषज्ञों के अनुसार, एक रात में छह घंटे से कम की नींद इंसुलिन संवेदनशीलता को 15 से 25 प्रतिशत तक कम कर देती है।

3. पानी कम, चाय ज्यादा

आमतौर पर ऑफिस मीटिंग्स, छोटे ब्रेक के दौरान चाय और कॉफी कई बार हो जाती है। इससे थकान कुछ देर के लिए दूर हो जाती है, पर इसका असर रात की नींद पर पड़ता है। ऐसे में अगले दिन भी नींद का नशा बना रहता है। पानी कम पीना भी शरीर में थकान और उनींदापन बढ़ा देता है।

3. कुर्सी पर बैठे रहना

कई बार हम काम के बीच में देर तक बैठे ही रह जाते हैं। छोटे-छोटे ब्रेक में भी फोन में व्यस्त रहते हैं या आपसी बातचीत में कुर्सी पर ही बैठे रह जाते हैं। ये निष्क्रिय जीवनशैली थकान बढ़ा देती है। बीच-बीच में सीट से उठना या भोजन के बाद कुछ देर चलना जरूरी है, क्योंकि अधिकतम ग्लूकोज हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस तरह शुगर की खपत जल्दी हो जाती है। बेहतर है कि काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें, सीट से उठें। कुछ देर पैदल चलें। इससे मांसपेशियों के ग्लूकोज ग्रहण करने की प्रक्रिया बेहतर होती है, पेट में अफारा नहीं आता और खाने के बाद आने वाली नींद को रोकने में मदद मिलती है।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। कारोबार में वृद्धि होगी। कारोबार के लिए यात्रा लाभदायक रहेगी।

वृष : मन में निराशा व असंतोष रहेगा। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों की अधिकता रहेगी। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। बाधाएं आ सकती हैं।

मिथुन : आत्मसंयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। बातचीत में संतुलित रहें। परिवार का साथ मिलेगा। मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि के साधन बन सकते हैं।

कर्क : कारोबारी कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। घर-परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य हो सकते हैं। भवन के रख-रखाव तथा साज-सज्जा पर खर्च बढ़ सकते हैं।

सिंह : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। करोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे।

कन्या : मन में शांति व प्रसन्नता रहेगी। भवन सुख में वृद्धि हो सकती है। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा।

तुला : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नए कारोबार की शुरुआत के लिए परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। भागदौड़ अधिक रहेगी।

वृश्चिक : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। कारोबार में कठिनाई आ सकती हैं। परिवार का साथ मिलेगा। शैक्षिक कार्यों के प्रति सचेत रहें। व्यवधान आ सकते हैं।

धनु : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। आय में वृद्धि के साधन भी बन सकते हैं।

मकर : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। जीवनसाथी की सेहत में सुधार होगा। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। आय में कमी व खर्च अधिक की स्थिति हो सकती है।

कुंभ : मन परेशान हो सकता है। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। वस्त्र उपहार में मिल सकते हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी।

मीन : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में अवसर मिल सकते हैं। कारोबार के लिए यात्रा पर जा सकते हैं।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

09 जनवरी, शुक्रवार **शक संवत्:** 19 पौष (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग:** 26 पौष मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम:** 19 रज्जब, 1447, **विक्रमी संवत्:** माघ कृष्ण सप्तमी तिथि (दिन-रात), उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 01.41 बजे तक पश्चात हस्त नक्षत्र, शोभन योग सायं 04.56 बजे तक पश्चात अतिगण्ड योग। चंद्रमा कन्या राशि में (दिन-रात)।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा सायं 07.45 मिनट तक।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कृपया यह बताएं कि वास्तु के अनुसार भूमि की सतह किस प्रकार से होनी चाहिए?
-चंद्रकांता शर्मा, मेरठ

- पूर्व दिशा में ऊंची भूमि पुत्र और धन का नाश करती है।
- दक्षिण दिशा में ऊंची भूमि कामनाओं की पूर्ति और स्वास्थ्य प्रदान करती है।
- दक्षिण पश्चिम में ऊंची भूमि धन प्रदान करती है। पश्चिम में ऊंची भूमि पुत्र प्रदान करने वाली तथा धन धान्य की वृद्धि करने वाली होती है।
- उत्तर दिशा में ऊंची भूमि पुत्र और धन के लिए बहुत अशुभ होती है। उत्तर पूर्व दिशा में ऊंची भूमि क्लेश कारक तथा सब प्रकार से नुकसान करती है।

वर्ग पहेली : 8204

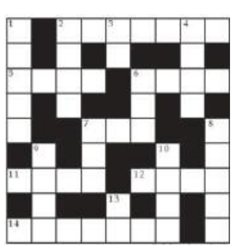

बाएं से दाएं
2. निष्ठा न होना; भरोसा न करना; विश्वास न करना; यकीन न करना (4,3)
5. ऊंचा करके बांधना, खड़ा करके झुकाना; काम लंबित रखना (4)
6. बारीक सूत से बुना पतला कपड़ा (4)
7. परंपरा; परिपाटी; प्रथा; रिवाज; व्यवहार (3)
11. यंत्र रखने का स्थान; यंत्रालय; वेधशाला (4)
12. धीरे-धीरे मलना; हाथ फेरना; गुदगुदाना; खुजलाना (4)
14. नष्ट करना; तहस-नहस करना (4,3)

ऊपर से नीचे
1. आहत होना; क्षत होना; घाव लगना; चोट खाना; (3,2)
2. अड़ंगा लगाना; अड़ाना; उलझाना; रोकना (4)
3. असु; उदान; प्राण तत्व; सांस (2)
4. कृपा; दया (4)
6. कनकना; झीना; पतला; बारीक (3)
7. रोटी बेलने का गोल पाटा; चक्की; चौड़ा (3)
8. जिसका आकार बेलन जैसा हो; गोलाकार; गोल लंबे दस्ते जैसा (5)
9. समाचार लिखने वाला; संपादक; संवाददाता (4)
10. कलरव करना; पक्षियों जैसे मधुर स्वर करना; प्रसन्न होकर अधिक बोलना (4)
13. गलती; भूल; दरार; दर्ज (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8203

सुडोकू : 8186

*मध्यम

		5		2				
1					4			2
2			8		7	9		
4	5					8		6
3								9
7		2					5	4
		7	4		6			5
6			3					1
				8		3		

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8185

9	1	6	8	2	7	3	5	4
2	7	5	3	6	4	1	8	9
8	3	4	5	9	1	2	7	6
1	6	2	4	8	5	7	9	3
3	4	8	2	7	9	6	1	5
7	5	9	6	1	3	8	4	2
5	9	1	7	3	2	4	6	8
4	8	3	1	5	6	9	2	7
6	2	7	9	4	8	5	3	1

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 09-01-2026 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH10 User: cci Time: 01-08-2026 22:09 Color:

जहां शक्ति का मनमाना प्रयोग होता है, वहां अंतरराष्ट्रीय कानून टिक नहीं सकता।
– हांस मॉरगेनशॉ, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ

नाकामी पर परदा

वेनेजुएला और ग्रीनलैंड में उलझे डॉनल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। उनका नया प्रस्तावित बिल और भी एकतरफा, मनमाना और अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। खुद उनकी सरकार को यह कहने में संकोच नहीं कि इससे अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरे देशों पर दबाव बनाने की शक्ति मिलेगी।

दूसरों पर जिम्मेदारी । नए बिल के मुताबिक, रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाया जा सकता है। इस बिल पर अगले हफ्ते वोटिंग की उम्मीद है। अमेरिका के निशाने पर मुख्य रूप से भारत, चीन और ब्राजील हैं। बहाना उसका वही पुराना है कि रूस इन देशों को तेल बेचकर यूक्रेन युद्ध के लिए संसाधन जुटा रहा है। हालांकि हकीकत यही है कि अमेरिका और यूरोप की युद्ध रुकवाने की अभी तक की सारी कोशिशें नाकाफी साबित हुई हैं, लेकिन वॉशिंगटन उस नाकामी को दूसरों पर डालना चाहता है।

500% टैरिफ की धमकी

रूस पर असर नहीं । पिछले महीने अमेरिका ने उत्साह के साथ फ्लोरिडा में यूक्रेन, रूस और यूरोप के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठक की थी। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इन बैठकों का हिस्सा थे और इनमें यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर खास फोकस रहा। लेकिन, लगता नहीं कि इन बैठकों का कोई असर पड़ा, क्योंकि इनके साथ-साथ रूसी हमलों में भी तेजी आई है। अब ब्रिटेन और फ्रांस ने एक सहमति पत्र पर साइन किए हैं, जिसके मुताबिक शांति समझौते के बाद वे यूक्रेन में सेना तैनात करना चाहते हैं, जबकि रूस इसके विरोध में है।

तेल की हकीकत । रूस और यूक्रेन के बीच का मसला कई बिंदुओं पर उलझा हुआ है, पर ट्रंप प्रशासन उसका सरलीकरण करके उसे सिर्फ एक नजर से देख रहा है - तेल की खरीद। अजीब बात है कि खुद ट्रंप के दावे के मुताबिक, भारत अब रूस से कम तेल आयात कर रहा है।

कूटनीतिक जवाब । युद्ध से लेकर तेल तक, ट्रंप हर दिन कोई नया दावा करते हैं। हाल में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और अपाचे हेलिकॉप्टर की डील पर बयान दिया, जिसमें गलतियां थीं। ट्रंप की बातें पारंपरिक कूटनीतिक भाषा से अलग और असामान्य हैं। भारत को विरोध दर्ज कराने के लिए कूटनीतिक रास्ता ही अपनाना चाहिए। वॉशिंगटन तक यह बात पहुंचानी जरूरी है कि उसके कदम द्विपक्षीय रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर वार्ता चल रही है, तो फोकस उसी पर होना चाहिए। बहरहाल, ट्रंप सरकार की इन ऊटपटांग हरकतों की वजह से अमेरिका दुनिया का भरोसा गंवाता जा रहा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से उसकी सबसे बड़ी करंसी रही है।

तिराहा

'घंटा' एक इमोशन है

कड़कड़ाती ठंड में सुरम्य पसीने से तर था। वह हाफ टी-शर्ट पहने घर में जैसे ही घुसा, रजाई में बैठी उसकी मां सुधर्मा ने उलाहना दिया, 'इतनी ठंड में फैंटम मत बनो।' 10 किमी की दौड़ और युवा ऊर्जा से उबला रक्त स्वर बन फूट पड़ा, 'घंटा ठंड...।' वाक्य पूरा भी नहीं हुआ कि 'चटाक' की इतनी तेज आवाज आई कि सुखनंदन के हाथ से अखबार छूट गया। 'तमीज भूल गए हो बड़ों से बात करने की', वार के बाद सुधर्मा ने शब्द प्रहार किया।

प्रेम शंकर मिश्र

सुखनंदन ने भकुआए हुए बेटे के कंधे पर हाथ रखा, समझाया, 'बेटा! घंटा शब्द नहीं, दर्शन है। इसके उपयोग के नियम हैं। देखो! नेताजी ने कहा 'घंटा', उनका कुछ नहीं हुआ। अधीनस्थ ने सुन कर लिख दिया 'घंटा', सस्पेंड हो गया। इसलिए, वर्जनाओं को समझना होगा।'

'घंटा एक इमोशन है, इसके उपयोग के प्रकार पर अगला मोशन निर्भर करता है। विद्यालय में कर्मचारी ने घंटा बजाया तो छुट्टी और मिठाई, विद्यार्थी ने बजा दिया तो दंड और पिटाई। देवस्थल पर घंटा नहीं बजाया तो मान्यता है कि सदैव चैतन्य रहने वाले परमेश्वर तक भी आवाज नहीं पहुंचती। कोई कहे कि अमुक चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता, यानी उसे बहुत फर्क पड़ा है। आनंद, तंज, अवसाद, अहंकार, अवस्था पर इसका अर्थ निर्भर है।'

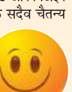

'घंटा में कायांतरण की अद्भुत क्षमता है। मसलन, मंत्री के लिए बच्चों की मौत घंटा है। तानाशाह के लिए लोकतंत्र घंटा है। सक्षम के लिए जवाबदेही, कानून घंटा है। कमजोर के लिए उसकी बेबसी घंटा है। ट्रंप के लिए वेनेजुएला का राष्ट्रपति घंटा है। नकल कर लिया तो सेना भेज कर घंटे की तरह टंगवा दिया। लोकतंत्र में आम आदमी घंटा है। दुष्यंत कुमार ने इसे झुनझुना भी कहा था - जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी हम झुनझुने हैं।'

'कुल मिलाकर आप कहना चाह रहे हैं कि घंटा यंत्र नहीं बल्कि सामाजिक, मानसिक स्थिति समझने का मंत्र है', सुरम्य ने निष्कर्ष दिया। बेटे की समझ से सुखनंदन का सीना गर्व से फूल उठा।

एकदा

संकलन : **दीनदयाल मुरारका**

शिवाजी का दान

महाराष्ट्र के सतारा में पवित्र स्थान माहुली-संगम है, जहां कृष्णा और वेन्ना नदियां मिलती हैं। एक दिन संत समर्थ रामदास यहां स्नान करने के बाद भिक्षा मांगते हुए शिवाजी महाराज के किले पर पहुंचे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, 'जय-जय श्रीरघुवीर समर्थ!' यह सुनते ही शिवाजी महाराज का हृदय आनंद से भर उठा। वह सोचने लगे कि सद्गुरु को क्या भिक्षा दी जाए। उन्होंने एक कागज पर लिखा, 'श्रीसमर्थ के चरणों में अपना संपूर्ण राज्य अर्पित करता हूं।' और कागज समर्थ की झोली में डाल दिया और प्रणाम किया। समर्थ ने सहज भाव से पूछा, 'क्यों शिवा, आज अन्न के स्थान पर कागज का टुकड़ा ही दे रहे हो?' जब उन्होंने पत्र पढ़ा, तो उसका आशय समझकर मुस्कराए और बोले, 'राज्य तुमने मुझे दे दिया, अब तुम क्या करोगे?' शिवाजी ने विनम्रता से कहा, 'आपकी चरण-सेवा में जीवन बिताऊंगा।' यह सुनकर समर्थ बोले, 'नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ब्राह्मणों का धर्म ज्ञान और तप है, और क्षत्रियों का धर्म राज्य की रक्षा। अपने-अपने कर्म को सही ढंग से निभाने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।' इस प्रकार समर्थ ने शिवाजी को कर्तव्य, धर्म और राजधर्म का मर्म समझाया।

Subrata Dhar

Grok से आपत्तिजनक तस्वीरें तैयार कराना तकनीक का ख़तरनाक पहलू

सभी को AI की क्या ज़रूरत

निमिष दुबे और आकृति राणा

AdobeStock

काबू में रखना होगा
- AI कंपनियों को सुरक्षा उपाय लागू करने चाहिए
- कंटेंट संग जानकारी हो कि रियल है या जेनरेटेड
- AI टूल्स तक आसान पहुंच पर फिर से विचार हो

हाल के दिनों में हमें AI के खतरनाक रूप के दर्शन हुए। जिस तरह से महाभारत में दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, वैसे ही X (पूर्व में ट्विटर) के AI, Grok ने अपने यूजर्स के कहने पर तस्वीरों से कपड़े गायब करने शुरू कर दिए।

चिंताजनक ट्रेंड । खतरे की घंटी यह है कि इस घटिया काम को करने के लिए किसी विशेष ज्ञान या हैकिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने सामान्य से चित्र डालकर ग्रोक से कहा कि इसके कपड़े हटा दो या कम कर दो। हैरान करने की बात है कि कई मामलों में Grok ने बिना कोई आपत्ति जताए ऐसा ही किया। हां, कुछ मामलों में उसने जरूर कहा कि उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं है, लेकिन कुछ में ही। नतीजा, इंटरनेट पर AI से तैयार लोगों की नग्न और अर्धनग्न तस्वीरें वायरल होने लगीं।

असली बनाम नकली । हमेशा की तरह इस हैवानियत के कई शिकार लड़कियां, महिलाएं और कम उम्र के बच्चे थे। इनकी तस्वीरों को करोड़ों लोगों ने देखा, वह भी बिना उनकी मंजूरी के और कई मामलों में बिना उनकी जानकारी के। और AI से तैयार इन चित्रों की क्वॉलिटी कई बार इतनी अच्छी थी कि लोगों को ये असली लगे! यह आर्टिकल लिखने तक परिस्थिति पर कुछ काबू पा लिया गया था। सरकार ने इसे लेकर X को कानूनी नोटिस भी भेजा। लेकिन, पूरे घटनाक्रम ने AI से जुड़े खतरों को एक बार फिर सबके सामने उजागर कर दिया है।

सुलभता भी परेशानी । यह कहना आसान है कि AI केवल एक माध्यम या यंत्र है और असली गलती उन लोगों की है, जो इसका दुरुपयोग करते हैं - लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस को काफी बेलगाम तरीके से चलाया जा रहा है। लोकप्रिय बनाने के चक्कर में इसे बहुत सुलभ बना दिया गया है। Airtel और Reliance Jio अपने सब्सक्राइबर्स को मुफ्त में काफी शक्तिशाली AI टूल्स इस्तेमाल करने दे रही हैं। इसका नतीजा यह है कि आज 10-12 साल का बच्चा भी ChatGPT से दुनिया के नामी लोगों के आपत्तिजनक चित्र बनवा सकता है।

गलत जानकारी । हमारा सोशल मीडिया AI से बनाए चित्रों और फिल्मों से भरा पड़ा है, जिन्हे अब AI Slop कहा जा रहा है। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये AI द्वारा बनाए गए हैं। कई दल और गुट AI की मदद लेकर गलत जानकारी और अपनी विचारधारा को बढ़ने में महारथ हासिल कर चुके हैं।

कंपनियां करें उपाय । AI के दुरुपयोग रोकने के लिए कानून हैं, लेकिन जैसा कि Grok के मामले में हुआ, जब तक कानून, कोर्ट और पुलिस हरकत में आते हैं, काफी नुकसान हो चुका होता है। इसीलिए समय की मांग है कि AI टूल्स बनाने वाली कंपनियां, मसलन - OpenAI, Google, Microsoft वगैरह सुरक्षा के ऐसे उपाय करें, जिससे इनका दुरुपयोग बहुत मुश्किल हो जाए।

जिम्मेदारी समझना जरूरी । Meta और X जैसी कंपनियों को ऐसे तरीके अपनाने होंगे, जिससे यूजर्स को पता रहे कि वह जो देख रहा है, उसे इंसान नहीं, AI ने बनाया है। Google और Bing जैसे सर्च इंजन को AI से लैस चित्रों और लेखों को चेतावनी के साथ दिखाना चाहिए। यह सब करना मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है दृढ संकल्प और सामाजिक जिम्मेदारी दिखाने की। इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन इस इससे Grok जैसे जो किस्से सुनने को मिल रहे हैं, काफी कम हो जाएंगे।

ताकतवर पर खतरनाक । कहावत है कि बंदर के हाथ में उस्तरा देना आपदा को निमंत्रित करना है। हाल की घटनाओं को देख कर लगता है कि सभी लोगों को बेधड़क AI इस्तेमाल करने देना इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें दो राय नहीं कि AI में इंसानियत का भला करने की असीम क्षमता है, लेकिन यह तभी संभव है, जब इसका सदुपयोग हो। गलत हाथ इसका क्या करेंगे, यह Grok दिखा चुका है।

खिलौना नहीं AI । रामधारी सिंह दिनकर ने विज्ञान के खतरों को देख कर लिखा था, 'सावधान, मनुष्य! यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक, तजकर मोह, स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी नादान, फूल-कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान।' ये पंक्तियां आज की स्थिति पर खरी उतरती हैं। AI के मामले में हममें से अधिकतर अज्ञानी बच्चों जैसे हैं, जो इसे खिलौने की तरह मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे। लेकिन, AI की धार बहुत तेज है। गलत और अनुभवहीन हाथों में यह हमारा ही सर कलम कर सकता है।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

सफ़र में करते हैं एडजस्टमेंट, तो परिवार में क्यों नहीं

निर्मल जैन

'मैं मन में कुछ नहीं रखता, मैं तो मुंह पर बोल देता हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा।' यूं हम खुद को स्पष्टवादी कहकर अपनी बातों को तीर-सा नुकीला बना देते हैं। सच को स्पष्टता के साथ कहने की कोशिश में जाने-अनजाने कठोर हो जाते हैं। स्पष्ट बोलने का मतलब है, साफ-साफ कुछ समझाना या बताना, न कि सच के बहाने किसी को जान-बूझकर पीड़ा पहुंचाना। जितना महत्व हमारी बात का होता है, उतना ही महत्व है हमारी बात कहने के अंदाज का भी।

सच कहने का मतलब यह नहीं कि किसी की भी भावनाओं को आहत कर दें। बात कितनी भी सही हो, सच क्यों न हो - अगर लहजा गलत है तो उसकी आंच रिश्ते पर आती है। हमें याद नहीं रहता कि हमने दूसरों के साथ क्या-क्या बुरा किया। लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या-क्या अप्रिय किया, यह सब सिलसिलेवार याद रखते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई चींटी हमें काट ले तो याद रहता है, लेकिन कितनी चीटियां हमारे पैरों के नीचे आकर मर गई, याद नहीं रहता। इतना ही नहीं, हमारे पास एक बचाव हमेशा सुरक्षित रहता है कि हमने पहल नहीं की थी, हमारे बर्ताव में कटुता उनके बुरे बर्ताव के एक्शन का रिएक्शन थी।

AI Image

छोटे-से सफर में हम हर तरह से अपने सहयात्रियों के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उनके साथ हंसते-मुसकुराते रहते हैं। लेकिन जिनके साथ स्थायी रूप से रहना है, जो हमारे हर सुख-दुख में भागीदार बनते हैं, उनमें से किसी का जोर से सांस लेना, ऊंची आवाज में बोलना भी हमें खल जाता है। हमारी तीव्र और कठोर प्रतिक्रिया उनको आहत कर जाती है। हम भूल जाते हैं कि किसी को अपना बनाने के लिए हमारी सारी खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, जबकि खोने के लिए एक कमी ही काफी है।

मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। सच बोलते समय आत्मविश्वास के साथ मधुर और विनम्र बने रहें। वाणी की कोमलता हर किसी के हृदय को छू जाती है।

गुस्सा सिर्फ़ अंकिता भंडारी को लेकर ही नहीं है...

उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने वाला मौसम अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही राज्य में तपिश बढ़ चुकी है। 2022 के एक हत्याकांड को लेकर कई शहरों में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं, देहरादून में एंजेल चकमा को लेकर बेचैनी है। त्रिपुरा के छात्र पर देहरादून में नस्लवादी हमला किया गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई।

कौन था VIP । साल 2022 में एक होटल में काम करने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी की उसी होटल के मैनेजर पुलकित आर्य ने हत्या कर दी थी। अंकिता ने एक 'VIP' मेहमान को सेक्सुअल फेवर देने से इनकार किया था। आरोप है कि वह 'VIP' व्यक्ति BJP से जुड़ा था। इस मामले को लेकर पिछले साल से ही नाराजगी थी, अब पूरे राज्य में आंदोलन खड़ा हो गया है। ।

बेरोजगारी बड़ा मुद्दा । विरोध-प्रदर्शनों में बेरोजगारी का मुद्दा भी उठ रहा है। कहा जा रहा है कि रोजगार की कमी के कारण अंकिता जैसों को असुरक्षित जगहों पर काम करना पड़ता है। राज्यसभा में पिछले साल दिसंबर में पेश PLFS के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 8.9% है, पूरे देश में सबसे ज्यादा।

महिलाओं की स्थिति । उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर ज्यादा नहीं है, इसी वजह से अंकिता केस को लेकर गुस्सा भड़कना स्वाभाविक है। पिछले 10 बरसों से 18-23 आयु वर्ग की महिलाओं में उच्च शिक्षा के मामले में राज्य का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत के बराबर या फिर उससे बेहतर ही रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों ने आधी आबादी को सशक्त किया है।

कॉमन रूम

पलायन की समस्या । जंगलों की कटाई और टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में पर्यावरणीय संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया। इसने उत्तराखंड को असुरक्षित और बेहद संवेदनशील बना दिया है। इसकी वजह से ग्रामीण इलाकों से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में पलायन से प्रभावित आबादी 64% है। यही वजह है कि 15वें वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन में उत्तराखंड का हिस्सा बढ़ाकर 4.2% कर दिया है।

जरूरी मुद्दे गौण । इन सब को देखते हुए कह सकते हैं कि अंकिता के नाम पर फूट रहा गुस्सा अकेला नहीं है। इसके पीछे वे तमाम चुनौतियां हैं, जिनका सामना आम लोग कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार की दिलचस्पी सामाजिक नियंत्रण के कानून बनाने में है। वह UCC ले आई। अब हरिद्वार के घाटों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश को रोकने पर विचार किया जा रहा है, जबकि यह असंवैधानिक है। धरना-प्रदर्शन दरअसल सरकार से पुकार है कि वह उन मुद्दों पर ध्यान दे, जो जरूरी हैं यानी कानून व्यवस्था, रोजगार और हिमालय की पवित्रता की रक्षा। (NBT)

कांटे की बात

कैरोलाइन लेविट,
वाइट हाउस की प्रवक्ता

सप्ताह की शख़्सियत

आम भागीदारी से धरती बचाने निकले थे गाडगिल

प्रख्यात इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल का बुधवार को निधन हो गया। वह पर्यावरण आंदोलन की सोच और दिशा तय करने वाले शख्स थे। उनका मानना था कि जंगल, नदियों और जमीन पर पहला हक स्थानीय समुदाय का होता है।

वेस्टर्न घाट पर काम

गाडगिल की पहल पर 1983 में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु में सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज (CES) की स्थापना हुई। 2010 में उनकी अध्यक्षता में वेस्टर्न घाट पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसमें संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम सुझाए गए थे। गाडगिल को पद्म श्री, पद्म भूषण समेत कई सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा गया। 2024 में उन्हें 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ' अवॉर्ड मिला।

ग्राम सभा पर जोर

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले माधव गाडगिल को पीपल्स इकोलॉजिस्ट कहा जाता था। वह कहते थे कि पर्यावरण से जुड़े फैसलों में ग्राम सभा की भूमिका को तवज्जो दी जानी चाहिए। वह हमेशा स्थानीय समुदायों को अधिकार देने के पक्ष में रहे। भारत के जैव विविधता अधिनियम, 2002 में उनकी प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक नीति से जोड़ने की वकालत की।

जनता जंक्शन

इरफ़ान

राज्य के सभी अग्निवीरों को मिलेगी नौकरी

*चार साल पहले भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती का तरीका बदलने और अग्निवीरों की भर्ती पर काफी राजनीतिक घमासान मचा था। अब अग्निवीरों के पहले बैच के चार साल पूरे होने वाले हैं। नेवी के अग्निवीर इसी साल चार साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। सेना के अग्निवीरों का अगले साल की शुरुआत में चार साल का टर्म पूरा होगा। हरियाणा के युवा बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होते हैं। इसके अलावा, दिल्ली से सटे होने के कारण हरियाणा का जिक्र यहां से जुड़ी हर परेशानी में होता है। इन्हीं सब मुद्दों पर **पूनम पाण्डे** ने हरियाणा के मुख्यमंत्री **नायब सिंह सैनी** से बातचीत की, पेश हैं मुख्य अंशः*

■ हरियाणा से बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होते हैं। अब अग्निवीरों में से तो 25% परमानेंट हो जाएंगे। मगर बाहर होने वाले 75% के रोजगार के लिए क्या इंतजाम हैं?

हमारी तैयारी पूरी है। अग्निवीरों का जब चार साल का टर्म पूरा हो जाएगा, तो हम उन्हें उनकी पसंद की नौकरी देंगे। राज्य के सभी विभागों में उन्हें नौकरी दी जाएगी। हम 100% अग्निवीरों को रोजगार देंगे। उनकी सेवा पुलिस, फायर, फॉरेस्ट सहित सभी विभागों में ली जाएगी। इसके अलावा, हम फायर डिपार्टमेंट में अलग बटालियन बना रहे हैं, जिसके लिए ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। ये NDRF (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) की तर्ज पर होगा। उसमें भी अग्निवीरों को लेंगे।

■ दिल्ली के प्रदूषण के लिए हरियाणा में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस पर क्या कहेंगे?

दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार थी, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा झूठ बोलते थे। हरियाणा के किसानों को जब हमने पराली जलाने से मना किया, तब वे मान गए। हम पहले पराली नहीं जलाने वालों को 1,000 रुपये देते थे। अब 1,200 रुपये दे रहे हैं। बायो प्लांट में पराली का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार हरियाणा के करीब 95% किसानों ने पराली नहीं जलाई, बल्कि पंजाब में 100% किसानों ने पराली जलाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पंजाब को हरियाणा से यह सीखना चाहिए।

विशुद्ध राजनीति
इंटरव्यू

■ दिल्ली में भी अब BJP की सरकार है। आपको कितना बदलाव दिखता है?

दिल्ली व हरियाणा में BJP की सरकारें हैं और हम मिलकर काम कर रहे हैं। इसका असर भी दिखने लगा है। पिछले कुछ समय से तेजी से काम हो रहे हैं। पीएम मोदी ने भी कहा है कि गंदा पानी यमुना नदी में न जाए। पिछले साल दिल्ली में छठ अच्छे से मनाई गई। हमने भी कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं, ताकि यहां का गंदा पानी यमुना नदी में न जाए।

■ आपकी सरकार ने साल पूरा कर लिया। सबसे अच्छा काम क्या रहा?

पिछले एक साल में काफी काम हुए हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर सरकारी नियुक्तियों का रिजल्ट रुकवा दिया। कांग्रेस माहौल बना रही थी कि अब उसकी ही सरकार आएगी। उस वक्त 2,000 से अधिक अभ्यर्थी मेरे पास आए और कहा कि कांग्रेस आ जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। मैंने उनसे वादा किया कि मैं शपथ बाद में लूंगा और रिजल्ट पहले आएगा। वही हुआ। सरकारी नौकरी के नतीजे आए और 25,000 युवाओं को नौकरी मिली।

■ आपकी सरकार में अफसरशाही की क्या स्थिति है?

प्रशासन का काम ठीक है। आदेश तुरंत लागू किए जाते हैं। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सरकारी अस्पतालों में किडनी मरीजों का डायलिसिस निःशुल्क होगा। शपथ लेने के फौरन बाद मैंने उस फाइल पर साइन किया और नियम उसी दिन से लागू हो गया।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

वैचारिक पतन

8 जनवरी का संपादकीय 'कुर्सी के लिए दोस्ती' पढ़ा। आज की राजनीति में कब क्या होगा, कोई नहीं कह सकता। सत्ता की लालसा किस तरह वैचारिक सीमाएं मिटा देती है, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में अंबरनाथ और अकोट इसी का उदाहरण है। BJP-कांग्रेस या BJP-AIMIM जैसे गठबंधन यह संदेश देते हैं कि विचारधारा अब चुनावी भाषणों तक सिमट गई है। वास्तविक राजनीति सत्ता गणित से संचालित हो रही है। सत्ताधारी सहयोगियों के बीच अविश्वास, घुसपैठ के आरोप और सार्वजनिक बयानबाजी दर्शाते हैं कि गठबंधन भीतर से कितना अस्थिर है। जिन दलों ने एक-दूसरे के खिलाफ जनादेश मांगा हो, उनका केवल कुर्सी के लिए हाथ मिलाना जनता के लिए निराशाजनक है।

सुधीर अग्रवाल, पीतमपुरा

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

आर.एन.आई. नं. 510/57 © सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु.; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

जागरूक संपादकीय

जागरूक टाइम्स। मुंबई | शुक्रवार, 9 जनवरी 2026

श्रीरामचरितमानस

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या
द्यच्छोकमुच्छोषणमिंद्रियाणाम्।
अवाप्य भूमावसपत्रमृद्धं राज्यं सुराणामपि
चाधिपत्यम्॥२-८॥

भावार्थ : पृथ्वी का सब प्रकार से समृद्ध और निष्कण्टक राज्य पाकर या देवताओं का आधिपत्य पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं, जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके॥

बंगाल में बवाल

पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव है। चुनाव की मुनादी से पहले ही सियासी हलचल तेज हो गई है। राजधानी कोलकाता में उस वक्त हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया, जब ईडी ने आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर और आईपैक दफ्तर पर छापेमारी की। आईपैक पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपेक टीएमसी को अपनी चुनावी रणनीति के लिए सेवा दे रही है। जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी (आई-पैक) के चीफ प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर रेड मार रही थी, तभी ममता बनर्जी उनके आवास पर आ धमकीं। ममता बनर्जी के यहां पहुंचते ही पारा हाई हो गया। ममता बनर्जी ने ईडी पर आरोप लगाया कि वे तृणमूल कांग्रेस की गोपनीय फाइलें और डेटा जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि अगर वह भाजपा के दफ्तर पर रेड मार दें तो?

बहरहाल, इस दौरान ममता की गाड़ियों में कुछ फाइलें भी रखवाईं गईं। दरअसल, ममता बनर्जी ने पहले ईडी पर डॉक्यूमेंट चोरी और टीएमसी की रणनीति की चोरी का आरोप लगाया। ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर से एक फाइल कलेक्ट करके आईपैक दफ्तर पहुंचीं। उसके बाद आईपैक दफ्तर में मौजूद कुछ फाइलों को उठाकर ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ी में रखा गया। जब अंदर छापा चल रहा था, तभी कुछ फाइलें ममता के अधिकारी ले गए। खुद ममता के हाथ में एक ग्रीन कलर की फाइल देखी गई। आईपैक दफ्तर से जो फाइलें निकलीं, वो ग्रीन कलर की थी। अब सवाल है कि आखिर उन फाइल्स में क्या है? क्या उन्हीं फाइल्स के लिए ममता बनर्जी आनन-फानन में पहुंचीं थीं? अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। अब ईडी जब रेड पर बयान जारी करेगी, तब शायद इसका खुलासा हो। सूत्रों का कहना है कि टीएमसी की आईटी सेल से जुड़े दस्तावेज थे, जो ममता के अधिकारी लेकर गए हैं। उनमें टीएमसी की कुछ जानकारियां थीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी यहां आई-पीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर तलाश अभियान के दौरान तृणमूल कांग्रेस की हार्ड डिस्क, आंतरिक दस्तावेज और संवेदनशील संगठनात्मक डाटा जब्त करने का प्रयास कर रहे थे। ममता बनर्जी ने जैन के आवास पर हुई छापेमारी को राजनीतिक रूप से प्रेरित और असंवैधानिक बताया। आई-पीएसी तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल की जिम्मेदारी भी संभालता है। ममता बनर्जी ने जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास से बाहर निकलने के बाद ये आरोप लगाए, जहां तलाश अभियान जारी है। प्रतीक जैन के नेतृत्व वाली फर्म 'इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी' (आई-पीएसी) के कार्यालय में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय सत्तारूढ़ पार्टी की आंतरिक रणनीति, उम्मीदवारों की सूचियां और गोपनीय डिजिटल सामग्री तक पहुंचने की कोशिश में था।

अहंकार में डूबे ट्रंप

बार-बार भारत का अपमान

वीना गौतम

दादागीरी की अपनी हरकतों से दुनिया में हड़कंप मचाने वाले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर रह-रहकर हमारे देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी का बार-बार अपमान क्यों कर रहे हैं? कभी वह पत्रकारों से खुलासा करने के अंदाज में यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे खुश करने के लिए रूस से तेल लेना लगभग बंद कर दिया है और इस तंज को कूटनीतिक गलियारे में अभी भुलाया भी नहीं गया था कि ट्रंप फिर प्रधानमंत्री मोदी का लगभग अपमान करने वाले अंदाज में खुलासा करते हैं कि बीते दिनों उन्होंने उन्हें फोन करके कहा, 'सर प्लीज़ क्या मैं आपसे मिल सकता हूं?' गौरतलब है कि अभी दो दिन पहले ही अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लगभग चेतावनी देते हुए यह भी कहा था कि अगर वह रूस के साथ व्यापार जारी रखता है, तो उस पर जल्द टैरिफ और बढ़ाया जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप बार-बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कूटनीतिक गलियारे में ये व्यंग्यभरी टिप्पणियां करते हुए हर बार प्रधानमंत्री मोदी को अपना खास दोस्त बताना भी नहीं भूलते, जैसे वो जानबूझकर व्यंग्य कर रहे हों।

सवाल है आखिरकार उनके इस सनकभरे व्यवहार का मतलब क्या है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपने इस अंदाज के जरिये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वह किस तरह भारत से बहुत ऊपर पोजीशन में है और सामने वाले को याचक या इच्छुक के रूप में पेश कर रहे हैं। राजनीति में लोग दुश्मनों के लिए भी इस तरह की भाषा बोलने से परहेज रखते हैं। फिर ट्रंप तो प्रधानमंत्री मोदी को बार-बार अपना दोस्त बताते हैं, फिर आखिर अच्छा दोस्त बताकर इस तरह अपमान करने की कोशिश क्यों करते हैं? दरअसल ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि उनके पास ताकत है और मिलने की जरूरत उन्हें नहीं बल्कि सामने वाले को है। यह एक कूटनीतिक हमला और सूक्ष्म तरीके से देखा जाए तो हमारा अपमान है। आखिरकार कूटनीतिक दुनिया में कोई नेता दूसरे के लिए उल्टी-सीधी गालियों का इस्तेमाल नहीं करता, ऐसी ही शब्दावली से अपना अहंकार, अपना बड़बोलापन और सामने वाले की इज्जत न करने का अपना रवैय्या दर्शाता है। किसी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते।

डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से रह-रहकर जो शब्द हमारे देश और प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वह बिना हमलावर हुए या बिना कोई खुली दुश्मनी को प्रदर्शित किए हुए एक तरह से बार-बार हमें राजनयिक दायरे में नीचा दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वह अपने इन शब्दों और घृणात्मक शब्दावली से सिर्फ हमें छोटा कर रहे हों, वे षड्यंत्रकारी तरीके से हमें निशाना बनाकर पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो भारत जैसी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था और कुशल मानव संसाधन के सबसे बड़े वैश्विक हब को कुछ नहीं समझते, तो दुनिया में बाकी देशों की क्या विसात है? इसके अलावा वह इस तरह की शब्दावली अपनी आंतरिक राजनीति के समीकरण को दुरुस्त करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप जिस तरह से हर मौके का इस्तेमाल भारत को अपमानित करने के लिए कर रहे हैं, उसके जरिये वो हमसे ज्यादा दुनिया को टारगेट कर

रहे हैं कि वह एक वैश्विक शक्ति हैं। जबकि हकीकत यह है कि वेनेजुएला प्रकरण के बाद जिस तरह से अमरीकी संसद दो खेमों में बंट गई है और ब्रिटेन को छोड़कर लगभग पूरे यूरोप ने ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी की है, उससे ट्रंप हिल गए हैं।

उन्होंने वेनेजुएला में जो साम्राज्यवादी हरकत चीन को दहशत में लाने और रूस की अनदेखी करने के लिए किया था, उससे रूस और चीन तो ज्यादा घबराए नहीं उल्टे यूरोप उनका साथ छोड़ने की स्थिति में आ गया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वेनेजुएला के बाद उनकी नजर ग्रीनलैंड पर है और जैसा कि अपने अब तक के दूसरी बार के कार्यकाल में उन्होंने रह-रहकर अपनी हठधर्मिता दिखाई है, उस कारण नाटो का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। अपनी इन्हीं नाकामियों से खिसियाकर वह मौका मिलते ही भारत और हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करने का मौका नहीं गंवाते। जबकि हकीकत ये है कि जब दुनिया के दो राजनेता मुलाकात करते हैं, तो यह मुलाकात कभी व्यक्तिगत इच्छा के या किसी एक के हित के चलते नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं के बीच मुलाकाते हमेशा कूटनीतिक रिश्तों को गति देने के लिए और अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए होती हैं।

आज अगर भारत को अमेरिका से टैरिफ न बढ़ाये जाने की चाहत है तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका को भी भारत से बहुत सारी चीजें चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसे भारत का विशाल बाजार चाहिए, जहां वह अपनी पूंजी लगा सके और उससे बेहतर रिटर्न हासिल कर सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरह से ट्रंप जाने-अनजाने रूस और चीन को अपना खुलेआम दुश्मन बना रहे हैं, उसमें अगर भारत भी उनके साथ न हुआ तो अमेरिका न केवल ग्लोबल मोर्चे में अलग-थलग पड़ जाएगा बल्कि ग्लोबल साउथ से उसकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाएंगी। भारत इस समय अमरीका के लिए एकमात्र ऐसा सहयोगी हो सकता है, जो अमेरिका को रूस और चीन की साझी नाराजगी की भरपाई कर सके। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रही है और भारत में कुशल मानव संसाधनों का जो जखीरा है, इस एआई के तूफानी दिनों में वही है जो भविष्य की अर्थव्यवस्था को एक स्थिरता और निरंतरता की दिशा दे सकता है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप बार-बार भारत का और प्रधानमंत्री मोदी का अपमान कर रहे हैं, उससे लगता है कि वह या तो कूटनीति के वैश्विक भविष्य में हमारी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे या वह जरा भी दूरदर्शी सोच नहीं रखते। अगर रखते होते तो जरूर रह-रहकर हमारे खिलाफ इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं करते। जब वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे कहा कि सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, तो वह यह भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कोई उनके दरवाजे पर नहीं खड़े थे, जो अंदर आने की उनसे इजाजत मांग रहे हों। दरअसल ट्रंप का यह जहरीला मनोविज्ञान है जिसके प्रभाव में वह इस तरह के शब्दों का चयन करके हमें मनोवैज्ञानिक ढंग से नीचा दिखाना चाहते हैं। यह वास्तव में पावर प्ले की बहुत पुरानी और घटिया सोच की शब्दावली है। ऐसे बयानों पर भारत अकसर प्रतिक्रिया नहीं देता, चुप्पी साध लेता है, तो इसलिए नहीं कि भारत, अमेरिका की इस बेहूदा शब्दावली से डर गया है बल्कि भारत अपने स्वतंत्रत इतिहास की कूटनीतिक विरासत को मैच्योरिटी से आगे बढ़ाते हुए वैश्विक कूटनीति का लिहाज रखता है।

(लेखिका विशिष्ट मीडिया एवं शोध संस्थान, इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर में कार्यकारी संपादक हैं)

इमेज

गीता सार

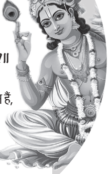

राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल।
जापक जन प्रह्लाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल॥27॥

भावार्थ : राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलियुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रह्लाद के समान हैं, यह राम नाम देवताओं के शत्रु (कलियुग रूपी दैत्य) को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा॥

फन विद फिजिक्स

टूथपेस्ट भी कमाल करता है!

निकहत कुंवर

बच्चो! अगर तुम रोज़ सुबह उठने के बाद अपने दांत टूथपेस्ट से साफ़ नहीं करते हो तो आज मैं तुम्हें जो प्रयोग करना सिखा रही हूं उसे करने के बाद तुम कभी भी दांत ब्रश करने से नहीं भागोगे क्योंकि विज्ञान बताता है कि टूथपेस्ट भी कमाल करता है। इस प्रयोग के लिए सबसे पहले स्टिकी नोट्स पर सोडा 1, सोडा 2, जूस 1 और जूस 2 लिख लो। फिर इन नोट्स को एक पंक्ति में काउंटर पर रख दो। अब दो गिलासों को आधा आधा ब्राउन सोडा से भरो और उन्हें सोडा 1 व सोडा 2 स्टिकी नोट्स के पीछे रख दो। इसके बाद दो अन्य गिलासों को लेमन जूस से आधा आधा भरने के बाद उन्हें जूस 1 व जूस 2 स्टिकी नोट्स के पीछे रख दो। ध्यानपूर्वक एक अंडे को एक कटोरी में रखो और एक चाय के चम्मच में जितना टूथपेस्ट आ सकता है, उसे अंडे के ऊपर निकालकर आहिस्ता-आहिस्ता पूरा मल दो, जब तक कि पूरा अंडा टूथपेस्ट की परत से ढक जाए। ऐसा ही दूसरे अंडे के साथ करो। इसके बाद टूथपेस्ट से कवर किए किए अंडों में से एक को सावधानीपूर्वक सोडा 1 गिलास में और दूसरे को जूस 1 गिलास में डाल दो। अपने हाथ धोकर सुखा लो। फिर दो अंडे लो, जिन पर टूथपेस्ट न लगा हो। उनमें से एक को सोडा 2 और दूसरे को जूस 2 गिलासों में डाल दो। अंडों को गिलासों में 12 घंटों तक पड़ा रहने दो। जब 12 घंटे पूरे हो जाएं तो अंडों को एक-एक करके सोडा वाले गिलासों में से बाहर निकाल लो। उन्हें ठंडे पानी से धोकर तौलिये से सुखा लें। दोनों अंडे जिन गिलासों में थे, उन्हें क्रम से उनके पास रख दो। क्या दोनों अंडे समान रंग के हैं या अलग रंग के? फिर एक-एक करके अंडों को जूस के गिलासों से बाहर निकालो। उन्हें भी धोकर सुखा लें और फिर जिस गिलास से निकले थे उसके पास रख दें। इन दोनों अंडों को महसूस करो। क्या वह मज़बूत महसूस होते हैं या कमज़ोर? इस प्रयोग में अंडों के बाहरी खोल एनेमल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आपके दांतों के ऊपर की कोटिंग होती है। टूथपेस्ट आपके दांतों को साफ करता है और उनको दाग धब्बों से बचाता है। दांतों में जो खाने-पीने से अंश रह जाते हैं उन्हें हटाता है। दांतों पर डार्क रंग के तरल पदार्थों जैसे कॉफ़ी, कोला या चाय से आसानी से दाग लग जाते हैं। जिन अंडों पर टूथपेस्ट नहीं था वह ब्राउन और मटमैले हो जायेंगे। जिन अंडों पर टूथपेस्ट था वह अपने मूल रंग में रहेंगे। टूथपेस्ट आपके दांतों को सड़ने-गलने से भी बचाता है। जो अंडा लेमन जूस में बिना टूथपेस्ट के कवर के डाला गया था।

तिथि विशेष

प्रवासी भारतीय दिवस

प्रवासी भारतीय दिवस या अनिवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मान्यता दी गई है

क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और अंततः दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों और औपनिवेशिक शासन के तहत लोगों के लिए और भारत के सफल स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरणा बने। यह दिन हर साल प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 'प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय' का प्रमुख कार्यक्रम है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डायस्पोरा है। प्रवासी भारतीय समुदाय अनुमानतः 2.5 करोड़ से अधिक है। जो विश्व के हर बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। फिर भी किसी एक महान् भारतीय प्रवासी समुदाय की बात नहीं की जा सकती। प्रवासी भारतीय समुदाय सैंकड़ों वर्षों में हुए उत्प्रवास का परिणाम है और इसके पीछे विभिन्न कारण रहे हैं, जैसे- वाणिज्यवाद, उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण। इसके शुरू के अनुभवों में कोशिशों, दुःख-तकलीफों और दृढ़ निश्चय तथा कड़ी मेहनत के फलस्वरूप सफलता का आख्यान है। 20वीं शताब्दी के पिछले तीन दशकों के उत्प्रवास का स्वरूप बदलने लगा है और "नया प्रवासी समुदाय" उभरा जिसमें उच्च कौशल प्राप्त व्यावसायिक पश्चिमी देशों की ओर तथा अकुशल,अर्धकुशल कामगार खाड़ी, पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया की और ठेके पर काम करने जा रहे हैं। प्रवासी भारतीय समुदाय एक विविध विजातीय और मिलनसार वैश्विक समुदाय है जो विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक आम सूत्र जो इन्हें आपस में बांधे हुए है, वह है भारत और इसके आंतरिक मूल्यों का विचार। प्रवासी भारतीयों में भारतीय मूल के लोग और अप्रवासी भारतीय शामिल हैं।

बड़ा पर्दा

शर्मिला टैगोर के अनसुने किस्से

कैलाश सिंह

शर्मिला टैगोर का नाम सुनते ही दर्शकों के जहन में 'अमर प्रेम', 'आराधना', 'मौसम' जैसी हिट फिल्में, सुंदर मुस्कान और राजेश खन्ना, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन आदि सुपरस्टार्स के साथ उनकी सफल जोड़ी याद आ जाती है। शर्मिला ने अपने लगभग 68-वर्ष के लम्बे करियर में केवल अभिनय ही नहीं किया बल्कि अपने आकर्षक अंदाज़ व ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री से अपने प्रशंसकों के दिल में खास जगह बनायी, जिससे वह बॉलीवुड की यादगार व सदाबहार अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। हालांकि शर्मिला टैगोर ने सत्यजीत रे के साथ पांच फिल्में कीं, जो उनका सर्वश्रेष्ठ कार्य कहा जा सकता है, लेकिन 'आराधना' (1969) की 'मेरे सपनों की रानी' को कौन भूल सकता है, जिसका 'रूप तेरा मस्ताना' था।

इमेज

फ्रांस के आर्डर ऑफ़ आर्ट्स एंड लेटर्स (1999), भारत के तीसरे उच्चतम नागरिक अवार्ड पद्म भूषण (2013), दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (मौसम व अबर अरण्य) और तीन फिल्मफेयर अवाड्र्स (आराधना, गुलमोहर व लाइफटाइम अचीवमेंट) से सम्मानित पटौदी की 'बेगम मां' शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसम्बर 1944 को कानपुर में हुआ था, जहां उनके पिता जितेंद्रनाथ टैगोर ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन में जनरल मनेजर थे। उनके पिता की ही नहीं बल्कि मां इरा बरुआ की वंशावली भी नोबेल पुरस्कार विजेता रबींद्रनाथ टैगोर से मिलती है। इसके अतिरिक्त वह अभिनेत्री देविका रानी व पेंटर अबनींद्रनाथ टैगोर की भी रिश्तेदार हैं और भोपाल व पटौदी के नवाबी खानदान में उनका ब्याह हुआ है। शर्मिला अपनी दो अन्य बहनों से बड़ी हैं। उनकी बहन ओइनड्राला कुंडा (अब दिवंगत) ने एक बाल कलाकार के रूप में उनसे पहले फिल्मों में काम किया- तपन सिन्हा की 'काबुलीवाला' (1957) में और फिर बाद में वह अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज खिलाड़ी बनीं। शर्मिला की दूसरी बहन रोमिला सेन हैं। हमेशा से विद्रोही स्वभाव की रहीं शर्मिला टैगोर ने मात्र 13 वर्ष की आयु में सत्यजीत रे की फिल्म 'अपूर संसार' से काम करना शुरू किया था। उनके एक्टिंग करियर से उनकी प्रधानाचार्या इतनी अधिक नाराज़ हो गईं थीं कि शर्मिला टैगोर को दूसरे स्कूल में प्रवेश लेना पड़ा था। जब वह 17 साल की हुईं तो अकेले होटल में रहते हुए अपने

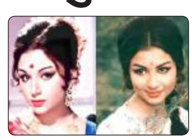

चयन किए किए करियर को आगे बढ़ा रही थीं। 22 साल की उम्र में वह एक फिल्म पत्रिका (फिल्मफेयर) के लिए बिकनी में पोज़ करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनीं। इस तस्वीर ने इतनी सनसनी मचाई कि इस पर संसद तक में प्रश्न मालूम किए किए थे। हालांकि उन्हें क्रिकेटर एमएल जयसिम्हा पर क्रश था, लेकिन एक दूसरे क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी को अपना दिल दे बैठीं और वह भी इस हद तक कि अपनी फिल्म शूटिंग के बाद एयरपोर्ट पर टाइगर को सी-ऑफ़ करने के लिए गईं जो विदेशी दौरे पर जा रहे थे, टाइगर ने उनसे मजाक में साथ चलने के लिए कहा और वह बिना किसी सामान के उनके साथ चल पड़ीं। यात्रा के दौरान उन्हें टाइगर के शोर्ट्स पहनने पड़े थे। शर्मिला टैगोर के अनुसार, "टाइगर को जोक्स सुनाने का शौक था, लेकिन उनका ब्रिटिश एक्सेंट मेरी समझ में नहीं आता था, इसलिए टाइगर खुद ही अपने जोक्स पर हंसते थे।" इस सिलसिले में दो अन्य किस्से भी दिलचस्प हैं। शर्मिला टैगोर जिस समय टाइगर की जिंदगी में आईं तब वह सिमी ग्रेवाल को डेट कर रहे थे। अब टाइगर ने फैसला कर लिया था कि वह पेरिस में शर्मिला टैगोर के समक्ष घुटने पर जाकर विवाह प्रस्ताव रखेंगे, इसलिए सिमी ग्रेवाल से ब्रेकअप ज़रूरी था। वह सिमी ग्रेवाल के घर पहुंचे और उनसे जाकर राहें अलग अलग होने की बात कही, उस समय बाहर उनकी कार में शर्मिला टैगोर बैठी हुईं थीं यानी वह एक प्रेमिका से ब्रेकअप करने के लिए दूसरी प्रेमिका को साथ लेकर गए थे। 24 साल की आयु में शर्मिला टैगोर ने टाइगर से शादी कर ली, जब वह अपने फिल्मी करियर की बुलंदियों पर थीं। हर किसी का यही मानना था कि यह शादी नहीं चलेगी और शर्मिला टैगोर का फिल्मी करियर समाप्त हो जाएगा। वैसे भी उस दौर में विवाहित लड़की को कोई निर्माता अपनी फिल्म में हीरोइन बनाना पसंद नहीं करता था। लेकिन शर्मिला टैगोर ने इन अटकलों को गलत साबित किया। उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत सफल रही, वह अब भी टाइगर की कब्र के निकट ही रहती हैं और 1970 में सैफ को जन्म देने के बाद वह फिल्मों में सफलतापूर्वक फिर लौटीं, अभिनय के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए। एक बार उनकी सास साजिदा सुल्तान, जिनको पटौदी व भोपाल की नवाबी विरासत में मिली हुई थी, को उनके पास मुंबई में आना था। शर्मिला टैगोर के घर के पास 'एन इवनिंग इन पेरिस' के पोस्टर्स लगे हुए थे, जिनमें उन्हें बिकनी में दिखाया गया था। शर्मिला टैगोर ने अपने ड्राइवर से कहकर रात में ही उन सब पोस्टर्स को हटवा दिया था।

वायरल

रेस्त्रां के वीडियो ने खोला बेवफा पति का राज! होटल पर ठोका केस

सोशल मीडिया ने एक बार फिर किसी की जिंदगी उलट-पुलट कर दी है। इटली के सिसिली द्वीप पर कैटानिया शहर में एक 42 वर्षीय शख्स अपनी पत्नी से झूठ बोलकर रेस्त्रां गया था। ये उसकी प्रेमिका के साथ डिनर डेट थी। लेकिन रेस्त्रां के एक वीडियो ने उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पोल खोल दी। शस्का पत्नी से 'काम के डिनर' का बहाना बनाकर घर से निकला था। लेकिन वह अपनी प्रेमिका के साथ रेस्त्रां में था। रेस्त्रां ने प्रमोशनल वीडियो बनाया और टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया, जिसमें वह जोड़े को रोमांटिक डिनर करते दिखाया गया। यह वीडियो वायरल हुआ तो पत्नी ने देखा और फिर राज खुल गया। वायरल वीडियो शख्स की पत्नी के मोबाइल में भी पहुंच गया। इसके बाद पत्नी ने तुरंत पति को घर से निकाल दिया, जिसके बाद तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब उसी शख्स ने रेस्त्रां के खिलाफ कोर्ट में केस ठोंक दिया है। आरोप है कि रेस्त्रां ने बिना उनकी सहमति के वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला।

पंचांग

9 जनवरी 2026

- विक्रम संवत् - 2082
- शक संवत् - 1947
- रवि - उत्तरायण
- ऋतु - शिशिर
- मास - माघ
- पक्ष - कृष्ण
- तिथि - सप्तमी अहोरात्र
- वार - शुक्रवार
- नक्षत्र - उत्तराफाल्गुनी 13.41 तक
- योग - शोभन 16.55 तक
- करण - विष्टि 19.39 तक
- सूर्योदय - 07.15 प्रातः (मुंबई)
- सूर्यास्त - 06.15 शाम (मुंबई)
- सूर्योदय - 07.27 प्रातः (भीनमाल)
- सूर्यास्त - 06.08 शाम (भीनमाल)
- चंद्र राशि - कन्या
- अभिजीत - 12.23 से 13.07
- राहु काल - 11.22 से 12.45
- दिशा शूल - पश्चिम
- व्रत त्यौहार - सप्तमी वृद्धितिथि, रवियोग 13.41 तक, भद्रा 19.39 तक

• शास्त्री प्रवीण त्रिवेदी, भीनमाल

X का एक्सरे

जनवरी 1026 में सोमनाथ पर पहला हमला हुआ था, लेकिन 1026 के हमले और उसके बाद हुए आक्रमण भी करोड़ों लोगों की आस्था और उस सभ्यतागत चेतना को नहीं तोड़ सके, जिसने सोमनाथ को बार-बार खड़ा किया। 2001 के कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री आडवाणी शामिल हुए थे।

नरेंद्र मोदी

यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी ने टीएमसी के आईटी प्रमुख के घर पर छापा मारा। क्या राजनीतिक दलों के आईटी प्रमुखों के घरों पर छापा मारना केंद्रीय गृह मंत्री का काम है? टीएमसी के आईटी प्रमुख के घर पर ईडी की छापेमारी राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित और असंवैधानिक है, यह गृह मंत्री का घिनौना काम है।

ममता बनर्जी

जब मैं अकेले यात्रा करता था, तब इमिग्रेशन जांच में मुझे कई बार रोका गया, शायद कान की बालियों या किसी चीज की वजह से। लेकिन अब जब वे मुझे मेरे प्यारे परिवार के साथ देखते हैं, तो उन्हें मुझ पर शक नहीं होता। पहले 2000 के दशक की शुरुआत में मुझे अक्सर अलग कर दिया जाता था। इसे ही प्रोफाइलिंग कहते हैं।

इमरान हाशमी

अंडर-19 वर्ल्ड कप आने वाला है, जहां वैभव सूर्यवंशी शो स्टॉपर बन सकते हैं। इसके तुरंत बाद आईपीएल होगा, जहां वह संजू सैमसन की जगह को भरने का प्रयास करेंगे। अगले चार महीने हैशटेग वैभव को देखो वाले होंगे और बहुत रोमांचक होंगे। यह उनके स्वभाव, रनों की भूख और चरित्र का पता देंगे।

रविचंद्रन अश्विन

नारायण पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए मुद्रक-प्रकाशक-हेमल पुरोहित द्वारा एआईएस प्रिंटिंग सोल्यूशंस, प्लॉट नं. ए-544, टीटीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, ठाणे-बेलापुर रोड, महापे, नवी मुंबई 400709 से मुद्रित एवं प्रिमाइसेस नं. 1303/चेंबर्स, 13वां माला, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन के पास, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 099 से प्रकाशित, पोस्टल रजि. MCN/325/2023-24, (चकाला MIDC पी.ओ.) रजि. नं. MAHHIN/2004/13755, संपादक-हेमल पुरोहित, स्थानीय संपादक-नीरज दवे, फोन : 022-46024646, ईमेल : jagruktimes@gmail.com

राष्ट्रीय सहारा
पटना। शुक्रवार • 9 जनवरी • 2026
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

सकारात्मक रहना और आभारी रवैया रखना तय करेगा कि आप जिंदगी कैसे जीने जा रहे हैं।

-जोएल ऑस्टिन

एसआईआर : राष्ट्रहित और राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल

उत्तर प्रदेश में जारी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कई तरह की चर्चाएं स्वाभाविक हैं। अब पहला चरण का कार्य पूरा हो चुका है। अब दूसरे चरण में कार्य चल रहा है। परंतु किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी शुचिता, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकार ये तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ऐसे में एसआईआर की पहल को केवल प्रशासनिक कार्रवाई या तकनीकी प्रक्रिया समझना भूल होगी। यह एक ऐसा प्रयास है जो राष्ट्रहित, पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा-तीनों को मजबूत करने का कार्य करता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में मतदान सूची की शुद्धता, मतदाताओं की सही पहचान और उनके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का लक्ष्य इसी चुनौती को सरल और

अधिक विश्वसनीय बनाना है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि किसी भी प्रकार की फर्जी प्रविष्टियाँ, दोहराव, या गैर-प्रामाणिक सूचनाएँ हटाई जा सकें, ताकि वास्तविक मतदाता अपने अधिकारों का उपयोग बिना किसी बाधा के कर सकें। यह भी स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा भर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचों की मजबूती से भी जुड़ी होती है। यदि मतदाता सूची शुद्ध रहे, पहचान प्रमाणिक हो और प्रत्येक नागरिक को सही ढंग से दर्ज किया जाए, तो लोकतंत्र अधिक सुरक्षित बनता है। ऐसे में एसआईआर केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि व्यापक सुरक्षा तंत्र का हिस्सा बनकर उभरता है। हालांकि, आवश्यक है कि इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित किया जाए। जनता का विश्वास किसी भी सरकारी पहल की सबसे बड़ी शक्ति होता है। इसलिए सरकार और प्रशासन को चाहिए कि प्रत्येक चरण की जानकारी नागरिकों तक समय से पहुँचाई जाए, किसी भी संदेह का निवारण खुले मंचों पर किया जाए, और यह भी स्पष्ट किया जाए कि यह प्रक्रिया किसी भी वर्ग, मत या क्षेत्र के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के हित में है। साथ ही जनता की जिम्मेदारी भी कम नहीं। नागरिकों को चाहिए कि वे एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग करें, अपने दस्तावेज़ समय पर उपलब्ध कराएँ और जागरूकता फैलाने में प्रशासन के साथ खड़े हों। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सरकार और जनता दोनों एक-दूसरे के हितों और कर्तव्यों को समझते हुए साथ चलें। अंततः, एसआईआर एक ऐसा कदम है जो न केवल भविष्य के चुनावों को अधिक विश्वसनीय बनाएगा, बल्कि देश की सुरक्षा और लोकतांत्रिक ढांचे को भी मजबूत करेगा। आवश्यकता केवल इतनी है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जनसहयोग के साथ आगे बढ़े तभी इसका वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सकेगा। यह भी देखना होगा कि वैद्य मतदाता न छूटने पाये। सरकार की जिम्मेदारी की यह असली परीक्षा है।

कटाक्ष/ सहीराम

अब कागज तुम्हीं दिखाओगे

कल तक बड़े नारे गूंज रहे थे और गाने गाए जा रहे थे कि जनाब हम कागज नहीं दिखाएंगे। पर अब नहीं दिखाओगे तो वोट कट जाएगा। लोग कह रहे हैं कि जब गृह मंत्री पूरे देश में एनआरसी करवाने की बात कह रहे थे और जब शाहीन बाग में कागज नहीं दिखाएंगे के नारे लगाए जा रहे थे तो वक्त रहते चुनाव आयोग का ट्यूशन क्यों नहीं लगवा दिया। भैया, वो क्रोनोलॉजी नहीं समझाते।

वो तो झटके में आपके नाम पर वैसे ही कलम फेर देते, जैसे गर्दन पर चाकू।

खैर, एनआरसी के वक्त जिस क्रोनोलॉजी का इतना खौफ था, आज उससे भी ज्यादा खौफ चुनाव आयोग के गहन पुनरीक्षण का हो गया है। जी, लोग कह रहे हैं कि यह एनआरसी का ही दूसरा नाम है और रस्ता दूसरा है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि गुरु गुड़ ही रह गया और चेला शक्कर निकल गया। जी, लोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अमित शाह का चेला बता रहे हैं न इसलिए। उधर, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अपनी काबलियत पर पहली बार शक हुआ होगा कि यार, महाराष्ट्र में वोट बढ़ा कर भक्ति-भजन करने का क्या फायदा हुआ, जब वोट काट कर उससे भी बड़ा भक्त बना जा सकता है। जी, लोग यही कह रहे हैं कि यह रिवर्स टाइप का महाराष्ट्र चुनाव प्रकरण है। महाराष्ट्र की मतदाता सूची में जब लाखों की संख्या में नाम जोड़े गए तो किसी ने पता तक नहीं पूछा। बिहार में मतदाता सूची से करोड़ों नाम कटने की आशंका हो रही है, तो लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या-क्या पूछा जा रहा है। क्या-क्या कागज मांगे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो वोटर कार्ड है। चुनाव आयोग अपने ही वोटर कार्ड के बारे में कह रहा है-बेकार है। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास आधार कार्ड भी है, पर चुनाव आयोग कह रहा है-बेकार है। अब सवाल मत पूछने लगना कि जब न वोटर कार्ड मान्य है, और न आधार कार्ड तो इनको बनाना आवश्यक क्यों किया गया था, क्यों एक पूरी व्यवस्था खड़ी की गई थी, क्यों हजारों करोड़ खर्च किए गए थे। चुनाव आयोग तो कह रहा है तुम तो अपना जन्मतिथि का प्रमाण पत्र दिखाओ, माता-पिता का जन्मतिथि प्रमाण पत्र दिखाओ। सीधी बात है कागज नहीं दिखाओगे तो वोटर नहीं रहोगे और वोटर नहीं रहोगे तो फिर नागरिक भी नहीं रहोगे। एनआरसी कंपलीट!

कलमाड़ी का यूं ही चले जाना

शंभूनाथ शुक्ल
वरिष्ठ पत्रकार

> कांग्रेस आलाकमान की आंख का तारा थे कलमाड़ी, आखिरी सांस से पहले धुला खेल माफिया का दाग

सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस आलाकमान को सदैव प्रिय रहे. तब भी जब वे महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनकी सक्रियता देख कर ही तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें 1982 में ही राज्यसभा में बुला लिया था. बाद में वह लोकसभा के लिए भी चुने गए। तेजी से कामयाबी हासिल करने वाले कलमाड़ी पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो उनका ग्राफ तेजी से नीचे गिर गया।

कांग्रेस आलाकमान की आंख का तारा थे कलमाड़ी, आखिरी सांस से पहले धुला खेल माफिया का दाग पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का आज सुबह निधन हो गया। सुरेश कलमाड़ी को एक राजनीतिक के तौर पर याद किया जाए या एक खेल प्रेमी के तौर पर अथवा भारतीय वायु सेना के कुशल पायलट के तौर पर! यह भ्रम सदैव बना रहेगा. वे 3 बार राज्यसभा में रहे और दो बार लोकसभा में। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में रेल राज्य मंत्री रहे और राज्य मंत्री होते हुए रेल बजट भी पेश किया था। वह भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे और इसी नाते उन पर कई तरह के आरोप भी लगे. हाकी स्टार परगट सिंह ने तो उन्हें खेल माफिया करार दिया था। राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इसी नाते उन्होंने ओलंपिक संघ से इस्तीफा भी दे दिया था। वे थोड़े नकचढ़े भी थे. एक बार उन्हें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बगल वाली कुर्सी नहीं ऑफर की गई तो वे ओलंपिक समारोह की बैठक छोड़ कर चले गए थे। इसके बावजूद सुरेश कलमाड़ी कभी भुलाये नहीं गए।

कांग्रेस आलाकमान की आँख के तारे थे कलमाड़ी : वे कांग्रेस आलाकमान को सदैव प्रिय रहे. तब भी जब वे महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनकी सक्रियता देख कर ही तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें 1982 में ही राज्यसभा में बुला लिया था. एक मई 1944 को पुणे में जन्मे सुरेश कलमाड़ी 1960 में N D A (भारतीय रक्षा अकादमी) के लिए चुन लिए गए थे। 1972 तक वे भारतीय वायुसेना में रहे. 1978 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई में युवा विंग के अध्यक्ष बने. और फिर 1982 से 1995 तक राज्यसभा में रहे।साल 1996 और 2004 में कलमाड़ी पुणे से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इसके बाद वे भारतीय ओलंपिक संघ (IOC) के अध्यक्ष रहे और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के चेयरमैन भी रहे। लेकिन खेलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद वे शांत बैठ गए।

भ्रष्टाचार और निलंबन, अकेलेपन की मृत्यु : मृत्यु के करीब एक साल पहले फरवरी 2025 में उन्हें इस आरोप से क्लीनचिट मिल गई जब ED की क्लोजर रिपोर्ट अदालत में स्वीकार कर ली गई। इस रिपोर्ट में E D ने कहा था कि सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ मनी लांड्रिंग के सबूत नहीं है। और इसी के साथ उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप का केस भी खत्म हो गया। किंतु कांग्रेस ने उन पर खेलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सस्पेंड कर दिया था। उनका राजनीतिक करियर भी समाप्त हो गया और खेलों में उनकी सक्रियता भी। वे काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और छह जनवरी की तड़के उनका निधन हो गया। पार्टी से बर्खाश्त होने के बाद से वे बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। पार्टी नेताओं ने भी उनसे दूरी बना ली थी। लेकिन पुणे में कांग्रेस को स्थापित करने वालों में सुरेश कलमाड़ी का अहम रोल था।

शरद के खालीपन को कलमाड़ी ने भरा : शरद पवार के जाने के बाद कलमाड़ी ने ही महाराष्ट्र में कांग्रेस को खड़ा किया। कलमाड़ी एक जमाने में शरद पवार के बेहद करीबी हुआ करते थे। लेकिन जब शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ी तब कांग्रेस ने कलमाड़ी को शरद खेमे से तोड़ लिया। यही कांग्रेस की चतुराई रही। अन्यथा महाराष्ट्र से उसी समय कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाता। शरद के जाते ही कांग्रेस महाराष्ट्र में समाप्त होने की कगार पर थी। तब सुरेश कलमाड़ी शरद की छत्रछाया में कांग्रेस में सक्रिय थे। मगर शरद के कांग्रेस से अलग होने के बाद कांग्रेस ने युवक सुरेश कलमाड़ी को पकड़ लिया। उन्हें युवक कांग्रेस की कमान सौंपी। कलमाड़ी ने कांग्रेस को निराश भी नहीं किया और महाराष्ट्र में कांग्रेस को सक्रिय करते रहे। कलमाड़ी के बढ़ते कद से महाराष्ट्र कांग्रेस के धाकड़ नेताओं ने उनके पर कतरने शुरू कर दिए किए। इसलिए कांग्रेस आलाकमान उन्हें केंद्र में लेकर आ गई। 1982 से 2009 तक वे संसद में रहे।

कलमाड़ी पर लगे खेल माफिया के आरोप : किंतु अति अहंकार और सक्रियता सुरेश कलमाड़ी को ले डूबी. उन पर इस तरह के आरोप लगाए गए कुछ से तो उनका कोई वास्ता नहीं था। हाकी के खेल को पुनर्स्थापित करने वाले सुरेश कलमाड़ी को हाकी टीम के कप्तान रहे परगट सिंह ने ही खेल माफिया बता दिया। मगर भारतीय ओलंपिक संघ में रहते हुए उन्होंने बहुत-सी मनमानी भी की। भारत में खेलों को प्रमोट करने के चक्कर में वे ऐसे-ऐसे खेलों को भारत में ले आए जिनका आम लोगों से कोई वास्ता नहीं था। फॉर्मूला वन रेस को उन्होंने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पेश किया। 2007 में जेपी समूह की कंपनी JPSK के साथ इंग्लैड की फॉर्मूला वन रेस की कंपनी से 16 बिलियन डॉलर का करार हुआ। JPSK के साथ 13 प्रतिशत की हिस्सेदारी सुल्भा रियल्टी के साथ थी और सुल्भा के एक निदेशक सुरेश कलमाड़ी के बेटे समीर कलमाड़ी थे।

दस महीने तिहाड़ जेल में भी गजारे : इसके बाद से सुरेश कलमाड़ी पर अंगुलियां उठने लगीं. 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के वे चेयरमैन थे। तब इसकी तैयारियों के लिए जो उपकरण खरीदे गए उनकी कीमतों को लेकर हंगामा मचा और इस खरीद-फरोख्त की जांच की माँग उठी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ने इस घोटाले की जांच क्एक्ष को सौंप दी। कलमाड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और विपक्ष ने ओलंपिक संघ से उनके इस्तीफे की मांग की। एसी और ट्रेडमिल की अंधाधुंध खरीद में कलमाड़ी फंस गए। 2011 में CBI ने उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। ओलंपिक संघ की अध्यक्षता भी उन्हें छोड़नी पड़ी और उसी साल अगस्त में कांग्रेस ने उनकी पार्टी सदस्यता निलंबित कर दी। साल 2013 की जुलाई में एशियन एथेलिटिक्स एसोसिएशन का चुनाव भी वे हार गए। इसके बाद उन्हें 10 महीने दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी रहना पड़ा।

बहमखी प्रतिभा वाले राजनेता का दखद अंत : सुरेश कलमाड़ी का आज तड़के पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में निधन हो गया। इस तरह बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एक राजनेता का दुखद अंत हुआ। वे जहां भी रहे आकाश को छुआ। आखिर वे भारतीय वायु सेना के कुशल पॉयलट रह चुके थे और प्रशिक्षक भी। खेलों में उनकी रुचि थी और राजनीति के हर दांव-पेच से वे वाकिफ भी थे।

धनिया पत्ती : फायदे बड़े-बड़े

- दाल हो या सब्जी, रायता हो या चटनी, धनिया की पत्तियां हर खाने का स्वाद और खुश्बू बढ़ा देती हैं। आयुर्वेद में धनिया को औषधि का रूप माना गया है
- अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, धनिये की पत्तियों में विटामिन्स, मिनरल्स के अलावा फोलेट, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन व मैग्नीशियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं
- धनिया की पत्तियों को सुबह खाली पेट चबाने या इनका रस पीने से गैस, एसिटिडी और कब्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इन्हें चबाने से मुंह में दुर्गंध दूर हो जाती है

(मीडिया इनपुट्स)

अमेरिका और चीन के बीच भावी तकनीक के हस्तांतरण के लिए खूब छन रही हैः अमेरिका चिप डिजाइन सॉफ्टवेयर का निर्यात उदार बना रहा है, जबकि चीन रेयर अर्थ मैग्नेट्स का अमेरिका को किया जा रहा निर्यात खोल रहा है। इस घटनाक्रम के बीच भारत कहां है?

एम.के. वेणु,पत्रकार@mkvenu1

मकर संक्रांति 15 को

आचार्य पवन तिवारी

षट्तिला एकादशी का मन 14 जनवरी बुधवार को है भगवान भास्कर मकर राशि में 14 जनवरी बुधवार को रात्रि 9:19 में आएंगे एवं इसी के साथ सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे और खरमास समाप्त हो जाएगा मकर संक्रांति का यह शास्त्रोक्त नियम है कि प्रदोष के बाद यदि रात्रि में किसी भी समय संक्रांति लगती है तो उसका पुण्यकाल दूसरे दिन होता है इस प्रकार मकर संक्रांति खिचड़ी का पर्व 15 जनवरी गुरुवार को मनाया जाएगा। स्नान दान के लिए यह पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है सर्वत्र गंगा नदी अन्यत्र नदी तीर्थ एवं कुआं सरोवर में स्नान किया जाएगा ऊनी वस्त्र दुशाला कंबल जूता धार्मिक पुस्तक विशेष कर पंचांग का दान विशेष पूर्ण फल कारक होता है इस पर्व को पूरे देश में अपनी स्थानीय परंपरा रीति रिवाज के समय मनाया जाता है।

मकर संक्रांति में 'मकर' शब्द मकर राशि को इंगित करता है जबकि 'संक्रांति' का अर्थ संक्रमण अर्थात प्रवेश करना है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। एक राशि को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करने की इस विस्थापन क्रिया को संक्रांति कहते है।

मकर संक्रांति का महत्व इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी भूलाकर उनके घर गए थे। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान और पूजा करने से व्यक्ति का पुण्य प्रभाव हजार गुना बढ़ जाता है। इस दिन से मलमास खत्म होने के साथ शुभ माह प्रारंभ हो जाता है। इस खास दिन को सुख और समृद्धि का दिन माना जाता है। यह पर्व 'पतंग महोत्सव' के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग पतंग उड़ाते है। हालांकि पतंग उड़ाने के पीछे कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताने की मुख्य वजह बताई जाती है। सर्दी के इस मौसम में सूर्य का प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थयवर्द्धक और त्वचा और हड्डियों के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आद्यशक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन-मन-आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत-महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है। संकल्प शक्ति बढ़ती है। ज्ञान तंतु विकसित होते है। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारत वर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है।

विष्णु धर्मसूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्व स्वास्थ्यवर्द्धन तथा सर्वकल्याण के लिए तिल के छः प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते है- तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पण, तिल से आहुति, तिल का उबटन लगाना। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्यकाल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा-अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धिकाल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते है। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए।

रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा भगीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भगीरथ तप साधना के परिणामस्वरूप पापनाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगाजल, अक्षत, तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रिकाल तक जन-जन का पापहरण करेंगी और भक्तजनों की सात पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेंगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की सातवीं किरण भारत वर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। सातवीं किरण का प्रभाव भारत वर्ष में गंगा-जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ तथा अर्द्धकुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। सूर्य की सातवीं किरण का शुभ प्रभाव चाहिए तो मकर संक्रांति का अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सुख, सेहत, सौभाग्य, सफलता, संतान और समृद्धि के लिए यही किरण मार्ग रोशन करती है। इसी में आशीर्वाद की और किस्मत चमकाने की अचूक शक्ति होती है।

संक्रांति का 12 राशियों को मिलेगा यह फल

मेष उच्च पद की प्राप्ति होगी।
वृषभमहत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ होनेके योग बनेगें।
मिथुन- ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी।
कर्क- कलह-संघर्ष, व्यवधानों पर विराम लगेगा।
सिंह- किसी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी।
कन्या- शुभ समाचार मिलेगा।
तुला- व्यवसाय में बाहरी संबंधों से लाभ तथा शत्रु अनकूल होंगे।
वृश्चिक- विदेशी कार्यो से लाभ तथा विदेश यात्रा होगी।
धनु- चहुंओर विजय होगी।
मकर- अधिकार प्राप्ति होगी।
कुंभ- विरोधी परास्त होंगे। भेंट मिलेगी।
मीन- सम्मान, यश बढ़ेगा।

सखा

मित्र या दोस्त शब्द सुनते ही हमारा मन यादों, संवेदनाओं और खुशी से भर जाता है, और तत्काल ही मन में सबसे करीबी व्यक्ति की छवि मुखरित हो उठती है किंतु सच्चा सखा वह नहीं जो केवल सुख के समय साथ हो, हंसी-ठिठोली में सहभागी बने या समय काटने का साधन मात्र हो; सच्चा सखा वह होता है जो हृदय की गहराइयों को बिना कहे समझ ले, संकट की घड़ी में पतवार बन जाए, और जीवन यात्रा में दीपक की भांति मार्ग को आलोकित करे। वह न तो चाटुकार होता है, न आलोचक; न हां में हां मिलाता है, न केवल टोकता है-बल्कि वह ऐसा प्रतिबिंब होता है जो तुम्हें तुम्हारे सबसे प्रामाणिक रूप से परिचित कराता है। ऐसे सखा का होना सौभाग्य नहीं, बल्कि भगवान की सबसे मूल्यवान कृपा है। भगवीता में भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को अनेक बार 'सखा' कह कर संबोधित कर रहे हैं। यह संबोधन मात्र सामाजिक संबंधों का संकेत नहीं देता, बल्कि गहन आध्यात्मिक योग्यता और आत्मीयता को भी प्रकट करता है। भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ऐसा रहस्य, जो साधारण जन को सुलभ नहीं, केवल उस व्यक्ति को बताया जा सकता है जो मित्रता और निष्कपट भक्ति के गुणों से युक्त हो। अर्जुन न केवल कृष्ण का पार्थिव मित्र है, बल्कि ऐसा साधक है, जो प्रश्न करता है, जिज्ञासा करता है, और समर्पण करता है। ये गुण उसे वह पात्रता प्रदान करते हैं कि भगवान स्वयं उसे परम ज्ञान और विज्ञान प्रदान करें। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या, संशय और स्वार्थ को त्याग देता है, तभी वह 'अनसूय' बनता है-और वही स्थिति उस अंतिम रहस्य की पात्रता बनाती है, जो स्वयं भगवान प्रदान करने वाले है। महंत स्वामी महाराज बताते हैं कि यहां गीता का यह सखा-संवाद इस उपदेश को अधिक पारदर्शी, सहज और प्रभावकारी बनाता है। इसमें गहनतम जीवन रहस्य आलोकित हुए हैं। अर्जुन के साथ कृष्ण का संवाद केवल युद्ध भूमि पर दिया गया उपदेश नहीं है, बल्कि यह जीवात्मा और परमात्मा के मध्य हुआ मित्रता का ऐसा संवाद है जो युगों से मानवता को प्रेरणा दे रहा है।

रीडर्स मेल

बच्चों की खातिर

क्या सोशल मीडिया एवं इंटरनेट का बेतहाशा उपयोग से दुनिये भर के बच्चों पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है? इसका उत्तर है हां। ऐसा ही हो रहा है। पढ़ाई में मन नहीं लगना, अवसाद का शिकार होना, बच्चों में खराब शारीरिक छवि एवं अकेलेपन का शिकार बना सकता है। रात में शयन कक्ष में इसका इस्तेमाल से नींद की कमी के कारण अन्य शारीरिक एवं मानसिक विकार को जन्म दे सकता है। सामाजिक संपर्क में कमी आना, खेलकूद से दूर होना, ऑनलाइन शिकारियों के जाल में फंस कर कई बच्चे यौन शोषण का भी शिकार बन जाते हैं। सोशल मीडिया बच्चों को पक्षपातपूर्ण या गलत जानकारी के संपर्क में ला सकता है। शायद इसी के कारण ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। प्रस्तावित कानून को लेकर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनिसि ने घोषणा की कि सरकार 2024 के अंत तक सोशल मीडिया से बच्चों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पेश करेगी।

जंग बहादुर सिंह ई-मेल से

साइबर अपराध पर अंकुश जरूरी

गलत राह पर चलने का अंजाम बुरा होता है, सब जानते हैं लेकिन कुछ लोग अंजाम की फिक्र किए बिना गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं। उन्हीं में से एक हैं साइबर क्राइम वाले लोग। पैसे की लालच और शॉर्टकर्ट के चक्कर में कुछ लोग इसमें ऐसे जकड़ते चले जा रहे हैं कि उन्हें लगता भी नहीं कि वे जुर्म कर रहे हैं। जिनका पैसा चुरा रहे हैं, उन पर क्या गुजरती होगी, कोई बेटी की विवाह के लिए पैसे जमा करता है, तो कोई इलाज के लिए, तो कोई पढ़ाई के लिए। यह बात वे तनिक भी नहीं सोचते। बिना मेहनत और कम समय में अत्यधिक पैसा कमाने के फेर में वे पैसे की कीमत नहीं समझते और नशा एवं न जाने क्या-क्या शौक पाल लेते हैं। प्रशासन और बैंकों द्वारा लोगों को जागरूक करने के बाद भी आये दिन अखबारों में साइबर ठगी के मामले देखने को मिल जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि प्रशासन की कोशिशों के बावजूद साइबर अपराध पर अंकुश नहीं लग सका है।

महीप सिंह, झारखंड

पर्यावरण पर असंवेदनशील हम

दिवाली पर जिस प्रकार दिल्ली वालों ने देर रात तक अप्रत्याशित आतिशबाजी की वह तस्दीक करती है कि वे दिल्ली के बिगड़ते पर्यावरण के प्रति कितने असंवेदनशील हैं। प्रदूषण पर उनकी चिंता घड़ियाली आंसू हैं। यद्यपि दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री, फोड़ने तक पर जितने भी प्रतिबंध लगाए वे सब स्थानीय राजनीति की झूठी बहस का हिस्सा बन कर रह गए। यूपी और हरियाणा, दोनों पड़ोसी राज्यों से पटाखों का खूब अवैध व्यापार हुआ जहां बीजेपी की सरकारें हैं। वह तो शुक्र रहा बहती हवा का जिसने अपनी 10 किमी. प्रति घंटे की बढ़ोतरी से प्रदूषण के राक्षस को दूर भगाने में मदद की वरना सोचो कि पिछले वर्ष की भांति हवा सुस्ती बनी रहती तो दिल्ली वालों का बम, पटाखों के प्रदूषण से किस प्रकार दम निकल जाता। राहत की सांस का एक कारण यह भी है कि दिवाली इस बार दो अलग-अलग दिन मनाई गई। यह त्योहार दीयों द्वारा रोशनी फैलाने का त्योहार है, न कि पटाखों से प्रदूषण फैलाने का।

ज्ञानेश सिंह कुशवाहा, मप्र

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
वर्ष - 20, अंक 6885 आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

दैनिक नवज्योति
आपके लिए, आपके साथ
dainiknavajyoti.com
जयपुर, शुक्रवार, 9 जनवरी, 2026
90 विश्वसनीयता के dainiknavajyoti.com

रफ्तार में देश की अर्थव्यवस्था

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.4 फीसदी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। पिछले साल यह 6.5 फीसदी थी। इसी तरह नॉमिनल जीडीपी में भी 8 फीसदी की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। विकास का यह पहला अनुमान महज आंकड़ा भर नहीं है बल्कि देश की समग्र आर्थिक दशा, दिशा, नीतिगत प्रभावशीलता की स्थिति को दर्शाने वाला संकेतक है। वह भी ऐसे समय में जब ट्रंप की टैरिफ नीतियों से अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची हुई है, भू-राजनीतिक तनाव, महंगाई, आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियां खड़ी हैं। आज अमेरिका, यूरोप, चीन और रूस जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि, मंदी के दौर से गुजर रही हैं। ऐसे में भारत की यह वृद्धि अनुमान महत्वपूर्ण है। इसकी बुनियाद में घरेलू मांग है। शहरी क्षेत्रों में उपभोग बढ़ा है। सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति में सुधार हुआ है। फिर भी ग्रामीण मांग अभी पूरी तरह सशक्त नहीं है। सरकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे में निवेश और कृषि सहायता कार्यक्रमों से इसमें धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं। विकास का मुख्य कारण सेवा क्षेत्र की दमदार चाल है। सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर इस वृद्धि में अहम कारक रहा है। सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेष से न केवल तत्काल रोजगार सृजन हुआ है बल्कि दीर्घकालिक उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र भी धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है। सेवा क्षेत्र-आईटी, बैंकिंग, पर्यटन, परिवहन और संचार क्षेत्र वृद्धि का मजबूत स्तंभ बना हुआ है। साथ ही मेक इन इंडिया और पीएलआई योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी इस क्षेत्र में और वृद्धि की गुंजाइश बनी हुई है। फिर भी यह स्थिरता आर्थिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। विकास वृद्धि दर से रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना बनती है। खासकर सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में। इससे आय स्तर में सुधार होता है और गरीबी में कमी लाने में मदद मिलती है। हालांकि यह भी है कि गुणवत्तापूर्ण और रोजगार अभी भी एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। तेज आर्थिक वृद्धि से सरकार की कर आय बढ़ती है जिससे राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। साथ ही यह सरकार को सामाजिक क्षेत्र और विकासात्मक योजनाओं पर अधिक खर्च करने का अवसर भी देती है। दूसरी और बढ़ती वृद्धि के साथ महंगाई को नियंत्रित रखना और ब्याज दरों में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। हालांकि यह वृद्धि अनुमान उत्साहजनक है लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुस्ती, आय असमानता, वैश्विक अनिश्चितताएं और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, कौशल विकास और मानव संसाधन की गुणवत्ता की ओर भी गौर करना जरूरी होगा। सही रणनीति के साथ आगे बढ़ते रहे तो यह वृद्धि देश को दीर्घकाल में मजबूत और आत्मनिर्भर आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकती है।

नया साल निराशावाद को संशयवाद से अलग करने का क्षण है

मिथ्या चेतना का दर्शनशास्त्र

हरदीप एस पुरी
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, भारत सरकार

“ वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। यानी औसतन प्रति माह 1.8 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का संग्रह किया गया। डिजिटल भुगतान ने वित्तीय प्रदर्शन का एक और निशान छोड़ा है।

भारत में 2026 के आरंभ में सार्वजनिक बहस नववर्ष के अनुशासन के साथ शुरू होनी चाहिए। हमें पड़ताल और तीखी आलोचनाओं का भी स्वागत करना चाहिए। लेकिन इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि बहस के साथ जवाबदेही शामिल हो। कुल 1.4 अरब की आबादी वाले गणराज्य को निराशावाद से नहीं सुधारा जा सकता। रोजगार, उत्पादकता, निर्यात और समावेशन सबसे अच्छे समय में भी आसान नहीं होते। प्रगति डिजाइन, क्रियान्वयन, सुधार और परिमापन के नीरस मेल से आती है। नया साल निराशावाद को संशयवाद से अलग करने का भी क्षण है। फ्रेडरिक नीत्शे ने बेयांड गुड एंड ईवल में लिखा है दार्शनिक को सिर्फ आलोचक या दर्शक होने के बजाय मूल्यों का सर्जक होना चाहिए।

आलोचनाओं का स्वागत है

लोकनीति में इसी तरह के दृष्टिकोण की दरकार है। आलोचनाओं का स्वागत है। मगर ये साक्ष्य तथा एक जटिल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र का शासन चलाने की ज्वलंत बाधाओं से आबद्ध होनी चाहिए। जब संशयवाद एक भंगिमा बन जाए तो यह सुधार संभव बनाने वाली संस्थाओं में विश्वास को खत्म करता है। पिछले वर्षों में टिप्पणी की एक नई विधा सामने आई है। यह संदेह को सुसंस्करण के तौर पर पेश करती है। यह सुधार के कार्य को मजाक में तब्दील कर देती है। यह एक चिरपरिचित सांत्वना पेश करती है: भारत कदाचित अपने ही नीति निर्माताओं से अभिशप्त है।

निवेशकों में नियतिवाद

यह उद्यमियों और निवेशकों में नियतिवाद को प्रोत्साहित करता है। साथ ही यह बाहरी ताकतों को वार्ताओं में भारत को दबाव में लाने के लिए तैयार कथानक भी प्रदान करता है। विशेषज्ञता को तथ्यों के प्रति जवाबदेह बने रहना चाहिए। मजबूत पेशेवर और शैक्षिक पृष्ठभूमि का दंभ भरने वाले कुछ टिप्पणीकारों का इस तरह की भंगिमा का सहारा लेना चिंता की बात है। इनमें से कुछ ऐसे टिप्पणीकारों को मैं जानता हूं जिनकी पहचान और विश्वसनीयता भारत पर आधारित है। लेकिन वे संभवत ध्यानाकर्षण या अब सरकार का हिस्सा नहीं होने के बावजूद प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए देश के खिलाफ अनाप-शनाप बोल कर अपना कॅरियर बनाने की कोशिश में लगे हैं।

डिलीवरी दुरुस्त हुई

नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार 2013-14 और 2022-23 के बीच लगभग 24 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए। अब बहुआयामी निर्धनता लगभग 30 प्रतिशत से घट कर तकरीबन 11 प्रतिशत रह गई है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) से डिलीवरी दुरुस्त हुई है। वर्ष 2025 में 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हुआ। डीबीटी काल में धन के अपव्यय में कमी के जरिए 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की बचत हुई। वित्तीय समावेशन 56 करोड़ से ज्यादा जन धन खातों के साथ अब सार्वजनिक अवसंरचना बन गया है। वित्तीय अनुशासन में सुधार के प्रभाव अब दिखाई देने लगे हैं।

डिजिटल भुगतान

माल और सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत टैक्स संग्रह में जो वृद्धि हुई और इसने अनुपालन की जिस संस्कृति को पैदा किया है वह एक दशक पहले नहीं थी। वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। यानी औसतन प्रति माह 1.8 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का संग्रह किया गया। डिजिटल भुगतान ने वित्तीय प्रदर्शन का एक और निशान छोड़ा है। नवंबर 2025 में यूपीआई के जरिए 26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम के 20 अरब लेन-देन किए गए। ये वृहत और परखे जाने योग्य आंकड़े परिमापन, सत्यापन और तौरतरीकों में सुधार के लिए संभावना का विस्तार करते हैं।

मैन्युफैक्चरिंग परिवेश

भारत बड़े पैमाने पर निर्माण नहीं कर सकता यह आरोप लगाने वाले मैन्युफैक्चरिंग परिवेश में हुए बदलावों को नज़रअंदाज़ करते हैं। उत्पादन-से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) कार्यक्रम के तहत, 14 क्षेत्रों में 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश हुआ है जिससे 18 लाख करोड़ रूपए से ज़्यादा का अतिरिक्त उत्पादन और बिक्री हुई और 12 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र इसका सबसे सटीक उदाहरण है: साल 2024-25 में इलेक्ट्रॉनिक्स का कुल उत्पादन 11 लाख करोड़ रुपये के पार पहुँच गया।

बड़े पैमाने पर उत्पादन

व्यापार में आपकी पकड़ बेहतर प्रदर्शन और निरंतर टिके रहने से बनती है, न कि केवल निराशा जताने से। साल 2024-25 में सामान और सेवाओं का कुल निर्यात 825 अरब अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। टैरिफ और संरक्षणवादी प्रतिक्रियाओं की इस दुनिया में साझेदार आपकी क्षमता के आधार पर फैसला करते हैं। भारत की स्थिति तब और मजबूत होती है जब दुनिया उसे एक ऐसे बाजार के रूप में देखती है जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है और खरीदता भी है और अब देश ज़रूरी क्षेत्रों में भरोसेमंद तरीके से अलग-अलग तरह की आपूर्ति कर सकता है। केंद्र सरकार ने इस प्रतिस्पर्धी संघवाद को और मज़बूत किया है। इसके लिए ऐसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जिनसे राज्य जुड़ सकते हैं, ऐसा फंड बनाया है जो बेहतर काम करने पर इनाम के तौर पर दिया जाता है और सुधारों के आंकड़ों को इतना पारदर्शी बना दिया है कि जनता खुद सरकार के काम का फैसला कर सके। भारत की प्रगति की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, इस पर हमेशा बहस होती रहेगी। सवाल यह है कि नए साल की शुरुआत में हम किस तरह की बहस चुनते हैं। भारत ने काम करके दिखाने का कठिन रास्ता चुना है। ये नतीजे ही हैं, जो आंकड़ों में भी दिखते हैं और महसूस भी किए जाते हैं।

“

जीवन बोध

वह विश्वचेतना

'ईश्वर' यानि वह विश्वचेतना जो विश्व का संचालन कर रही है। ईश्वर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी गुरु के साथ तुलना की जाए। ईश्वर एक शक्ति है और गुरु उसका माध्यम है। तो शक्ति की माध्यम के साथ तुलना नहीं हो सकती। ये दोनों अलग-अलग हैं। ईश्वर अलग है, गुरु अलग है। गुरु ईश्वर का माध्यम है और गुरु के माध्यम से हम ईश्वर की परिकल्पना कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है ना, गुरु साक्षात् परब्रह्म। ईश्वर का साक्षात् स्वरूप गुरु के रूप में है। और माता-पिता वे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हमें देह की प्राप्ति हुई है, देह धारण करने मिली है। देह धारण करने के लिए माता-पिता निमित्त बने। और देह धारण हुआ है, इसीलिए आत्मा मिल पाई। और आत्मा मिल पाई, इसलिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए आप आगे बढ़ पाए। इसलिए माता-पिता वह नींव है जिस नींव पर आध्यात्मिकता का मंदिर खड़ा होता है। तो बिना नींव को महत्त्व दिए, मंदिर की, कलश की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इनको आध्यात्मिक शिखर की नींव समझना चाहिए।

-शिवकृपानंद स्वामी

हेथ इज वेथ

- सर्दियों के मौसम में खानपान को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं, इन्हीं में से एक सवाल दही को लेकर भी है,दही हमें गर्मियों में तो बहुत पसंद होता है, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है कई लोग इसे खाना बंद कर देते।
- आमतौर पर माना जाता है कि सर्दियों में दही खाने से सर्दी, जुकाम या गले में खराश हो सकती है,लेकिन क्या दही वाकई सेहत के लिए नुकसानदायक है या फिर इसको लेकर एक आम धारणा बन गई है कि ठंड है इसलिए दही नहीं खाना चाहिए, सर्दियों में दही खाने के क्या फायदे हैं और इसे खाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
- दही में कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम और बी विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं,ये पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत रखने, नर्वस सिस्टम को सही तरह से काम करने में मदद करते हैं और शरीर को एनर्जी देते हैं, सर्दियों में जब लोग कम बाहर निकलते हैं और फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है।

जल तरंग

मीनार पर घंटा

इंदौर के बीचोंबीच खड़ी घड़ी मीनार पर लटका वह घंटा,जो कभी ब्रिटिश साहबों के जमाने में बजता था, तो अफसरों के पेट में हलचल मच जाती थी,आजकल बजता है तो जनता के कानों में बस घंटा ही गूंजता है। शहर साफसुथरा है, स्मार्ट है, नंबर वन है,यह नारे रोज लगते हैं, मगर गलियों में गंदगी, भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण देखकर लगता है, सबका जवाब एक ही है,घंटा ! नगर निगम की योजनाएं घंटा हैं, पुलिस की कार्रवाई घंटा है, नेताओं के वादे घंटा हैं। जनता पूछे तो अफसर हंसते हुए कहें,घंटा चिंता करो ! यह घंटा अब लोकोक्ति नहीं, मुहावरा नहीं, बल्कि शहर का संविधान बन चुका है। हर समस्या का समाधान घंटा करो ! हर आश्वासन घंटा होगा ! और हर न्याय घंटा मिलेगा !श् इंदौर की जनता अब इतनी समझदार हो चुकी है कि घंटे की पहली घनघनाहट सुनते ही ताली बजाने लगती है,क्योंकि जानती है, इसके बाद तो बस घंटा ही बचेगा। परसाई जी कहते तो यों,यह घंटा बजता है तो लगता है, समाज का पेट फटने वाला है, मगर फटता कुछ नहीं, बस गैस निकलती है।पिछले हफ्ते नगर निगम ने डंके की चोट पर ऐलान किया, अवैध कब्जे हटेंगे ! ड्रामा शुरू,बुलडोजर लाए गए, कैमरे चले, नेता चिल्लाए इंदौर बदलेगा ! अगले दिन वही कब्जे, वही दीवारें, बस नई पुताई। पत्रकार ने अफसर से पूछा क्या हुआ,जवाब मिला घंटा हुआ भाई, घंटा ! यहां घंटा शब्द नहीं, प्रतीक है,खोखले वादों का, नकली कार्रवाई का, भ्रष्टाचार के पेट का। पुलिस आए तो बोली,घंटा डरना ! कोर्ट गए तो फैसला,घंटा मिलेगा ! नेता चुनाव लड़ें तो वादा,घंटा भूल जाओ ! जनता हंसती है, क्योंकि जानती है,यह घंटा हर जगह बज रहा है। स्कूलों में,पढ़ाई घंटा है ! अस्पतालों में, दवा घंटा है ! सड़कों पर ट्रैफिक नियम घंटा हैं ! इंदौर का घंटा बजता है जैसे भ्रष्ट नेता का पेट भरपूर आवाज,अंदर से खाली ! और जनता वह अब घंटे की धुन पर थिरक रही है,क्योंकि विकल्प ही क्या बचा है, घंटा बजाओ, ताली बजाओ !अब शहर में नया खेल शुरू,घंटा चोरी का षड्यंत्र ! कुछ ने कहा विपक्ष ने चुराया ! कुछ बोले,अफसरों ने बेच दिया ! सच्चाई कोई नहीं जानता, क्योंकि सच्चाई भी घंटा है। मीमों में लिखा गया,घंटा चोरी नहीं हुआ, बस असली चोर ने पहचान लिया कि यह शहर का सबसे मूल्यवान प्रतीक है,खोखला लेकिन चमकदार। परसाई जी हंसते तो कहते चोरी का सबसे बड़ा अपराध यह है कि चोर ने घंटे को ही चुरा लिया, जो पहले से समाज का घंटा था ! जनता अब घंटे के बिना और भी खाली,क्योंकि अब कोई बहाना भी नहीं बचा। नगर निगम ने नया घंटा लगाने का ऐलान किया, विकास का प्रतीक ! समारोह धूमधाम से फीता कटा, मंत्रियों ने भाषण दिए,यह घंटा इंदौर की गूंज बनेगा ! बटन दबा,घंटा लटका मगर न बजा। बिजली चली गई। अफसर बोले, टेक्निकल फॉल्ट, घंटा ठीक हो जाएगा !

-डॉ.सुरेश कुमार मिश्रा
यह लेखक के अपने विचार हैं।

आज का विचार

एक कदम भी आगे बढना खड़े रहने से अच्छा है आगे बढने का मंत्र है, हर रोज थेड़ा बेहतर, चमत्कार के लिए इतना काफी है।

-चंद्रप्रभजी

विंडो टू द वर्ल्ड

बेरिजम झील , तमिलनाडु

बेरिजम झील दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के दिंडीगुल जिले में कोडाइकनाल शहर के पास स्थित एक जलाशय है । यह ऊपरी पलानी पहाड़ियों में फोर्ट हैमिल्टन के पुराने स्थल पर स्थित है । बांध द्वारा निर्मित यह झील एक सूक्ष्म जलसंभर विकास परियोजना का हिस्सा है। दक्षिण-पूर्व में 18.7 किलोमीटर (11.6 मील) दूर स्थित पेरियाकुलम शहर को इस झील से सार्वजनिक पेयजल प्राप्त होता है । झील के पानी की गुणवत्ता उत्कृष्ट है।

अपनों से अपनी सी बात

असली बडप्पन

एक बार एक व्यक्ति की उसके बचपन की टीचर से मुलाकात होती है।वह व्यक्ति चरण स्पर्श कर अपना परिचय देता है।वे बड़े प्यार से पूछती है-अरे वाह, आप मेरे विद्यार्थी रहे हो, अभी क्या करते हो,क्या बन गए हो ? मैं भी एक टीचर बन गया हूँ, वह व्यक्ति बोला,और इसकी प्रेरणा मुझे आप से ही मिली थी जब मैं सात वर्ष का था। उस टीचर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोली कि ,मुझे तो आपकी शक्ल भी याद नहीं आ रही है,उस उम्र में मुझ से कैसी प्रेरणा मिली थी ?वो व्यक्ति कहने लगा कि यदि आपको याद हो,जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था,तब एक दिन सुबह सुबह मेरे सहपाठी ने उस दिन उसकी महंगी घड़ी चोरी होने की आप से शिकायत की थी।आप ने क्लास का दरवाजा बन्द करवाया और सभी बच्चों को क्लास में पीछे एक साथ लाइन में खड़े होने को कहा था।फिर आप ने सभी बच्चो की जेबें टटोली।मेरी जेब मे आपको घड़ी मिल गई थी जो मैंने चुराई थी।पर चूँकि आपने सभी बच्चों को अपनी आँख बन्द रखने के लिए कहा था तो किसी को पता नहीं चला कि घड़ी मैंने चुराई थी।टीचर उस दिन आप ने मुझे लज्जा और शर्म से बचा लिया था।और इस घटना के बाद आप ने कभी भी अपने व्यवहार से मुझे यह नहीं लगने दिया कि मैंने एक गलत कार्य किया था।आपने बगैर कुछ कहे मुझे क्षमा भी कर दिया।और दूसरे बच्चे मुझे चोर कहते ,इससे भी बचा लिया।ये सुनकर टीचर बोली -मुझे भी नहीं पता था कि वो घड़ी किसने चुराई थी। वो व्यक्ति बोला-नहीं टीचर,ये कैसे सम्भव है ?आप ने स्वंय अपने हाथों से चोरी की गई घड़ी मेरी जेब से निकाली थी।टीचर बोली-बेटा, जब मैं सबके पॉकेट चेक कर रही थी।

-ललित अकिंचन

Feedback@dainiknavajyoti.com

अभिमत

आज बच्चा समय से पहले बड़ा होने को मजबूर

बच्चों की मानसिक सेहत : एक अनदेखा संकट

“ क्या आज का बच्चा सचमुच बचपन जी रहा है, या वह समय से पहले बड़ा होने को मजबूर कर दिया गया है ? जब कंधों पर स्कूल बैग से ज़्यादा अपेक्षाओं का बोझ हो, और मुस्कान के पीछे डर व असुरक्षा छिपी हो, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अंकों, तुलना और स्क्रीन की दुनिया में घिरा बच्चा चुपचाप टूट रहा है और हम उसे सामान्य समझकर आगे बढ़ जाते हैं।

भारत में बचपन अब केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं रहा, बल्कि निरंतर दबाव का अनुभव बनता जा रहा है। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, सवाल पूछते हैं और दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, उसी उम्र में वे प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं की कसौटी पर तौले जा रहे हैं। शिक्षा, जो कभी विकास का माध्यम थी, अब कई बच्चों के लिए चिंता और डर का स्रोत बन गई है। इस पूरे बदलाव में सबसे ज़्यादा उपेक्षित मुद्दा है आंकड़ों के अनुसार किशोर किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य विकार से प्रभावित पाए गए हैं। इसका अर्थ है कि हर स्कूल, हर कक्षा और हर मोहल्ले में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो भीतर ही भीतर संघर्ष कर रहे हैं।

विशेषज्ञ मानते हैं

विशेषज्ञ मानते हैं कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है, क्योंकि मानसिक समस्याओं को आज भी खुलकर स्वीकार नहीं किया जाता। 2024 में ही तेलंगाना और कर्नाटक के स्कूलों में किए गए एक बड़े सर्वे में सामने आया कि लगभग 24 प्रतिशत बच्चों में गंभीर मानसिक तनाव के लक्षण थे। इनमें से6 से 10 प्रतिशत बच्चों को तत्काल परामर्श और उपचार की आवश्यकता बताई गई। यह स्थिति किसी एक राज्य या वर्ग तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश में फैलता हुआ संकट है। फर्क बस इतना है कि कहीं यह शोर बनकर सामने आता है और कहीं खामोशी में दबा रह जाता है।

शैक्षणिक दबाव

इस संकट का सबसे बड़ा कारण है शैक्षणिक दबाव। आज बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन उनके अंकों, रैंक और तुलना से किया जाता है।अच्छा बच्चा वही माना जाता है, जो बेहतर परिणाम दे सके। असफलता का डर, माता-पिता की अपेक्षाएँ और सामाजिक तुलना बच्चों के मन में स्थायी तनाव पैदा कर रही हैं। परीक्षा अब ज्ञान की जाँच नहीं, बल्कि मानसिक सहनशक्ति की परीक्षा बनती जा रही है। कई बच्चे इसी डर में अपनी नींद, रुचियाँ और आत्मविश्वास खो बैठते हैं।

डिजिटल दुनिया में

इस शैक्षणिक दबाव के साथ-साथ डिजिटल दुनिया ने बच्चों की मानसिक दुनिया को और जटिल बना दिया है। एक राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार, भारत में60 प्रतिशत से अधिक बच्चे रोज़ तीन घंटे से अधिक समय स्क्रीन पर बिताते हैं। सोशल मीडिया बच्चों के सामने एक ऐसी दुनिया रखता है, जहाँ सब कुछ सुंदर, सफल और परिपूर्ण दिखता है। इस निरंतर तुलना में बच्चा स्वयं को अधूरा और असफल महसूस करने लगता है। धीरे-धीरे यह भावना आत्म-सम्मान को कमजोर करती है और चिंता व अवसाद को जन्म देती है।

अत्यधिक स्क्रीन-टाइम

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि अत्यधिक स्क्रीन-टाइम का सीधा संबंध एकाग्रता में कमी, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या और सामाजिक अलगाव से है। लेकिन विडंबना यह है कि इन संकेतों को अक्सर मोबाइल की लत या अनुशासन की कमी कहकर टाल दिया जाता है, जबकि असल समस्या कहीं गहरी होती है। घरेलू वातावरण भी बच्चों की मानसिक सेहत पर गहरा असर डालता है। पारिवारिक तनाव, आर्थिक दबाव, माता-पिता के बीच तनाव या अत्यधिक नियंत्रण ये सभी बच्चे के मन में असुरक्षा पैदा करते हैं।

अकेलापन खतरनाक है

यह अकेलापन ही सबसे खतरनाक है। जब बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, जब उसकी चिंता को गंभीरता से नहीं लिया जाता, तब वह भीतर-ही-भीतर टूटने लगता है। कई बार यह टूटन पढ़ाई छोड़ने, आत्म-अलगाव या आत्म-नुकसान जैसे गंभीर रूप भी ले लेती है। ये घटनाएँ हमें झकझोरती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें अपवाद मानकर आगे बढ़ जाते हैं। हकीकत यह है कि बच्चों की मानसिक सेहत को नज़रअंदाज़ करना उनके भविष्य को जोखिम में डालना है। बचपन में अनदेखी गई समस्याएँ आगे चलकर कम आत्मविश्वास, संबंधों में कठिनाई, कार्यक्षमता में कमी और गंभीर मानसिक रोगों का कारण बन सकती हैं। एक समाज के रूप में यह हमारी सामूहिक विफलता होगी।

बच्चों की मानसिक सेहत

अब समय आ गया है कि हम बच्चों की मानसिक सेहत को दया या शर्म के चश्मे से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और समझ के साथ देखें। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श को अनिवार्य करना, शिक्षकों को भावनात्मक संकेत पहचानने के लिए प्रशिक्षित करना और अभिभावकों को बच्चों से संवाद के लिए तैयार करना, ये कदम अब टाले नहीं जा सकते। बचपन को बोझ से मुक्त करना केवल सरकारी नीतियों का सवाल नहीं है, यह हमारे समाज की सोच की परीक्षा है। यदि हम सचमुच एक सशक्त और मानवीय भारत का सपना देखते हैं, तो हमें अपने बच्चों को केवल सफल नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना होगा।

-डॉ सुनिधि मिश्रा
यह लेखक के अपने विचार हैं।

सम्पादकीय

पीएम की खुदेगी कब्र!

राजधानी दिल्ली का जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) नफरत, हिंसा और छद्म वामपंथ का ऐसा अड्डा है, जहां छात्रों की युवा पीढ़ियों को, साल-दर-साल, जहरीला और देश-विरोधी बनाया जा रहा है। दुर्भाग्य है कि आतंकवादी अफजल गुरु और उमर खालिद, शरजील इमाम इन छात्रों के 'आदर्श' हैं। पाकिस्तान के लिए वे मर्माहत होते हैं और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अपमान करते हैं। संसद को वे ढकोसला करार देते हैं, लिहाजा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ भी आंदोलित होते हैं। अब उन्हीं छात्रों की एक जमात देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की कब्र खोदने के नारे लगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की कब्र जेएनयू की 'लाल मिट्टी' पर, 'लाल दीवारों' वाली जमीन पर ही खुदेगी और ये छात्र 'लाल सलाम' की हुंकारें भरेंगे। आखिर प्रधानमंत्री की कब्र क्यों खुदेगी? ऐसे ही नारे कांग्रेस नेताओं ने भी लगाए थे। उन अपराधों की नियति क्या हुई? देश आज भी जानना चाहता है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने जेएनयू के छात्रों के साथ क्या अपराध किया है? भारत सरकार करोड़ों रुपए सालाना का अनुदान देकर ऐसे विश्वविद्यालय को संचालित कर रही है, जहां छद्म वामपंथ और देशद्रोही प्रवृत्तियां पलती रही हैं। वामपंथ शेष देश में अप्रासंगिक हो चुका है। उसके कुछ अवशेष बचे हैं, लेकिन छात्रों के एक वर्ग में आज भी यह फैशन के तौर पर जिंदा है। कैसी विडंबना और विरोधाभास है यह? 'कब्र खुदेगी' किसी वैचारिक लड़ाई, संघर्ष का भी हिस्सा नहीं है। संविधान हम सभी को अधिकार देता है कि हम प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, राजनीति और विचारधारा का विरोध कर सकते हैं। आंदोलन छेड़ सकते हैं, लेकिन जिस शख्स को देश के लोकतंत्र ने बहुमत देकर प्रधानमंत्री चुना है और उस प्रधानमंत्री ने एक निर्वाचित सांसद को अपना गृहमंत्री चुना है, उनकी 'कब्र खुदेगी' के नारे लगाना, डफली की ताल पर तालियां बजा कर विरोध-प्रदर्शन करना तो 'लोकतांत्रिक मजाक' है। यह देश के कार्यकारी प्रमुख को गालियां देना है, लिहाजा यह असंवैधानिक है और अस्वीकार्य भी है। ऐसे 'लाल-लाल' छात्रों को विश्वविद्यालय से बर्खास्त कर हमेशा के लिए 'काली सूची' में डाल देना चाहिए। उनका शैक्षिक करियर बर्बाद होता है, तो उसकी भी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह भडक़ी, उकसाई गई, उच्छृंखल जमात पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय में नहीं आई है। वे देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की कब्र इसलिए खोदने के उत्तेजक नारे लगा रहे हैं, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं दी है। बल्कि उन्हें 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश का 'केंद्रीय आरोपित' माना है। वे आगामी एक साल तक जमानत के लिए दोबारा आवेदन भी नहीं कर सकेंगे। दिल्ली दंगों में 53 मासूम मौतें हुई थीं, 581 लोग घायल हुए थे और 1200 से अधिक घर और दुकानें जला दी गईं या तबाह कर दी गई थीं।

एआई से बदलता राजस्थान: डबल इंजन सरकार का डिजिटल क्रांति मॉडल

डॉ. नयन प्रकाश गांधी

> राजस्थान ने सिद्ध कर दिया है कि डिजिटल परिवर्तन क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय विज़न का सुंदर संगम हो सकता है। भजनलाल शर्मा सरकार और केंद्र सरकार की यह संयुक्त पहल न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे भारत के लिए एआई युग का स्वागत है। त्रिम बुद्धिमत्ता अब केवल भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि भारत के वर्तमान विकास एजेंडे का केन्द्रीय आधार बन चुकी है। जयपुर के जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्टकॉन्फ्रेंस-2026 ने सिद्ध कर दिया कि राजस्थान अब तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि एआई नवाचार और नीति-निर्माण का अग्रणी केंद्र बनने को तैयार है।

राजस्थान ने सिद्ध कर दिया है कि डिजिटल परिवर्तन क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय विज़न का सुंदर संगम हो सकता है। भजनलाल शर्मा सरकार और केंद्र सरकार की यह संयुक्त पहल न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे भारत के लिए एआई युग का स्वागत है।

त्रिम बुद्धिमत्ता अब केवल भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि भारत के वर्तमान विकास एजेंडे का केन्द्रीय आधार बन चुकी है। जयपुर के जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्टकॉन्फ्रेंस-2026 ने सिद्ध कर दिया कि राजस्थान अब तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि एआई नवाचार और नीति-निर्माण का अग्रणी केंद्र बनने को तैयार है।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस उद्घाटन सत्र में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद की वर्चुअल उपस्थिति ने डबल इंजन सरकार के तकनीकी समन्वय का जीवंत प्रमाण प्रस्तुत किया।

यह घटना केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि राजस्थान के डिजिटल परिवर्तन की नई दिशा का प्रतीक बनी।इस कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉन्च किया गया नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम राज्य के युवाओं, छात्रों और शिक्षकों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह कार्यक्रम तकनीकी ज्ञान को ग्रामीण विद्यालयों से शहरी कॉलेजों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा, जिससे राजस्थान के युवा वैश्विक एआई अर्थव्यवस्था में सहज प्रवेश कर सकेंगे।भजनलाल सरकार की यह पहल विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह स्थानीय भाषा और संस्कृति के अनुरूप प्रशिक्षण पर जोर देती है। इससे डिजिटल असमानता मिटेगी और तकनीक हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचेगी।राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी 2026 का लॉन्च इस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। यह नीति स्टार्टअप्स, शोध संस्थानों और उद्योगों के बीच साझेदारी को मजबूत करेगी, साथ ही एआई के नैतिक उपयोग पर कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित करेगी।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह दृष्टिकोण कि 'एआई अब सामाजिक-आर्थिक विकास का शक्तिशाली इंजन है' राज्य के प्रशासनिक परिवर्तन का संकेत देता है। यह पॉलिसी डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और निष्पक्षता पर आधारित है, जो राजस्थान को जिम्मेदार एआई का मॉडल राज्य बनाएगी।

आई स्टार्ट एलएमएस और एवीजीसी-एक्सार भविष्य की नींव

iStart LMS के माध्यम से स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई गति मिलेगी। यह लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम युवाओं को एआई-एमएल कौशल प्रदान करेगा, जिससे कौशल अंतर को पाटा जा सकेगा।राजस्थान AVGC-XR पोर्टल रचनात्मक उद्योगों के लिए नया अवसर खोलेगा। एनिमेशन, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी क्षेत्र में राजस्थानी युवा अब वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। राजस्थान एआई पोर्टल सभी एआई संबंधी सूचनाओं का एकीकृत केंद्र बनेगा।होलोग्राफी तकनीक के माध्यम से गूगल,आईआईटी दिल्ली और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर जैसे संस्थानों के साथ एमओयू प्रदर्शन ने तकनीकी साझेदारी का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। यह केवल औपचारिक समझौते नहीं, बल्कि नवाचार के लिए रणनीतिक गठबंधन हैं।केंद्र सरकार का यह समर्थन राजस्थान को भारत के एआई हब के रूप में स्थापित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता दर्शाता है। अश्विनी वैष्णव और जितिन प्रसाद की उपस्थिति ने संघीय सहयोग का आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिद्ध कर दिया है कि तकनीकी नेतृत्व केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि ठोस क्रियान्वयन से मापा जाता है।

ई-मित्र से राज-ई-साइन और अब एआई पोर्टल तक की यात्रा राजस्थान के डिजिटल परिवर्तन की गति को दर्शाती है।यह सरकार ग्रामीण राजस्थान को भी डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कटिबद्ध है। एआई आधारित कृषि सलाहकार, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा समावेशी विकास के नए द्वार खोलेंगी।

केंद्र-राज्य समन्वय: डिजिटल इंडिया का वास्तविक स्वरूप

केंद्रीय नेतृत्व का सक्रिय सहयोग इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल इंडिया अब केवल केंद्रीय योजना नहीं, बल्कि राज्यों के माध्यम से धरातल पर उतर रहा है। राजस्थान ने डिजिटल इंडिया मिशन को न केवल अपनाया, बल्कि इसे क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला भी है।यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। जब तकनीक और नीति का यह तालमेल बना रहेगा, भारत वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की दौड़ में अवश्य अग्रणी होगा।

ग्रामीण राजस्थान का एआई सशक्तिकरण -समय की आवश्यकता

सच्ची सफलता तब होगी जब एआई का लाभ मुख्य स्मार्ट सिटीज तक सीमित न रहे। भजनलाल सरकार को ग्रामीण पंचायतों में एआई आधारित निर्णय सहायता प्रणाली स्थापित करने पर ध्यान देना होगा। स्थानीय भाषा में एआई चैटबॉट्स, कृषि पूर्वानुमान और स्वास्थ्य निदान ग्रामीण जीवन को बदल सकते हैं।महिला साक्षरता और कौशल विकास में भी एआई की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट डॉ नयन प्रकाश गांधी का मानना है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता ही सच्चा परिवर्तन लाएगी।राजस्थान ने सिद्ध कर दिया है कि डिजिटल परिवर्तन क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय विज़न का सुंदर संगम हो सकता है। भजनलाल शर्मा सरकार और केंद्र सरकार की यह संयुक्त पहल न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे भारत के लिए एआई युग का स्वागत है।

भूख से मुक्ति का राष्ट्रीय संकल्प है अटल कैंटीन योजना

ललित गर्ग

> किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे पहली जिम्मेदारी यह होती है कि उसका कोई भी नागरिक भूखा न रहे। इसी बुनियादी और मानवीय सोच के साथ दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार द्वारा शुरू की गई रुपये 5 में भोजन उपलब्ध कराने की 'अटल कैंटीन योजना' निस्संदेह एक दूरदर्शी, करुणामय, मानवीय और जनकल्याणकारी पहल है। इस योजना का उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट और मानवीय है कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। राजधानी जैसे महानगर में, जहाँ एक ओर समृद्धि और चमक-दमक है, वहीं दूसरी ओर असंगठित श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शाचालक, ठेला-पटरी वाले, घरेलू कामगार और बेघर लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं।

भूख केवल एक शारीरिक पीड़ा नहीं है, वह सामाजिक असंतुलन, मानसिक कुंठा और नैतिक विचलन की जननी भी है। इतिहास साक्षी है कि जब पेट खाली होता है, तो विचार उग्र हो जाते हैं, व्यवस्था के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है और विद्रोह की भावना पनपती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे पहली जिम्मेदारी यह होती है कि उसका कोई भी नागरिक भूखा न रहे। इसी बुनियादी और मानवीय सोच के साथ दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार द्वारा शुरू की गई रुपये 5 में भोजन उपलब्ध कराने की 'अटल कैंटीन योजना' निस्संदेह एक दूरदर्शी, करुणामय, मानवीय और जनकल्याणकारी पहल है। इस योजना का उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट और मानवीय है कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। राजधानी जैसे महानगर में, जहाँ एक ओर समृद्धि और चमक-दमक है, वहीं दूसरी ओर असंगठित श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शाचालक, ठेला-पटरी वाले, घरेलू कामगार और बेघर लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। इनके लिए दो वक्त का सम्मानजनक और पौष्टिक भोजन आज भी एक चुनौती बना हुआ है। अटल कैंटीन योजना इन्हीं वर्गों के लिए जीवनरेखा बनकर सामने आई है, जो 'संकल्प से सिद्धि' के लक्ष्य को दर्शाता है और इसे देश में भोजन सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस योजना का शुभारंभ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर किया जाना केवल एक औपचारिक तिथि चयन नहीं, बल्कि एक वैचारिक निरंतरता का प्रतीक है। अटलजी का संपूर्ण राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन अंत्योदय अर्थात समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के विचार से प्रेरित रहा। वर्ष 2000 में शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अटलजी के लिए गरीब केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि नीति का केंद्र था। उस योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया गया, जिससे करोड़ों लोगों को भुखमरी से राहत मिली। अटल कैंटीन योजना उसी सोच का आधुनिक शहरी संस्करण है, जहाँ अनाज के बजाय तैयार, पौष्टिक और स्वच्छ भोजन सीधे थाली में परोसा जा रहा है। यह नीतिगत निरंतरता इस बात का प्रमाण है कि सुशासन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि संवेदनशील क्रियान्वयन से साकार होता है। अटल कैंटीन में भोजन की कीमत रुपये 5 रखी गई है, जबकि सरकार प्रत्येक थाली पर रुपये 25 की सब्सिडी दे रही है। यह मूल्य निर्धारण अत्यंत सोच-समझकर किया गया है। भोजन पूरी तरह मुफ्त न देकर एक न्यूनतम राशि तय करने का उद्देश्य यह है कि भोजन की कद्र बनी रहे और लाभार्थी इसे भीख नहीं, बल्कि अधिकार और सम्मान के रूप में ग्रहण करे। यह नीति सामाजिक मनोविज्ञान को समझने का उत्कृष्ट उदाहरण है।

रेखा गुप्ता सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए जिस संवेदनशीलता, निर्णय क्षमता और प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया है, वह उनके प्रभावी राजनीतिक नेतृत्व को रेखांकित करता है; अटल कैंटीन जैसी योजनाएँ बताती हैं कि वे शासन को सत्ता नहीं, सेवा का माध्यम मानती हैं। किंतु सर्दी के इस कठोर मौसम में दिल्ली की सड़कों, फुटपाथों और फ्लाईओवरों के नीचे ठिठुरती रातें काटने को विवश गरीब और बेघर लोगों के लिए केवल मौसमी रैन-बसेरे पर्याप्त नहीं हैं, आवश्यकता एक स्थायी, समन्वित और मानवीय शीत-रक्षा योजना की है, जिसमें अस्थायी आश्रय के साथ गरम वस्त्र, पौष्टिक भोजन, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा और पुनर्वास की स्पष्ट व्यवस्था हो, ताकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी की सड़कों पर कोई भी व्यक्ति सर्द रात में बेसहारा और अदृश्य न रहे; ऐसा कदम न केवल प्रशासनिक संवेदनशीलता का प्रमाण होगा, बल्कि लोकतंत्र की नैतिक जिम्मेदारी का भी सशक्त निर्वाह बनेगा। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि उपलब्ध कराया जा रहा भोजन पोषण मानकों के अनुरूप है। भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई मानकों का पालन किया जाता है, जिसमें प्रति थाली 700-800 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन होता है। डिजिटल टोकन, सीसीटीवी और निगरानी के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। प्रत्येक कैंटीन प्रतिदिन लगभग 1000 लोगों को भोजन परोसने की क्षमता रखी है, और 100 कैंटीन खोलने का लक्ष्य है। दाल, सब्जी, रोटी/चावल जैसे संतुलित आहार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें आरओ वाटर एवं अचार आदि भी परोसा जा रहा है ताकि यह योजना केवल पेट भरने तक सीमित न रहकर स्वास्थ्य सुधार में भी योगदान दे सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा गरीबों और निम्न आय वर्ग के लिए मुफ्त एवं रियायती अनाज योजनाएँ लगातार संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी पहलों ने संकट काल में करोड़ों परिवारों को राहत दी है। इन योजनाओं का मूल दर्शन यही है कि भूखा नागरिक न आत्मनिर्भर बन सकता है और न ही राष्ट्रनिर्माण में भागीदार। रेखा गुप्ता सरकार की अटल कैंटीन योजना इन राष्ट्रीय प्रयासों के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। यह दर्शाती है कि केंद्र और राज्य, यदि समान मानवीय दृष्टि से काम करें, तो सामाजिक समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से संभव है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों ही इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि भुखमरी और अपराध के बीच गहरा संबंध होता है। जब व्यक्ति की मूल आवश्यकताएँ पूरी नहीं होतीं, तो वह व्यवस्था के प्रति विद्रोही दृष्टिकोण अपनाने लगता है। यही कारण है कि अनेक महान नेताओं ने यह कहा है कि गरीब को पहले रोटी दो, उपदेश

वैश्विक विश्व युद्ध के मुहानें पर बैठी मानवता

संजीव ठाकुर

सावधान?मानवीय जीवन आज परमाणु युद्ध के कगार पर खड़ा है और पूरी पृथ्वी जैसे किसी सक्रिय ज्वालामुखी के मुख पर बैठी हुई प्रतीक्षा कर रही है कि अगला सनकी आदेश किस राजधानी से निकलेगा। परमाणु संपन्न देशों के शासक स्वयं को वैश्विक सिरमौर सिद्ध करने की खतरनाक होड़ में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, विस्तारवादी मंसूबों और व्यक्तिगत सनकों को मानवता के अस्तित्व से ऊपर रख चुके हैं। चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे देश जहाँ परमाणु शक्ति तानाशाही प्रवृत्तियों के हाथों में केंद्रित है। वहाँ यह खतरा और भी भयावह हो जाता है क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब सत्ता विवेक से कट जाती है तब युद्ध अपरिहार्य हो जाता है, अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम आज भी मानवता के माथे पर कलंक की तरह दर्ज हैं। उसे समय के परमाणु हमले के विकिरण के दुष्प्रभाव आज भी जापान के बच्चों के शरीर और भविष्य में देखे जा सकते हैं।उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन द्वारा 2022 के बाद से सौ से अधिक हथियारों के परीक्षण जिनमें अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान को लक्ष्य करने वाली परमाणु मिसाइलें शामिल हैं। यही इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि यह देश किसी भी क्षण सनक में विनाशकारी कदम उठा सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहते बल्कि वैश्विक संतुलन को झकझोर कर रखा देते हैं और यूक्रेन को नाटो तथा अमेरिका से मिल रही सहायता के कारण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी दे चुके हैं ।जबकि उन्हें यह अनुमान ही नहीं था कि यूक्रेन इतना लंबा प्रतिरोध कर पाएगा, चीन और ताइवान विवाद में भी अमेरिका के परोक्ष हस्तक्षेप से नाराज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र युद्ध के केंद्र में आ सकता है। यह भी सर्वविदित तथ्य है कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में अमेरिका के सबसे बड़े रणनीतिक विरोधी बन चुके हैं और अमेरिका स्वयं को विश्व का सर्वशक्तिमान बनाए रखने के दबाव में लगातार युद्धोन्मुखी नीति अपनाए हुए है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया द्वारा उत्तर कोरिया की सीमा पर लगातार सैन्य अभ्यास को प्योंगयांग हमले के पूर्वाभ्यास के रूप में देख रहा है।जबकि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय समझौतों के तहत संयुक्त बैलिस्टिक मिसाइल रणनीति पर आगे बढ़ चुके हैं।, इन तैयारियों के जवाब में उत्तर कोरिया द्वारा रणनीतिक क्रूज मिसाइल परीक्षणों का निरीक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि टकराव की जमीन पूरी तरह तैयार हो चुकी है।

पश्चिम एशिया में वेनेजुएला संकट, इसराइल-फिलिस्तीन युद्ध और यूक्रेन संघर्ष आपस में जुड़कर एक ऐसे वैश्विक युद्ध की प्रस्तावना रच रहे हैं जिसमें पाकिस्तान और खाड़ी देशों की भागीदारी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अमेरिका में चुनावी दबावों के चलते वहां का नेतृत्व अपनी वैश्विक बादशाहत बचाने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार दिखाई देता है और उसके साथ ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इसराइल जैसे देश आंख मूंदकर खड़े रहते हैं।भारत की स्थिति इन परिस्थितियों में अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि एक ओर उसकी चीन से परंपरागत शत्रुता है तो दूसरी ओर रूस से गहरे रणनीतिक संबंध और अमेरिका से बढ़ती निकटता है जबकि भारत लगातार शांति और संतुलन की भूमिका निभाने का प्रयास करता रहा है। परंतु जब विश्व की प्रमुख शक्तियां ही संवाद की बजाय दंभ और हथियारों की भाषा बोलने लगें तो किसी भी क्षण चिंगारी विश्वयुद्ध में बदल सकती है और यदि ऐसा हुआ तो यह युद्ध केवल देशों का नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता और पृथ्वी के अस्तित्व का युद्ध होगा, ऐसे समय में विश्व को नेताओं की सनक नहीं बल्कि विवेक की आवश्यकता है और मानवता के पास अब केवल यही एक प्रार्थना शेष रह जाती है कि युद्ध नहीं हो और शांति ही अंतिम विकल्प बने।

गाँव तक योजना पहुंची है रोशनी नहीं

कविता हुलेरिया

भारत के गांवों में रात का अँधेरा सिर्फ अँधेरा नहीं, बल्कि सुरक्षा-संकट, अवसरों का नुकसान, स्वतंत्र आवाजाही में बाधा और रोज़मर्रा की ज़िन्दगी को जोखिम में डालने वाला अनुभव बन जाता है। यह वह मुश्किलें हैं जो उत्तराखंड के बागेश्वर जिला के एक दूर दराज गाँव जखेड़ा के लोगों को रोज झेलनी पड़ती है। इस छोटे से गांव में जहाँ लगभग 1546 लोग रहते हैं, रात के समय कच्चे रास्तों पर चलते हुए डर और असहजता आम बात है। बच्चों से लेकर पुरुष, महिलाएँ और बुजुर्ग सभी को अँधेरे से जूझना पड़ता है क्योंकि रास्तों पर पर्याप्त रौशनी नहीं होती है। गाँव वालों का कहना है कि सड़क पर लाइट की व्यवस्था न होने की वजह से रात में चलना जोखिम भरा हो जाता है। जंगली जानवरों से लेकर ठोकर खाकर गिरने तक के भय के साथ लोगों की इस पर से गुजर होती है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार सोलर लाइट की व्यवस्था की जाती है, और जखेड़ा गाँव के कुछ रास्तों पर इसकी व्यवस्था भी है, लेकिन अभी भी गाँव के सभी रास्तों पर लोगों को इस सुविधा का इंतज़ार है।

देश स्तर पर भी सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने की कई योजनाएं मौजूद हैं। अटल ज्योति योजना के तहत अब तक 257 जिलों में लगभग 2.72 लाख सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं, और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, ताकि उन इलाकों को रोशन किया जा सके जहाँ ग्रिड-बिजली भरोसेमंद नहीं है। राज्य स्तर पर भी कई योजनाएं चल रही हैं। हरियाणा में बिजली पहुँचाने के प्रयासों के तहत सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं, लेकिन कई गांवों में अभी भी पर्याप्त संख्या में रोशनी नहीं पहुँची है।

अब उत्तराखंड राज्य के उदाहरण को देखें तो यह राज्य हिमालयी भौगोलिक क्षेत्र में बसा हुआ है, जहां बिजली की निरन्तरता चुनौतीपूर्ण रही है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) और अन्य विभागों ने ग्रामीण हिस्सों में सोलर लाइटों की स्थापना के लिए कदम उठाए हैं। चम्पावत जिले के ग्रामीण इलाकों के लिए उरेडा को लगभग ?72 लाख की धनराशि मिली है, जिससे चार विकासखंडों में एलईडी-आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह धनराशि सोलर लाइटें लगाने और ग्रामीण रास्तों, सार्वजनिक स्थानों को रोशन करने के लिए आवंटित की गई है जिससे अँधेरे में आवाजाही आसान हो सके। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2025 में अल्मोड़ा जिले में लगभग ?90 लाख की लागत से गाँवों में सोलर लाइट लगाई गई, जो छह ब्लॉकों में 72 स्थानों तक रात की आवाजाही को आसान बनाने में मदद कर रही है। इस तरह की पहल से यह क्षेत्र न सिर्फ अँधेरे को कम करता है, बल्कि रात में स्कूलों, बाज़ारों और चिकित्सकीय सेवाओं तक पहुँच भी सुलभ बनाता है। पिछले कुछ महीनों में नैनीताल जिले के लिए निजी कंपनी के सीएसआर फंड और सांसद के सहयोग से लगभग 1400 सोलर स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था की गई, ताकि गाँवों की गलियों और सड़क किनारों को उजाला मिल सके। स्थानीय प्रशासकों ने कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा योग्य स्थलों का चुनाव किया जाना चाहिए ताकि रोशनी का लाभ सभी तक समान रूप से पहुँचे। इन आँकड़ों और परियोजनाओं को देख कर यह समझ में आता है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में सोलर लाइट की आवश्यकता सिर्फ एक तकनीकी समाधान नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक बदलाव लाने वाली आवश्यकता भी है। जहां बिजली का ग्रिड की समुचित व्यवस्था नहीं पहुंच रही है, वहाँ सोलर स्ट्रीट लाइट गाँवों को रात में सुरक्षित महसूस कराने का एक सरल और टिकाऊ उपाय बन रही हैं, जो स्थानीय लोगों की आवाजाही, बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की स्वतंत्रता तथा बुजुर्गों की रात की सुरक्षा को बेहतर बनाती हैं। जब हम जखेडा जैसा गाँव देखते हैं, जहाँ लोग रात में सड़क पर चलते समय डर महसूस करते हैं, उनकी ज़रूरत और अपेक्षा निर्विवाद रूप से स्पष्ट होती है। वे चाहते हैं कि हर रास्ता, हर घर मोड़ पर पर्याप्त रोशनी हो ताकि कोई भी रात के अँधेरे में अपने दैनिक कामों, घर-परिवार, और सामाजिक भागीदारी से वंचित न रहे। गांव वाले यह भी कहते हैं कि रोशनी बिना भेदभाव सब तक पहुँचनी चाहिए। किसी जाति, समूह या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न हो ।

संपादकीय

जेएनयू और वामपंथः विचारधारा के नाम पर अराजकता

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर किसी शैक्षणिक उपलब्धि, शोध या बौद्धिक योगदान के लिए नहीं, आपत्तिजनक नारेबाजी, उग्र मानसिकता और लोकतंत्र विरोधी आचरण के कारण राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध लगाए गए उत्तेजक और हिंसक नारे इस बात का प्रमाण हैं कि जेएनयू में लंबे समय से पनप रही वामपंथी राजनीति अब असहमति की सीमा लांघ चुकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इसे जानबूझकर किया गया कृत्य बताते हुए पुलिस से गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग करना भी आज यह बता रहा है कि वर्षों से चले आ रहे वैचारिक अराजकता के विरुद्ध एक अनिवार्य हस्तक्षेप अब अनिवार्य हो गया है। वामपंथी सोच का सबसे बड़ा और घातक प्रभाव यह रहा है कि उसने भारत के विकास को हमेशा संदेह और शत्रुता की दृष्टि से देखा। आर्थिक सुधार, बुनियादी ढांचे का विस्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णय, आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कदम या सामाजिक सुधार, हर पहल को ह्यफासीवादह्ल, ह्यराज्य दमनह्ल या ह्यकॉरपोरेट साजिशह्ल बताकर खारिज करने की प्रवृत्ति लगातार देखने को मिलती है। जेएनयू में फीस वृद्धि, अनुच्छेद 370, सीएए या अन्य किसी भी विषय को लेकर आंदोलन का तरीका हमेशा एक जैसा रहा है। पढ़ाई ठप करो, परीक्षाएं रोक दो, रजिस्ट्रेशन बाधित करो और सामान्य छात्रों को बंधक बना लो। पिछले महीनों में यही रणनीति खुलकर सामने आई। सेमेस्टर परीक्षाओं को बाधित किया गया, छात्रों को कक्षाओं में जाने से रोका गया, विश्वविद्यालय के मुख्य भवन पर कब्जा किया गया और जब छात्रों ने धमकियों के बावजूद रजिस्ट्रेशन शुरू किया तो सर्वर रूम में घुसकर इंटरनेट बंद कर दिया गया। इसके बाद भी जब अधिकांश छात्रों ने वैकल्पिक माध्यमों से पंजीकरण कर लिया, तो उन पर डंडों, रॉड और धारदार हथियारों से हमला किया गया। यह सब किसी छात्र आंदोलन का स्वरूप नहीं हो सकता है, ये सीधे तौर पर संगठित हिंसा और वर्चस्व की राजनीति है। कहना होगा कि यह घटना किसी एक दिन, एक समूह या एक प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं है। यह उस वैचारिक परंपरा का नवीन अध्याय है, जिसने जेएनयू को शिक्षा और शोध के केंद्र से अधिक एक राजनीतिक अखाड़े में बदल दिया है। साल 1969 में स्थापना के बाद से ही वामपंथी छात्र संगठनों और उनके वैचारिक समर्थकों का इस विश्वविद्यालय पर लगभग एकाधिकार रहा है। इस आधिपत्य का परिणाम यह हुआ कि कैंपस में सहमति और असहमति को तार्किकता की कसौटी पर नहीं पखरा जाता। आज भी यहां हिंसा, धमकी और दबाव के जरिए तर्कों को कुचला जा रहा है। साल 1983 में तो हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि पूरे एक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय को बंद करना पड़ा था। उस समय न तो किसी गैर वामपंथी सरकार का दबाव था।

नई दिल्ली कार्यालय
एक्शन बालाजी हाउस, बी-244, मजलिस पार्क, दिल्ली- 110033

उत्तरी दिल्ली कार्यालय
शक्ति कॉम्पलैक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली- 110042

चंडीगढ़ कार्यालय
फर्स्ट फ्लोर, देश सेवक बिल्डिंग, सेक्टर- 29डी, चंडीगढ़

पंजाब कार्यालय
7/2, थर्ड फ्लोर, मोनिका, टावर, ईआर-146, पक्का बाग, मिलाप चौक, जालंधर

करनाल कार्यालय
224, सेक्टर 32पी, करनाल- 132001

सोनीपत कार्यालय
एक्शन इंडिया कार्यालय, अपोजिट एनएस कम्प्यूटर, झंडी रोड़, गीता भवन चौक सोनीपत- 131001

शिमला कार्यालय
किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला- 171001

ऊना कार्यालय
कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना-174303

देहरादून कार्यालय
7/1, बल्लूपुर रोड़, कृष्णा नगर चौक, देहरादून

बांग्लादेश में हिंदुओं से बर्बरता का सिलसिला कब तक चलेगा?

मनोज कुमार अग्रवाल

> 5 जनवरी को रात नरसिंग्दी जिले के पोलाश उपजिला के चोसिंर्दूर बाजार में किराना दुकान चलाने वाले हिंदू व्यापारी मोनी चक्रवर्ती पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल मोनी को अस्पताल ले जाते समय ही मौत हो गई। तो वहीं, परिवार का कहना है कि मोनी का किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था। वे शांत स्वभाव का था उनकी पत्नी अंतरा मुखर्जी हाउसवाइफ हैं और उनका 12 वर्षीय बेटा अभिक चक्रवर्ती है

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सोमवार को देर रात एक हिंदू दुकानदार मोनी चक्रवर्ती की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जो पिछले 24घंटों में इस तरह की दूसरी घटना है। इससे पहले राणा प्रताप बैरागी नाम के युवक को जान से मार डाला। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। हिन्दुओं के साथ की जा रही बर्बरता भरी हिंसा के खिलाफ पश्चिमी देशों और कथित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन शर्मनाक चुप्पी साधे हुए हैं क्या हिन्दुओं के लिए कोई संवेदनशील नहीं है?

आपको बता दें 5जनवरी को रात नरसिंग्दी जिले के पोलाश उपजिला के चोसिंर्दूर बाजार में किराना दुकान चलाने वाले हिंदू व्यापारी मोनी चक्रवर्ती पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल मोनी को अस्पताल ले जाते समय ही मौत हो गई। तो वहीं, परिवार का कहना है कि मोनी का किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था। वे शांत स्वभाव का था उनकी पत्नी अंतरा मुखर्जी हाउसवाइफ हैं और उनका 12वर्षीय बेटा अभिक चक्रवर्ती है।इसी दिन जेस्सोर जिले में एक अन्य हिंदू कारोबारी 38 वर्षीय राणा प्रताप बैरागी की सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जो एक समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक भी थे।

आप जानते हैं कि इन दिनों बांग्लादेश में कट्टरपंथी उन्मादी हिन्दुओं के खिलाफ खून खराबा कर रहे हैं।बंगलादेश में जून, 2024 में शेख हसीना की सरकार के विरुद्ध आरक्षण और नौकरियों आदि में भेदभाव जैसे मुद्दों को लेकर छात्रों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के 3 महीनों बाद अंततः 5 अगस्त, 2024 को शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ी और तब से उन्होंने भारत में ही शरण ले रखी है। 'शेख हसीना' के भारत आने के बाद सेना ने जब 'मोहम्मद यूनुस' को देश की सत्ता सौंप दी तो उम्मीद थी कि शायद वह उदारवादी रवैया अपना कर देश में व्याप्त असंतोष दूर करने और वातावरण सामान्य बनाने में सहायता करेंगे।

आशा के विपरीत 'मो. यूनुस' ने देश की पाठ्य पुस्तकों से बंगलादेश के मुक्ति संग्राम और बंग बंधु शेख मजीबुर्रहमान से संबंधित अध्याय निकाल देने का आदेश जारी करके देश के मुक्ति संग्राम का इतिहास मिटाने की कोशिशें शुरू कर दीं और सैंकड़ों आतंकवादियों को जमानत देकर या उनके विरुद्ध आरोप वापस लेकर उन्हें जेलों से बाहर कर दिया है।

सेना और कट्टरपंथियों के दबाव में आकर यूनुस प्रशासन ने देश में 12 फरवरी, 2026 को चुनाव करवाने की घोषणा की है। इसके साथ ही यूनुस ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाकर उसे क्रियात्मक रूप से चुनावों में भाग लेने से रोक दिया है।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के अगले ही दिन कट्टरपंथी संगठन 'इन्कलाब मंच' के प्रवक्ता और छात्र नेता 'शरीफ उस्मान हादी' ने 'ढाका-8' सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी परंतु इसके अगले ही दिन सरेआम एक मोटरसाइकिल सवार ने उसकी हत्या कर दी।

दरअसल चुनावों के लिए तय तारीख की घोषणश के साथ ही बंगलादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ गए तथा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दो दिसंबर, 2025 से पिछले लगभग 35 दिनों में बांग्लादेश में कम से कम एक दर्जन हिंदुओं की हत्या की गई है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद द्वारा आज जारी एक बयान के अनुसार, अकेले दिसंबर में सांप्रदायिक हिंसा की कम से कम 51 घटनाएं दर्ज की गईं।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, 19 दिसंबर को शरत चक्रवर्ती ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर देश में हिंसा पर चिंता जताई थी, जिसमें उन्होंने अपनी जन्मभूमि को "मौत की घाटी" बताया था। एक चश्मदीद और रिश्तेदार प्रदीप चंद्र बर्मन ने इस हमले को सोची-समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा, "पहले से दुश्मनी थी.. उन्होंने (हमलावरों ने) उनका मोबाइल फोन या मोटरसाइकिल नहीं छीनी।"

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दो दिसंबर, 2025 : 42 वर्षीय सोने के हिंदू व्यापारी प्रांतोष कर्मकार की रात के समय बांग्लादेश के नरसिंगदी जिले के रायपुरा उपजिला में गोली मारकर हत्या कर दी गई।दो दिसंबर, 2025 : 35 वर्षीय हिंदू मछली व्यापारी उत्पल सरकार की सुबह के समय फरीदपुर जिले के साल्था उपजिला में बेरहमी से हत्या कर दी गई।सात दिसंबर, 2025 : 1971 के मुक्ति संग्राम के मुक्तिजोद्धा 75 वर्षीय जोगेश चंद्र राय और उनकी पत्नी सुबोर्ना राय सात दिसंबर की रंगपुर में गला रेतकर हत्या।12 दिसंबर, 2025 : 18 वर्षीय हिंदू ऑटो रिक्शा ड्राइवर शांतो चंद्र दास कुमिला जिले में मृत पाए गए। उनका गला रेतकर शव मक्के के खेत में फेंक दिया गया था।18 दिसंबर, 2025 : मैमनसिंह के भलुका में 27 वर्षीय हिंदू गारमेंट वर्कर दीपू चंद्र दास को इस्लामी भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला।24 दिसंबर, 2025 : राजबाड़ी जिले के 30 वर्षीय हिंदू अमृत मंडल को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे।29 दिसंबर, 2025 : बांग्लादेश के अर्धसैनिक सहायक बल अंसार वाहिनी के हिंदू सदस्य बजेंद्र बिस्वास को मैमनसिंह जिले में फैक्ट्री में साथी नोमान मियां ने गोली मारी।3 जनवरी, 2026 : शरियतपुर जिले के हिंदू व्यवसायी खोकन चंद्र दास को घर लौटते समय हमलावरों ने रोककर चाकू मारा, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 3 जनवरी, 2026 को बंगलादेश के 'झिनाइदह' में हिंदू विरोधी तत्वों ने एक विधवा हिंदू महिला से सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसे पेड़ से बांध कर बुरी तरह पीटा और उसके बाल भी काट दिए।5 जनवरी, 2026 : एक अखबार के 38 वर्षीय कार्यवाहक संपादक और बर्फ फैक्ट्री के मालिक राणा प्रताप बैरागी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और अब 5 जनवरी की रात सोमवार को देर रात एक हिंदू दुकानदार मोनी चक्रवर्ती की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जो पिछले 24घंटों में इस तरह की दूसरी घटना थी । कोई गारंटी नहीं है कि यह अमानवीयता दरिंदगी और बर्बरता का सिलसिला यहीं थमेगा।

आपको बता दें कि ऐसी घटनाओं पर बंगलादेश की अंतरिम सरकार की चुप्पी उसकी नीयत में खोट का संकेत देती है जिस पर विश्व भर में चिंता व्यक्त की जा रही है। बंगलादेश में 'जमात-ए-इस्लामी' जैसी कट्टरवादी ताकतों तथा पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ने से वहां के लोगों में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ गई हैं और सुरक्षा मामलों में सहयोग भी प्रभावित हुआ है। इस समय राजनीतिक अस्थिरता झेल रहा बंगलादेश कट्टरपंथियों के दबाव में आकर आज आक्रामकता अराजकता और कानून व्यवस्था के सबसे बुरे दौर में पहुंच रहा है जहां से लौटना और कानून व्यवस्था अराजकता पर नियंत्रण पाना अस्थिर सरकार के बूते से बाहर की बात होगी । आखिर भारत सरकार कब तक बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ की जा रही बर्बरता को नजरअंदाज कर सकती है?

एक जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और देश विरोधी गैंग सक्रिय?

मृत्युंजय दीक्षित

माननीय सुप्रीमकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में फरवरी 2020 में उत्तर- पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मुख्य आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। इसी केस में उमर और शरजील के 5 साथियों को 12 कड़ी शर्तो के साथ जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर और शरजील इमाम पर कड़ी टिप्पणियां करी हैं । अब ये दोनों अभियुक्त आने वाले एक साल में जमानत के लिए अपील भी नहीं कर पाएंगे। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगे अत्यंत वीभत्स दंगो में से एक थे। इस दंगे में मारे गए 53 निर्दोष लोगों में एक युवा आईबी अधिकारी अंकित शर्मा, पौढ़ी गढ़वाल से पांच महीने पहले आया गरीब माता का बेटा दिलबर नेगी और दो पुलिस कर्मी भी शामिल थे। ऐसे कुख्यात दंगों के अपराधियों को जमानत न मिलने पर सर्व साधारण में संतोष का भाव है किन्तु कुछ लोग इस पर भी तुष्टीकरण की रोटियां सेंकते हुए उमर खालिद और शरजील इमाम के लिए न केवल आंसू बहा रहे हैं वरन अनर्गल प्रलाप भी कर रहे हैं । शरजील इमाम केवल दिल्ली दंगों का ही अपराधी नहीं है वरन चिकन नेक तोड़कर पूर्वोत्तर भारत को देश से अलग करने कि बात करने वाला देशद्रोही है । शरजील इमाम भारत को खंड -खंड मे विभाजित देखना चाहता हैं। भारत के जो विपक्षी दलो ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत ण मिलने पर उसको सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं क्या वे इन विचारों से सहमत हैं?

दरअसल उमर व शरजील के साथ खड़े लोग अपनी कुंठा और हताशा को ही जगजाहिर कर रहे हैं। इस कुंठित टोली मे कोई जमानत न मिलने को कायरता पूर्ण कार्रवाई कह रहा है तो कोई इसे बेतुका बता रहा है जबकि कोई इसे अत्याचार बता रहा है । एक ने तो सारी लज्जा त्यागते हुए इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बता दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि 5 साल से अधिक बिना किसी दोष साबित हुए जेल में रखना बर्बरता बता दिया। यह बात भारतीय जनमानस के समझने योग्य है कि इन सेक्युलर नेताओं को सुप्रीम कोर्ट का फैसला बर्बर लग रहा है। अमेरिकी अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि जो अदालतों के अधिकार व उनके फैसलों को नकारता है वह राष्ट्र की नींव को नकारता है । इस तुष्टीकरण गैंग से पूछा जाना चाहिए कि आज देश में 4 लाख 34 हजार 302 विचाराधीन कैदी हैं जो सजा पाए बिना जेल में बंद हैं। करीब 26 हजार ऐसे कैदी हैं जो 3 से 5 साल तक जेल में बंद हैं और करीब साढ़े 11 हजार ऐसे कैदी हैं जो 5 वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद हैं । यह आंकड़े केवल 2020 तक के ही हैं।

विचार

आर्थिक मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ता भारत

डॉ. ओपी त्रिपाठी, चिकित्सक एवं लेखक

भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती की राह पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। यदि 1990 के दशक में कोई कहता कि भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ सकती है, तो कोई भी उद्योगपति या अर्थशास्त्री इसे स्वीकार नहीं करता। तब जापान विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और भारत बहुत पीछे था। भारत ने अर्थव्यवस्था को खोलने और आर्थिक उदारीकरण की शुरूआत ही की थी, लेकिन आज यथार्थ सामने है। आज भारत 4.187 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसने जापान को पीछे कर दिया है।

भारत सबसे तेज गति वाली अर्थव्यवस्था है और वह दिन दूर नहीं है, जब भारत में कामगार आबादी 1 अरब होगी। फिलहाल भारत की कुल आबादी 1.47 अरब को पार कर चुकी है। राजनेता अपने आंकड़े सुधार लें। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और कई विख्यात रेटिंग एजेंसियां 2025-26 (31 मार्च, 2026 तक) वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर औसतन 7 फीसदी आंक रही हैं। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन इससे भी अधिक विकास दर को लेकर आशान्वित हैं। यकीनन भारत बदल रहा है और आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। जर्मनी 4.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ तीसरे स्थान पर है। यकीनन भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर है। ऐसी अनुकूल स्थिति के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने शीर्ष नौकरशाहों को यह सलाह क्यों दी है कि विनियमन प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएं। प्रधानमंत्री देश की बढ़ती आर्थिक ताकत के रास्ते में किसी भी नियम, कानून और प्रक्रिया को रोड़ा बनने के पक्षधर नहीं हैं। साफ है कि प्रधानमंत्री सुधारों को गति देना चाहते हैं। फालतू के नियम, कानून, प्रतिबंध और प्रक्रियाओं को समाप्त करना चाहते हैं, ताकि जिंदगी और व्यापार करना आसान हो सके। इसी बिंदु पर भारत जापान से बहुत अलग है। 2004 को याद करें, जब एक अनुबंध या ठेका प्राप्त करने में औसतन 425 दिन लगते थे। करीब 40 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। दिवालियापन के समाधान की प्रक्रिया आराम से 10 साल तक चलती थी। नीति आयोग ने 2017 की अपनी रपट में स्वीकार किया था कि भारत में एक दुकान स्थापित करने में औसतन 118 दिन लगते थे। असम में यह अवधि 248 दिन तक फैल जाती थी। बेशक आज स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फालतू के सैकड़ों कानूनों को खत्म किया है, लेकिन प्रक्रियाएं आज भी व्यापार, उद्योग के पहिये को अवरुद्ध कर रही हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री को विनियमन प्रकोष्ठ स्थापित करने की बात कहनी पड़ी है। यदि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है, तो ऐसी स्थितियां बनानी पड़ेगी, जिनमें कायदे-कानून और फालतू की प्रक्रियाएं शासन न करती हों, बल्कि नियमन को सहज-सुगम बनाती हों। बेशक उससे भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। अब भारत ऐसा देश है, जिसमें 2025 में 1.95 लाख करोड़ रुपए के आईपीओ आए और डीमैट खातों की संख्या 21 करोड़ के पार चली गई। अभी तक 1350 स्टार्टअप में 25,320 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। आज भारत 159 प्रकार के गोला-बारूद, गोलियां, रॉकेट आदि का उत्पादन देश में ही कर रहा है। रक्षा-क्षेत्र करीब 91 फीसदी आत्मनिर्भर हो चुका है। मेक इन इंडिया उत्पादों में ब्रह्मोस और पिनाका मिसाइलों की मांग बढ़ रही है। 2029 तक भारत ने 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा-निर्यात का लक्ष्य तय किया है। आधा तो हम हासिल कर चुके हैं।

बहरहाल संसद में बजट पेश करते हुए राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य तय किया गया था, वह नियंत्रण में है। मुद्रास्फीति 0.7 फीसदी तक गिर गई है। चालू खाते का घाटा दोगुना हो सकता है, लेकिन यह जीडीपी के 1.2 फीसदी तक ही रहेगा, जो एक सहज स्थिति है। यह हमारी आर्थिक और बाजारी ताकत है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी विख्यात बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में 67.5 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणाएं की हैं। इस निवेश का खास फोकस कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), आधारभूत ढांचे पर है। बुधवार को जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमानों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में देश की वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 7.4 फीसदी रहने का अनुमान है।

एक्शन इंडिया दैनिक

भगवान शंकर जी के ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

आरएनआईः DELHIN / 2006 / 19302

एक्शन इंडिया मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए संपादक, मुद्रक, प्रकाशक एवं रवि भारद्वाज द्वारा एक्शन बालाजी हाउस, 244, ब्लॉक- बी, लेन- 3, राकेश भारद्वाज चौक के नजदीक, दिल्ली - 110033 से प्रकाशित एवं मारुतिनंदन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, शक्ति कॉम्प्लेक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110042 से मुद्रित।

संस्थापक : श्रद्धेय राकेश भारद्वाज जी

समूह संपादक : रवि भारद्वाज (9999889104)

मेट्रो संपादक : दीपचंद्र कांडपाल (8447314925)

'एक्शन इंडिया' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। संपादक केवल पीआरबी एक्ट के तहत ही उत्तरदायी। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली ही होगा।

वैधानिक सूचना

पाठकों को सलाह है कि एक्शन इंडिया, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के आधार पर कोई निर्णय लेने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित उक्त उत्पाद या सेवा के बारे में आवश्यक जांच-पड़ताल कर लें। समाचार पत्र प्रबंधक किसी भी विज्ञापन में गुणवत्ता, सेवा आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है। अतः समाचार पत्र उक्त विज्ञापनों के बारे में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

व्यंग्य

मोदी की गारंटी, मोहन सरकार की तैयारी

पवन वर्मा

केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ह्यविकसित भारत ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम, 2025 जिसे आम भाषा में ह्यजी राम जी कहा जा रहा है, अब मध्यप्रदेश की धरती पर केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं रह गया है। यह प्रदेश में शासन की मंशा, संगठन की सक्रियता और प्रशासनिक प्रतिबद्धता की कसौटी बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर लाए गए इस अधिनियम को मध्यप्रदेश में जमीन पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार पूरी तरह कमर कस चुकी है।

यह संदेश साफ है कि 125 दिन की मजदूरी गारंटी केवल घोषणा बनकर नहीं रहेगी। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री इसे अधिकार के रूप में लागू कराने के लिए सरकार और संगठन दोनों मोर्चों पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि यह कानून मध्यप्रदेश में सिर्फ रोजगार योजना नहीं, बल्कि शासन की प्राथमिकता बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से यह कहते रहे हैं कि गांव मजबूत होंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। उसी सोच से जन्मा यह अधिनियम अब राज्यों के माध्यम से साकार होना है। मध्यप्रदेश में मोहन यादव सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए संकेत दे दिए हैं कि कानून का पालन गांव-गांव में कराया जाएगा।

सरकार के स्तर पर विभागीय निर्देश, अधिकारियों की जवाबदेही और समयबद्ध कार्ययोजना पर काम शुरू हो चुका है। इससे लग रहा है कि सरकार इस अधिनियम को बोझ नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देख रही है। एक ऐसा अवसर, जिससे ग्रामीण मजदूरों को स्थायित्व में बदला जा सके।

इस अधिनियम को लागू कराने में केवल प्रशासन ही नहीं, बल्कि सरकार के मंत्री और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी पूरी ताकत से जुटने की तैयारी में है। मंत्रियों को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में निगरानी और संवाद की जिम्मेदारी दी जा रही है। संगठन स्तर पर मंडल से लेकर जिला इकाईयों तक कार्यकताओं को योजना की जानकारी देने और लाभार्थियों तक पहुंच बनाने का काम सौंपा जाएगा। यह केवल सरकारी योजना का प्रचार नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि कहीं भी कानून के पालन में ढिलाई न हो।

पीला अहंकार

डॉ. सुरेश

उस वातानुकूलित दफ्तर की खिड़की से बाहर देखें, तो पूरा शहर एक पीले कोहरे में लिपटा दिखाई देता था, पर भीतर साहब के चेहरे पर गजब का 'पिंक' ग्लो था। साहब का कमरा इतना ठंडा था कि वहाँ संवेदनाएं जम चुकी थीं। उनके सामने मेज पर एक पीली फाइल रखी थी–वही 'गोल्डन' फाइल, जिसमें शहर की प्यास और मौतों का हिसाब-किताब 'प्रॉफिट एंड लॉस' के कॉलम में कैद था। साहब ने अपनी मोंट ब्लांक कलम घुमाई और सामने खड़े मातहत से पूछा, "यह जो मोहल्ले में कल तीन 'यूनिट्स' कम हुई हैं, इनका कारण क्या लिखा?" मातहत ने अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा और झुकाया और विनीत स्वर में बोला, "साहब, तकनीकी रूप से वे 'मर' चुके हैं, पर हमने फाइल में लिखा है कि वे 'निर्वाण' को प्राप्त हुए। कारण–अत्यधिक हाइड्रेशन। उन्होंने पानी पीया और उनके फेफड़ों ने विकास की उस भारी मात्रा को झेलने से इनकार कर दिया।" साहब मुस्कराए। उनकी मुस्कराहट में वैसी ही चमक थी जैसी उस पीले पानी की ऊपरी सतह पर तैरते हुए केमिकल की होती है। वे बोले, "गुड! देखो, डेटा को कभी रोना नहीं चाहिए। डेटा को हमेशा मुस्कराना चाहिए। अगर दस लोग पीला पानी पीकर नीले पड़ गए हैं, तो इसे 'कलर ट्रांज़िशन' की उपलब्धि बताओ। कहो कि हमने शहर को बहुरंगी बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है।" सस्पेंस तो उस अलमारी में था, जो साहब के ठीक पीछे रखी थी। उसमें उन पाइपों के सैंपल थे, जो कागजों पर तो सोने के थे, पर जमीन के नीचे वे पीतल से भी गए-गुजरे निकले। साहब जानते थे कि पाइप में छेद नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम ही एक बड़ा 'छेद' है, जिससे पैसा रिसकर सीधे उनके स्विस बैंक के खातों में जा रहा है। तभी फोन बजा। दूसरी तरफ से कोई बड़ा 'आका' बोल रहा था। साहब की आवाज में अचानक चाशनी घुल गई, "जी मंत्री जी... बिल्कुल! पानी का रंग पीला इसलिए रखा है ताकि वह 'स्वच्छ भारत' के विजन में 'गोल्डन इंदौर' का अहसास दिलाए। जी, जो लोग अस्पताल में हैं, उन्हें हम 'स्मार्ट सिटी' के पहले प्रयोगकर्ता मान रहे हैं।

अपनी कॉलोनी में ही डॉक्टर परामर्श, जांच, दवाइयां, टीकाकरण सब मुफ्त। दिल्लीवासियों से जानें- कैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर ने स्वास्थ्य सेवाओं को आसान और भरोसेमंद बनाया है।

-रेखा गुप्ता

आज पंचकूला में आयोजित ज्ञानसेतु MoU एक्सचेंज कार्यक्रम में सहभागिता की। आज संपन्न हुए ये MoU, 'विकसित भारत' में 'विकसित हरियाणा' के योगदान की एक मजबूत और दूरदर्शी नींव स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

-नायब सिंह सैनी

संपादकीय

इंदौर त्रासदी उत्तराखंड के लिए सबक

मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने देशभर को झकझोर दिया। यह केवल एक शहर की त्रासदी नहीं, बल्कि उस बुनियादी ढांचे की विफलता का संकेत है, जिस पर शहरी जीवन की सबसे मूल आवश्यकता, पेयजल टिकी होती है। दुर्भाग्य से, उत्तराखंड के शहर भी इस खतरे से अछूते नहीं हैं । पहाड़ों की स्वच्छता और प्राकृतिक जलस्रोतों की छवि के पीछे छिपी सच्चाई यह है कि राज्य के अनेक शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। उत्तराखंड जल संस्थान के अधीन लगभग 90,044 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइनों में से करीब 30 प्रतिशत लाइनें 30 से 40 वर्ष पुरानी हैं । इन जर्जर लाइनों के साथ-साथ कई स्थानों पर सीवेज लाइनें भी पुरानी और क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं। नतीजा यह कि रिसाव, क्रॉस-कंटैमिनेशन और गंदे पानी के पेयजल में मिलने की आशंका लगातार बनी रहती है। विशेषज्ञों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति लाइनों में लीकेज की समस्या आम हो चुकी है, लेकिन इसका स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। आंकड़े इस संकट की गंभीरता को स्पष्ट करते हैं। बीते दो महीनों में अकेले देहरादून में दूषित पानी की 900 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि पूरे प्रदेश में यह संख्या 1500 के पार पहुंच चुकी है। ये केवल दर्ज शिकायतें हैं; वास्तविक समस्या इससे कहीं व्यापक हो सकती है, क्योंकि हर नागरिक शिकायत दर्ज नहीं कराता। हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, पौड़ी, टिहरी और चमोली जैसे जिलों में भी समय-समय पर पानी की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। समस्या केवल पाइपलाइन की उम्र तक सीमित नहीं है । शहरी विस्तार, अनियोजित निर्माण, सड़क चौड़ीकरण और ड्रेनेज कार्यों के दौरान अक्सर पेयजल और सीवर लाइनों को नुकसान पहुंचता है। कई बार बिना समुचित मरम्मत के आपूर्ति बहाल कर दी जाती है, जिससे गंदगी और बैक्टीरिया सीधे नलों तक पहुंच जाते हैं । इसके अतिरिक्त, सीवेज शोधन क्षमता भी अपर्याप्त है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य में सीवेज शोधन की कुल क्षमता सीमित है और कई शोधन संयंत्र पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में गंदा पानी नदियों और भूमिगत स्रोतों में मिलकर पेयजल स्रोतों को भी प्रभावित करता है। यह स्थिति शासन और प्रशासन दोनों के लिए चेतावनी है । इंदौर की घटना ने दिखा दिया कि लापरवाही की कीमत कितनी भारी हो सकती है। उत्तराखंड में अभी समय है कि इस खतरे को गंभीरता से लिया जाए और ठोस कदम उठाए जाएं। केवल अस्थायी मरम्मत और शिकायत निस्तारण से काम नहीं चलेगा; जरूरत है प्रणालीगत सुधार की। सरकार ने हाल ही में अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत पेयजल लाइनों की अनिवार्य डिजिटल मैपिंग का निर्णय लिया है। यह एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम है। डिजिटल मैपिंग से यह स्पष्ट होगा कि कहां कौन सी लाइन है, उसकी उम्र क्या है, वह किस सामग्री की बनी है और किन स्थानों पर सीवेज लाइनों के साथ उसका टकराव हो सकता है। इससे मरम्मत, प्रतिस्थापन और आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। लेकिन यह पहल तभी सफल होगी, जब इसे कागजों तक सीमित न रखकर जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इसके साथ ही सरकार को कुछ ठोस उपायों पर तत्काल ध्यान देना होगा। पहला, जर्जर और अत्यधिक पुरानी पेयजल लाइनों को चरणबद्ध तरीके से बदलने के लिए स्पष्ट समयबद्ध योजना बनाई जाए। दूसरा, सीवेज और पेयजल नेटवर्क के बीच न्यूनतम सुरक्षित दूरी और मानकों का सख्ती से पालन कराया जाए। तीसरा, शहरी क्षेत्रों में नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण को अनिवार्य किया जाए और उसके परिणाम सार्वजनिक किए जाएं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। चौथा, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया जाए, जिससे नागरिकों की शिकायतों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हो सके। इसके अलावा, स्थानीय निकायों और जल संस्थान के बीच बेहतर समन्वय भी जरूरी है। उत्तराखंड की पहचान स्वच्छ नदियों, हिमालयी जलस्रोतों और प्राकृतिक संपदा से जुड़ी रही है। यदि शहरी क्षेत्रों में ही लोगों को सुरक्षित पेयजल न मिल पाए, तो यह राज्य के विकास मॉडल पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इंदौर की त्रासदी को चेतावनी मानते हुए अब उत्तराखण्ड को निर्णायक कदम उठाने होंगे। सुरक्षित पेयजल कोई सुविधा नहीं, बल्कि नागरिकों का मूल अधिकार है और इस अधिकार की रक्षा सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी।

बांग्लादेश में बढ़ती लक्षित हिंसा का संकट

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

हाल - फ़िलहाल बांग्लादेश में जिस प्रकार की लक्षित हिंसा देखने को मिल रही है, वह सामान्य कानून-व्यवस्था की विफलता से कहीं अधिक गहरी और चिंताजनक समस्या की ओर संकेत करती है। जो स्थिति प्रारंभ में आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से उपजे असंतोष के रूप में सामने आई थी, वह अब धीरे-धीरे पहचान-आधारित घृणा, संस्थागत निष्क्रियता और सामाजिक विश्वास के क्षरण में बदलती दिखाई दे रही है। देश के विभिन्न जिलों से सामने आ रही हत्याओं, हमलों और धमकियों की घटनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि हिंसा अब अराजक या आकस्मिक नहीं रही, बल्कि वह चयनित, सुनियोजित और विशेष समुदायों व व्यक्तियों को निशाना बनाकर की जा रही है।

यह प्रवृत्ति बांग्लादेशी समाज की दिशा और राज्य की उस क्षमता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है, जिसके तहत वह अपने सभी नागरिकों को समानता और सुरक्षा देने के संवैधानिक वादे को निभाने के लिए बाध्य है।

इस हिंसा की पृष्ठभूमि उस लंबे दौर के असंतोष से जुड़ी है, जिसकी शुरुआत राजनीतिक सुधारों और आर्थिक जवाबदेही की मांगों के साथ हुई थी। बीते एक वर्ष में शासन की विफलताओं, बढ़ती महंगाई, रोजगार के अवसरों की कमी और भ्रष्टाचार के आरोपों के विरुद्ध हुए आंदोलनों ने राज्य की नींव को हिला दिया। समय के साथ ये आंदोलन अपना केंद्रीकृत नेतृत्व और स्पष्ट दिशा खोते चले गए। इसी शून्य का लाभ उठाकर चरमपंथी प्रवृत्तियों, आपराधिक गिरोहों और अवसरवादी तत्वों को खुला मैदान मिल गया। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह अराजकता अब उन लोगों पर हमलों के रूप में सामने आ रही है, जिन्हें उनके कर्मों के कारण नहीं, बल्कि उनकी पहचान के कारण निशाना बनाया जा रहा है, विशेषकर धार्मिक अल्पसंख्यकों, छोटे व्यापारियों और उन व्यक्तियों को, जिन्हें सामाजिक या राजनीतिक रूप से कमजोर समझा जाता है।

हालिया घटनाएं इस भयावह वास्तविकता को और स्पष्ट करती हैं। कम समय के भीतर सामने आए कई मामलों में यह पाया गया कि

जब पहचान ही अपराध बन जाए

पीड़ितों की हत्या उनकी धार्मिक या सामुदायिक पहचान की पुष्टि के बाद की गई। छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और यहां तक कि सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों पर ऐसे हमले हुए, जिनसे यह प्रतीत होता है कि ये कृत्य अचानक उपजे क्रोध का परिणाम नहीं, बल्कि पहले से सोचे-समझे और योजनाबद्ध अपराध थे। एक घटना में एक व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि कुछ ही समय पहले पास के जिले में एक अन्य व्यवसायी को इसी तरह गोली मार दी गई थी। एक अन्य मामले में एक सांस्कृतिक कार्यकर्ता को पहले सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई और इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर प्रसारित किया गया। यह न केवल क्रूरता को दर्शाता है, बल्कि समाज में भय फैलाने और हिंसा को सामान्य बनाने की सोची-समझी कोशिश भी प्रतीत होती है।

ये घटनाएं अलग-थलग नहीं हैं, बल्कि उस व्यापक पैटर्न का हिस्सा हैं, जो तब उभरता है जब राज्य की सत्ता कमजोर पड़ जाती है और जवाबदेही की व्यवस्थाएं ढहने लगती हैं। इतिहास गवाह है कि राजनीतिक संक्रमण या अस्थिरता के दौर में अल्पसंख्यक समुदाय अक्सर आसान निशाना बन जाते हैं। बांग्लादेश में भी यह प्रवृत्ति पहले देखी जा चुकी है, लेकिन वर्तमान दौर इसलिए अधिक खतरनाक है क्योंकि इसमें हिंसा की तीव्रता और आवृत्ति दोनों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। विशेष रूप से हिंदू नागरिकों को बार-बार निशाना बनाए जाने से व्यापक भय का वातावरण बन गया है और लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या केवल नागरिक होना ही सुरक्षा की गारंटी देने के लिए पर्याप्त है।

इस स्थिति को और गंभीर बनाने वाला एक पहलू अंतरिम प्रशासन की स्पष्ट निष्क्रियता या अक्षमता है। यद्यपि सरकारी बयान इन घटनाओं की निंदा करते हैं और जांच का आश्वासन देते हैं, लेकिन धरातल पर ठोस परिणाम बहुत कम दिखाई देते हैं। गिरफ्तारियां यदि होती भी हैं तो प्रायः देर से, और दोषसिद्धि तो और भी दुर्लभ है। यह विफलता केवल प्रशासनिक नहीं है; यह अपराधियों को यह संदेश देती है कि वे बिना किसी भय के हिंसा कर सकते हैं। जब न्याय में देरी होती है या वह मिलता ही नहीं, तब हिंसा एक अपवाद न रहकर सत्ता और नियंत्रण का साधन बन जाती है, जिसके माध्यम से असहमति और भिन्नता को दबाया जाता है।

इस हिंसा की जड़ें जटिल और आपस में जुड़ी हुई हैं। इसमें संदेह नहीं कि आर्थिक दबाव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बढ़ती कीमतें, सिकुड़ते रोजगार और आजीविका की अनिश्चितता ने समाज में व्यापक असंतोष को जन्म दिया है। किंतु केवल आर्थिक संकट यह नहीं समझा सकता कि हिंसा विशेष समुदायों की ओर ही क्यों निर्देशित हो रही है। पहचान की राजनीति, दुष्प्रचार और चरमपंथी विचारधाराओं ने सामाजिक विभाजनों को और गहरा कर दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें तेजी से फैलती हैं, जिनमें अल्पसंख्यकों को बाहरी, विशेषाधिकार प्राप्त या तथाकथित 'सच्ची राष्ट्रीय पहचान' में बाधा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे वातावरण में क्रोध को दिशा मिल जाती है और वह कमजोर लक्ष्यों की ओर मुड़ जाता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण कारण संस्थागत संतुलन और नियंत्रण की कमजोर होती व्यवस्था है। जब पुलिस बल अत्यधिक दबाव में होते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करते हैं या निर्णायक कार्रवाई से हिचकते हैं, तब अपराधी तत्वों का मनोबल बढ़ता है। जब न्यायपालिका धीमी या आम नागरिकों के लिए अप्राप्य प्रतीत होती है, तब पीड़ितों का कानूनी उपायों से विश्वास उठने लगता है। इस प्रकार एक दुष्चक्र बनता है- भय चुप्पी को जन्म देता है, चुप्पी आक्रामकों को प्रोत्साहित करती है और आक्रामकता कानून के शासन को और कमजोर करती है।

इस स्थिति के परिणाम केवल तात्कालिक मानवीय पीड़ा तक सीमित नहीं हैं। लक्षित हिंसा एक बहुलतावादी राष्ट्र की मूल अवधारणा को ही कमजोर कर देती है। बांग्लादेश की पहचान ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक विविधता, भाषाई गर्व और एक धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे से निर्मित रही है। जब नागरिकों पर उनकी धार्मिक या सामाजिक पहचान के कारण हमला होता है, तो यह उस बुनियादी आत्मा पर प्रहार है। इसके अतिरिक्त, ऐसी हिंसा बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय छवि को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे पड़ोसी देशों, निवेशकों और मानवाधिकार संगठनों में चिंता बढ़ती है।

वर्षों से न्याय के इंतजार में पीढ़ियां-दर-पीढ़ियां

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के गत वर्ष के आंकड़ों की ही मानें तो देश के उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में ही 65 लाख से अधिक मुकदमे निर्णय के इंतजार में दशकों से प्रतीक्षारत हैं। 3 हजार से अधिक मामले तो 50 साल भी अधिक समय से लंबित हैं। 10 साल या इससे अधिक समय से निर्णय का इंतजार कर रहे मुकदमों की बात करें तो यह संख्या इतनी अधिक है कि सोचने पर मजबूर कर देती है। देश के 25 उच्च न्यायालयों व राज्यों के जिला अदालतों में लबित मुकदमों की बात की जाए तो यह सामने आ रहा है कि 54 लाख 58 हजार 832 मुकदमे 10 से 20 साल की अवधि के हैं और निष्पादन का इंतजार कर रहे हैं। 20 से 30 साल और 30 से 40 साल की अवधि के निर्णय के इंतजार के मुकदमे भी लाखों में हैं।

अदालतों की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी नहीं की जा सकती क्योंकि नित नए सुधार और मुकदमों के अंबार से स्वयं अदालतों में बैठे माननीय न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत और सरकार चिंतित और गंभीर है। इसका हल खोजने के प्रयास जारी हैं। चिंता की बात यह है कि उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में 50 साल से अधिक समय से आज भी 3442 मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से 2329 मुकदमे उच्च न्यायालयों व 1113 मुकदमे जिला न्यायालयों में पेंडिंग हैं।

मुकदमों की संख्या को लेकर सवाल नहीं है क्योंकि यदि 50 साल से एक मुकदमा भी पेंडिंग है तो यह अपने आप में गंभीर है। सवाल 50 साल की अवधि का विश्लेषण करने का भी है। 50 साल की अवधि का मतलब कई मामलों में तो निश्चित रुप से अदालतों में हाजिरी देते-देते दो से तीन पीढ़ियां खप गई होंगी। दोनों ही अदालतों में 50 साल से अधिक अवधि के लंबित मुकदमों में सिविल प्रकरण ही अधिक है। निश्चित रुप में इनमें से अधिकांश मामले जमीन जायदाद को लेकर होंगे। हालांकि दोनों अदालतों के मिलाकर 459 मुकदमें आपराधिक श्रेणी के हैं और 50 साल से अधिक समय से निर्णय के इंतजार में है। अब आज से 50 साल पहले जिसने भी जैसा भी अपराध किया था या जिसने भी जैसा भी अपराधी के कारण मानसिक-शारीरिक संताप या

प्रताड़ना झेली थी उनमें से कई तो हो सकता है दुनिया में न हों या उनकी शारीरिक-मानसिक हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है।

सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर इस समस्या पर गंभीर चिंतन किया जाता रहा है। इसके समाधान खोजने के प्रयास भी किये जाते रहे हैं। अच्छी बात है कि अब सर्वोच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों के अधिकांश पद भरे रहने लगे हैं। समग्र प्रयासों से उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों के न्यायमूर्तियों के पद भी भरने के प्रति गंभीर प्रयास जारी हैं। पर तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि एक मोटे अनुमान के अनुसर उच्च न्यायालयों के करीब 1100 से अधिक स्वीकृत पदों में से 300-350 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। जहां तक जिला अदालतों का प्रश्न है, एक मोटे अनुमान के अनुसार करीब 4 से 5 हजार पद रिक्त हैं। इसमें दो राय नहीं कि इससे काम प्रभावित होता है। पर दस साल से अधिक के कुल मिलाकर 65 लाख से अधिक मुकदमों में निर्णय का इंतजार कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था पर प्रश्न तो उठाता ही है।

इसी तरह से निस्तारण में देरी के लिए किसी पर दोष जड़ने से भी कोई समाधान नहीं होने वाला है। यह कोई विवाद का विषय भी नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह का सिस्टम विकसित करना होगा जिससे पुराने मुकदमों को प्राथमिकता से निपटाया जा सके। सरकार ने कुछ माह पहले कानून में संशोधन कर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाये हैं। उससे निस्तारण की समय-सीमा तय होगी। पर कुछ इस तरह का रोस्टर सिस्टम या केवल और केवल पुराने मुकदमों के निस्तारण के लिए अलग से ही माननीय न्यायाधीशों की बेंच बना दी जाएं तो प्राथमिकता से वर्षों से न्याय की आस में चल रहे मुकदमों का निष्पादन हो सके। न्यायालयों व सरकार दोनों के पास मुकदमों की वर्षवार बकाया सूची उपलब्ध है।

यह तय हो जाए कि प्रति कार्य दिवस निश्चित संख्या में पुराने मुकदमों की भी सुनवाई होगी तो बैकलॉग निपटाना आसान हो जाएगा। इन मुकदमों से जुड़े वकीलों का भी यह दायित्व हो जाता है कि पक्ष-विपक्ष दोनों के वकील मुकदमे के निस्तारण में सहभागी बनें। इससे अदालतों में पुराने मुकदमों का बोझ कम होगा और लोगों को न्याय मिल सकेगा। अदालत और संबंधित व्यक्तियों दोनों को राहत मिल सकेगी।

कविता

उम्मीद का उगे सूरज

उम्मीद से सूरज उगे हैं,
उम्मीद से जीवन चले हैं,
उम्मीद से सपने जगे हैं,
उम्मीद से मंज़िल मिले हैं।
अंतस में रख विश्वास अगर,
उम्मीद से संकट टले हैं,
सदैव होंगी जीत उन्हीं की,
मेहनत से जो लोग पले हैं।
चिंता,फिकर तुम सब छोड़ दो,
जहां हार है,वही जीत है,
उगाना है हथेली पर रवि,
जीवन का अब यही गीत है।
संशय नहीं हो मन में तनिक,
बनकर निर्भय चलता ही चल,
जीतना तुम्हें दुनिया को गर,
बेफिक्र आगे बढ़ता ही चल।
जीवन में हो घोर निराशा,
उम्मीद का दामन थामना,
दूर होगी मन की उलझनें,
हृदय में भर यह शुभ कामना।

-नलिन खोईवाल

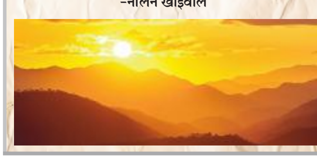

आपका मत

'जेन-जी' की सियासी भाषा को कैसे समझें

भारतीय गणराज्य की सबसे निर्णायक ताकत उसकी युवा आबादी में है। 18 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के करोड़ों युवा वोटर आज चुनावी नतीजों का सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली तथा सबसे परिवर्तनकारी फैक्टर बन चुके हैं। जेन-जी की यह नई, ऊर्जावान, जागरूक तथा महत्वाकांक्षी पीढ़ी पुरानी राजनीतिक भाषा, पुरानी शैली, पुरानी रणनीतियों तथा पुरानी सोच से पूरी तरह अलग, दूर और कहीं न कहीं असहमत है। इसलिए, इन युवा वोटरों को जीतना आसान नहीं है, लेकिन सही, आधुनिक, डेटा-आधारित तथा युवा-उन्मुख रणनीति अपनाकर ये सबसे वफादार, सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली तथा सबसे दीर्घकालिक वोट बैंक बन सकते हैं। ये युवा वोटर भावनाओं से कम और तर्क, आंकड़ों, व्यावहारिक समाधान तथा रीयल एक्शन से ज्यादा प्रभावित होते हैं। यदि आप इनकी आकांक्षाओं, इनकी चुनौतियों, इनकी दुनिया तथा इनकी सोच को गहराई से समझकर सही, एडवांस तथा इनोवेटिव रणनीति अपनाते हैं, तो ये न केवल चुनाव जीताएंगे, बल्कि आने वाले दशकों के लिए मजबूत, स्थायी, दीर्घकालिक तथा अटूट आधार बनाएंगे। मैं तो यह भी कहूंगा कि जेन-जी भारत का भविष्य हैं और जिसने इनको जीत लिया, उसने चुनाव नहीं, पूरा देश तथा आने वाली पीढ़ियां जीत लीं।

-डॉ अतुल मलिकराम

लोकसत्य

आप अपना मत व लेख हमें इस ई-मेल भेज सकते है।

loksatyaeditO1@gmail.com

वेनेजुएला के बहाने से 'भेड़िया न्याय' की वापसी की आहट

घनश्याम बादल

'अमेरिका फर्स्ट' के नारे के साथ सत्ता में लौटे डोनाल्ड ट्रंप लैटिन अमेरिकी देशों की सीमा एवं परिधि से बाहर भी यदि ऐसी कार्रवाई करने तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अमेरिकी मनमानी के एक नहीं कई उदाहरण हैं 1980 के दशक में अमेरिका ने इराक पर रासायनिक हथियार रखने का आरोप लगाकर भीषण हमला किया बाद में यह आरोप झूठे निकले तब संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि इराक युद्ध अवैध था और यह बात आज खुद पश्चिमी विश्लेषक मानते हैं। लेकिन अमेरिका ने अपनी मनमानी करते हुए इराक से सद्दाम हुसैन की सरकार का तख्ता ही नहीं पलटा अपितु उसे फांसी पर भी लटकवा दिया

दुनिया एक बार फिर उसी पुराने और ख़तरनाक सवाल के सामने खड़ी है कि क्या अंतरराष्ट्रीय कानून सिर्फ़ कमज़ोर देशों के लिए है? क्या अमेरिका को यह अधिकार है कि वह तय करे कि कौन वैध राष्ट्रपति है, कौन अपराधी, और किस देश में किसकी सत्ता रहेगी?

वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप और वहां के राष्ट्रपति को पकड़कर मुकदमे चलाना कोई अचानक घटित घटना नहीं अपितु यह उस नीति की अगली कड़ी है, जिसे अमेरिका दशकों से अलग-अलग नामों से लागू करता आया है । कभी "लोकतंत्र की रक्षा", कभी "ड्रग्स के खिलाफ युद्ध", और कभी "मानवाधिकार"। नाम बदलते रहे, इरादा वही रहा ताक़त के दम पर दूसरे देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने एवं वहां अपनी मनपसंद के शासक बैठाने राजनीति। अमेरिका यह कहकर अपने कदमों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है कि वेनेजुएला "नार्को-स्टेट" बन चुका था । सवाल यह है कि अगर किसी देश में अपराध है, तो क्या इसका फ़ैसला वाशिंगटन करेगा? और सज़ा भी वही देगा? और यदि ऐसा होता है तो फिर वहां की सरकार शासन एवं प्रशासन की क्या भूमिका रह जाएगी?

हो सकता है नई पीढ़ी या जैन जी को लगे कि वेनेजुएला जैसी घटना पहली बार घटित हुई है लेकिन ऐसा नहीं है अमेरिका पहले भी एक बार नहीं अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग जगह पर कई बार ऐसा कर चुका है थोड़े बहुत अंतर के साथ।

2 जनवरी की रात को दुनिया को हतप्रभ कर देने वाली राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण की घटना के साथ भी सब कुछ खत्म होता नहीं दिख रहा है बल्कि वेनेजुएला के बाद मेक्सिको और कोलंबिया को लेकर अमेरिकी चेतावनियाँ बताती हैं कि यह मामला एक देश तक सीमित रहने वाला नहीं है। ड्रग तस्करी और सीमा सुरक्षा की आड़ में सैन्य कार्रवाई

की भाषा दरअसल पुराने औपनिवेशिक दृष्टिकोण की वापसी है, जिसमें लैटिन अमेरिका को अमेरिका का प्रभाव-क्षेत्र माना जाता था। यह वही इलाक़ा है जिसने अमेरिकी हस्तक्षेपों की सबसे भारी कीमत चुकाई है, कभी तख़्तापलट,कभी गृहयुद्ध, और कभी आर्थिक तबाही की मार लैटिन अमेरिकी देशों ने बार-बार सही है। 'अमेरिका फर्स्ट' के नारे के साथ सत्ता में लौटे डोनाल्ड ट्रंप लैटिन अमेरिकी देशों की सीमा एवं परिधि से बाहर भी यदि ऐसी कार्रवाई करने तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

अमेरिकी मनमानी के एक नहीं कई उदाहरण हैं 1980 के दशक में अमेरिका ने इराक पर रासायनिक हथियार रखने का आरोप लगाकर भीषण हमला किया बाद में यह आरोप झूठे निकले तब संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि इराक युद्ध अवैध था और यह बात आज खुद पश्चिमी विश्लेषक मानते हैं। लेकिन अमेरिका ने अपनी मनमानी करते हुए इराक से सद्दाम हुसैन की सरकार का तख्ता ही नहीं पलटा अपितु उसे फांसी पर भी लटकवा दिया गौर कीजिए ख़ुद अमेरिका में फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है लेकिन एक देश के पूर्व राष्ट्रपति को अनेक आरोप लगाकर फांसी पर लटकवा दिया गया। दूसरा उदाहरण लीबिया का है जहां कभी कर्नल गद्दाफ़ी की तूती बोलती थी जब उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाने शुरू कर दी तब तत्कालीन अमरीकी शासन ने लीबिया में हस्तक्षेप कर पूरे देश को अराजकता में झोंक दिया। कर्नल गद्दाफ़ी को भी न केवल गिरफ्तार किया गया अपितु भारी अपमानित भी किया गया । लेकिन किसी ने अमेरिका से जवाबदेही नहीं मांगी। इससे पहले अफगानिस्तान के शासक को भी जीप से बांधकर घसीटने जैसा नृशंस दृश्य दुनिया ने देखा था लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया।

प्रतिबंध: बम से भी क्रूर हथियार अमेरिका अब सिर्फ़ मिसाइलों से नहीं लड़ता, वह प्रतिबंधों से देश घुटने टेकने पर मजबूर करता है। वेनेजुएला इसका सबसे भयावह उदाहरण है, जहां जनता दवाओं और भोजन के लिए तरस रही है। प्रतिबंध सरकारों को नहीं, आम लोगों को तोड़ते हैं। अस्पताल बंद होते हैं, महँगाई आसमान छूती है,और फिर उसी बदहाली को "शासन की विफलता" कहकर हस्तक्षेप का नया बहाना तैयार किया जाता है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान में दवाइयां की कीमतों में पिछले एक वर्ष में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

अवैध कब्जे और बेघर होता भारतः एक अंतहीन राष्ट्रीय संकट

ललित गर्ग

सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण की समस्या भारत में न तो नई है और न ही किसी एक क्षेत्र तक सीमित। यह एक ऐसी जटिल और बहुआयामी चुनौती है, जो शहरीकरण, पलायन, राजनीतिक स्वार्थ, प्रशासनिक लापरवाही और सामाजिक मजबूरियों के सम्मिलित परिणाम के रूप में सामने आती है। देश के लगभग हर राज्य, हर बड़े शहर और अनेक कस्बों में सरकारी जमीन पर मकान, दुकानें, झुग्गियां, गोदाम, यहां तक कि बड़े-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान और संस्थान खड़े मिल जाते हैं। वर्षों तक यह सब कुछ खुलेआम होता रहता है, लेकिन जिम्मेदार तंत्र या तो आंखें मूंदे रहता है या जानबूझकर चुप्पी साधे रहता है।

सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण की समस्या भारत में न तो नई है और न ही किसी एक क्षेत्र तक सीमित। यह एक ऐसी जटिल और बहुआयामी चुनौती है, जो शहरीकरण, पलायन, राजनीतिक स्वार्थ, प्रशासनिक लापरवाही और सामाजिक मजबूरियों के सम्मिलित परिणाम के रूप में सामने आती है। देश के लगभग हर राज्य, हर बड़े शहर और अनेक कस्बों में सरकारी जमीन पर मकान, दुकानें, झुग्गियां, गोदाम, यहां तक कि बड़े-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान और संस्थान खड़े मिल जाते हैं। वर्षों तक यह सब कुछ खुलेआम होता रहता है, लेकिन जिम्मेदार तंत्र या तो आंखें मूंदे रहता है या जानबूझकर चुप्पी साधे रहता है। जब अचानक विकास परियोजनाओं, सड़क चौड़ीकरण, रेलवे, मेट्रो, औद्योगिक गलियारों या स्मार्ट सिटी योजनाओं की जरूरत सामने आती है, तब सरकार की नींद खुलती है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होती है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा संकट उन लोगों पर टूटता है, जो वर्षों से वहां रह रहे होते हैं और जिनका जीवन, आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य उसी जमीन से जुड़ चुका होता है। हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क जैसे संगठनों के आंकड़े इस समस्या की भयावहता को उजागर करते हैं। वर्ष 2017 से 2023 के बीच साढ़े तीन लाख से अधिक मकानों पर बुलडोजर चलाए गए और करीब सोलह लाख लोग बेघर हुए। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आने वाले समय में लगभग 1.7 करोड़ लोग ऐसे दायरे में हैं, जिनके घर विकास परियोजनाओं या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के कारण टूट सकते हैं। इनमें से बड़ी संख्या उन लोगों की है, जिन्होंने अपनी जीवनभर की पूंजी लगाकर घर बनाए, बच्चों को स्कूल में डाला, आसपास रोजगार तलाशा और एक स्थायी जीवन की कल्पना की। जब ये घर टूटते हैं तो केवल दीवारें नहीं गिरतीं, बल्कि पूरे परिवार की सामाजिक और आर्थिक संरचना ढह जाती है।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को प्रायः एक आवश्यक प्रशासनिक कदम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसके मानवीय पक्ष को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बेघर होना केवल सिर से छत छिनने की समस्या नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की संभावनाओं पर सीधा प्रहार है। बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है, महिलाएं असुरक्षा और अस्थिरता के भय में जीने लगती हैं, बुजुर्ग इलाज और सहारे से वंचित हो जाते हैं और पुरुष वर्ग बेरोजगारी तथा मानसिक तनाव से जूझने लगता है। पुनर्वास योजनाएं कागजों पर तो आकर्षक लगती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में वे या तो अधूरी होती हैं या इतनी दूरस्थ जगहों पर लागू की जाती हैं कि वहां रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है। इस पूरी समस्या का एक कड़वा सच यह भी है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एक दिन या एक रात में नहीं हो जाता। यह एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें प्रशासनिक उदासीनता, स्थानीय स्तर पर मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण की बड़ी भूमिका होती है। जब गांवों से पलायन कर गरीब परिवार शहरों की ओर आते हैं, तो उन्हें सबसे पहले सस्ती या खाली जमीन की तलाश होती है। सरकारी जमीन इस दृष्टि से सबसे आसान निशाना बनती है। पहले अस्थायी झोपड़ियां खड़ी होती हैं, फिर धीरे-धीरे पक्के मकान, दुकानें और अन्य निर्माण होने लगते हैं। सरकारी एजेंसियां एवं जिम्मेदार तो तब ही हरकत में आते हैं जब या तो कोई हादसा होता है या फिर विकास कार्यों के दौर में इन्हें हटाने की जरूरत पड़ती है। महज सात साल में 16 लाख लोगों के बेघर होने का आंकड़ा छोटा नहीं है। इनमें भी 58 प्रतिशत से ज्यादा के बेघर होने की वजह अतिक्रमण ही है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों की मिलीभगत से अनदेखी होती है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। बिजली, पानी, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसी सुविधाएं भी किसी न किसी रास्ते से मिल जाती हैं, जिससे यह अतिक्रमण धीरे-धीरे ह्यवैधताह्न का भ्रम पैदा करने लगता है।

इस पूरी प्रक्रिया में भू-माफिया की भूमिका भी बेहद खतरनाक है। वे सरकारी जमीनों की पहचान कर गरीबों को वहां बसाते हैं, उनसे पैसे वसूलते हैं और बाद में राजनीतिक संरक्षण के जरिए उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। चुनाव आते ही ये बस्तियां वोट बैंक में बदल जाती हैं। इस राजनीतिक खेल में न तो कानून की प्रतिष्ठा बचती है और न ही आम नागरिकों का भविष्य सुरक्षित रहता है। अतिक्रमण हटाने के बाद होने वाले नुकसान को यदि समग्र रूप से देखा जाए तो यह केवल प्रभावित परिवारों का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे देश का नुकसान है। एक ओर लोग अपने सीमित संसाधनों से घर बनाते हैं, दूसरी ओर सरकार अतिक्रमण हटाने पर भारी खर्च करती है। यदि शुरूआत में ही सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, समय पर निगरानी हो और अवैध कब्जे को बढ़ने से रोका जाए, तो यह दोहरा नुकसान टाला जा सकता है। दुर्भाग्य से हमारे यहां किसी परियोजना की घोषणा और उसके क्रियान्वयन के बीच लंबा अंतराल रहता है, जिसका फायदा अतिक्रमणकारी उठाते हैं। वर्षों तक जमीन खाली पड़ी रहती है और देखते ही देखते वहां एक पूरी बस्ती खड़ी हो जाती है।

विकास के लिए कई बार राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए विध्वंस की कार्रवाई जरूरी हो जाती है। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए केवल बुलडोजर चलाना पर्याप्त नहीं है। जरूरत एक ऐसी दूरदर्शी नीति की है, जिसमें अतिक्रमण रोकने की व्यवस्था शुरूआत से ही सख्त और प्रभावी हो। सरकारी जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड, नियमित सर्वेक्षण, स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही और दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई इस दिशा में जरूरी कदम हो सकते हैं। साथ ही शहरी गरीबों के लिए सस्ती आवास योजनाओं को वास्तविक जरूरतों के अनुरूप और रोजगार के करीब लागू करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि वे मजबूरी में अवैध कब्जे की ओर न जाएं। राजनीतिक दलों को भी इस मुद्दे पर ईमानदार आत्ममंथन करना होगा। वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध अतिक्रमण को संरक्षण देना अंततः समाज और शासन दोनों के लिए घातक सिद्ध होता है। यदि कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से हो और अवैध कब्जे को किसी भी स्तर पर समर्थन न मिले, तो ऐसी स्थितियां स्वतः कम होंगी। सरकारी भूमि जनता की साझा संपत्ति है और इसका उपयोग योजनाबद्ध विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए होना चाहिए, न कि अव्यवस्था और अवैध कब्जों के लिए। अंततः सवाल यही है कि क्या हम समस्या के मूल कारणों पर गंभीरता से विचार करेंगे या हर बार बुलडोजर के बाद कुछ दिनों की संवेदना दिखाकर आगे बढ़ जाएंगे। यदि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की प्रवृत्ति को समय रहते नहीं रोका गया, तो आने वाले वर्षों में बेघर होने वालों की संख्या और बढ़ेगी, सामाजिक असंतोष गहराएगा और विकास का दावा खोखला साबित होगा। जरूरत इस बात की है कि सरकार, प्रशासन, राजनीतिक दल और समाज मिलकर इस जटिल समस्या का मानवीय, न्यायपूर्ण और दूरगामी समाधान तलाशें, ताकि विकास भी हो और किसी का जीवन उजड़ने से भी बच सके।

समुचित देश एवं विभिन्न प्रांतो में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके लोगों ने न केवल अपने मकान बने कुछ भी खड़े कर लिए हैं कुछ व्यापारिक संस्थान और कुछ संस्थाएं भी संचालित हो रही है जब सरकार की नींद खुलती है तो इन सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके बनाए गए मकान में रहने वाले लोगों को बेघर किया जाता है या उन्हें अन्यत्र बसाने की योजनाएं लागू की जाती है जिससे इन परिवारों और उनके सदस्यों की न केवल बेघर होने की समस्या खड़ी होती है बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी खड़ी होती है इन गतिविधियों को संचालित करने में विभिन्न राजनीतिक दलों को अपना वोट वोट बैंक दिखाई देता है और यह राजनीतिक दल ही ऐसी सरकारी भूमि पर लोगों को बचाने के षड्यंत्र करते हैं फिर उन्हें विस्थापित होने पर आंदोलन खड़े किए जाते हैं और अन्यत्र बसाने की मांग की जाती है यह भारत की एक जटिल समस्या है। क्यों नहीं सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा होने की स्थितियों को सरकार पहले से ही गंभीरता से लेती?

संपादकीय

एक बेतुका आदेश

हाल के दिनों में देश की शीर्ष अदालत से लेकर आम विमर्श तक में आवारा कुत्तों का मामला सुर्खियों में रहा है। इस संवेदनशील, जटिल व विवादास्पद मुद्दे से जुड़े कई तरह के अंतर्विरोध सामने आ रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में बिहार के एक नगर निगम के बेतुके फरमान को लेकर आलोचना की जा रही है। यह निर्णय न केवल बेतुका है बल्कि हास्यास्पद भी है। बिहार के सासाराम के नगर निगम ने शिक्षकों से सड़कों में घूमने वाले आवारा कुत्तों की गिनती करने को कहा है। दरअसल, अदालत के निर्देशों के अनुरूप स्थानीय निकायों की इस बाबत जवाबदेही तय की गई है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों व गिरते परीक्षा परिणाम के बावजूद शिक्षकों को गैर-शिक्षण कार्यों में लगाना दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। वहीं दूसरी ओर हर छोटे-बड़े सरकारी अभियान में शिक्षकों की जिम्मेदारी लगाना प्रशासनिक विफलता को भी उजागर करता है। कभी जनगणना, कभी चुनावी ड्यूटी तो कभी आपदा सर्वेक्षण, और अब कुत्तों की गिनती का बेतुका काम शिक्षकों के जिम्मे लगा दिया गया है। दरअसल, बिहार के शिक्षक विषम परिस्थितियों के चलते पहले ही अत्यधिक दबाव में हैं। जिसके कारण वे शैक्षणिक जिम्मेदारियों व गैर-शिक्षण दायित्वों के लगातार बढ़ते बोझ के बीच संतुलन बनाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि हर इस तरह का व्यवधान कक्षा के समय, पाठ योजना और छात्रों की सहभागिता को गहरे तक प्रभावित करता है। निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा बच्चे के विकास की नींव रखती है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहद निराशाजनक रहता है। वर्षों से पेश की जा रही एएसईआर रिपोर्टों में कई बार उजागर किया गया है कि बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम देश में सबसे कमजोर रहा है। जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में जब पहले ही बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम निराशाजनक रहता है तो शिक्षकों को एक और गैर-शैक्षणिक कार्य के लिये कक्षाओं से बाहर निकालना, निस्संदेह शिक्षा व्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम ही कहा जाएगा। इससे भी बुरी बात यह है कि यह आदेश कई वास्तविक खतरों से भरा है। आवारा कुत्तों की गिनती करना शिक्षण के कागजी कार्य के समान सहज नहीं है। निश्चित रूप से अनेक शिक्षक ऐसे होंगे जो कुत्तों से डरते भी होंगे। खासकर शिक्षिकाओं के लिये यह कार्य खासा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ लोग इस गणना प्रक्रिया में वास्तविक खतरे का सामना भी कर सकते हैं। इस बात का संकेत शीर्ष अदालत की टिप्पणी में भी मिलता है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि किसी कुत्ते के मन को पढ़ना या यह अनुमान लगाना असंभव है कि कोई जानवर कब आक्रामक हो जाएगा। निश्चित रूप से अप्रशिक्षित शिक्षकों को ऐसे कार्य करने के लिए कहना, उनकी सुरक्षा के लिये भी चुनौती होगी।

चिंतन-मनन

प्रेम और दया से ही प्रसन्न होंगे ईश्वर

ईश्वर को खुश करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। मंत्र साधक लाखों बार मंत्र जप करते हैं, भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोग मंदिर जाकर ईश्वर की पूजा करते हैं। धूप-दीप आरती से भगवान को प्रसन्न करने की भी कोशिश करते हैं। इतना करने के बाद भी यह पता नहीं होता कि ईश्वर हमें प्यार करता है या नहीं। प्रेम में सफलता तभी मिलती है जब हमें जिसे प्यार करते हैं वह हमें प्यार करे। इसलिए हमेशा ऐसा काम करें जिससे ईश्वर आपको प्यार करे। यह काम पूजा-पाठ और मंत्र जप से भी आसान है। सभी धर्म एक बात पर सहमत है कि प्रेम और दया यह दो ऐसे साधन है जिसकी बदलौत हम ईश्वर को मजबूर कर सकते हैं कि वह हमें प्यार करे। प्रेम और दया ऐसी चीज है जिसके लिए न तो धन की जरूरत पड़ती है और न ही किसी दूसरे साधनों की। यह अपने आप में पूर्ण और पवित्र है। हम किसी के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं तो बदले में हमें भी प्रेम मिलता है। इसका कारण यह है कि जिसके प्रति हम प्रेम दशार्ते हैं उसके हृदय में मौजूद आत्मा जो ईश्वर का स्वरूप होता है वह प्रसन्न होता है और बदले में हमें अपने प्रेम की अनुभूति कराता है। गीता, कुरान अथवा बाइबल सभी में दया को ईश्वर को पाने का माध्यम बताया गया है। ईश्वर को फूल, फल अथवा मंत्र से ध्यान करने का उद्देश्य भी यही है कि हमारा मन निर्मल हो और मन में दया की भावना बढ़े। जिसने दया करना सीख लिया वह ईश्वर का पुत्र हो जाता है। ईसा मसीह, भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, साईं सभी ने अपने जीवन में दया का अनुपम परिचय दिया। अपने इसी गुण के कारण ईश्वर ने इन्हें प्यार किया और ईश्वरीय शक्ति इनमें समाहित हो गयी।

वेनेजुएला पर ट्रंप की सख्ती- नया वैश्विक टकराव

सनत जैन

वेनेजुएला को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया आक्रामक कार्रवाई ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति एवं सामरिक तनाव को तेज कर दिया है। प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना, समुद्री मार्गों पर निगरानी बढ़ाना और कथित तौर पर रूस से जुड़े जहाज की जप्ती जैसे कदम केवल वेनेजुएला तक सीमित नहीं हैं। इनके दूरगामी अंतरराष्ट्रीय प्रभाव जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। यह घटनाक्रम स्पष्ट संकेत देता है, अमेरिका, लैटिन अमेरिका क्षेत्र में अपने वर्चस्व को आर्थिक एवं सामरिक दृष्टिकोण अपनाते हुए ट्रम्प कब्जा करना चाहते हैं। भले ही इसके लिए रूस और चीन के साथ सीधा टकराव लेने की ट्रंप की सोच है। अमेरिका और वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी और अर्थव्यवस्था पर जो संकट देखने को मिल रहे हैं उसके बाद यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, आने वाले दिनों में अमेरिका अपनी डॉलर मुद्रा तथा वैश्विक व्यापार के वर्चस्वको बनाए रखना चाहता है। उसके लिए ट्रंप अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्रम्प ने टेरिफ के बहाने जो नया खेल खेला था। उसमें वह असफल हो गए है। अमेरिका में मंहगाई और आर्थिक स्थिति पर इसके दुष्परिणाम दिखने लगे है। इससे बचने के लिये अब ट्रम्प ने वेनेजुएला का मुद्दा खड़ा करके अमेरिका में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते है? वेनेजुएला लंबे समय से रूस और चीन का रणनीतिक साझेदार है। रूस ने वहां ऊर्जा, हथियार और सैन्य सहयोग किया है। जबकि चीन ने कर्ज, बुनियादी ढांचा और तेल समझौतों के जरिए अपनी गहरी पैठ बनाई है। रूस और चीन के हथियार भी वेनेजुएला में है। ऐसे में किसी रूसी जहाज की जप्ति केवल एक कानूनी या तकनीकी कार्रवाई के रूप में नहीं देखी जा सकती है। इस कार्रवाई को रूस के प्रभाव को खुली चुनौती के रूप में ही देखा जाएगा। मॉस्को ट्रंप की इस कार्रवाई को अपनी संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्रता पर हमला बताकर कूटनीतिक विरोध, जवाबी प्रतिबंध या समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने जैसे कदम उठा सकता है। हालांकि रूस सीधे सैन्य टकराव से बचता हुआ दिख रहा है। समय आने पर इसकी प्रतिक्रिया बड़े रूप में हो सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दुनिया के देशों में अमेरिका, विरोधी मंचों पर इस मुद्दे का जोर-शोर से उठना तय है। चीन का रुख अपेक्षाकृत संतुलित होते हुए भी व्यापारिक दृष्टिकोण से दीर्घकालिक होगा। बीजिंग आमतौर पर प्रत्यक्ष टकराव से बचते हुए अंतरराष्ट्रीय कानून, बहुपक्षवाद और संप्रभुता के सिद्धांतों की बात करते हुये इस समस्या के समाधान की कोशिश करेगा, ऐसी संभावना देखने को मिलती है। अमेरिका की कार्रवाई को चीन ह्लएकतरफा दबाव नीतिह्व करार देकर वैश्विक मंच पर अमेरिका को अलग-थलग करने की कोशिश करेगा। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों तथा वैश्विक व्यापार संधिकरण की नीति को लेकर अपना विरोध दर्ज करा सकता है। इसके साथ चीन वेनेजुएला में अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों, गुप्त या अप्रत्यक्ष रूप से वेनेजुएला की मदद रूस के साथ तालमेल कर ट्रंप की दादागिरी को चुनौती देने का काम कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का वैश्विक प्रभाव तेल बाजारों,समुद्री व्यापार, वैश्विक व्यापार और विकासशील देशों की आर्थिक एवं विदेश नीति पर पड़ना तय है। वह देश जो अमेरिकी प्रतिबंधों से असहमत हैं। वह चीन-रूस खेमे की नीतियों की और झुक सकते हैं। अमेरिका समर्थक देश भी ट्रंप की इस तरह की कार्यवाही के खुले समर्थक नहीं है। इसका असर नाटो देश और यूरोपियन संगठन में भी देखने को मिल रहा है। वह ट्रंप की इन नीतियों का कितना समर्थन करेंगे, वर्तमान में कहना मुश्किल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की नीतियां आ रही हैं। उसके बाद दुनिया एक बार फिर आर्थिक एवं सामरिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। विकासशील देश एवं वेनेजुएला जैसे देश

महाशक्तियों की रस्साकशी का मैदान बन रहे हैं। यह स्थिति वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सारी दुनिया के सामने है। अमेरिका की इस कार्रवाई से वैश्विक व्यापार संधि के बाद जो आर्थिक परिवर्तन सारी दुनिया के देशों में देखने को मिला था। निश्चित रूप से वह तेजी के साथ सिमटने लगेगा। जिसका दुष्प्रभाव आर्थिक मंदी के रूप में जल्द ही सामने आ सकता है। इसको लेकर तरह-तरह की वैश्विक चिंताएं सामने आने लगी हैं।

सुप्रीम कोर्ट का उपद्रवियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नजरिया

मनोज कुमार अग्रवाल

दिल्ली के दंगाइयों को शीर्ष अदालत ने राहत देने से सीधा इंकार कर दिया यह अदालत की अराजकता से निबटने की जीरो टॉलरेंस को नीति का हवाला देता है। उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से साफ इंकार करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने साथ ही उमर खालिद और शरजील इमाम पर इस मामले में एक साल तक जमानत याचिका दाखिल करने पर भी रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की बैंच ने हालांकि इस मामले में अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाय अहमद को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है।

इस मामले में बैंच ने कहा, अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से याचिकाकताओं उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होते हैं। इन याचिकाकताओं के संबंध में वैधानिक कसौटी लागू होती है। कार्यवाही के इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। अदालत ने कहा कि जिन लोगों को जमानत मिली है, उनकी भूमिका सीमित और परिस्थितिजन्य मानी गई है, जबकि उमर खालिद और शरजील इमाम पर दंगों की साजिश रचने, भीड़ को भड़काने और सुनियोजित तरीके से हिंसा को दिशा देने के गंभीर आरोप हैं। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। देखा जाये तो उच्चतम न्यायालय का यह फैसला केवल दो व्यक्तियों की जमानत याचिका का निपटारा नहीं है, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय संकल्प का स्पष्ट संदेश है।

आपको पता रहे उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे लोग कोई साधारण आरोपी नहीं हैं। ये वह चेहरे हैं जिन्होंने विचारधारा की आड़ में सड़कों पर आग लगाने की मानसिकता को खाद पानी दिया। यह साबित हो चुका है कि दिल्ली दंगे अचानक नहीं भड़के थे। उनके पीछे शब्दों के बारूद, भाषणों की चिंगारी और योजनाबद्ध उकसावे की लंबी तैयारी थी। ऐसे मामलों में यदि अदालत नरमी दिखाती, तो यह न केवल न्याय के साथ अन्याय होता बल्कि समाज के लिए एक खतरनाक संकेत भी जाता। अदालत ने सही कहा कि इन दोनों की स्थिति अन्य आरोपियों से अलग है। यह अंतर केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक भी है। दंगा केवल पत्थर फेंकने से नहीं होता, दंगा उस सोच से पैदा होता है जो समाज को बांटने का काम करती है। जब किसी मंच से यह कहा जाए कि सड़कों पर उतर कर व्यवस्था को जाम कर दो, तब वही शब्द बाद में आग वन जाते हैं। जमानत खारिज करने का फैसला उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो खुद को एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी बताकर कानून को ठेंगा दिखाना चाहते हैं। यह फैसला बताता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अराजकता फैलाने की छूट नहीं है। मुकदमे में देरी को लेकर अदालत की टिप्पणी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वर्षों से एक तर्क गढ़ लिया गया था कि अगर मुकदमा लंबा चल रहा है, तो आरोपी को स्वतः राहत मिलनी चाहिए। यह सोच न्याय व्यवस्था को कमजोर करती है। अगर गंभीर साजिशों में केवल समय के आधार पर जमानत मिलने लगे, तो हर देश विरोधी ताकत समय को हथियार बना लेगी। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उपद्रवी और दंगाई मानसिकता वाले लोगों पर पड़ेगा। अब यह भ्रम टूटेगा कि लंबी कानूनी प्रक्रिया अंततः उन्हें बचा लेगी। देखा जाये तो अदालत का सख्त रुख भारत की आतंकवाद के खिलाफ चल रही लढाई को मजबूत करता है।

आपको बता दें यह फैसला उन आम नागरिकों के लिए भी भरोसे का आधार है जिन्होंने दंगों में अपने घर, दुकानें और परिजन खोए। उनके लिए न्याय केवल सजा नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि सिस्टम उनके साथ खड़ा है। कुछ लोग इसे कठोरता कहेंगे, लेकिन सच यह है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कठोर फैसले जरूरी होते हैं। उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत खारिज होना इस बात का प्रमाण है कि भारत की न्यायपालिका आज भी राष्ट्र की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और संविधान की मूल भावना को समझती है। यह फैसला आने वाले समय में न केवल कानूनी मिसाल बनेगा, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी भी होगा जो भारत को भीतर से तोड़ने का सपना देखती हैं। यह निर्णय बताता है कि भारत कमजोर नहीं है, भारत चुप नहीं है और भारत अब दंगों की राजनीति को वर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हालिया कानूनी घटनाक्रमों और न्यायिक टिप्पणियों के अनुसार, खुद को एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी बताकर कानून से ऊपर समझने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्ती बढ़ी है। अदालतों ने स्पष्ट किया है कि एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी होने का लेबल किसी व्यक्ति को आपराधिक जांच या कानूनी प्रक्रिया से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं। पिछले कुछ वर्षों में भीमा कोरेगांव और दिली दंगों जैसे मामलों में कई चर्चित चेहरों की गिरफ्तारियों और अदालतों द्वारा उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज किए जाने को इस दिशा में एक बड़ा झटका माना गया है। जांच एजेंसियों ने इन पर अर्बन नक्सल या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। यूएपीए जैसे कड़े कानूनों के तहत की गई कार्रवाई और अदालतों द्वारा साक्ष्यों के आधार पर दी गई कड़ी टिप्पणियों ने यह संदेश दिया है कि वैचारिक स्वतंत्रता की आड़ में हिंसा या अस्थिरता को बढ़ावा देना स्वीकार्य नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में कहा है कि विरोध का अधिकार मौलिक है, लेकिन यह कानून के शासन के उल्लंघन का अधिकार किसी को नहीं देता है।

जाहिर है कि कानून का शासन बनाए रखने के लिए अदालत का भी सख्त रुख होना अत्यंत महत्वपूर्ण है इसके बिना सामूहिक गुंडई अराजकता फैलाने और भीड़ तंत्र कायम करने के षडयंत्रों पर नकेल डालना संभव नहीं होगा।

संपादकीय जयपुर टाइम्स

जयपुर, शुक्रवार
9 जनवरी, 2026

कहानी

अभागा बुनकर

एक नगर में सोमिलक नाम का जुलाहा रहता था। विविध प्रकार के रंगीन और सुन्दर वस्त्र बनाने के बाद भी उसे भोजन-वस्त्र मात्र से अधिक धन कभी प्राप्त नहीं होता था। अन्य जुलाहे मोटा-सादा कपड़ा बुनते हुए धनी हो गये थे। उन्हें देखकर एक दिन सोमलिक ने अपनी पत्?नी से कहा--- 'प्रिये ! देखो, मामूली कपड़ा बुनने वाले जुलाहों ने भी कितना धन-वैभव संचित कर लिया है और मैं इतन सुन्दर, उत्कृष्ट वस्त्र बनाते हुए भी आज तक निर्धन ही हूँ। प्रतीत होता है यह स्थान मेरे लिये भाग्यशाली नहीं है; अतः विदेश जाकर धनोपार्जन करूँगा।'

सोमिलक-पत्?नी ने कहा--- 'प्रियतम ! विदेश में धनोपार्जन की कल्पना मिथ्या स्वप्न से अधिक नहीं। धन की प्राप्ति होनी हो तो स्वदेश में ही हो जाती है। न होनी हो तो हथेली में आया धन भी नष्ट हो जाता है। अतः यहीं रहकर व्यवसाय करते रहो, भाग्य में लिखा होगा तो यहीं धन की वर्षा हो जायगी।'

सोमिलक--- 'भाग्य-अभाग्य की बातें तो कायर लोग करते हैं। लक्ष्मी उद्योगी और पुरुषार्थी शेर-नर को ही प्राप्त होती है। शेर को भी अपने भोजन के लिये उद्यम करना पड़ता है। मैं भी उद्यम करूँगा; विदेश जाकर धन-संचय का यत्?न करूँगा।'

यह कहकर सोमिलक वर्धमानपुर चला गया। वहाँ तीन वर्षों में अपने कौशल से 300 सोने की मुहरें लेकर वह घर की ओर चल दिया। रास्ता लम्बा था। आधे रास्ते में ही दिन ढल गया, शाम हो गई। आस-पास कोई घर नहीं था। एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर रात बिताई। सोते-सोते स्वप्न आया कि दो भयंकर आकृति के पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा ---- 'हे पौरुष ! तुझे क्या मालूम नहीं है कि सोमिलक के पास भोजन-वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता; तब तूने इसे 300 मुहरें क्यों दीं ?' दूसरा बोला---- 'हे भाग्य ! मैं तो प्रत्येक पुरुषार्थी को एक बार उसका फल दूंगा ही। उसे उसके पास रहने देना या नहीं रहने देना तेरे अधीन है।'

स्वप्न के बाद सोमिलक की नींद खुली तो देखा कि मुहरों का पात्र खाली था। इतने कष्टों से संचित धन के इस तरह लुप्त हो जाने से सोमिलक बड़ा दुःखी हुआ, और सोचने लगा--- 'अपनी पत्?नी को कौनसा मुख दिखाऊँगा, मित्र क्या कहेंगे ?' यह सोचकर वह फिर वर्धमानपुर को ही वापिस आ गया। वहाँ दित-रात घोर परिश्रम करके उसने वर्ष भर में ही 500 मुहरें जमा करलीं। उन्हें लेकर वह घर की ओर जा रहा था कि फिर आधे रास्ते में रात पड़ गई। इस बार वह सोने के लिये ठहरा नहीं; चलता ही गया। किन्तु चलते-चलते ही उसने फिर उन दोनों---पौरुष और भाग्य---को पहले की तरह बात-चीत करते सुना। भाग्य ने फिर वही बात कही कि---- 'हे पौरुष ! क्या तुझे मालूम नहीं कि सोमिलक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता। तब, उसे तूने 500 मुहरें क्यों दीं ?' पौरुष ने वही उत्तर दिया ---- 'हे भाग्य ! मैं तो प्रत्येक व्यवसायी को एक बार उसका फल दूंगा ही, इससे आगे तेरे अधीन है कि उसके पास रहने दे या छीन ले।' इस बात-चीत के बाद सोमिलक ने जब अपनी मुहरों वाली गठरी देखी तो वह मुहरों से खाली थी।

इस तरह दो बार खाली हाथ होकर सोमिलक का मन बहुत दुःखी हुआ। उसने सोचा---- 'इस धन-हीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। आज इस वृक्ष की टहनी से रस्सी बाँधकर उस पर लटक जाता हूँ और यहीं प्राण दे देता हूँ।'

गले में फन्दा लगा, उसे टहनी से बाँध कर जब वह लटकने ही वाला था कि उसे आकाश-वाणी हुई--- 'सौमिलक ! ऐसा दुःसाहस मत कर। मैंने ही तेरा धन चुराया है। तेरे भाग्य में भोजन-वस्त्र मात्र से अधिक धन का उपभोग नहीं लिखा। व्यर्थ के धन-संचय में अपनी शक्तियाँ नष्ट मत कर। घर जाकर सुख से रह। तेरे साहस से तो मैं प्रसन्न हूँ ; तू चाहे तो एक वरदान माँग ले। मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा।'

सोमिलक ने कहा ---- 'मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो।'

अदृष्ट देवता ने उत्तर दिया---- 'धन का क्या उपयोग ? तेरे भाग्य में उसका उपभोग नहीं है। भोग-रहित धन को लेकर क्या करेगा ?'

कूटनीति में बौद्ध विरासत का उपयोग

भारत से निकले असंख्य ज्ञानी भिक्षुओं के कारण बौद्ध धर्म दुनिया के अनेक देशों में प्रचलित और स्वीकार्य है। चूंकि दक्षिण पूर्वी एशिया में शासक आपसी संवाद में बौद्ध धर्म को बहुत महत्व देते थे, इसलिए विश्व सुलह और शांति के लिए बौद्ध धर्म का उपयोग स्वाभाविक है। वर्तमान एशिया में लगभग 45 करोड़ बौद्ध रहते हैं, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म एक साफ्ट पावर है। भारत से ही बौद्ध धर्मावलंबी तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम आदि गए। बौद्ध धर्म पर आधारित कूटनीति चलाना भारत के लिए नई बात नहीं है। मनमोहन सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। इस विश्वविद्यालय का एक उद्देश्य शास्त्रीय भाषा पाली का प्रचार-प्रसार करना और एशिया से छात्रों और शोधकर्ताओं को भारत आकर्षित करना भी है। बौद्ध धर्म का कूटनीतिक उपयोग मोदी सरकार का एक अंग बन गया है। इस संदर्भ में यह ठीक ही कहा गया है कि कि मोदी सरकार की नीति है-हिंदू संस्कृति, बौद्ध विरासत। पिपरहवा अवशेषों की कहानी भी दिलचस्प है। 1898 में अमूल्य रत्न उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में अंग्रेज जमींदार विलियम पेप को मौर्यकालीन स्तूप की खोदाई में मिले। उनके साथ कुछ अस्थि-अवशेष एक कलश में पाए गए, जिस पर प्राचीन ब्राह्मी में उत्कीर्ण था कि स्वयं भगवान बुद्ध के शाक्य कुल के सदस्यों ने इसे यहां रखा है। अंग्रेजों ने कुछ रत्न श्याम (प्राचीन थाईलैंड) के

बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष केवल कलाकृतियां नहीं हैं। ये हमारी विरासत एवं सभ्यता का अभिन्न हिस्सा हैं और भारत इसका संरक्षक है। पिपरहवा अवशेषों को एक सदी से अधिक समय बाद देश वापस लाया गया है। भारत लाए जाने के बाद इन अवशेषों को रूस के काल्मिकिया क्षेत्र में ले जाया गया, जहां 1.5 लाख से अधिक भक्तों ने उनका अवलोकन किया। इसके अलावा उन्हें भूटान, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड भी ले जाया गया।

भारत से निकले असंख्य ज्ञानी भिक्षुओं के कारण बौद्ध धर्म दुनिया के अनेक देशों में प्रचलित और स्वीकार्य है। चूंकि दक्षिण पूर्वी एशिया में शासक आपसी संवाद में बौद्ध धर्म को बहुत महत्व देते थे, इसलिए विश्व सुलह और शांति के लिए बौद्ध धर्म का उपयोग स्वाभाविक है। वर्तमान एशिया में लगभग 45 करोड़ बौद्ध रहते हैं, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म एक साफ्ट पावर है। भारत से ही बौद्ध धर्मावलंबी तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम आदि गए। बौद्ध धर्म पर आधारित कूटनीति चलाना भारत के लिए नई बात नहीं है। मनमोहन सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। इस विश्वविद्यालय का एक उद्देश्य शास्त्रीय भाषा पाली का प्रचार-प्रसार करना और एशिया से छात्रों और शोधकर्ताओं को भारत आकर्षित करना भी है। बौद्ध धर्म का कूटनीतिक उपयोग मोदी सरकार का एक अंग बन गया है। इस संदर्भ में यह ठीक ही कहा गया है कि कि मोदी सरकार की नीति है-हिंदू संस्कृति, बौद्ध विरासत। पिपरहवा अवशेषों की कहानी भी दिलचस्प है। 1898 में अमूल्य रत्न उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में अंग्रेज जमींदार विलियम पेप को मौर्यकालीन स्तूप की खोदाई में मिले। उनके साथ कुछ अस्थि-अवशेष एक कलश में पाए गए, जिस पर प्राचीन ब्राह्मी में उत्कीर्ण था कि स्वयं भगवान बुद्ध के शाक्य कुल के सदस्यों ने इसे यहां रखा है। अंग्रेजों ने कुछ रत्न श्याम (प्राचीन थाईलैंड) के बौद्ध नरेश को उपहार में दिए, कुछ श्रीलंका और म्यांमार के बौद्ध मंदिरों में भेजे और एक हिस्सा कोलकाता के संग्रहालय में रखा और करीब 334 रत्नाभूषण जमींदार पेप ने अपने पास रखे। इन्हें बीते साल उनके वंशजों ने एक नीलामी घर सूथबीज को बोली लगाने के लिए सौंप दिया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सूथबीज को नोटिस भेज नीलामी रुकवाई और गोदरेज समूह ने इस अमूल्य धरोहर को भारत लाने में आर्थिक योगदान दिया, पर हर देश ऐसा नहीं कर पाता।

कोरियाई युद्ध के बाद हजारों-हजार बौद्ध पुरावशेष चोर बाजार में हाथों-हाथ बिके। कोरिया में बौद्ध धर्म का सबसे तेजी से ह्रास हुआ है, पर अपने आसपास के बौद्ध देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने के लिए बड़े पैमाने पर वहां बौद्ध गोष्ठियां होती हैं। कभी चोल साम्राज्य और तदनंतर भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव में रहे दक्षिण-पूर्वी एशिया देशों की हमने उपेक्षा की। इसका फायदा पहले पश्चिमी देशों और फिर चीन ने उठाया। 2000 में मीकांग-गंगा कोआपरेशन के तहत भारत ने पांच आसियान देशों कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम के पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा के साथ-साथ परिवहन और संचार क्षेत्र में सहयोग की पहल की।

आज ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका में कई संसाधनसंपन्न विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म और पाली के पठन-पाठन के माध्यम से अपने राजनीतिक हित पूरे कर रहे हैं। इससे बौद्ध धर्म के अध्ययन में अप्रासंगिक त्रुटियां घर कर जाने का खतरा है, जो चिंताजनक है। हमें यह समझना चाहिए कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म पालन और संरक्षण में हमारी स्वाभाविक और निर्णायक भूमिका है। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की गांधार सभ्यता और उसकी शैव और बौद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत भारत की है।

अपने बौद्ध स्थलों का हवाला देते हुए कुछ समय पहले पाकिस्तानी राजदूत नबील मुनीर ने कहा था कि बौद्ध धर्म पाकिस्तान से कोरिया गया और वहां प्रचलित महायान बौद्ध धर्म का उद्भव भी पाकिस्तान में ही हुआ। भारत अगर पाकिस्तान की ऐसी कुटिलता का प्रत्युत्तर नहीं देगा और बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म नामक वृक्ष की ही एक डाली नहीं कहेगा, तो पाकिस्तान हमारी अनमोल विरासत को हथिया सकता है। बौद्ध धर्म का सर्वेसर्वा बनने के लिए चीन भी हाथ-पांव मार रहा है। दरअसल जब भारत अपना भविष्य यूरोप और अमेरिका में देख रहा था, तब बौद्ध धर्म के सहारे चीन एशिया में अपने पांव जमा रहा था।

भारत को आज ज्यादा से ज्यादा मित्र राष्ट्रों की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति में बौद्ध धर्म पर आधारित कूटनीति बहुत कारगर हो सकती है। इसका भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि हम वैश्विक स्तर पर बौद्ध धर्म से प्रभावित जनता की सद्भावना आकर्षित कर सकें।

सम्पादकीय

सड़कों से सत्ता तक अराजकता और टारगेटेड हमले

बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की अराजकता बेलगाम होती देखी जा रही है, उससे साफ है कि बदलाव की मांग के साथ वहां जो आंदोलन शुरू हुआ था, वह अब दिशाहीन हो चुका है। अब वहां हो रही लक्षित हिंसा की घटनाएं व्यापक चिंता का कारण बन रही हैं। गौरतलब है कि पिछले दो दिनों में जिन दो लोगों की हत्या कर दी गई, उनकी सामुदायिक पहचान हिंदू थी। सोमवार रात को वहां के नरसिंगदी शहर में अज्ञात हमलावरों ने एक किराना दुकान के चालीस वर्षीय मालिक की हत्या कर दी। इस घटना से कुछ घंटे पहले ही जेस्सोर जिले में एक अन्य व्यापारी की सिर में गोली मार कर जान ले ली गई, जो एक अखबार के कार्यवाहक संपादक भी थे। इसके अलावा, एक विधवा से सामूहिक बलात्कार, उसका निर्मम उत्पीड़न करने और उसका वीडियो बना कर जारी कर देने की भी खबर आई। इससे पहले भी वहां हिंदू पहचान को निशाना बना कर हत्या की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। साफ है कि बांग्लादेश में जारी हिंसा और अफरा-तफरी अब किसी खास एजंडे के तहत हो रही लगती है। वरना क्या कारण है कि एक ही प्रकृति की घटनाएं लगातार सामने आने और इसी वजह से नई जटिलताएं खड़ी होने के बावजूद वहां की अंतरिम सरकार इसे रोकने को लेकर कुछ भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। यह बेवजह नहीं है कि लगातार और सरेआम हो रही हत्या की घटनाओं से स्थानीय अल्पसंख्यक समुदायों के आम लोगों और व्यापारियों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। अशांति और हिंसा की घटनाओं में तेजी की तात्कालिक वजह जुलाई, 2024 के विद्रोह के एक प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या हो सकती है, जो भारत का कट्टर आलोचक भी था। सवाल है कि अगर हादी का मकसद देश को बदलना था, तो क्या उसका रास्ता यह होगा कि वहां के अल्पसंख्यक तबकों और खासतौर पर चुन कर हिंदू पहचान वाले निर्दोष लोगों की हत्या की जाए? फिर अगर अराजकता का यह सिलसिला जारी रहता है और वहां की सरकार तथा कानून-व्यवस्था संभालने वाली एजंसियां ऐसी घटनाओं को रोक नहीं पाती हैं, तो इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? बांग्लादेश में तत्कालीन शेख हसीना सरकार के खिलाफ विद्रोह की घोषित वजहें चाहे जो रही हों, लेकिन आज वहां भीड़तंत्र जिस तरह हावी होता दिख रहा है, वह खुद बांग्लादेश के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। धार्मिक पहचान को आधार बना कर हत्या या बलात्कार की घटनाओं के दौरान स्थानीय लोग जिस तरह अराजक होते या जैसी प्रतिक्रियाएं देते दिखते हैं, वह कुछ समूहों के दिशाहीन और संवेदनहीन हो जाने का संकेत तो है ही, जघन्य अपराधों के बेलगाम होते जाने को नहीं रोक पाना दरअसल शासन के नाकाम हो जाने का भी सबूत है। अगर अब भी वहां शांति और लोकतंत्र की बहाली के लिए ठोस कवायद नहीं हुई, अल्पसंख्यक समुदायों के बीच फैली असुरक्षा की भावना बनी रही, तो इसका खमियाजा समूचे देश को उठाना पड़ सकता है। सही है कि लक्षित तौर पर हिंसा करने वालों के बरक्स वहां अब भी वैसे लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने पर चिंता जाहिर करते हैं।

सोमनाथ मंदिर हमारी सभ्यतागत चेतना का प्रतीक

छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के संकल्प से लेकर ज्योतिर्लिंगों की मर्यादा की रक्षा तक, यह यात्रा निरंतर जारी रही। स्वराज की इस लौ को छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर मेरे पूर्वज महाराजा महादजी सिंधिया जैसे हजारों योद्धाओं ने अनवरत अपने शौर्य से जलाए रखा। इस ऐतिहासिक अन्याय के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिकार अठारहवीं शताब्दी में तब देखने को मिला, जब महाराजा महादजी सिंधिया की शक्ति ने भारत के स्वाभिमान को पुनर्जीवित किया। पानीपत के तृतीय युद्ध (1761) की भीषण त्रासदी के पश्चात, जब महादजी महाराज ने अपने परिवार के सोलह सदस्यों को खोया तो यह मराठाओं की शक्ति के अस्तित्व की कठोर परीक्षा थी।
तब महादजी महाराज ने अदम्य धैर्य, निरंतर संघर्ष और दूरदर्शी रणनीति के बल पर 10 फरवरी, 1771 को दिल्ली के लालकिले पर मराठा-भगवा ध्वज फहराया।

सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के एक हजार वर्ष पूर्ण होना हमें उस शाश्वत चेतना का स्मरण कराता है, जिसने सदियों से भारत के आत्मा को पोषित किया। सोमनाथ की यह यात्रा प्रमाण है कि हमारी सभ्यतागत चेतना वह 'अक्षयवट' है, जिसे कोई भी आक्रांता नष्ट नहीं कर सका। महमूद गजनवी द्वारा इस पवित्र मंदिर पर किया गया आक्रमण मात्र एक स्थापत्य संरचना पर आघात नहीं, बल्कि वह उस गौरवशाली सभ्यतागत पहचान को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास था, जो युगों-युगों से इस पुण्यभूमि को भारत के रूप में परिभाषित करती आई है। वर्ष 1026 का वह घाव गहरा था, जिसने न केवल मंदिर की शिलाओं को खंडित किया, बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान को भी चुनौती दी थी। हालांकि समय की धारा ने यह सिद्ध किया कि भारत की सांस्कृतिक चेतना कभी समाप्त नहीं होती।

छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के संकल्प से लेकर ज्योतिर्लिंगों की मर्यादा की रक्षा तक, यह यात्रा निरंतर जारी रही। स्वराज की इस लौ को छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर मेरे पूर्वज महाराजा महादजी सिंधिया जैसे हजारों योद्धाओं ने अनवरत अपने शौर्य से जलाए रखा। इस ऐतिहासिक अन्याय के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिकार अठारहवीं शताब्दी में तब देखने को मिला, जब महाराजा महादजी सिंधिया की शक्ति ने भारत के स्वाभिमान को पुनर्जीवित किया। पानीपत के तृतीय युद्ध (1761) की भीषण त्रासदी के पश्चात, जब महादजी महाराज ने अपने परिवार के सोलह सदस्यों को खोया तो यह मराठाओं की शक्ति के अस्तित्व की कठोर परीक्षा थी।

तब महादजी महाराज ने अदम्य धैर्य, निरंतर संघर्ष और दूरदर्शी रणनीति के बल पर 10 फरवरी, 1771 को दिल्ली के लालकिले पर मराठा-भगवा ध्वज फहराया। यह विजय मात्र एक नगर की प्राप्ति नहीं, बल्कि मराठा-सनातन स्वाभिमान

और राजनीतिक प्रभुत्व की पुनः स्थापना का प्रतीक भी थी। वर्ष 1771 से 1803 तक दिल्ली पर सिंधिया वंश का प्रभावी नियंत्रण रहा। वर्ष 1785 में महाराजा महादजी सिंधिया ने दिल्ली विजय के बाद लाहौर विजय अभियान आरंभ किया। उन्होंने सिखों के साथ रणनीतिक गठबंधन और स्थानीय समर्थन के बल पर सशक्त युद्धनीति अपनाई। 29 मई, 1785 को दिल्ली से भारी तोपखाने के साथ लाहौर की ओर कूच करते हुए उन्होंने अफगान गढ़ी को घेर लिया। जुलाई में हुए लगातार संघर्षों में अफगान सेनापति शाह गुलजार हुसैन, परवेज खान और अशरफ अली मारे गए। मानसून के बाद सितंबर में निर्णायक विजय मिली और मोहम्मद शाह अब्दाली को मराठाओं की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। इस विजय के साथ अटक से कटक तक और प्रयागराज से भरूच तक 'हिंदवी स्वराज्य' की सुदृढ़ और प्रतिष्ठित स्थापना हुई। 1785 का लाहौर युद्ध महाराजा महादजी सिंधिया की अद्वितीय सैन्य कुशलता का प्रमाण था, जिसने अफगान सेनाओं में भय उत्पन्न किया। उनके शासन में मराठा साम्राज्य अटक से कटक तथा भरूच से प्रयागराज तक विस्तृत हुआ और भगवा ध्वज सर्वत्र लहराया। इस बार लाहौर की धरती पर उन्होंने विजय पताका फहराई और अफगान सेनाओं को सिंधु के पार खदेड़ा। इस युद्ध में महादजी महाराजा ने सदियों पहले 1026 ईस्वी में सोमनाथ पर किए गए उस आघात का वह सभ्यतागत प्रतिशोध लिया, जिसने भारत के आत्मा पर गहरी चोट की थी।

महाराजा महादजी सिंधिया लाहौर में मोहम्मद शाह अब्दाली के महल से वे ऐतिहासिक चांदी के द्वार वापस लेकर आए, जिन्हें गजनवी सोमनाथ से लूटकर ले गया था।

अमेरिका की अराजकता

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह यह कहा कि वेनेजुएला अमेरिका को पांच करोड़ बैरल तेल देगा और उसकी बिक्री वे खुद करेंगे, वह उनकी मनमानी का एक और शर्मनाक उदाहरण है। इससे यही सिद्ध होता है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी सेनाओं के हमले का मूल उद्देश्य इस देश के तेल संसाधन पर कब्जा करना ही था। वे इस कब्जे को लेकर जिस तरह कोई शर्म-संकोच नहीं कर रहे हैं, उससे यही पता चलता है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों की कोई परवाह नहीं। वे सैन्य शक्ति के मद में चूर होकर यह देखने से भी इन्कार कर रहे हैं कि उनकी अराजकता किस तरह विश्व को संकट की ओर धकेल रही है। वे अपनी हरकतों से विश्व के दबंग देशों को मनमानी करने का लाइसेंस दे रहे हैं। उनके रवैये से विश्व में उथलपुथल मच

सकती है और कुछ नए युद्ध भी छिड़ सकते हैं। खुद को शांति का मसीहा बताने और इसी बहाने नोबेल पुरस्कार की चाह रखने वाले ट्रंप दुनिया को अशांत और अस्थिर करने का काम जिस बेशर्मी से कर रहे हैं, वह उन्हें भी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि एक के बाद एक देश उनसे आजिज आ रहे हैं। उन्होंने जिस तरह डेनमार्क के अर्द्ध स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी दी, उसके बाद वे यूरोपीय देश भी उनसे खफा हैं, जो हर बात में उनकी हां में हां मिलाते थे। अब इन देशों को यह समझ आ जाए तो अच्छा कि अहंकारी ट्रंप अपने मित्र देशों के भी सगे नहीं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ट्रंप कूटनीतिक शिष्टाचार को धता बताकर भारतीय प्रधानमंत्री समेत अन्य अनेक शासनाध्यक्षों पर तंज कस रहे हैं। उनके बड़बोलेपन से यह नहीं लगता कि निकट भविष्य में भारत और अमेरिका के बीच कोई व्यापार समझौता हो पाएगा। ट्रंप भले ही ड्रग्स तस्करी पर रोक लगाने और लोकतांत्रिक शक्तियों को बल देने की आड़ ले रहे हों, लेकिन उनकी मनमानी का मूल कारण डालर के प्रभुत्व को कायम रखना है। डालर के दबदबे के पीछे एक बड़ी भूमिका तेल व्यापार में अमेरिकी मुद्रा का चलन है। चूंकि अमेरिका एक लंबे समय से मनमानी करता चला आ रहा है, इसलिए विश्व के देशों ने डालर से दूरी बनानी शुरू की। जब इराक और लीबिया ने ऐसा किया तो उन पर हमला किया गया। वेनेजुएला ने भी डालर के बजाय अन्य मुद्राओं में तेल बेचना शुरू कर दिया था। हालांकि तेल बिक्री-खरीद में रूस और चीन भी डालर से परहेज कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का इन देशों पर जोर नहीं , इसलिए वे कमजोर देशों को अपना निशाना बना रहे हैं। वे यह नहीं देख पा रहे कि उनके अराजक रवैये से डालर का वर्चस्व कायम नहीं रहने वाला, क्योंकि उनकी दादागीरी विश्व को डालर में व्यापार न करने के लिए ही विवश कर रही है।

दैनिक ट्रिब्यून
स्थापना 15 अगस्त 1978

संक्रमण का आईसीयू

सतर्क निगरानी से बचेंगी जिंदगियां

यह बात परेशान करने वाली है कि जिस इंटेंसिव केयर यूनिट में बेहद गंभीर मरीजों को जीवन बचाने के लिये रखा जाता है, रिपोर्ट बता रही हैं कि वहां संक्रमण का खतरा सबसे अधिक हो सकता है। ऐसे में इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में भर्ती गंभीर अवस्था में, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों के जीवन का क्या कुछ हो सकता है, उसकी कल्पना सहज की जा सकती है। हालांकि, अब तक तो कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने भारतीय अस्पतालों में आईसीयू की स्थिति को लेकर सवाल उठाये थे, खासकर ब्रिटेन के बहुचर्चित मेडिकल जर्नल 'द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ' में प्रकाशित एक रिपोर्ट में भारतीय इंटेंसिव केयर यूनिट में महज रक्त संक्रमण से संबंधित आंकड़ों का उल्लेख था। लेकिन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के माइक्रोबायोलॉजी एवं इंफेक्शन नियंत्रण विभाग द्वारा किए गए हालिया अध्ययन के निष्कर्ष गंभीर चिंता बढ़ाने वाले हैं। दरअसल, एम्स का यह ताजा अध्ययन बताता है कि जिस आईसीयू में गंभीर हालात में पहुंचे मरीजों को जीवन बचाने वाले उपचार देने के लिये भेजा जाता है, वहीं संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। चिंता इसलिए भी अधिक है क्योंकि एम्स का यह अध्ययन व्यापक स्तर पर किया गया था। इसमें देश के चौंतीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एक सौ नब्बे से अधिक आईसीयू को शामिल किया गया था। अध्ययन ने बताया है कि इन इंटेंसिव केयर यूनिटों में संक्रमण का सर्वाधिक खतरा होता है। खासकर कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले रोगियों के लिये यह स्थिति चुनौतीपूर्ण होती है। उन्हें लंबे समय तक जीवन रक्षा के लिये यहां भर्ती रहना पड़ता है। वहीं इन मरीजों की आधुनिक उपकरणों पर अधिक निर्भरता, इस संकट को बढ़ा सकती है। दरअसल, इस व्यापक अध्ययन में कहा गया है कि ऑपरेशन के बाद होने वाले संक्रमणों में रक्त,फेफड़ों तथा मूत्र मार्ग का संक्रमण शामिल है। जिन मरीजों की बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होती है, उनके लिये तो यह स्थिति अधिक खतरनाक बन सकती है। जिसके लिए अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है।

निश्चित रूप से भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का यह सर्वेक्षण इंटेंसिव केयर यूनिट की संवेदनशील स्थिति को लेकर आंख खोलने वाला है। अध्ययन बेहद सजग होकर निगरानी की जरूरत बताता है। दरअसल, गंभीर रोगों से जूझ रहे मरीज अक्सर आईसीयू में लंबे समय तक भर्ती रहते हैं। इस दौरान वे लगातार जीवन रक्षक उपकरणों पर ही निर्भर रहते हैं। अलग-अलग रोगों के रोगियों द्वारा इनके प्रयोग से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। असल में, आमतौर पर रोगी को कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन देने के लिए वेंटिलेटर, यूरिन पास करने के लिये कैथेटर आदि उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ये उपकरण तब संक्रमण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हो जाते हैं। वैसे तो अनेक रोगों की आशंका बनी रहती है लेकिन इंटेंसिव केयर यूनिट में वेंटिलेटर से होने वाला निमोनिया जरा सी लापरवाही से जानलेवा साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, लापरवाही व सजगता के अभाव में कई ऐसे बैक्टीरिया भी पनपते हैं, जिन पर एंटीबायोटिक दवाएं भी प्रभावी नहीं होती हैं। एम्स का अध्ययन मानता है कि इंटेंसिव केयर यूनिट में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बेहद घातक साबित हो सकता है। इस संकट की कीमत तमाम मरीजों को चुकानी पड़ सकती है। जिसके लिये मरीजों को लंबे समय तक आईसीयू में भर्ती रहना पड़ सकता है, जिसकी उनके तिमारदारों को बड़ी आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। यह संक्रमण अतिरिक्त सावधानी के अभाव में जानलेवा भी साबित हो सकता है। अध्ययन से जुड़े विशेषज्ञों की सलाह है कि चिकित्सक व अन्य सहयोगी कर्मचारी हाथ की व अन्य सफाई पर विशेष ध्यान दें। इसके अलावा जीवन रक्षक उपकरणों को जीवाणु व बैक्टीरिया आदि से मुक्त रखने के लिये नियमित विशेष प्रयास किए जाएं। साथ ही एंटीबायोटिक दवाओं का संयमित उपयोग हो। वहीं इंटेंसिव केयर यूनिट में मरीजों की संवेदनशील ढंग से निरंतर जांच-पड़ताल की जानी चाहिए। इसमें जहां चिकित्सा बिरादरी से अधिक सजगता व सतर्कता की उम्मीद है, वहीं इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती मरीजों के तिमारदारों को को भी सजग व सतर्क रहने की जरूरत है।

आज का विचार

जिस प्रकार वनस्पति को सूर्य से जीवन प्राप्त होता है, उसी प्रकार आशावाद से आप में जीवन संचरित होता है। – स्वेट मार्डेन

एकदा

वास्तविक सम्राट

सम्राट अशोक एक दिन अपने साम्राज्य का निरीक्षण करते हुए एक बौद्ध भिक्षु से मिले। भिक्षु के हाथ में केवल एक मिट्टी का कटोरा था। अशोक ने पूछा— 'तुम्हारे पास इतना ही है?' भिक्षु मुस्कराया— 'महाराज, इससे अधिक मेरी आवश्यकता नहीं।" यह उत्तर अशोक को भीतर तक छू गया। उनके पास असीम सत्ता, सोना और सेनाएं थीं, फिर भी मन अशांत था; जबकि सामने खड़ा व्यक्ति अल्प साधनों में पूर्ण शांत था। उसी क्षण अशोक को बोध हुआ कि विजय बाहरी नहीं, भीतर की होनी चाहिए। उस दिन के बाद उन्होंने शासन का अर्थ बदला—दमन नहीं, सेवा; भय नहीं, विश्वास; और अपने इस विचार को जीवन में उतारा, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं, वह निर्धन है; और जो कम में संतुष्ट है, वही वास्तव में सम्राट है। **प्रस्तुति : राजेन्द्र कुमार जांगिड़**

40 साल पहले

दैनिक ट्रिब्यून

'रास्ता रोको' आंदोलन से निपटने के व्यापक प्रबंध

चंडीगढ़, 8 जनवरी (प्रेट्र)। अखिल भारतीय सिख छात्र महासंघ के 10 जनवरी को प्रस्तावित रास्ता रोको आंदोलन से निपटने के लिए पंजाब सरकार आज हरकत में आ गयी। आज महासंघ के बहुत से सक्रिय कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन उनमें कोई बड़ा नेता शामिल नहीं है। बहुत से कार्यकर्ता एवं नेता भूमिगत हो गये हैं। उपद्रवग्रस्त जिलों में शिक्षण संस्थान तीन दिन के लिए बंद कर दिये गये हैं।

हरियाणा का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समिति गठित

हमारे कार्यालय द्वारा

चंडीगढ़। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (इ) के प्रधान एवं सांसद सदस्य चौधरी वीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समक्ष हरियाणा का मामला प्रस्तुत करने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति हिंदी भाषी क्षेत्र पंजाब से हरियाणा को सौंपने और नहर को पूरा करवाने के लिए राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। ये सात सदस्य हैं वीरेंद्र सिंह प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष, भजनलाल मुख्यमंत्री, सुल्तान सिंह सांसद, दलबीर सिंह सांसद, चिरंजीलाल शर्मा सांसद, सागर राम गुप्ता वित्तमंत्री हरियाणा और एससी चौधरी भूतपूर्व मंत्री हरियाणा।

अज्ञानता को हथियार बनाने के प्रयासों का हो विरोध

अविजित पाठक

शिक्षक इस तरह से शिक्षा दें कि शिक्षार्थी में रचनात्मकता बढ़े। उसकी आकांक्षाएं एक न्यायपूर्ण, समानता युक्त, मानवीय और पारिस्थितिकी के प्रति संवेदनशील मूल्यों के प्रति विकसित हों। आशा के शिक्षाशास्त्र के जरिये ही नई पीढ़ी अपनी सोच व प्रयासों से बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में प्रेरित होगी। शिक्षा मूलतः जाग्रत बुद्धि के बारे में है।

इस भयानक रूप से विषैली, हिंसक और ध्रुवीकृत दुनिया में, किसी के लिए हमारे मौजूदा समय का चरित्र बन चुकी सर्वव्यापी नकारात्मकता से बहक जाना आसान है। फिर भी, एक शिक्षक के रूप में, मुझे लगता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, और हमें आशा के बीज बोने चाहिए और नई पीढ़ी को एक बेहतर दुनिया की कल्पना करने और उसके लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

मैं शिक्षण समुदाय से हार्दिक प्रार्थना के साथ नए साल की शुरुआत में अपील करता हूं : आशा के शिक्षाशास्त्र को कक्षा की गतिशीलता में बदलने दें, शिक्षा के उद्देश्य को फिर से परिभाषित करें और आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक कल्पना, सहानुभूति और प्रेम की शक्ति को सक्रिय करें। हालांकि, यह स्वीकार करना जरूरी है कि समकालीन छात्रों और शिक्षकों में जो निराशा हम देख रहे हैं, वह अक्सर किसी न किसी प्रकार की सनकी व्यावहारिकता के रूप में प्रकट होती है। जैसे-जैसे नवउदारवाद का बाजार-संचालित/उपकरणवादी तर्क शिक्षा को एक उच्च और महान उद्देश्य से वंचित कर रहा है, और इसे आर्थिक उत्पादकता के लिए मात्र एक तकनीकी कौशल में बदल रहा है, कई युवा सामाजिक डार्विनवाद या अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को एक नए गुण के रूप में, पैसे को नए भगवान के रूप में, और अहंकारी गर्व को रुतबे के प्रतीक के तौर पर देखने लगे हैं। उनके आंतरिक जगत में कोई फूल नहीं खिलता;वे शायद ही कभी गांधी और मार्क्स से संवाद करते हैं; और उनके पास समानता, पारिस्थितिकी, शांति एवं न्याय के लिए संघर्ष करने के वास्ते कोई 'फालतू' समय नहीं। इस प्रकार की व्यावहारिकता का मतलब है एक नई दुनिया में आशा की अनुपस्थिति।

इसी तरह, अति-राष्ट्रवाद की संस्कृति कई शिक्षकों के बीच ऐसी व्यावहारिकता को और तेज करती है। जैसे-जैसे डिजिटल निगरानी सामान्य होती जाती है, हमारे कॉलेजों-विश्वविद्यालयों में कई शिक्षकों को लगता है कि उन पर लगातार नज़र रखी जा रही है और निगरानी में हैं। और संभवतः, ऐसा डर उन्हें इसके प्रति बेहद सतर्क कर देता है कि वे क्या पढ़ा सकते हैं, क्या बोल सकते हैं और क्या लिख सकते हैं। जैसे-जैसे

अति-राष्ट्रवाद के विमर्श द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र का उपनिवेशीकरण शिक्षा को उसकी स्वतंत्रतावादी क्षमता से वंचित कर रहा है, शिक्षकों का एक ऐसा बड़ा वर्ग पैदा होना असंभव नहीं है जो चुप रहना पसंद करे, या व्यवस्था के प्रति वफादारी दिखाने के लिए अति उत्साही हो जाए। इसलिए, यह हैरानी की बात नहीं है कि ऐसे 'व्यावहारिक' शिक्षक अपने छात्रों में एक नई कल्पना, या प्रतिरोध की भाषा जगाने में विफल रहते हैं। यहां पर, एक ऐसी दुनिया है जो युद्ध, अधिनायकवाद और जलवायु आपातकाल से त्रस्त है। फिर भी, हमारे कॉलेज और विश्वविद्यालय 'रैंकिंग' की आकांक्षा, और 'प्लेसमेंट और सैलरी पैकेज' की बातों से परे कुछ भी देखने से इनकार करते हैं।

इसलिए, सवाल उठता है : मैं जिस उम्मीद के शिक्षाशास्त्र की बात कर रहा हूं, वह क्या है? और क्या यह सच में मुमकिन है? यहां साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि यह कोई खोखला आदर्श या काल्पनिक खुशफहमी नहीं । आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र के बिना इसे बढ़ावा देना नामुमकिन है : यह उस तरह की शिक्षा है जो युवा शिक्षार्थी को अपना रचनात्मक गुण वापस पाने और उन चीज़ों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है जो एक न्यायपूर्ण, समानता युक्त, मानवीय और पारिस्थितिकी के प्रति संवेदनशील दुनिया की संभावना को नुकसान पहुंचाती हों। यह समझने और गहराई से सिद्धांत बनाने जैसा है, मसलन, चरम-राष्ट्रवाद की आक्रामकता जो युद्ध, नरसंहार, सशस्त्र विद्रोह, आतंकवाद और धार्मिक कट्टरपंथ का कारण बनती है; आधुनिक तकनीक चालित पूंजीवाद के तर्क में छिपा लालच जो हर चीज़ को -चाहे वह पेड़, नदी, जंगल हो या पहाड़- उसे निरंतर 'संवृद्धि' और 'विकास' की खातिर सिर्फ एक 'संसाधन' में बदल देता है, और जलवायु आपदा की भयानक स्थितियों की ओर ले जाता है; और सबसे बढ़कर है, अरबपति प्रौद्योगिकीवादी और नव-फासीवादियों का अपवित्र गठबंधन जो लोकतंत्र की भावना खत्म कर रहा है। इसके अलावा, उम्मीद के शिक्षाशास्त्र का अर्थ है कि शिक्षा को सिर्फ एक तकनीकी कौशल तक सीमित नहीं किया जा सकता; इसकी बजाय यह जाग्रत समझ के बारे में है, या वह, जिसे हेनरी गिरौक्स –जो बेहतरीन शिक्षाविदों में से एक हैं - ने जानकारी से युक्त एवं राजनीतिक रूप से जागरूक लोकतांत्रिक नागरिकों को तैयार करने हेतु एक परिवर्तनकारी औजार के रूप में बताया है। अज्ञानता को हथियार बनाने का विरोध करने का यही एकमात्र तरीका है।

आलोचनात्मक चिंतन के अलावा, उम्मीद के शिक्षाशास्त्र को कुछ और भी चाहिए। वो है सीखने का ऐसा तरीका जो सीखने वाले हर युवा की छिपी हुई क्षमता को जगाए - यानी एक नई दुनिया का सपना देखने की हिम्मत; ज्ञान और आचार को जोड़ने, सोच और भावना, और विज्ञान और सौंदर्यशास्त्र को एक साथ लाने की इच्छा। एक तरह से, यह आलोचना की शक्ति और प्यार एवं दयालुता से सुनने की संभावना को एक साथ लाने की कोशिश करता है। असल में, उम्मीद के शिक्षाशास्त्र के हर गंभीर समर्थक को पाउलो फ्रेयरे और बेल हुक्स, रवींद्रनाथ टैगोर और जिद्दू कृष्णमूर्ति, या मार्टिन लूथर किंग (जूनियर) और थिच न्हाट हान के साथ लगातार संवाद में शामिल होने की ज़रूरत है।

एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर होने के बावजूद, मैं युवाओं से वार्तालाप करता हूं, और उनकी दुविधाओं, चिंताओं और उलझनों को समझता हूं। और मुझे उनके साथ दूसरी कहानियां साझा करना पसंद है- बेशक, तय पाठ्यक्रम से इतर। सांप्रदायिक रूप से बंटी हुई दुनिया में, मैं उन्हें महात्मा गांधी के नोआखली के दिनों (1946-47) की कहानियां सुनाता हूं, और लोगों के दिलों में अच्छाई जगाने, सांप्रदायिक हिंसा से लड़ने, और प्यार, सहानुभूति और अलग-अलग धर्मों में परस्पर संवाद का संदेश फैलाने के उनके अथक प्रयास के बारे में बताता हूं। ऐसी दुनिया में जो इंसान की क्रूर प्रवृत्ति का जश्न मनाती हो, मैं उनके साथ बैठता हूं, और जॉन लेनन का यह ज्ञानवर्धक गाना सुनता हूं : *'आप कह सकते हैं कि मैं एक स्वप्नद्रष्टा हूं/लेकिन मैं अकेला नहीं हूं/मुझे उम्मीद है कि किसी दिन आप हमसे जुड़ेंगे/और दुनिया एक बनकर साथ रहेगी'*।

और ऐसी दुनिया में जहां उपभोगवाद सबसे पसंदीदा सिद्धांत है, और 'विकास' सबसे ज़्यादा नशा करने वाली चीज़ है, मुझे उनके साथ हेनरी डेविड थोरो की उत्कृष्ट रचना 'वाल्डेन' पढ़ना पसंद है, और प्रकृति के प्रति उनकी संवेदनशीलता, सादगी और काव्यात्मक विस्मय का अनुभव करना पसंद है।

आज जबकि इस तकनीक-परक दुनिया में, सोशल मीडिया का नशा एक व्याकुल पीढ़ी को जन्म दे रहा है, और यहां तक कि हमारे नीति निर्माता भी तीसरी कक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की पढ़ाई शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति का आह्वान करना चाहता हूं, और उनसे आग्रह करता हूं कि वे बारिश की बूंदों को या सूर्यास्त के अद्भुत नज़ारे को निहारें, और महसूस करें कि संवेदनशीलता ही बुद्धि का उच्चतम स्वरूप है।

शिक्षण समुदाय उम्मीद के शिक्षाशास्त्र को न भूले।

लेखक समाजशास्त्री हैं।

चर्चा में चेहरा

तमिल जन आकांक्षाओं के विजयी सेनापति

अरुण नैथानी

सुपरस्टार विजय, तमिलनाडु में फिल्मों से राजनीति में कदम रखते हुए, अपनी पार्टी 'टीवीके' के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का आह्वान कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता और युवा समर्थकों से आगामी चुनाव रोचक हो सकते हैं।

कुछ लोग उन्हें दक्षिण का एंग्री यंगमैन बता रहे हैं, तो कुछ राजनीति के जरिये सामाजिक-सांस्कृतिक उद्धार करने वाला सेनापति। दक्षिण भारत में फिल्मों से राजनीति में वर्चस्व करने वालों की कड़ी में एक और नाम जुड़ने जा रहा है सुपर स्टार विजय का। राजनीति में किस्मत आजमाने के लिए उन्होंने फिलहाल फिल्मों से किनारा कर लिया है। हिट थलपति-69 को उनकी आखिरी फिल्म बताया जा रहा है। इसी वजह से अब उन्हें थलपति विजय का नाम दिया जा रहा है। दरअसल, थलपति का तमिल में मतलब सेनापति होता है। उन्होंने बाकायदा पार्टी का झंडा व चिन्ह भी लॉन्च किया है और अब उनकी पार्टी टीवीके को चुनाव आयोग से मान्यता भी मिल गई है। कहा जा रहा है कि इस साल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी भागीदारी बड़ा राजनीतिक उलट फेर कर सकती है। उनकी सभाओं में जुटने वाली लाखों की भीड़ कम से कम यही इशारा कर रही है।

बहरहाल, आज विजय महज फिल्म स्टार भर नहीं हैं, उन्हें तमिलनाडु के सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य में बदलाव के वाहक के रूप में देखा जा रहा है। उनके चाहने वालों में सिर्फ फिल्म प्रेमी ही नहीं हैं, बल्कि वे युवा भी हैं जो बेहतर रोजगार की स्थिति, साफ-सुथरी राजनीति और तमिल अस्मिता की रक्षा की आकांक्षा रखते हैं। वे सभाओं में कहते हैं कि हम बांटने वाली राजनीति के खिलाफ हैं। वे द्रविड़ राजनीति के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों की निंदा करते हैं। वे एक परिवार पर राज्य को लूटने का आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि हम द्रविड़ राष्ट्रवाद और तमिल राष्ट्रवाद को अलग नहीं करेंगे। पार्टी की विचारधारा को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि पार्टी की सोच धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय विचारधारा पर टिकी होगी। उनका कहना है कि उनकी पार्टी संत पेरियर के बताये रास्ते पर चलेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्त्री सशक्तीकरण और सामाजिक न्याय रहा है। यद्यपि उन्होंने पेरियर के

नास्तिकता से जुड़े सिद्धांत से असहमति जतायी है।

दरअसल, विजय के इस अभियान से जुड़ने वाले सिर्फ उनके फिल्मों के प्रशंसक ही नहीं हैं। दरअसल, युवा उन्हें बदलाव के वाहक नायक के रूप में देख रहे हैं। युवा उन्हें अपनी आकांक्षाओं के प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि विजय उनके मन की बात कर रहे हैं। दरअसल, विजय की फिल्मों का नायक एक ऐसा यंग एंग्रीमैन होता है जो सिस्टम की विसंगतियों के खिलाफ विद्रोह करता है। जैसा कभी हिंदी फिल्मों में सत्तर के दशक में अमिताभ बच्चन करते दिखाई देते थे। उनकी लोकप्रियता का आलम यह रहा है कि सिनेमाघर में बोला गया उनका हर संवाद सड़कों पर नारे की शक्ल में आता रहा है। यही वजह है कि आज उन्हें थलपति विजय के नाम से संबोधित किया जा रहा है, जो युवा मनोविज्ञान का प्रतिनिधि चेहरा बन गया है।

दरअसल, अन्य राज्यों की तरह ही तमिलनाडु का युवा समकालीन विसंगतियों से जूझ रहा है। इसमें- बेरोजगारी का संत्रास है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की हताशा है, गैर-बराबरी बढ़ाने वाला विकास है तो तमिलनाडु के राजनेताओं से मोहभंग की स्थिति भी है। यही वजह है कि विजय की घोषणाएं युवाओं को लुभाती हैं और उन्हें विश्वास है कि विजय फिल्मों में निभाए किरदार जैसी भूमिका से समाज में बदलाव ला सकते हैं। वैसे भी तमिलनाडु में फिल्मी सितारों के प्रति जुनून का पुराना इतिहास रहा है। मौजूदा सोशल मीडिया के दौर में वे हर प्लेट फॉर्म में छाए हुए हैं। अब चाहे रील्स हों, मीम्स हों या वायरल संवाद, वे हर जगह नजर आते हैं। आज की एक हकीकत यह भी है कि यह ऑनलाइन लोकप्रियता अब हकीकत में भी नजर आने लगी है।

दरअसल, इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिये थलपति विजय कमर कसकर आए हैं। निश्चित रूप से 2026 में तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव खासा रोचक होने जा रहा है। माना जा रहा है कि वे राज्य में डीएमके व एआईडीएमके के वर्चस्व को कड़ी चुनौती देने जा रहे हैं। वे एक सधे राजनेता की तरह बात करते हैं। वे राज्य में दो भाषाओं के समर्थक हैं- यानी सरकारी कामकाज में तमिल व अंग्रेजी का उपयोग। वे जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं। साथ ही भविष्य में किसी राजनीतिक गठबंधन से भी इनकार नहीं करते हैं। बहरहाल, विजय आज तमिलनाडु की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि राज्य में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक बदलाव के लिये उन्होंने फिल्में छोड़ दी हैं। राजनीति में आने पर वे सिर्फ समाजसेवा करेंगे।

बहरहाल, अब दक्षिण भारत में एमजी रामचंद्रन, जयललिता, विजयकांत, एनटी रामाराव व कमल हासन व पवन कल्याण जैसे सुपरस्टारों की राजनीतिक कामयाबी में थलपति विजय का नाम भी जुड़ने जा रहा है। पवन कल्याण आंध्र की राजनीति में कमाल करके उप-मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उन्होंने जन सेना नामक राजनीतिक दल बनाया। वे एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे। वे राजनीतिक दल बनाने वाले प्रसिद्ध एक्टर चिरंजीवी के छोटे भाई हैं। चिरंजीवी ने भी प्रजा राज्यम पार्टी बनायी थी। कालांतर वे राज्यसभा सदस्य व केंद्रीय मंत्री भी बने।

जहां तक तमिलनाडु में फिल्म सितारों के राजनीतिक वर्चस्व का सवाल है तो मशहूर अभिनेता एम.जी. रामचंद्रन ने एआईएडीएमके बनाई और एक दशक तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। फिर चर्चित अभिनेत्री जयललिता भी इसी पार्टी में शामिल होकर पहली बार 1991 में मुख्यमंत्री बनीं। वहीं दूसरी ओर अभिनेता कमल हासन भी वर्ष 2018 में मक्कल 'नीधि मय्यम पार्टी' बना चुके हैं। लगता है कि इस कड़ी में नया नाम थलपति विजय का जुड़ने जा रहा है।

तिरछी नज़र

ठंड में हम न नहाएं, कहे चाहे सारा संसार

अशोक गौतम

सर्दियों में रोज नहाने से जहां एक ओर सर्दियों में भी शहर में पानी का संकट खड़ा होने की पूरी-पूरी संभावना होती है, वहीं दूसरी ओर सर्दियों में रोज मेरे जैसों के नहाने पर फिट से फिट जीव की भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है।

मित्रो! तुम जानो या नहीं, पर मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सर्दियों में रोज नहाने से जहां एक ओर सर्दियों में भी शहर में पानी का संकट खड़ा होने की पूरी-पूरी संभावना होती है, वहीं दूसरी ओर सर्दियों में रोज मेरे जैसों के नहाने पर फिट से फिट जीव की भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोज नहाने के इतने नुकसान होने के बाद भी एक मेरे घरवाले हैं कि मेरे इस वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित चिंतन को मसखरों का चिंतन मान मुझे हर सुबह नहाने के लिए गुसलखाने में घुसाने के लिए पूरा जोर लगाए रहते हैं।

मैं जानता हूं कि मेरे जैसे त्यागी, तपस्वी, कर्तव्यनिष्ठ, कुशल, योग्य, ईमानदार कर्मचारी के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो कोई होता है तो वह केवल और केवल धर्म ही होता है। धर्म मेरे जैसे जीव को रिश्वत लेने में गतिरोध पैदा करता है। मैं अपने जीवन में हर धार्मिक गतिरोध सहन कर सकता हूं, पर रिश्वत लेने के गतिरोध को कदापि सहन नहीं कर सकता।

मित्रो! मेरे फैमिली डॉक्टर का खुले चैलेंज के साथ कहना है कि सर्दियों में रोज नहाने से किसी और पर बुरा असर पड़े या न पर पाचन तंत्र पर बहुत असर पड़ता है। रोज रोज नहाने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। और मुझे अपने पाचन तंत्र से प्रिय कोई नहीं। मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ तो मैं बिल्कुल स्वस्थ। मुझसे पहले के रिटायरी कह गए हैं कि सरकारी पद पर होने वाले का और कुछ मजबूत हो या न, पर पाचन तंत्र मजबूत होना चाहिए ताकि उसे कुछ भी खाकर बदहजमी न हो।

मित्रो! सर्दियों में नहाएं रोज वे जिन्हें कठोर मेहनत भरा काम करना है। धूल-मिट्टी में काम करना है। मुझे तो केवल ऑफिस में जा कुर्सी तोड़नी है। सुबह बारह बजे गिरते-पड़ते ऑफिस पहुंचे, दो चार बार चाय-शाय पी, कुर्सी पर कभी इस ओर पलटे तो कभी उस ओर। जब कुर्सी पर दाएं-बाएं पलटते-पलटते थक गए तो आसपास के कमरे में आज की ताजा खबरें सुनने को हो लिए। कोई काम करवाने आ ही गया तो उसे लताड़ हड़का दिया। ऐसे ही लंच हो गया। लंच में घर से लाया लजीज लंच रगड़ा और फिर धूप सेंकने हो लिए अपने कमरे से बाहर।

बंधुओ! अजीब डायरेक्शन है मेरी कुर्सी की भी! सर्दियों में अपनी कुर्सी के पास धूप पांच बजे के बाद आती है। अब हीटर भी कितना सेंका जाए? मोटी चमड़ी में खुश्की के साथ खुजली भी होने लग जाती है। और जब गर्मियों में धूप की कतई जरूरत नहीं होती तो मेरे ऑफिस में आने से पहले ही मेरी कुर्सी हीटर की तरह गर्म हुई रहती है। कई बार सूरज से कहा भी कि यार! ऑफिस का सीनियर मोस्ट बंदा हूं। कम से कम मेरी कुर्सी पर धूप का ख्याल तो रख ले, पर वह भी मेरी तरह इस कान से सुनता है उस कान से निकाल देता है। कोई बात नहीं! जिस दिन मेरे गेड़े में आएगा, उस दिन उसे भी देख लूंगा।

आपकी राय

हिंदी का सशक्तीकरण

हिंदी को वैश्विक समुदाय की प्रभावी भाषा बनाने के लिए इसे ज्ञान-विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और व्यापार की भाषा के रूप में सशक्त करना आवश्यक है। जब हिंदी उच्च शिक्षा, शोध और डिजिटल अर्थव्यवस्था में समाहित होगी, तभी इसकी विश्वस्तरीय स्वीकार्यता बढ़ेगी। प्रवासी भारतीयों को सांस्कृतिक राजदूत बनाकर विदेशों में हिंदी शिक्षण और मीडिया को सक्रिय करना होगा। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर हिंदी के आधिकारिक प्रयोग के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने होंगे।

अमृतलाल मारू, इन्दौर, म.प्र.

संकल्प की परंपरा

नए साल में संकल्प लेने की परंपरा है, जो किसी व्यक्ति, समाज, देश या संगठन द्वारा लिए जा सकते हैं। हालांकि, संकल्प किसी भी समय लिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ संकल्पों को पूरा करने में समय लगता है, इसलिए हम नए साल के पहले दिन इन्हें लेते हैं। यह एक औपचारिकता बन चुका है, लेकिन अगर दृढ़ निश्चय हो तो कुछ विशेष संकल्प पूरे किए जा सकते हैं। संकल्प तभी मायने रखते हैं जब हम उन्हें पूरा करें।

शामलाल कौशल, रोहतक

प्रताड़ित अल्पसंख्यक

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति हिंसा, अत्याचार और हत्या अत्यंत दुखदाई और निंदनीय है। हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर बांग्लादेशी शायद भारत द्वारा उनकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देने पर ग़ुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वर्तमान में बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। भारत सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

आस्था का प्रतीक

गुजरात का सोमनाथ मंदिर एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना है, जिसके ऐतिहासिक महत्व और पुनर्निर्माण को प्रधानमंत्री ने प्रमुखता से पेश किया है। सोमनाथ मंदिर 17 बार नष्ट होने के बावजूद भारत की अटूट सभ्यता और पुनर्निर्माण की शक्ति का प्रतीक बना है। प्रधानमंत्री 11 जनवरी को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशनार्थ लेख इस ईमेल पर भेजें :-
dtmagzine@tribunemail.com

प्रेरणा

अज्ञान को कर्म में बदलते हुए देखने से ज्यादा बुरा कुछ नहीं है।- **गेटे,** लेखक

संपादकीय

टैरिफ के बावजूद अच्छी विकास दर सुखद है

चालू वित्त वर्ष में जीडीपी विकास दर (वास्तविक) 7.4% रहने की संभावना एक उत्साह पैदा करती है कि ट्रम्प टैरिफ के बावजूद भारत आगे बढ़ रहा है। बजट के चंद दिनों पहले सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रथम एडवांस आकलन के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेवा क्षेत्र ने बेहतर परफॉर्मेंस किया। ये अलग बात है कि बजट-सत्र के दौरान ही नए आधार वर्ष (2022-23) पर आधारित आंकड़े की सीरीज शुरू होगी। अभी तक 2011-12 को आधार-वर्ष मानकर आंकड़े जारी किए जाते थे। ताजा एडवांस आकलन के अनुसार नॉमिनल जीडीपी विकास दर पिछले पांच वर्षों में सबसे कम (8%) है। नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन को घटाकर वास्तविक जीडीपी निकाली जाती है। नॉमिनल जीडीपी के अन्य वर्षों से कम होने के पीछे मूल कारण महंगाई का कम होना भी है। बहरहाल, भारतीय इकॉनोमी में घरेलू उपभोग का अंश ज्यादा होने के कारण अर्थव्यवस्था में लचीलापन भी ज्यादा होता है। साथ ही लम्बे समय से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दबा हुआ था, जिसमें अब कुछ गति आई है। फिर भी उम्मीद की किरण है सेवा क्षेत्र, खासकर टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर नई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत के प्रति रुझान। इससे निवेश आएगा, उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार बढ़ेंगे और जीडीपी विस्तार का चेन-रिएक्शन शुरू हो सकेगा।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

कुछ ऐसा करें कि सपने अशांति का कारण न बनें

नींद भी निराली होती है। कम आए तो बीमारी, ज्यादा आए तो भी बीमारी। नींद का संबंध सपनों से भी है। नींद के सपने बीमारी के लक्षण हैं। जागते हुए सपने देखना संकल्प का प्रतीक है। वैज्ञानिक कहते हैं जब हम सपने देखते हैं तो हमारी आंखों की पुतलियां इधर-उधर घूमती हैं। इसे आरईएम यानी रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी बताते हैं कि पुतलियां यदि भीतर ही भीतर घूमें तो सपने आते हैं या सपनों में ऐसा होता है। अब चूंकि अधपकी नींद सपनों की संतानें हैं और नई-नई बीमारियों को जन्म देने वाली हैं, इसलिए दिन में एक प्रयोग किया जा सकता है। कमर सीधी रखें, आंखें बंद करें, अपनी पुतलियों को भीतर ही भीतर अपने मस्तिष्क में देखें- जैसे छतरी खोलकर भीतर से झांका जा रहा है। उसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं, जहां देखना है। अगर दिन में दो-तीन बार इसका अभ्यास करें तो पुतलियां घूमेंगी नहीं, सपने नहीं आएंगे। या सपनों में पुतलियां नहीं घूमेंगी तो सपने अशांति का कारण नहीं बनेंगे।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

दूरदृष्टि • आप दखल देकर मुंह नहीं फेर सकते

वेनेजुएला में व्यवस्था कायम करने का जिम्मा भी ट्रम्प का

अमेरिका

थॉमस एल. फ्रीडमैन

तीन बार पुलित्ज़र अवॉर्ड विजेता एवं 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' में स्तंभकार

वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद आगे क्या होगा, इस बारे में स्पष्ट जवाब देना कठिन है। लेकिन दुनिया के अन्य क्षेत्रों में अमेरिका के ऐसे हस्तक्षेपों को देखते हुए मेरे मन में कई सवाल हैं। मसलन, 19 मार्च 2011 को नाटो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने लीबिया के गृहयुद्ध में सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया था। इसका अंत गद्दाफी की सरकार के पतन के रूप में हुआ और उसी वर्ष अक्टूबर में विपक्षी बलों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तब मैंने लिखा था कि ओबामा ने लीबिया के नेता को हटाने की प्रक्रिया को तो संभव बना दिया, पर उसके बाद हालात को संभालने के लिए जमीन पर हमारे पास कोई फोर्स नहीं थी। सवाल था कि गद्दाफी के बाद वहां अगले दौर की कमान किसके हाथों में होगी?

विद्रोहियों को केवल हवाई समर्थन देकर हमने लीबिया की जमीनी हकीकत को स्थानीय प्रतिस्पर्धी ताकतों, कबीलों और मिलिशियाओं के हवाले कर दिया। 15 साल बाद भी लीबिया में व्यवस्था कायम नहीं हो सकी है। मैं वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कब्जे की वकालत नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह सवाल जरूर उठा रहा हूं कि जमीन पर सैन्य मौजूदगी के बिना हम वहां के घटनाक्रमों और रुझानों को इस तरह से कैसे दिशा दे सकते हैं कि वे हमारे हितों और वेनेजुएला की जनता दोनों के लिए अच्छे हों? ट्रम्प की 'झपटो और निकलो' वाली रणनीति बहुत दूरगामी नहीं हो सकती।

एक प्रेस वार्ता में ट्रम्प ने कहा कि हम यह जोखिम नहीं ले सकते कि जरूरत पड़ने पर हम वेनेजुएला में अपने फौजी भी भेज सकते हैं। तो क्या अमेरिका इराक और अफगानिस्तान के बाद अब तक की सबसे बड़ी 'नेशन-बिल्डिंग' परियोजना हाथ में लेने जा रहा है? क्या ट्रम्प को जरा भी अंदाजा है कि यह कितना भयावह और अनिश्चितकालीन काम हो सकता है?

यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि ट्रम्प प्रशासन वेनेजुएला को कैसे चलाने वाला है। क्या मादुरो की सरकार के बचे-खुचे हिस्से के साथ कोई समझौता किया गया है? क्या ट्रम्प मादुरो की शेष टीम के सामने यह अल्टीमेटम रखने वाले हैं कि वे सत्ता छोड़ें, और फिर अमेरिका वहां चुनाव कराएगा? इतना तो साफ है कि वेनेजुएला को चलाना एक बहुत बड़ा काम होगा और ट्रम्प समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं होगा।

कई वेनेजुएला-वासियों ने मादुरो के पतन का जश्न मनाया है, लेकिन वहां अब भी मादुरो के सशस्त्र समर्थकों का मजबूत नेटवर्क मौजूद है। इन्हें गुंडों और नशीले पदार्थों के तस्करों का गिरोह ही कहा जा सकता है। वे हिंसक दमन और वोट चोरी के जरिए वेनेजुएला को नियंत्रित करते रहे हैं। ऐसे में मादुरो समर्थकों और विरोधी खेमों के बीच शक्ति-संतुलन क्या होगा?

कुछ देश ऐसे होते हैं, जहां नेतृत्व बदल देने पर व्यवस्था ढह जाती है। यमन तो मजबूत पड़ोसियों और समुद्र से घिरा होने के कारण खुद को सम्भाल पाया, लेकिन सीरिया जैसे देश बशर अल-असद के पतन के बाद बिखराव की स्थिति में आ गए हैं और उन्होंने अपने शरणार्थियों, नशीले पदार्थों और अस्थिरता को आसपास के देशों तक फैला दिया है।

यूएन के शरणार्थी मामलों के उच्चायुक्त के अनुसार पहले ही लगभग 80 लाख वेनेजुएला-वासी अपना देश छोड़ चुके हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक है, जिसमें से अधिकांश का प्रवाह अन्य लैटिन अमेरिकी व कैरेबियाई देशों की ओर हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है।

वैसे इस समय जिनपिंग, पुतिन, जेलेंस्की और

जिसे आप तोड़ते हैं, उसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी आप ही की होती है। ट्रम्प ने वेनेजुएला की मौजूदा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। अब वहां पर आगे क्या होता है, इसकी जिम्मेदारी भी ट्रम्प के ही कंधों पर है।

लाई चिंग-ते क्या सोच रहे होंगे? अमेरिका ने मादुरो पर मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप लगाया और फिर उन्हें पकड़ लाया। लेकिन जब नाटो ने लीबिया में गद्दाफी को सत्ता से हटाया था तो उसने पहले यूएन का प्रस्ताव हासिल किया था। चीन इस अमेरिकी कार्रवाई को एक और ऐसे उदाहरण के रूप में देख सकता है, जो उसे अपनी सुविधा से ताइवान को हड़पने का बहाना प्रदान करे। चीन के लिए यह भी मुफीद है कि अमेरिका अब पहले की तुलना में कहीं अधिक अपने ही गोलार्ध में उलझा रहेगा और चीन को रोकने के लिए उसके पास कम समय और ऊर्जा बचेगी। पुतिन भी ठीक यही सोच रहे होंगे। यह स्थिति तब है, जब यूक्रेन और गाजा में शांति प्रक्रियाएं अभी भी अधूरी हैं।

जब अमेरिका ने इराक पर धावा बोला था, तब मैंने लिखा था कि जिसे आप तोड़ते हैं, उसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी आप ही की होती है। आज फिर वही बात दोहराने का समय आ गया है। ट्रम्प ने वेनेजुएला की मौजूदा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। अब वहां पर आगे क्या होता है, इसकी जिम्मेदारी भी ट्रम्प के ही कंधों पर है। **(द न्यूयॉर्क टाइम्स से)**

मुद्दा • अदालतों के दरवाजे न्याय के लिए हमेशा खुले हों

लंबी बहसों और पेचीदा फैसलों से मुकदमों का बोझ बढ़ता है

न्यायिक

विराग गुप्ता

सुप्रीम कोर्ट के वकील

viragguptа@hotmail.com

नए साल पर सुधारों का पहला ताकतवर संदेश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह मेडिकल इमरजेंसी से मरीजों को इलाज की सुविधा होती है, उसी तरह अदालतों के दरवाजे भी न्याय के लिए हमेशा खुले रहने चाहिए।

ताकतवर लोग महंगे और बड़े वकीलों के दम पर प्रतिकूल मामलों में लंबी, जटिल बहस और अनुकूल मामलों में जल्द सुनवाई पर जोर देते हैं। इस मर्ज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश में नियमित मामलों में वकीलों की बहस के लिए समय-सीमा तय करने की बात कही गई है। विधि आयोग ने 2009 में 230वीं रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उसके अनुसार देश में सरकारी कामकाज में गिरावट का असर न्यायपालिका में भी दिखने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने कहा था कि जजों को पूरा समय न्यायिक कार्यों में ही लगाना चाहिए। लेकिन लम्बित मामलों के बढ़ते आंकड़े मर्ज के बदतर होने की गवाही दे रहे हैं। 2009 में 2.74 करोड़ मामले लम्बित थे, जिनकी संख्या अब दोगुनी है।

संसद और विधानसभा में हुल्लड़बाजी हो तो कानून निर्माण की प्रक्रिया कमजोर होती है। नौकरशाही का समय मीटिंग और रिपोर्ट में बीते तो प्रशासन शिथिल होता है। शिक्षकों की ड्यूटी वोटर लिस्ट दुरुस्त करने, मिड-डे मील बनाने और कुत्तों की गणना करने में लग जाए तो बच्चों के शैक्षणिक स्तर पर बुरा असर पड़ता है। पुलिस का समय वीआईपी ड्यूटी, कोर्ट में हाजिरी और आरोप पत्र का पुलिंदा बनाने में नष्ट हो तो अपराध बढ़ने के साथ जांच में देरी होती है। इसी तरह वकीलों की बड़ी बहस और जजों के भारी-भरकम फैसलों से भी मुकदमों का बोझ बढ़ता है। विधि आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोगों की धूल खाती रिपोर्टों पर अमल के बजाय सतही चिंतन और भाषणों के बढ़ते चलन से जनता का सिस्टम पर भरोसा डगमगाता है।

भारत में शिक्षा के साथ कानून निर्माण में भी मैकाले की बड़ी भूमिका थी, जिसकी साम्राज्यवादी विरासत को दुरुस्त करने की बात इन दिनों की जा रही है। विधि आयोग ने मैकाले के कथन को दोहराते हुए कहा था कि अनुशासित और सुनिश्चित परिणामों वाली न्यायिक व्यवस्था से सही और जल्द न्याय मिल सकता है। अमेरिका में प्रत्येक पक्ष के वकील को अधिकतम 30 मिनट सुनवाई का मौका मिलता है। विधि आयोग ने भी बहस के लिए अधिकतम डेढ़ घंटा समय तय करने की अनुशंसा की थी। तीन साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जज संजय किशन कौल ने कहा था कि दुनिया के किसी भी प्रगतिशील देश में वकीलों को असीमित बहस की इजाजत नहीं मिलती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पहल के अनुसार भी नियमित मामलों की सुनवाई के पहले अधिकतम 5 पेज का संक्षिप्त नोट और बहस की समय-सीमा सूचित करना जरूरी है।

किंतु आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई के दौरान जब वकीलों ने बहस की समय-सीमा तय करने की बात की तो 3 जजों की पीठ ने उसे नकार दिया। संवैधानिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सभी जज बराबर हैं लेकिन चीफ जस्टिस का दर्जा अग्रणी है। चीफ जस्टिस कॉलेजियम के साथ मास्टर ऑफ रोस्टर और सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक मुखिया भी माने जाते हैं। इसलिए सर्कुलर के अनुसार न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि बेहतर परंपरा के तौर पर हाईकोर्टों के सभी जजों को भी बहस के लिए समय-सीमा और फैसलों के सीमित पेज की प्रक्रिया पर व्यावहारिक अमल करना चाहिए।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में छोटे निर्णय देने की परम्परा है। जबकि भारत में केशवानंद भारती मामले में 1973 में 700 पेज, 2018 में आधार कानून के मामले में 1448 पेज और 2019 में अयोध्या विवाद में 1045 पेज का फैसला आया था।

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में छोटे और तर्कसंगत फैसले देने की परम्परा है। भारत में केशवानंद भारती मामले में 1973 में 700 पेज, 2018 में आधार कानून के मामले में 1448 पेज और 2019 में अयोध्या विवाद में 1045 पेज का फैसला आया था। आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर मामले में असहमति का ऐतिहासिक फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज एचआर खन्ना ने रिटायरमेंट के बाद कहा था कि जजों को साहित्यिक उपमाओं और लम्बे फैसलों से थीसिस लिखने के बजाय तर्क आधारित कानून सम्मत छोटे फैसले देने चाहिए। सभी अदालतों के जज और वकील, न्यायिक अनुशासन का कड़ाई से पालन करें तो लोगों को जल्द न्याय मिलेगा और मुकदमों के बोझ से देश को मुक्ति मिलेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

ब्रांड से सबक | क्रिसलर, प्रसिद्ध कार ब्रांड

अमेरिका की टॉप-3 ऑटो कंपनियों में थी क्रिसलर 2009 में दिवालिया होने लगी, अब फिर चर्चित ब्रांड

साल 1979, क्रिसलर के एमडी 'ली इयाकोका' ने घोषणा की कि वे अगले एक साल तक वेतन के रूप में केवल एक डॉलर लेंगे। यह वह दौर था जब कंपनी गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही। आखिरकार 2009 में चैप्टर-11 के तहत खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन करना पड़ा। अमेरिका में तत्कालीन ओबामा प्रशासन ने क्रिसलर को बैंकरप्सी प्रोटेक्शन के जरिए रीस्ट्रक्चर करने के लिए आर्थिक मदद दी। कभी अमेरिका की तीन सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल रही। क्रिसलर आखिर इस स्थिति में कैसे पहुंची?

दरअसल वर्षों तक बड़ी एसयूवी और मिनीवैन बेचकर कमाई करने वाली क्रिसलर बदलते वक्त को समझ नहीं पाई। पेट्रोल महंगा हुआ, ग्राहक छोटी गाड़ियों की तरफ मुड़े, लेकिन क्रिसलर इसका विकल्प नहीं दे पाया। 2008 की मंदी ने रही-सही कसर पूरी कर दी। हालांकि 2009 के बाद अमेरिकी सरकार से मिली मदद और रणनीतिक समझौतों ने न केवल इसे उबारा बल्कि फिर से प्रतिष्ठित ब्रांड बनाया। क्रिसलर की बैंकरप्सी से उबरने की यह कहानी सिखाती है कि सही समय पर लिया गया कड़ा फैसला और सही पार्टनरशिप किसी डूबते हुए जहाज को भी किनारे लगा सकती है। आज ब्रांड से सबक में पढ़िए कहानी मशहूर कार ब्रांड क्रिसलर की।

वर्तमान स्थिति

2028 तक पूरी तरह ईवी में बदलना लक्ष्य

क्रिसलर इस समय नीदरलैंड की स्टेलैंटिस एनवी ऑटो कंपनी का हिस्सा है, जो दुनिया की चौथी बड़ी ऑटो मोबाइल कंपनी है। समूह करीब 130 से अधिक देशों में गाड़ियां बेचता है। भारत में बिकने वाला जीप ब्रांड भी इसी का हिस्सा है। 'डेयर फॉरवर्ड 2030' योजना के तहत समूह ईवी पर फोकस कर रहा है। कंपनी ने क्रिसलर ब्रांड को 2028 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा है। समूह 2026 में क्रिसलर की फुल इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने जा रहा है।

सबक क्यों- कंपनी ने रणनीतिक समझौतों और मर्जर से खुद को न केवल दिवालिया होने से बचाया बल्कि स्थापित भी किया।

1.26 लाख यूनिट की बिक्री की क्रिसलर ने 2025 में यूएस मार्केट में।

1 नंबर पर है क्रिसलर का सबसे प्रमुख 'पैसेफिक' मिनीवैन मॉडल अमेरिका में।

100 % ईवी में बदल जाएगी क्रिसलर 2028 तक।

2026 में पूरी तरह इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने जा रही है क्रिसलर।

5 जनवरी 1924 को न्यूयॉर्क सिटी के कमोडोर होटल में क्रिसलर सिक्स का बी-70 मॉडल लॉन्च किया था।

यूं संकट में फंसी क्रिसलर

1. **पुरानी डिजाइन, टेक्नोलॉजी-** क्रिसलर साल 2000 के दौर में एसयूवी और ट्रक जैसे पुराने मॉडल पर टिकी रही जबकि टोयोटा और होंडा अधिक माइलेज वाली कारें ला रही थीं।
2. **अधिक कीमत, कमजोर फीचर-** क्रिसलर की गाड़ियां प्रतिद्वंद्वियों से महंगी थीं, लेकिन क्वालिटी और फीचर्स कम थे। मंदी में लोग सस्ती कारें चुन रहे थे।
3. **मैनेजमेंट और वित्तीय गड़बड़ियां :** जर्मन कंपनी डेमलर के साथ 1998-2007 के बीच हुआ मर्जर फेल हुआ। इससे तब 3600 करोड़ डॉलर का घाटा हुआ। वहीं 2007 में प्राइवेट इक्विटी फर्म सेर्बरस के अधिग्रहण में कर्ज और बढ़ गया।
4. **बढ़ती प्रतिस्पर्धा-** जापानी कंपनियों जैसे टोयोटा ने अमेरिकी बाजार में 20% शेयर कब्जा लिया, जबकि क्रिसलर की हिस्सेदारी 2000-09 में 15% से 11% गिरी। टोयोटा हाइब्रिड और सेडान में आगे थी।

इस तरह की वापसी

1. **फिएट से स्ट्रैटेजिक एलायंस-** 2009 में बैंकरप्सी के बाद फिएट ने 20% स्टेक लिया, जो बाद में 58% हुआ। फिएट की स्मॉल कार टेक्नोलॉजी से क्रिसलर की कारों का माइलेज बढ़ा।
2. **सरकारी बेलआउट और रीस्ट्रक्चरिंग-** अमेरिकी सरकार ने 1250 करोड़ डॉलर लोन दिया। दिवालिया होने से बची। कर्ज घटाया, घाटे वाले प्लांट बंद किए।
3. **प्रोडक्ट इनोवेशन-** बैंकरप्सी से उबरने के बाद क्रिसलर ने जीप और RAM ब्रांड पर फोकस किया। नई एसयूवी जैसे जीप चेरोकी लॉन्च की। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और डिजाइन अपडेट की। 2009 से 2014 के बीच 24 नए मॉडल लॉन्च किए।
4. **रणनीति बदली, ब्रांड रिवाइवल-** फिएट के साथ ग्लोबल एक्सपेंशन किया। यूरोपियन मार्केट में एंट्री की। 2014 तक अमेरिका में मार्केट शेयर 12 प्रतिशत तक पहुंच गया।

कंपनी के संस्थापक ने ब्रांड को दिया अपना नाम

शुरुआत : रेलवे इंजीनियर के बेटे का 'इंजीनियरिंग चमत्कार'

क्रिसलर की स्थापना 6 जून 1925 को वाल्टर पी. क्रिसलर ने की, जो रेलवे इंजीनियर के बेटे थे। 1920 के दशक में वाल्टर ने घाटे में चल रही मैक्सवेल मोटर कंपनी को उबारने का काम शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने 1924 में पहली कार 'क्रिसलर सिक्स' लॉन्च की। कार बेहद सफल रही। इसके बाद मैक्सवेल को बंद कर 'क्रिसलर कॉर्पोरेशन' की स्थापना की।

गिरावट : गलत अधिग्रहण और मंदी के कारण डूबी थी कंपनी

गिरावट का सबसे सटीक दौर 2007 से 2009 के बीच रहा। सबसे बड़ा कारण 'सेर्बरस कैपिटल मैनेजमेंट' कंपनी द्वारा अधिग्रहण और उसके बाद वैश्विक मंदी रहा। वहीं क्रिसलर ने सेडान से कॉम्पैक्ट कारों की ओर बढ़ते रुझानों को भांपने में देरी की। ऊंची कीमतें और पुराने ढर्रे के डिजाइनों ने फोर्ड और जीएम की तुलना में इसे सबसे कमजोर कड़ी बना दिया था।

ऐसे पड़ा नाम : क्रिसलर नाम कंपनी के संस्थापक वाल्टर पी. क्रिसलर के नाम पर रखा गया था। वाल्टर रेलवे से ऑटो इंडस्ट्री में आए थे।

सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी : इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी अमेरिका में जीएम और फोर्ड हैं। वहीं ग्लोबली, टोयोटा, होंडा और फॉक्सवैगन चुनौती बन रहे हैं।

पीपुल भास्कर | निकोलस मादुरो | वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति

'मजदूर राष्ट्रपति' कहे जाते थे मादुरो, युवाओं से टिकटॉक पर जुड़ते हैं, रॉक म्यूजिक के शौकीन

साल 2013, वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की मौत के बाद चुनाव हो रहे थे। चावेज के सबसे चहेतों में शामिल निकोलस मादुरो मैदान में थे। उन्होंने एक रैली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 'मैं चावेज नहीं हूं, लेकिन उनका बेटा हूं'। उनके इस एक वाक्य ने लोगों को आकर्षित कर लिया। नतीजा मादुरो की जीत के रूप में आया।

एक मामूली बस ड्राइवर और यूनियन लीडर देश का राष्ट्रपति बन गया। मादुरो का यह सफर लैटिन अमेरिकी राजनीति में 'असंभव को संभव' करने का उदाहरण माना जाता है। कहा जाता है मादुरो के पास बोलने की ऐसी कला है कि लोग घंटों उनका भाषण सुनते थे। वेनेजुएला में अगर देर रात तक लोग टीवी देख रहे हैं, तो लोग जान जाते थे कि मादुरो बोल रहे होंगे। 'कादेना' के नाम से मशहूर ये लाइव प्रसारण कई बार घंटों तक चलता था।

साल्सा और रॉक संगीत के शौकीन मादुरो किशोरावस्था में 'एनिग्मा' नाम के एक बैंड में बेस गिटार बजाते थे। यही नहीं वे युवावस्था में बेसबॉल के भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहे। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें एक बार मेजर लीग बेसबॉल (एमएलबी) के स्कॉउट ने कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की थी, हालांकि राजनीति में रुचि के कारण उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मादुरो सोशल मीडिया पर भी खूब सक्रिय रहते हैं। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियो शेयर कर युवाओं से जुड़ते हैं। उन तक अपनी बात रखने के लिए इसका खूब इस्तेमाल करते हैं।

चर्चा में क्यों- हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर निकोलस मादुरो को पत्नी सहित गिरफ्तार कर लिया है।

पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ मादुरो। सिलिया को मादुरो का रणनीतिक ब्रेन कहा जाता है। मादुरो की रणनीति वही बनाती हैं।

मादुरो पर 2018 से 2024 के बीच तीन बार जानलेवा हमले की कोशिश हुई। इसमें विस्फोटक लदे ड्रोन से लेकर भाड़े के शूटर तक शामिल थे।

जन्म : 23 नवंबर 1962 (63 वर्ष) काराकास, वेनेजुएला

शिक्षा : हाईस्कूल ड्रॉपआउट।

परिवार : पत्नी- सिलिया फ्लोरेस, बेटा- निकोलस एर्नेस्टो मादुरो

संपत्ति : करीब 17 करोड़ रुपए

(विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार)

परिवार

ट्रेड यूनियन के प्रमुख लीडर थे पिता

मादुरो का जन्म वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हुआ था। पिता निकोलस मादुरो गार्सिया, प्रमुख ट्रेड यूनियन नेता थे, जिससे उन्हें राजनीति विरासत में मिली। मां गृहिणी थीं। कहा जाता है किशोरावस्था में मादुरो पिता के साथ यूनियन बैठकों में जाते थे, जहां सत्ता और शोषण पर बहसें होती थीं। यही अनुभव उनके राजनीतिक झुकाव की नींव बना।

विवाह

पत्नी वकील, नेशनल असेंबली की अध्यक्ष रहीं

मादुरो ने सिलिया फ्लोरेस से 2013 में शादी की। सिलिया एक प्रभावशाली वकील और राजनेता हैं। दोनों की मुलाकात राजनीतिक सक्रियता के दौरान हुई। उन्होंने 1992 के विफल तख्तापलट के बाद ह्यूगो चावेज को जेल से छुड़ाने वाली कानूनी टीम का नेतृत्व किया था। उन्हें वेनेजुएला में 'फर्स्ट कॉम्बैटेंट' यानी 'पहली लड़ाकू' कहा जाता है।

करियर

मजदूर नेता से राष्ट्रपति पद तक पहुंचे

21 साल की उम्र में वे वेनेजुएला के लेफ्ट लीडर रहे जोस विसेंट रेंगल के बॉडीगार्ड बन गए। फिर बस चलाना शुरू कर दिया। बाद में ट्रेड यूनियन लीडर बने। 1999 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने ह्यूगो चावेज उनके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 2000 में मादुरो नेशनल असेंबली के सदस्य बने। 2006 में चावेज ने उन्हें विदेश मंत्री बनाया। 2013 में वे राष्ट्रपति चुने गए।

रोचक : सत्य साईं बाबा की मृत्यु पर वेनेजुएला में घोषित किया था राष्ट्रीय शोक

खास : सत्य साईं बाबा को आध्यात्मिक गुरु मानते थे

- निकोलस मादुरो सत्य साईं बाबा को गुरु मानते थे। 2011 में सत्य साईं बाबा की मृत्यु पर वेनेजुएला में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था।
- मादुरो के कई समर्थक उन्हें 'मजदूर राष्ट्रपति' कहते हैं। इसके पीछे का तर्क उनका बस ड्राइवर और यूनियन लीडर के रूप में किया गया काम तथा लोगों के लिए किया गया संघर्ष है।

उपलब्धि : गरीब तबके के लिए चलाया CLAP कार्यक्रम

- 2016 में मादुरो सरकार ने CLAP कार्यक्रम चलाया। इसमें गरीब परिवारों को सब्सिडी वाला राशन दिया जाता है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों परिवार भूखे रहने से बचे।
- ह्यूगो चावेज द्वारा शुरू किए गए 'बैरो एडेंट्रो' स्वास्थ्य मिशन और ग्रान मिसियोन विविएंडा आवास कार्यक्रम को जोर-शोर से चलाया।

विवाद : विरोधियों को प्रताड़ित करने, चुनावी धांधली के आरोप

- यूनाइटेड नेशंस की कई रिपोर्ट में मादुरो सरकार पर विरोधियों को जेल में डालने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं।
- 2018 और 2024 में वेनेजुएला में हुए चुनावों में इन पर धांधली के आरोप लगे। बड़ी संख्या में देशों ने इन चुनावों को पारदर्शी और निष्पक्ष मानने से इनकार कर दिया।

दैनिक सवेरा टाइम्स

नई दिल्ली, शुक्रवार, 9 जनवरी 2026

दूसरों को जानना बुद्धिमत्ता है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है।
-लाओ त्सू

नशों के विरुद्ध पंजाब सरकार के सक्रिय अभियान का दूसरा चरण

बुधवार 7 जनवरी को पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध चलाए जा रहे अपने अनवरत अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत जालंधर से कर दी। मंच पर उद्घोषक थे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, आप के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। नशों के विरुद्ध अभियान के पहले चरण का यह 312वां दिन था। दूसरे चरण में सरकार ने हर गांव में 'पिंड दे पहरेदार' नामक योजना शुरू करने की घोषणा की और जानकारी दी कि पहरेदारों में डेढ़ लाख स्वयंसेवक भर्ती किए जाएंगे। इनके साथ एप्प के माध्यम से संपर्क रखा जाएगा और नशा बेचने वालों के नाम और गतिविधियों की गुप्त रूप से जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसके साथ एक नंबर भी जारी किया गया है जिस पर मिस्ड काल करने से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ है कि अब मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से भी नशे के विरुद्ध कार्रवाई को और भी सक्रिय किया जाएगा। सरकार ने आंकड़े रिलीज किए हैं। एक मार्च 2025 से 5 जनवरी 2026 तक नशे के खिलाफ अभियान के दौरान 30,104 मामले दर्ज हुए, 43,437 आरोपी गिरफ्तार हुए, 1886 किलोग्राम हैरोइन, 0.266 किलोग्राम स्मैक, 603 किलो अफीम और 27,374 किलोग्राम भुक्की पकड़ी गई।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पंजाब में नशों के खिलाफ कार्रवाई में यह सफलता मिली है कि जितने मामले दर्ज हुए या जितने आरोपी गिरफ्तार हुए, उनमें से 80 प्रतिशत को सजा भी मिली है। आप नेताओं ने कहा कि अब इसे एक जन-आंदोलन बनाया जा रहा है। हमारी कोशिश यह है कि पंजाब से नशे का कलंक पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। इसलिए यह काम केवल छापामारी, बरामदगी, गिरफ्तारी या दंड देने से ही नहीं होगा, लोगों की मानसिक प्रवृत्ति को भी बदलना होगा ताकि वे नशों का दामन छोड़कर जिंदगी का आमना-सामना करें और पंजाब को रंगला पंजाब बनाने में अपना पूरा योगदान दें। बात बहुत अच्छी है।

नशे की जड़ें इतनी गहरी इसलिए हैं क्योंकि नशा तस्करों के लिए यह तेजी से लाभ देने वाला धंधा बन चुका है। इसकी जड़ें पंजाब तक ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई हैं। अब लड़ाई भी स्थानीय से सार्वजनिक स्तर पर लड़नी होगी। नशा माफिया बहुत सशक्त हो चुका है। मादक पदार्थों की अवैध आपूर्ति करने वाले केवल स्थानीय नहीं रहे, उनकी जड़ें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों तक पहुंच चुकी हैं। पंजाब में नशा फैलाने की जुगत में पाकिस्तान के ड्रोन दिन-रात जुटे हुए हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार नशे के विरुद्ध एक जागरूक अभियान चला रही है। सरकार का कदम नशे के मूल पर वार करने का है।

नशे के शिकार युवा वर्ग की सोच बदलकर उन्हें जिंदगी जीने के लिए बेहतर विकल्प देने होंगे जो रोजगार की गरिमा से भरपूर हों। युवा वर्ग के लिए इस समय विदेश पलायन करना भी कठिन हो चुका है, इसलिए बहुत संभव है कि देश में अपना भविष्य न पाकर युवा वर्ग नशा माफिया के चंगुल में फंस जाएं। इस स्थिति में अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान का नशे के खिलाफ अभियान समय की जरूरत है। यह अभियान बेलिहाज चलता रहना चाहिए और बड़े मगरमच्छों की गर्दन यूं ही दबोची जानी चाहिए।

पहले चरण में सरकार ने नशे के खिलाफ लड़ाई में भरपूर सफलता दिखाई है। दूसरे चरण में भी अगर नशे की बीमारी को जड़ से उखाड़ दिया जाए, तो यह दूसरे चरण की सफलता कही जाएगी। इस सफलता के लिए नौजवानों को साथ लाना बहुत जरूरी है। उन्हें नियमित रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध हों, जो उनकी योग्यता के अनुसार हों तो वे सरकार के साथ मिलकर पंजाब को रंगला पंजाब बनाने में कदम से कदम मिलाकर जुटेंगे। **-शीतल विज**

पंजाब में बाढ़ से हुई क्षति का सटीक आकलन

पिछले वर्ष पंजाब में अतिवृष्टि के कारण लोगों को असाधारण बाढ़ का सामना करना पड़ा। न केवल जन-सम्पदा की भारी हानि हुई बल्कि खेतीबाड़ी का भी भारी नुक्सान हुआ था। आम जनजीवन अस्तव्यस्त हुआ, सो अलग। पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से 60 हजार करोड़ रुपये अनुदान की मांग की थी लेकिन मिला 1600 करोड़ रुपया। हालांकि पंजाब सरकार का कहना है कि यह 1600 करोड़ भी अब तक नहीं मिला, केवल घोषणा हुई है। जवाब मिला था कि आप बाढ़ से नुक्सान के सटीक आंकड़े भेजिए तो सटीक मदद दी जा सकती है।

अब पंजाब सरकार ने आईआईटी रुड़की की मदद से तीन महीने से एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट के आधार पर पंजाब सरकार अपने राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में हुए नुक्सान की भरपाई केन्द्र से चाहती है। जुलाई की बाढ़ में पंजाब की 5 लाख एकड़ धान की फसल बर्बाद हुई थी। खेतों में रेत जमा होने के कारण कुछ हिस्सों में अभी तक भी खेती नहीं हो पा रही। अब आंकड़ा यह है कि पंजाब में कुल 11,855.65 करोड़ रुपये का नुक्सान हुअ है। इसके साथ सरकार ने 14 विभागों के नुक्सान का आंकड़ा भी पेश किया है। यह देखा गया कि जिन इलाकों में ऑपरेशन सिंदूर के कारण नुक्सान हुआ, वहां इस बाढ़ ने और भी अधिक हानि पहुंचाई।

इस असाधारण बाढ़ ने बिजली विभाग के ढांचे, जल सिंचाई विभाग के ढांचे और जलापूर्ति एवं सेनीटेशन विभाग के ढांचे को बहुत नुक्सान पहुंचाया। सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों का नुक्सान हुआ। मछलीपालन विभाग, पशुपालन विभाग और वन एवं पर्यावरण का भी नुक्सान हुआ। इनके नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र से सहायता मांगी है। सरकार का अनुमान है कि बिजली विभाग के लिए 37.20 करोड़ रुपये, जलस्त्रोत और सिंचाई विभाग के लिए 2077 करोड़ रुपये, सैनीटेशन के लिए 22 करोड़ रुपये मिलने चाहिए।

राज्य की सड़कें बुरी तरह टूट गईं। सरकार ने इनके लिए 3950 करोड़ रुपये की मांग की है। अस्पतालों और डिस्पैंसरियों के नुक्सान की भरपाई के लिए 1135 करोड़ रुपये और स्कूल-कालेजों के लिए 1137 करोड़ रुपये की मांग की है। अगला बड़ा नुक्सान कृषि और बागवानी का हुआ था जिसकी भरपाई के लिए 3034 करोड़ रुपये मांगे है। पशुपालन, मछलीपालन और वन पर्यावरण विभाग के लिए लगभग 190 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इस सबके लिए सरकारी मशीनरी को चलाने के लिए 274 करोड़ रुपया मांगा गया है। मांगों का विवरण तो सामने आ गया है, असल सवाल यह है कि क्या ये मांगें शत-प्रतिशत पूरी हो जाएंगी या आंशिक तौर पर? **-शीतल विज**

Email: letter2editor@dainiksaveratimes.net

मर्यादाएं
चन्द्र मोहन
संपादकः वीर प्रताप
chander_m@hotmail.com
BLOG: chandermohan.net

भारत और बांग्लादेश: बिगड़ता खेल

हम न दोस्ती कर सके न दुश्मनी, बयान दागने के सिवाय कुछ ठोस नहीं किया

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर विशेष तौर पर ढाका गए जहां उन्होंने बीएनपी के नेता और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को प्रधानमंत्री मोदी का शोक पत्र भी दिया। जिस समय भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत तनाव पूर्ण हैं जयशंकर की ढाका यात्रा को रिश्तों को पटरी पर लाने का प्रयास समझा गया। अपने दो पड़ोसियों, चीन और पाकिस्तान, के साथ पहले ही हमारे तनावपूर्ण संबंध हैं। हम बांग्लादेश को भी उस तरफ खिसकने से रोकना चाहते हैं। जयशंकर का कूटनीतिक प्रयास अच्छा था पर कुछ ही दिनों में उस पर पानी फेर दिया गया। मामला क्रिकेट से जुड़ा है। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को शाहरुख खान की केकेआर आईपीएल टीम ने 9.2 करोड़ रुपये में खरीद लिया था। कोई टीम उसी खिलाड़ी को खरीद सकती है जिसे बीसीसीआई ने पूल में रखा हो। स्पष्ट है कि केकेआर ने कोई गलत कार्यवाही नहीं की थी। पर यह चयन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार के बीच किया गया। पिछले 48 घंटों में दो हिंदू, राणा प्रताप और मोनी चक्रवर्ती को वहां मार दिया गया है।

भारत में लोकराय वहां के घटनाक्रम से उद्वेलित है इसीलिए मुस्ताफिजुर रहमान का मामला तूल पकड़ गया। विशेष तौर इसलिए भी क्योंकि टीम के मालिक शाहरुख खान हैं सह-मालिक जूही चावला और उनके पति जय मेहता भी है, पर तथाकथित हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर एसएआरके हैं। एक भाजपा नेता ने तो उन्हें 'गद्दार' तक कहा गया। और भारत सरकार तथा बीसीसीआई दबाव में आ गए। जयशंकर तो संबंध मुरम्मत करने वहां गए थे पर अप्रत्याशित कदम उठाते हुए बीसीसीआई ने केकेआर को आदेश दे दिया कि मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से हटा दिया जाए। खेल में फिर राजनीति घुस गई। बांग्लादेश की मुहम्मद युनस सरकार को भारत विरोधी भावना भड़काने का एक और सुनहरा मौका मिल गया। आईपीएल से अपने खिलाड़ियों को निकालने के साथ ही उन्होंने यह फैसला भी ले लिया गया कि उनकी टीम टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारत खेलने नहीं जाएगी। आईसीसी जिसके अध्यक्ष जय शाह है, से अनुरोध किया गया है कि बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में रखें जाएं क्योंकि भारत में उनके खिलाड़ी असुरक्षित हैं। दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंध भी रुक गए हैं। बांग्लादेश में आईपीएल प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई है।

भारत की विदेश नीति पर कथित हिंदूवादी संगठनों का दबाव हावी रहा। शशि थरूर ने इस कदम को 'बेतुका और शर्मनाक' कहा है। सचमुच कई बार भारत सरकार की विदेश नीति समझ से बाहर हो जाती है। पाकिस्तान के साथ अपने एशिया कप 2025 मैच में भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के क्रिकेट कप्तान से हाथ मिलाने से इंकार कर दिया था। भारत की टीम ने पाकिस्तानी अधिकारी मोहसिन नकवी के हाथ से ट्राफी लेने से भी इंकार कर दिया। इसे पहलगाम में आतंकी घटना के विरोध में किया बताया गया। कप्तान को आदेश भी ऊपर से मिला था। पर हाल की अपनी ढाका यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से आगे बढ़कर हाथ मिलाया। समाचारों के अनुसार हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के स्पीकर को अपना परिचय दिया और अच्छी तरह बातचीत की। सवाल तो यह है कि कौन सा कदम सही था? सूर्य कुमार यादव का हाथ न मिलाना या जयशंकर का हाथ मिलाना? इसी प्रकार यह सवाल भी उठता है कि क्या सही था, जयशंकर का ढाका जाना या मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालना?

कूटनीति लचीली होनी चाहिए पर अस्पष्ट नही। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, यह मानना पड़ेगा कि मुहम्मद यूनुस की सरकार का रवैया भारत विरोधी है। वह खुद निर्वाचित भी नहीं हैं पर किसी तरह से सत्ता पर काबिज हैं। अपने इतिहास को नकारते हुए वह पाकिस्तान के साथ संबंध घनिष्ठ बनाने में लगे हैं। पाकिस्तान के साथ सैन्य गठबंधन की बात चल रही है। पाकिस्तान के सैनिक और आईएसआई के अधिकारी बार-बार ढाका का दौरा कर रहे है। चीन-पाकिस्तान-बांग्लादेश का भारत विरोधी गुट उभर रहा है। जब तक शेख हसीना वहां सत्ता में थीं, भारत विरोधी तत्वों को उन्होंने नियंत्रण में रखा था। यूनुस उन्हें बेलगाम कर रहे हैं। हमारी भी गलती रही कि हम शेख हसीना के भरोसे रहे और बांग्लादेश के बाकी राजनीतिक ताकतों से संपर्क कम रहा। एक ही टोकरी में सारे अंडे डाल दिए। अब जरूर बीएनपी से रिश्ते बेहतर करने के लिए जयशंकर ढाका गए है। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के अमीर ने भी बताया है कि भारत के राजदूत उनसे मिले थे।

अगले महीने बांग्लादेश के चुनाव हैं। हैरानी है कि वह राजनीतिक दल जिसने उनकी आजादी की लड़ाई लड़ी थी, शेख हसीना की अवामी लीग, पर पाबंदी लगा दी गई है। हसीना बहुत लोकतांत्रिक शासक नहीं थीं। उन्होंने भी अपने विरोधियों को कुचल दिया था पर उनके समय बांग्लादेश ने प्रगति बहुत की थी। भारत के साथ 2009 और 2024 के बीच व्यापार में 600% की वृद्धि हुई थी। 2023 में उस देश

ने 6.1 % की दर से तरक्की की थी जो पाकिस्तान से दोगुनी है। पिछले साल यह गिर कर 3% के लगभग रह गई थी। जुलाई और दिसम्बर 2024 के बीच बांग्लादेश में 21 लाख रोजगार कम हुए थे। सड़क पर असंतोष को संभालने में असफल युनूस सरकार उसका मुंह भारत की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। जब से स्टूडेंट लीडर ओसमान हादी की हत्या हुई है, भारत विरोध और भड़क गया है। वहां की सरकार कह रही है कि हत्यारे भारत भाग गए हैं।

वहां का भारत विरोध हमें समझ नहीं आता। आखिर उनकी आजादी की लड़ाई में हमने भी खून बहाया है। उनकी तरक्की में हमारा बड़ा योगदान है। पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव ने लिखा है,'वह राष्ट्र जो नरसंहार के खिलाफ संघर्ष में पैदा हुआ था अब सड़क हिंसा को सामान्य बना रहा है और अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा पर खामोश है...सड़कों पर अस्थिरता, भय और खून है'। अनुमान है कि शेख हसीना के निर्वासन के बाद हिंदुओं पर दो हजार से अधिक हमले हो चुके हैं। देश के विभाजन के समय हिंदुओं की वहां जनसंख्या 28% के आसपास थी जो कम होकर 2022 की जनगणना के अनुसार, 7.95% रह गई थी। अब तो यह और भी कम रह गई होगी। वहां भी हम पाकिस्तान की तरह नस्ली सफाई देख रहे हैं। और भारत बेबस है।

विलियम वॉन शेंडल ने बांग्लादेश के इतिहास पर लिखी किताब में लिखा है, 'भारत में यह आम धारणा है कि बांग्लादेश ने स्वतंत्रता संग्राम में भारत के योगदान के प्रति पर्याप्त कृतज्ञता नहीं दिखाई वहीं बांग्लादेश में यह धारणा है कि भारत ने केवल रणनीतिक हितों के लिए दखल दिया'। परिणाम है कि दोनों तरफ अविश्वास चरम पर है। ढाका के अखबार डेली स्टार ने लिखा है, 'अब आपसी अविश्वास का शून्य पैदा हो गया है। बांग्लादेश समझता है कि नई दिल्ली साजिश करने वाले भगौड़ों को पनाह दे रही है जबकि भारत समझता है कि बांग्लादेश बहुसंख्यकों की अराजकता की तरफ फिसल रहा है'। यह सही है कि वह देश अराजकता की तरफ फिसल रहा है। डेली स्टार का अपना दफ्तर दंगाईयों ने जला दिया था। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे अराजक तत्व और दुःसाहसी बन जाएंगे। बांग्लादेश दोराहे पर खड़ा है। इस बात की संभावना बहुत कम नजर आती है कि चुनाव के बाद बांग्लादेश एक शांत लोकतांत्रिक देश की तरह उभरेगा। उल्टा नफरत, हिंसा और क्रोध से भरे इस देश को संभालना बहुत मुश्किल होगा। विभिन्न अंतराष्ट्रीय ताकतों की स्पर्धा स्थिति को और जटिल बना देगी।

उस देश का दुर्भाग्य है कि इस निर्णायक क्षण में बिना चुनाव लड़े मोहम्मद यूनुस शासक हैं। यूनुस भारत विरोधी कठपुतली हैं। उनके समय हालत और बिगड़े हैं। बांग्लादेशी वैबसाइट काउंटर पॉयंट में जफर सोभान लिखते हैं, 'सीधी सी बात है कि आज अल्पसंख्यक पिछली सरकार की तुलना में बहुत कम सुरक्षित हैं...धार्मिक असहिष्णुता में भारी वृद्धि हुई है। इसका सामना करने का इस सरकार ने बहुत कम प्रयास किया है'। और भारत यह सब देखता रहा। हम न दोस्ती कर सके न दुश्मनी। बयान दागने के सिवाय कुछ ठोस नहीं किया। उन्हें चीन और पाकिस्तान के साथ गठबंधन में जाने से भी हम रोक नहीं सके। पिछले साल अपनी चीन की यात्रा के दौरान यूनुस ने यह विवादास्पद बयान दिया कि 'उत्तर पूर्व के भारत के सात प्रांत घिरे हुए हैं। उनका समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। केवल हम बांग्लादेशी समुद्र के संरक्षक हैं। इससे कई सम्भावना निकलती है। यहां चीन की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है'। यह एक अत्यंत शरारती बयान है। चीन जाकर हमारे सात प्रांतों की बात करने की जरूरत क्या थी? फिर चीन को वहां पसारने का निमंत्रण भी दे दिया। उनके कुछ सलाहकारों ने तो 'ग्रेटर बांग्लादेश' के सपने देखना शुरू कर दिया। एक ने तो कह दिया कि वह हमारे उत्तर पूर्व पर कब्जा कर सकते हैं।

सवाल तो यह है कि इनकी ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत कैसे हो गई? बांग्लादेश को हमने तीन तरफ से घेरा हुआ है, केवल समुद्र रह जाता है। हम खुद को सुपर पावर समझते हैं। हम जब चाहें उनको जकड़ सकते हैं। हमें तो उनके समुद्र की अस्थायी नाकेबंदी कर ट्रेलर दिखाना चाहिए था लेकिन हमारी नीति ढीली है। न दोस्त ही बन सके न ही दुश्मनी ही निभाई। ट्रम्प तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बैडरूम से उठा कर ले आए। हमने बड़ा कदम उठाया तो मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया!

मिथ्या चेतना का दर्शनशास्त्र

भारत में 2026 के आरंभ में सार्वजनिक बहस नववर्ष के अनुशासन के साथ शुरू होनी चाहिए। हमें पड़ताल और तीखी आलोचनाओं का भी स्वागत करना चाहिए। लेकिन इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि बहस के साथ जवाबदेही शामिल हो। कुल 1.4 अरब की आबादी वाले गणराज्य को निराशावाद से नहीं सुधारा जा सकता। रोजगार, उत्पादकता, निर्यात और समावेशन सबसे अच्छे समय में भी आसान नहीं होते। प्रगति डिजाइन, क्रियान्वयन, सुधार और परिमापन के नीरस मेल से आती है। नया साल निराशावाद को संशयवाद से अलग करने का भी क्षण है। फ्रेडरिक नीत्शे ने 'बेयांड गुड एंड ईवल' में लिखा हैः 'दार्शनिक को सिर्फ आलोचक या दर्शक होने के बजाय मूल्यों का सर्जक होना चाहिए। उसे तत्वचिंतन जीवन के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके नजरिए से करना चाहिए।' लोकनीति में इसी तरह के दृष्टिकोण की दरकार है। आलोचनाओं का स्वागत है। मगर ये साक्ष्य तथा एक जटिल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र का शासन चलाने की ज्वलंत बाधाओं से आबद्ध होनी चाहिए।

जब संशयवाद एक भंगिमा बन जाए तो यह सुधार संभव बनाने वाली संस्थाओं में विश्वास को खत्म करता है। पिछले वर्षों में टिप्पणी की एक नई विधा सामने आई है। यह संदेह को सुसंस्करण के तौर पर पेश करती है। यह सुधार के कार्य को मजाक में तब्दील कर देती है। यह हर अपूर्ण परिवर्तन को स्थाई नाकामी के सबूत के तौर पर लेती है। यह एक चिरपरिचित सांत्वना पेश करती हैः भारत कदाचित अपने ही नीति-निर्माताओं से अभिशप्त है। इस दृष्टिकोण के अपने नतीजे हैं। यह आंकड़ों और बाजारों में विश्वास को घटाता है। यह उद्यमियों और निवेशकों में नियतिवाद को प्रोत्साहित करता है।

साथ ही यह बाहरी ताकतों को वार्ताओं में भारत को दबाव में लाने के लिए तैयार कथानक भी प्रदान करता है। विशेषज्ञता को तथ्यों के प्रति जवाबदेह बने रहना चाहिए। मजबूत पेशेवर और शैक्षिक पृष्ठभूमि का दंभ भरने वाले कुछ टिप्पणीकारों का इस तरह की भंगिमा का सहारा लेना चिंता की बात है। इनमें से कुछ ऐसे टिप्पणीकारों को मैं जानता हूं जिनकी पहचान और विश्वसनीयता भारत पर आधारित है। लेकिन वे संभवतः ध्यानाकर्षण या अब सरकार का हिस्सा नहीं होने के बावजूद प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए देश के खिलाफ अनाप-शनाप बोल कर अपना कॅरियर बनाने की कोशिश में लगे हैं।

उनका यह आरोप कि भारत के आंकड़े विशिष्ट तौर पर अविश्वसनीय हैं, हमारी विकास की दिशा के साथ मेल नहीं खाते। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत टैक्स संग्रह में जो वृद्धि हुई और इसने अनुपालन की जिस संस्कृति को पैदा किया है वह एक दशक पहले नहीं थी। वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। यानी औसतन प्रति माह 1.8 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का संग्रह किया गया। डिजिटल भुगतान ने वित्तीय प्रदर्शन का एक और निशान छोड़ा है। नवंबर 2025 में यूपीआई के जरिए 26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम के 20 अरब लेन-देन किए गए। ये वृहत और परखे जाने योग्य आंकड़े परिमापन, सत्यापन और तौर-तरीकों में सुधार के लिए संभावना का विस्तार करते हैं।

कल्याण और समावेशन में परिमापित परिणाम इस नियतिवाद की और हवा निकाल देते हैं। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार 2013-14 और 2022-23 के बीच लगभग 24 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए। अब बहुआयामी निर्धनता लगभग 30 प्रतिशत से घट कर तकरीबन 11 प्रतिशत रह गई है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) से डिलीवरी दुरुस्त हुई है। वर्ष 2025 में 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हुआ। डीबीटी काल में धन के अपव्यय में कमी के जरिए 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की बचत हुई। वित्तीय समावेशन 56 करोड़ से ज्यादा जन धन खातों के साथ अब सार्वजनिक अवसंरचना बन गया है। वित्तीय अनुशासन में सुधार के प्रभाव अब दिखाई देने लगे हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैरनिष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) 2018 में 11.2 प्रतिशत से घट कर 2025 में 2.1 प्रतिशत रह गई है। यह सिर्फ खयाली पुलाव बनाने से नहीं हुआ।

यह बैलेंस शीट्स की लगातार सफाई, सख्त निगरानी और एक ऐसे तंत्र को प्रतिबिंबित करता है जिसने सदाबहार ऋण और गुप्त हानियों की गुंजाइश को समय के साथ घटाया है। जब आलोचक कहते हैं कि शासन सुधार नहीं कर सकता तो यह आडंबरहीन कायाकल्प उनके लिए पहला जवाब है। भारत बड़े पैमाने पर निर्माण नहीं कर सकता यह आरोप लगाने वाले मैन्युफैक्चरिंग परिवेश में हुए बदलावों को नजरअंदाज करते हैं। उत्पादन-से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) कार्यक्रम के तहत, 14 क्षेत्रों में 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश हुआ है जिससे 18 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का अतिरिक्त उत्पादन और बिक्री हुई और 12 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। इलैक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र इसका सबसे सटीक उदाहरण हैः साल 2024-25 में इलैक्ट्रॉनिक्स का कुल उत्पादन 11 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। इसमें अकेले मोबाइल फोन का उत्पादन 5.5 लाख करोड़ रुपये रहा और मोबाइल का निर्यात लगभग 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। ये दुनिया के सबसे कठिन क्षेत्र के बाजार की परीक्षा है जिसमें भारत सफल रहा है। व्यापार में आपकी पकड़ बेहतर प्रदर्शन और निरंतर टिके रहने से बनती है, न कि केवल निराशा जताने से।

साल 2024-25 में सामान और सेवाओं का कुल निर्यात 825 अरब अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। टैरिफ और संरक्षणवादी प्रतिक्रियाओं की इस दुनिया में साझेदार आपकी क्षमता के आधार पर फैसला करते हैं। भारत की स्थिति तब और मजबूत होती है जब दुनिया उसे एक ऐसे बाजार के रूप में देखती है जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है और खरीदता भी है और अब देश जरूरी क्षेत्रों में भरोसेमंद तरीके से अलग-अलग तरह की आपूर्ति कर सकता है। घरेलू सुधार और बाहरी दुनिया से जुड़ाव मिलकर भारत को मजबूत बनाते हैं और यही मजबूती हमें व्यापार के क्षेत्र में और मजबूत बनाती है। किसी भी देश की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति केवल एक योजना या एक मंत्रालय से नहीं आती, बल्कि यह बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक सुधारों के मिले जुले प्रभाव का परिणाम होती है।

भारत में यह सुधार औद्योगिक गलियारों, मालगाड़ियों की बेहतर कनैक्टिविटी, बंदरगाहों के बेहतर जुड़ाव और एक साथ काम करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिससे समय की बचत होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी बाधाएं खत्म हो गई हैं बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अब व्यवस्था बनाने, प्रक्रियाओं को आसान बनाने और बड़े पैमाने पर परिणाम देने की अपनी क्षमता को साबित किया है। सही तरीके से काम करने से उत्पादकता हफ्तों में नहीं बढ़ती बल्कि इसमें कई वर्ष लग जाते हैं। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में कमियां गिनाना और यह मान लेना आसान है कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अब नीति का रुख बदल गया है। अब सरकार का ध्यान सीधे तौर पर मदद पहुंचाने और ऐसी संपदा बनाने पर है, जो उत्पादकता और सम्मान दोनों बढ़ाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जल जीवन मिशन है, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 12.5 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल से पानी का कनैक्शन पहुंचाया गया है। इससे न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बल्कि परिवारों पर पानी भरने के बोझ कम हुआ है और समय की बर्बादी भी कम हुई है। विकास के लाभ सब तक पहुंचने की कहानी स्वास्थ्य, आवास और ऊर्जा के क्षेत्र में भी दिखाई देती है। आयुष्मान भारत ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 42 करोड़ से ज्यादा कार्ड जारी किए हैं, जिससे परिवारों को गंभीर बीमारियों के भारी खर्च नहीं करने पर आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ घर बनकर तैयार हो चुके हैं, जिससे परिवारों को न केवल अपनी संपत्ति मिली है बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का एक ठोस आधार भी दिया है। इसी तरह, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनैक्शन दिए गए हैं, जिससे उन घरों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचा है जो कभी धुएं और कठिन परिश्रम के जाल में फंसे थे। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह वह व्यावहारिक आधार है जिस पर लोगों की आकांक्षाएं और उनकी कार्यक्षमता टिकी है।

हरदीप सिंह पुरी
केंद्रीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, भारत सरकार

सबसे ज्यादा निराशा अक्सर राज्यों की स्थिति को लेकर जताई जाती है जैसे कि एक अरब से ज्यादा लोगों के देश को एक ही तरीके से चलाया जा सकता हो। भारत का संघीय ढांचा थोड़ा शोर-शराबे वाला जरूर है, लेकिन यह वक्त के साथ बदलना भी जानता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे कई राज्यों ने यह दिखा दिया है कि बेहतर कानून-व्यवस्था, परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी और अवसंरचना के निर्माण में निरंतर काम से निवेश और बेहतर नौकरियां मिल सकती हैं। केंद्र सरकार ने इस प्रतिस्पर्धी संघवाद को और मजबूत किया है। इसके लिए ऐसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जिनसे राज्य जुड़ सकते हैं, ऐसा फंड बनाया है जो बेहतर काम करने पर इनाम के तौर पर दिया जाता है और सुधारों के आंकड़ों को इतना पारदर्शी बना दिया है कि जनता खुद सरकार के काम का फैसला कर सके।

भारत की प्रगति की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, इस पर हमेशा बहस होती रहेगी। सवाल यह है कि नए साल की शुरुआत में हम किस तरह की बहस चुनते हैं। जब बड़े-बड़े पेशेवर लोग केवल अनुमानों या इशारों को ही 'गहन विश्लेषण' मान लेते हैं, तो वे उन संस्थाओं को कमजोर करते हैं जो सुधारों को मुमकिन बनाती हैं। यहां नीत्शे की बात याद करना जरूरी है-एक गंभीर विचारक ऐसे मूल्य पैदा करता है जो समाज को जीने और बेहतर बनने में मदद करें। भारत ने काम करके दिखाने का कठिन रास्ता चुना है। ये नतीजे ही हैं, जो आंकड़ों में भी दिखते हैं और महसूस भी किए जाते हैं। यह किसी भी तरह की निराशा पर भारी पड़ेंगे और लंबे समय तक बने रहेंगे। साल 2026 में, भारत को ऐसी आलोचना की मांग करनी चाहिए जो नीतियों को बेहतर बनाए, न कि ऐसी टिप्पणियों की जो केवल वाहवाही लूटने के लिए देश के आत्मविश्वास को कमजोर करती हों। यह वह मानक हैं जो देश के भीतर सुधारों, निवेश और लोकतांत्रिक विकल्प की रक्षा करते हैं।

जय सोमनाथ!

भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात का सोमनाथ मंदिर एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके ऐतिहासिक महत्व आस्था एवं पुनर्निर्माण को जनता के सामने समक्ष रखा है। सोमनाथ मंदिर लगातार हमलों के बावजूद भारत की अटूट सभ्यता और पुनर्निर्माण की शक्ति का प्रतीक है।

अगर मंदिर बार-बार उठ सकता है तो हम निश्चित रूप से अपने राष्ट्र की महिमा को बहाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 11 जनवरी 2026 को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं जहां स्वाभिमान पर्व के तहत साल भर के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जो मंदिर की आस्था और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सेलिब्रेट करेंगे। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म का प्रमुख

धरोहर/ वीरेन्द्र कुमार जाटव

तीर्थस्थल रहा है और इसका इतिहास पुनर्निर्माण की गाथा है। प्रचलित किंवदंतियां बताती हैं कि मंदिर को 17 बार नष्ट किया गया लेकिन हर बार यह और मजबूत होकर जीवंत गौरव गाथा का साक्षी बना है। पहले हमले में 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर को लूटा, शिवलिंग को तोड़ा और हजारों भक्तों का कत्लेआम किया फिर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने 1299 में इसे ध्वस्त किया उसके बाद मुजफ्फर शाह महमूद बेगड़ा और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने इसे बार-बार नष्ट करने की कोशिश की लेकिन राजा परमार भोज सोलंकी, भीमदेव, कुमारपाल जैसे राजाओं ने इसे पुनर्निर्मित किया जो भारत के सांस्कृतिक लचीलेपन को दर्शाता है।

स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने इसके पुनर्निर्माण की पहल की और 1951 में मारु-गुर्जर शैली में इसका आधुनिक रूप तैयार हुआ जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने किया हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने इसे हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर विरोध किया लेकिन पटेल की दृढ़ता से यह संभव हुआ आज अरब सागर के किनारे चमकता हुआ सोमनाथ मंदिर भारत की सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री के अनुसार सोमनाथ का जीवित रहना भारत माता के असंख्य बच्चों के अटूट साहस का प्रमाण है। जहां प्रधानमंत्री की 11 जनवरी की यात्रा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी जो मंदिर के पुनर्निर्माण की कहानी को और मजबूत करेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी कि विनाश की शक्ति से बड़ा पुनर्निर्माण का सामर्थ्य है।

कार्टून कोना

विश्वा मित्र

इसरो का ड्रोग पैराशूट, जिसका रेल पटरी पर हुआ सफल ट्रायल

गगनयान मिशन की सुरक्षा के लिए अहम 'ड्रोग पैराशूट' का सफल परीक्षण कर इसरो ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। यह सफलता देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन को भरोसेमंद और सुरक्षित बनाने की दिशा में निर्णायक कदम बताया जा रहा है। 18-19 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ में ये परीक्षण टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी यानी टीबीआरएल की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज (आरटीआरएस) पर किया गया। गगनयान क्रू मॉड्यूल विकास के लिए ड्रोग पैराशूट का यह क्वालिफिकेशन टैस्ट है। यह परीक्षण गगनयान क्रू मॉड्यूल के डिसेलेरेशन सिस्टम यानी गति को कम करने वाले सिस्टम को विकसित करने के लिए किए गए।

गगनयान क्रू मॉड्यूल में 4 तरह के कुल 10 पैराशूट शामिल हैं। जानकारी के अनुसार इसका मकसद मुश्किल परिस्थियों में भी ड्रॉग पैराशूट की विश्वसनीयता बनी रहे और सफलतापूर्वक क्रू मेंबर्स टचलैंडिंग कर सकें, इसके लिए की गई है। इस दौरान ये भी सामने आया कि उड़ान की स्थितियों में बदलाव के बावजूद पैराशूट मजबूत और सक्षम था। इसमें डीआरडीओ, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र और एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमैंट एस्टेब्लिशमैंट ने अहम योगदान दिया है। भारतीय अंतरिक्ष एजैंसी 2026 में बिना क्रू वाले गगनयान मिशन के पहले लॉन्च की तैयारी कर रही है। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि भारत मानव स्पेस मिशन की दिशा में एक कदम और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इसरो ने 18-19 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ में टीबीआरएल की आरटीआरएस फैसिलिटी में गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रोग पैराशूट डिप्लॉयमैंट क्वालिफिकेशन टैस्ट सफलतापूर्वक पूरे किए है। उन्होंने कहा कि इन टैस्टों ने अलग-अलग फ्लाइट कंडीशंस में ड्रोग पैराशूट के परफॉर्मेंस और भरोसेमंद होने की पुष्टि करता है।

यह भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए पैराशूट सिस्टम को क्वालिफाई करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ड्रोग पैराशूट छोटे कॉनिकल रिबन तरह की पैराशूट होती है, जिनका व्यास 5.8 मीटर होता है। ये क्रू मॉड्यूल

तकनीक/ रामस्वरूप रावतसरे

के पृथ्वी पर उतरने से पहले काम करने वाले पैराशूटों में से है। इन्हें पायरो-आधारित उपकरणों (मोर्टार) के भीतर पैक किया जाता है, जो कमांड मिलने पर इन्हें बाहर निकालते हैं। ड्रोग पैराशूट अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसकी गति को कम करता है और उसे स्थिर करता है, ताकि बाद में मेन पैराशूट पूरी तरह सुरक्षित खुल सके और अंतरिक्ष यान की गति को और कम किया जा सके। ये प्रक्रिया अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी है। किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए ये प्रक्रिया सबसे जटिल मानी जाती है। गगनयान क्रू मॉड्यूल की डिसेलेरेशन सिस्टम में चार अलग-अलग तरह के कुल 10 पैराशूट हैं। शुरुआत दो 'एपेक्स कवर सेपरेशन' पैराशूट से होती है। ये सबसे पहले पैराशूट कम्पार्टमैंट के सुरक्षा कवच को अलग करते हैं। इसके बाद दो ड्रोग पैराशूट आते हैं जो घूमते हुए मॉड्यूल को स्थिर करने और उसकी स्पीड को सुरक्षित लेवल तक कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

एक बार जब ड्रोग अपना काम पूरा कर लेते हैं, तो सीक्वेंस में तीन पायलट पैराशूट बाहर निकलते हैं। ये पायलट फिर तीन बड़े मेन पैराशूट निकालते हैं, जो क्रू मॉड्यूल की वेलोसिटी को और कम करते हैं ताकि मिशन में सवार एस्ट्रोनॉट्स के लिए सुरक्षित टचडाउन यानी जमीन या समुद्र में उतरना सुनिश्चित किया जा सके। ड्रोग पैराशूट खास तौर पर बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष यान के वायुमंडल में घुसने के तुरंत बाद काम करना होता है। ये बहुत डायनामिक फेज होता है, जहां एयरोडायनामिक लोड और फ्लाइट की स्थिति दोनों में काफी बदलाव होते हैं। जानकारी के अनुसार इस परीक्षण का मकसद बहुत ज्यादा और असामान्य स्थितियों में ड्रोग पैराशूट के परफॉर्मेंस, विश्वसनीयता और मजबूती को अच्छी तरह से वेरिफाई करना था।

आरटीआरएस-आधारित दोनों ट्रायल ने सभी तय लक्ष्यों को पूरा किया। यूं साबित हुआ कि सिस्टम फ्लाइट पैरामीटर में बड़े बदलावों को झेल सकता है और सफलतापूर्वक काम कर सकता है। रेल की पटरियों पर हम अंतरिक्ष की सैर की कल्पना भी नहीं कर सकते लेकिन इसरो ने इसे सच कर दिखाया है। यह सफलता बताती है कि भारत अपने पहले मानव मिशन की दिशा में तकनीकी तौर पर तेजी से बढ़ रहा है। इसरो ने टैस्ट के सफल समापन को गगनयान पैराशूट सिस्टम को मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए क्वालिफाई करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।

दैनिक सवेरा टाइम्स

सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक शीतल कुमार विज के स्वामित्व में, दैनिक सवेरा न्यूज एंड मीडिया नैटवर्क, एस.-9, इंडस्ट्रियल एरिया जालंधर से मुद्रित एवं डी.-55, प्रीत विहार, नई दिल्ली से प्रकाशित किया।

DELHIN/2013/53563

पोस्टल रजि. नं. PB-JL-058/25-27

फोन 0181-2370100, 4625005, 4626006, 4629009

समाचार (फैक्स) 0181-2224455

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा उनसे उत्पन्न समस्त विवाद जालंधर न्यायालय के अधीन होंगे।

"मैं धीमी गति से आगे चलता जरूर हूं, लेकिन कभी पीछे वापस नहीं आता।

–अब्राहिम लिंकन

आधी रात दंगे की साजिश

जनवरी 6–7 की दरमियानी रात, करीब 1.30 बजे, गहरी नींद में सोने का वक्त था, लेकिन राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट में उपद्रव था, पथराव किया जा रहा था, कांच की बोतलों से भी हमले किए गए। एक उन्मादी, मजहबी और जेहादी किस्म की भीड़ थी, जो दंगा फैलाने पर आमादा लग रही थी। सिर्फ एक सफेद झूठ, मस्जिद तोड़ने की अफवाह, ने भीड़ को सड़कों पर उतरने को विवश किया था। एक वीडियो में एक शख्स भड़का–उकसा रहा था–'भाईयो! घरों से बाहर निकलने का वक्त है। अपनी दुकानें बंद करो। रात काली करो! मिलिट्री भी आ गई है। उधर कर्फ्यू लगा रखा है, ताकि मस्जिद को तोड़ा जा सके। देखो! मुसलमानों के क्या हाल किए जा रहे हैं! घरों से निकलो! हमें मस्जिद को बचाना है।' सिर्फ यही नहीं, किसी जलाल इमरान ने बड़े झूठ का वीडियो जारी किया–'मस्जिद तोड़ दी गई। 12 बजे से 3 बजे के बीच मस्जिद तोड़ दी गई।' रिजवान पाशा ने भी सोशल मीडिया पर झूठ बोल कर दंगा भड़काने की साजिश की और मस्जिद को तोड़ने की झूठी खबर फैलाई। दिल्ली पुलिस ने ऐसे करीब 100 वीडियो जारी किए जाने की बात कही है, जिनमें मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई। सर्दी की आधी रात में पत्थर, ईंटें, कांच की बोतलें, कीलें आखिर कहां से आ गईं, यह सवाल एक बार फिर उभरा है। यही दृश्य उन इलाकों में भी सामने आया है, जो मुस्लिम बहुल थे और जहां दंगे जैसी हिंसा हुई थी। दिल्ली दंगे भी इसी पृष्ठभूमि पर भड़के और फैले थे। अब तो राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है। ब्रह्म–सत्य सा यथार्थ यह है कि प्राचीन ''फैज–ए–इलाही'' मस्जिद पूरी तरह महफूज और सुरक्षित है। उसकी 0.195 एकड़ जमीन पूरी तरह वैध है। अलबत्ता उसके आसपास के करीब 36,400 वर्ग फुट के अवैध अतिक्रमण को, 32 बुलडोजरों और 4 क्रेन के जरिए, जरूर ध्वस्त किया गया है। मस्जिद के आसपास मिट्टी–मलबे के ढेर लगे हैं। यह दिल्ली उच्च न्यायालय का 12 नवंबर, 2025 का आदेश था और तीन माह की अवधि में अतिक्रमण ढहाए जाने थे। तुर्कमान गेट मुस्लिम–बहुल, संकरा, घनी आबादी वाला इलाका है, लिहाजा रात के वक्त ऑपरेशन करने का फैसला लिया गया। इलाके के दुकानदारों, ठेले–पटरीवालों से बातचीत कर पुलिस ने उन्हें सचेत और आगाह कर दिया था। बुनियादी मुद्दा अतिक्रमण और मजहब के बीच ऊंची दीवारें खड़ी हैं। वक्फ के खोखले, अवैध, दस्तावेजहीन दावे 'आग में घी' का काम करते हैं। जब अफवाहें फैलाई जा रही थीं और भीड़ सड़क पर उतर आई थी, तब सपा के रामपुर सांसद मोहिबुल्ला नदवी उस इलाके में क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने भी भीड़ को उकसाने का संबोधन दिया था? पुलिस उनसे भी सवाल–जवाब करेगी। बेशक आरोपितों और संदिग्धों की धरपकड़ की गई है, फर्जी वीडियो जारी करने वालों की भी पहचान की जा रही है, लेकिन चिंता यह है कि कट्टरपंथ और जेहादी मानसिकता को कैसे समझाया जाए? आधी रात में लगभग दंगे के हालात बन गए थे। पथराव से अर्द्धसैन्य बल और पुलिस के जवान घायल हुए हैं। वे अस्पताल में उपचाराधीन हैं। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हकीकत यह थी और आज भी है कि प्राचीन मस्जिद को उंगली तक नहीं लगाई गई। वहां से जामा मस्जिद तक के बीच करीब 10–12 छोटी मस्जिदें हैं, उन्हें भी खरोंच तक नहीं आई है। दरअसल राजधानी दिल्ली और देश में अवैध कब्जे और अतिक्रमण शाश्वत हो गए हैं। वे एक विकराल समस्या के तौर पर सामने हैं। भारत में 4 लाख से अधिक मस्जिदें हैं। उनसे अधिक करीब 8 लाख मस्जिदें इंडोनेशिया में ही हैं। यदि देश धर्मनिरपेक्ष न होता, तो क्या इतनी मस्जिदें देश में संभव थीं? वक्फ की बात करें, तो दिल्ली में ही उसकी 1047 संपत्तियां हैं, जिन पर विवाद नहीं है, लेकिन वक्फ राष्ट्रपति भवन परिसर, नए संसद भवन की जमीन, आईजीआई हवाई अड्डे, वायुसेना की जमीन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स आदि की जमीन पर भी दावे ठोंकता रहा है। इसका क्या औचित्य है? सेना और रेलवे की सैंकड़ों एकड़ जमीनों पर अवैध कब्जे हैं, अतिक्रमण किए गए हैं। क्या अदालत, सरकार या पुलिस उन्हें खाली करवा सकते हैं? फिलहाल हम 'न' में जवाब देने को विवश हैं।

विश्व राजनीति की नई पहचान

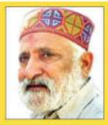

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

वरिष्ठ स्तंभकार

दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में एक नया ध्रुवीकरण हुआ था। उसमें दो नई महाशक्तियां उभरी थीं। रूस और अमेरिका। पूर्वी यूरोप के देश रूस की छाया में दे दिए गए। शेष यूरोप को अमेरिका ने अपनी छाया में ले लिया। जापान को सजा दी गई थी। उसे सेना रखने से रोक दिया गया। जर्मनी को सजा में दो हिस्सों में बांट दिया गया। आगे से लड़ाई न हो, इसकी व्यवस्था के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था बना दी गई। लेकिन मामला नियंत्रण से बाहर न हो जाए, इसके लिए रूस, अमेरिका, फ्रांस व इंग्लैंड इसकी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने। एशिया से चीन को स्थायी सदस्य बनाया गया, क्योंकि चीन ने विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की मदद की थी। इन पांच स्थायी सदस्यों को वीटो पावर दी गई। दूसरे विश्व युद्ध से एशिया और अफ्रीका को एक लाभ यह हुआ कि उसके अधिकांश देश यूरोप के देशों के शिकंजे से मुक्त होने लगे। भारत भी उनमें से एक था। मोटे तौर पर दो महाशक्तियां स्थापित हो गईं, अमेरिका (यूएसए) और सोवियत रूस। इन दोनों के वैचारिक धरातल भी अलग थे।

सोवियत रूस का दावा था कि वह कम्युनिज्म का पक्षधर है और अमेरिका पूंजीवाद का पोषक है। इस व्यवस्था को झटका तब लगा जब चीन में लंबे अरसे से चला आ रहा सिविल युद्ध कामयाब हो गया और चीन के अधिकांश हिस्से पर माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया और चीन की सरकार ताईवान तक सीमित हो गई। यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी ने देश का आधिकारिक नाम भी रिपब्लिक ऑफ चाईना से बदल कर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाईना कर दिया। लेकिन अमेरिका की जिद के कारण 1971 तक वीटो पावर रिपब्लिक ऑफ चाईना (ताईवान) के पास ही रही, जबकि उसके पास अपनी रक्षा कर पाने की ताकत भी नहीं थी। शुरू में तो चीन सोवियत रूस की छाया में रहा। इसके लिए उसके पास कम्युनिज्म का बहाना भी था। लेकिन धीरे धीरे जब उसने अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत समेट ली तो वह उसकी छाया से मुक्त हो गया। अलबत्ता अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से जिसमें ज्यादातर स्पेन के लोग आ बसे थे, के अनेक देशों ने कम्युनिज्म व्यवस्था को स्वीकार किया हुआ था। यूएसए की कूटनीतिक लड़ाई वैचारिक आधार के पर्दे में सोवियत रूस और लातीनी अमेरिका के देशों से हो रही थी। इस लड़ाई में सोवियत रूस टूट गया। उसके बाद सारी व्यवस्थाएं चरमरा गईं। मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप रूस के शिकंजे से निकल गया। पश्चिमी यूरोप में जर्मनी की दीवार टूट गई। चीन ने आर्थिक क्षेत्र में तो कम्युनिस्ट व्यवस्था छोड़ दी लेकिन शासन में पुरानी व्यवस्था जारी रखी। अमेरिका ने भी नए हालात में अपनी रणनीति बदली। उसने अपने आर्थिक हितों के लिए दूसरे देशों में सीधा सैन्य हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जिस देश का राष्ट्रपति/अध्यक्ष अमेरिका के अनुकूल न हो, उसे सजा देने का उत्तरदायित्व वाशिंगटन ने स्वयं उठा लिया। इराक का सद्दाम हुसैन अमेरिका की इसी नीति का शिकार हुआ था। लेकिन अब वाशिंगटन के पास इस प्रकार के कामों के लिए कोई वैचारिक ढाल नहीं थी क्योंकि सद्दाम हुसैन को कम्युनिस्ट तो कहा नहीं जा सकता था। इसलिए अब अमेरिका ने नई रणनीति में आतंकवाद/ड्रगवाद को आधार बनाया। जबकि अफगानिस्तान के समय से अमेरिका ने खुद ही इस्लामी आतंकवाद की फसलें तैयार की थीं। लेकिन पिछले कुछ समय से अमेरिका ने इस प्रकार के सभी छद्म पर्दों से मुक्ति पा ली है। अब वाशिंगटन साफ–साफ किसी चतुर व्यापारी की भाषा में बात करनी शुरू कर रहा है। अमेरिका की इस नई नीति का शिकार वेनेजुएला हुआ है। हो सकता है लातीनी अमेरिका के कुछ अन्य देश भी अगली किश्त में इसका शिकार हो जाएं। वेनेजुएला में तेल है। चतुर व्यापारी जानता है तेल की कीमत होती है। इसलिए उसे वेनेजुएला की जरूरत है। ऐसा नहीं कि तेल की जरूरत अमेरिका को अभी हुई है या फिर वाशिंगटन को इसकी अहमियत पहली बार पता चली है। यह लड़ाई पुरानी है। लंबे समय से विश्व की राजनीति में लड़ाई झगड़े का मुख्य कारण मध्य पूर्व का तेल ही रहा है। लेकिन तब इसकी प्राप्ति के लिए लंबे–लंबे छद्म शब्दों का प्रयोग किया जाता था और इनको गढ़ने के लिए विश्वविद्यालयों के विद्वानों की पूरी फौज मैदान में उतारी जाती थी। लेकिन अब शायद पर्दे में शिकार करने की अपनी रणनीति या कूटनीति अमेरिका ने बदल दी है। हो सकता अब वाशिंगटन यह सब ड्रामा करने की जरूरत ही न समझता हो।

> विश्वविद्यालयों में किसी अंतरराष्ट्रीय कानून को समझने समझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आम आदमी को इस माथापच्ची की जरूरत नहीं है। वह जानता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? अपनी लाठी मजबूत करो। इसलिए नहीं कि आपको पड़ोसियों की भैंसें खोलनी हैं। बल्कि इसलिए ताकि कोई आपकी भैंस अपनी लाठी के बल पर खोल कर न ले जाए...

अब यहां एक देसी मुहावरे की बात। जिसकी लाठी उसकी भैंस। वाशिंगटन को लगा कि वेनेजुएला एक ऐसी भैंस है जो दूध की जगह तेल देती है। अमेरिका को तेल की जरूरत है। अब तेल देने वाली भैंस अमेरिकी महाद्वीप में घूम रही है। लेकिन यूएसए की सीमा से बाहर है। परन्तु इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वाशिंगटन के पास लाठी है। वाशिंगटन यह भी जानता है कि तमाम मार्डर्न तकनीकों के बावजूद भैंस को लाठी से ही हांका जाता है। उसने सबसे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को समझाया कि यह भैंस हमारे हवाले कर दो। लेकिन वह नहीं माना। उसको शायद लगा होगा कि यह इक्कीसवीं शताब्दी है। भैंस और लाठी वाला कानून मध्ययुगीन कानून था। इसलिए उसका प्रयोग आजकल नहीं हो सकता। फिर एक दूसरी आशा भी थी। वाशिंगटन तो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाता और उसको पालता है। इसलिए वह तो भैंस और लाठी वाले विधि विधान पर नहीं चल सकता। लेकिन वाशिंगटन जानता था कि कानून तो आज भी वही है, बस उसकी व्याख्याएं अलग तरीके से हैं। लेकिन वाशिंगटन ने एक पुरानी व्याख्या के सहारे ही भैंस को हांकने का निर्णय किया। वह व्याख्या भेड़िए और लेले वाली है। भेड़िए किसी लेले को खाना चाहता था। लेकिन यह सजा सुनाने के लिए लेले का कोई अपराध तो किया होना चाहिए। इसलिए भेड़िए ने लेले को कहा कि दो साल पहले तुमने मुझे गालियां निकाली थीं। लेले ने कहा कि मेरी उम्र महज एक साल है।

भेड़िए को अपने झूठ पर शर्म नहीं आई। उसने निर्लज्जता से कहा कि तुम्हारे बाप ने निकाली होंगी और इस अपराध में वह लेले को खा गया। वाशिंगटन ने भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कहा कि तुम नशीले पदार्थों का धंधा करते हो और उसे अमेरिका भेजते हो। राष्ट्रपति मादुरो ने इन्कार किया। वाशिंगटन ने इसे उसकी धृष्टता माना। और अपने जहाज भेज कर उसका अपहरण कर उसे न्यूयार्क ले आया और अब कचहरी वगैरह का कोई प्रहसन चालू किया है। दुनिया भर के बुद्धिजीवी भारी भरकम शब्दों में इस विषय पर गुरु गम्भीर विवेचन कर रहे हैं। कागज काले हो रहे हैं। किताबें छप रही हैं। विश्वविद्यालयों में किसी अंतरराष्ट्रीय कानून को समझने समझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आम आदमी को इस माथापच्ची की जरूरत नहीं है। वह जानता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? अपनी लाठी मजबूत करो। इसलिए नहीं कि आपको पड़ोसियों की भैंसें खोलनी हैं। बल्कि इसलिए ताकि कोई आपकी भैंस अपनी लाठी के बल पर खोल कर न ले जाए। आप की ताकतवर लाठी का एक दूसरा लाभ भी हो सकता है। ताकि कोई दूसरा भी किसी निर्बल की भैंस हांक कर न ले जा सके। जब भारत के विश्वगुरु बनने की बात आती है तो इसी संदर्भ में आती है। अभी जिसके पास लाठी है, वह गुंडई पर उतर आया है।

ईमेल:kuldeepagnihotri@gmail.com

प्रसंगवश

प्रवासी भारतीयों का योगदान

हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसे एनआरआई दिवस भी कहा जाता है। पाठकों को बताता चलूं कि इस दिन को इसलिए चुना गया था, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, और भारत की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी। यदि हम यहां पर इस दिवस के इतिहास की बात करें तो यह दिवस साल 2003 से मनाया जा रहा है, जब पहली बार भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों के योगदान को सम्मान देने के लिए इसे आयोजित किया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित होता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के मुख्य उद्देश्यों की यदि बात करें तो इसमें क्रमशः विश्व में बसे भारतीयों द्वारा भारत के विकास और समाज में दिए योगदान को सम्मानित करना, भारत और प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच सम्बन्धों को मज़बूत करना, एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां प्रवासी भारतीय अपनी राय, अनुभव और सुझाव साझा कर सकें तथा प्रवासी भारतीय सम्मान (अवार्ड) जैसे पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित करना है। गौरतलब है कि यह पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा सम्मान है जो प्रवासी भारतीयों को दिया जाता है, जो विदेश में रहते हुए भारत और भारतीय समुदाय के लिए विशिष्ट योगदान देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रवासी भारतीय दिवस के प्राथमिक लक्ष्य भारत और विदेशों में बसे भारतीयों के बीच एक सशक्त सेतु का निर्माण करना है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य भारत के आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास में प्रवासी भारतीयों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करना है। साथ ही, यह विश्व समुदाय के बीच भारत की सकारात्मक छवि को सुदृढ़ करते हुए विदेशों में भारत के प्रति बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास करता है। प्रवासी भारतीय दिवस भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों के समर्थन को बढ़ावा देता है और विश्वभर में स्थानीय भारतीय समुदायों के कल्याण के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रवासी भारतीयों को अपनी पैतृक भूमि की सरकार और जनता से भावनात्मक व वैचारिक रूप से जुड़ने का एक प्रभावी मंच प्रदान करता है, जिससे पारस्परिक सहयोग और विश्वास और अधिक मजबूत होता है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि साल 2003 में पहला सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ और उसके बाद अन्य शहरों में भी पारंपरिक रूप से इसका आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के तहत प्रवासी भारतीय समुदाय को मान्यता देने एवं उनके साथ जुड़ने हेतु एक मंच के रूप में की गई थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 2015 में इसे दो साल में एक बार आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक दो साल में 9 जनवरी को मनाया जाने वाला प्रवासी भारतीय दिवस एक उल्लेखनीय आयोजन है जिसके तहत भारतीय प्रवासियों द्वारा अपनी मातृभूमि के लिए दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला जाता है।

–सुनील कुमार

सरोकार

पहाड़ की बेटियां

नीलम सूद

स्वतंत्र लेखिका

कहा जाता है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। दुर्भाग्यवश, यह कथन केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ का कड़वा सच बन चुका है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता हो या धर्मशाला डिग्री कालेज की छात्रा पल्लवी, दोनों के लिए न्याय की मांग प्रबल होती जा रही है, परंतु यह संघर्ष किसी एक या दो घटनाओं तक सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि हमें दशकों पीछे ले जाकर एक और पीड़ादायक स्मृति से रूबरू कराता है। बेटियों पर अत्याचार, उनका शारीरिक शोषण कोई नई कहानी नहीं है। राजनीति और अपराध का गठजोड़ भी आज का नहीं, बल्कि वर्षों से स्थापित एक भयावह परंपरा है। इसकी एक झलक हमें सन् 1979 में भी देखने को मिलती है, जब अखबारों की सुर्खियां एक नाम से गूंज उठी थीं– 'सुजाता हत्याकांड'। 23 सितंबर 1979 की वह काली रात, जब जिला कांगड़ा के गांव सलियाना की 21 वर्षीय छात्रा सुजाता, सोनीपत के गोहाना में अपने छात्रावास से महज 60 गज की दूरी पर अगले दिन मृत पाई गई थी। सुजाता एक स्कूल अध्यापक की बेटी थी। जिस शिक्षण संस्थान में वह पढ़ती और रहती थी, उसके मालिक पर तरह–तरह के आरोप लगे। उसके राजनीतिक संबंधों और चरित्र पर उंगलियां उठीं। छात्रावास में रहने वाली युवतियों के यौन शोषण की चर्चाओं ने समाज को झकझोर दिया। जनता में वही आक्रोश, वही बेचैनी और वही सवाल उठे, जो आज अंकिता के मामले में उठ रहे हैं। उस समय भी लोग सड़कों पर उतरे थे। न्याय की मांग बुलंद थी। परंतु व्यवस्था ने उस आवाज को सुनने के बजाय दबाने का रास्ता चुना। आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चलीं और भय के बल पर असहमति को कुचल दिया गया। सवाल यह नहीं था कि अपराध हुआ या नहीं, सवाल यह था कि अपराधी कौन है और वह कितना शक्तिशाली है। उस दौर में न इंटरनेट था, न सोशल मीडिया और न ही सूचनाओं की त्वरित पहुंच। फिर भी अखबारों की सीमित सुर्खियां समाज के अंतर्मन को झकझोर देने में सक्षम थीं। सुजाता हत्याकांड ने जिला कांगड़ा के सलियाना गांव को वो दर्द दिया था जिसकी याद आते ही आज भी बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा पर प्रश्न चिह्न अंकित हो जाता है! सुजाता भी हिमालयी क्षेत्र की एक साधारण परिवार से आने वाली बेटी थी, जो शिक्षा के उद्देश्य से हरियाणा के गोहाना गई थी। वह इस भ्रम में थी कि शिक्षा और छात्रावास उसे सुरक्षा प्रदान करेंगे। परंतु वास्तविकता कुछ और ही थी और आज भी उतनी ही भयावह है। आज भी सत्ता, प्रभाव और संरक्षण की परतों में लिपटी एक ऐसी व्यवस्था मौजूद है, जहां बेटियों की अस्मिता को महत्वहीन समझा जाता है। अंकिता की तर्ज पर सुजाता की हत्या कर दी गई, निर्ममता से, निर्दयता से। कई दिनों तक अखबारों ने न्याय की मांग को प्रमुखता से उठाया। संपादकीय लिखे गए, जनाक्रोश उभरा, लेकिन न्याय की प्रक्रिया सत्ता के दबाव में ठिठकती रही। कल सुजाता थी, आज अंकिता और पल्लवी है। कल भी पहाड़ रो रहा था, आज भी पहाड़ रो रहा है। यह केवल दो–तीन नामों की कहानी नहीं है, यह उस व्यवस्था का आईना है जो बार–बार बेटियों को असुरक्षा के हवाले करती है और फिर कुछ दिनों के शोर के बाद सब कुछ भुला देने की आदत डाल देती है। सवाल है कि क्या न्याय होगा?

संपादकीय लेखों पर सुधी पाठकों की प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं, भेजें : पाठकों के पत्र, द्वारा संपादक, पोस्ट बॉक्स 14, धर्मशाला–176215

फोन : 01892–264713, 260676

फैक्स : 01892–264700

Email : feature@divyahimachal.com या edit.dshala@divyahimachal.com

हिमाचल : मौसम

प्रदेश में घटता हिमपात एक बड़ी चुनौती

डा. सतपाल

शिक्षाविद

हिमाचल प्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सर्दियों में बर्फ की चादर व गर्मियों में ठंडी हवाएं पर्यटकों के मन को मोह लेती हैं। हिमाचल, हिम तथा अचल दो शब्दों का मेल है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'बर्फ का पहाड़' अर्थात 'बर्फ के पहाड़ों से लदा प्रांत' होता है। अपनी हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं, बर्फीली वादियों और सदानीरा नदियों के कारण ही हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक रहा है। यहां की भौगोलिक संरचना पूरी तरह हिमपात, ग्लेशियरों और उनसे निकलने वाली नदियों पर आधारित है, ऐसा कहने में अतिशयोक्ति न होगी। लेकिन पिछले कुछ दशकों की बात करें तो प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों ने इस संतुलन को गहराई से प्रभावित किया है। वैश्विक तापमान में निरंतर वृद्धि किसी से छुपी नहीं, कहीं न कहीं हिमाचल भी इस समस्या से अछूता नहीं रहता। तापमान वृद्धि के कारण हिमालयी क्षेत्रों में पड़ने वाली बर्फ व सर्दियों की अवधि में भी निरंतर कमी देखने को मिल रही है। प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी से ठंडी हवाओं का प्रवाह कमजोर पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बर्फबारी की मात्रा और आवृत्ति में भारी गिरावट देखने को मिलती है। प्रदेश की राजधानी शिमला, मनाली, धर्मशाला, चम्बा–पांगी, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल–स्पीति जैसे क्षेत्र बर्फ के लिए जाने जाते हैं। एक समय था जब सर्दियों के महीनों में लगातार और भारी हिमपात होता था। सर्दी में नवंबर के महीने से हिमपात होना शुरू हुआ करता था, जो मार्च तक जारी रहता था।

कभी–कभार तो हिमपात अक्तूबर में भी हो जाता था तथा अप्रैल तक भी बर्फबारी के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जनवरी में भी प्रदेशवासियों की आंखें हिमपात को निहारती रहती हैं, अगर हिमपात होता भी है, तो नाममात्र। प्रदेश की ऊंची–ऊंची चोटियां बारहों महीने बर्फ से ढकी रहती थी, जिनकी संख्या में साल दर साल कमी देखने को मिल रही है। हिमपात प्राकृतिक जल भंडारण, अपितु कृषि के लिए भी प्राकृतिक रूप से सहायक होता है। मृदा में बर्फ की परत चढ़ जाने के कारण अनेकों प्रकार के मृदा रोग, विषाणु–कीटाणुओं का नाश तथा जल स्त्रोंतो का प्राकृतिक रूप से शुद्धिकरण होता है। परंतु अब स्थिति यह है कि सर्दियों में बर्फ के स्थान पर बारिश अधिक हो रही है, जो हम सभी के लिए गहन चिंता का विषय है। प्रदेश मौसम विभाग के आंकड़े प्रदेश में हिमपात के इस बदलाव की गंभीरता को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। वर्ष 1990 से 2020 के बीच प्रदेश की पर्यटन नगरी शिमला में हिमपात में लगभग 37 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार 1990 से 2000 के दशक के बीच प्रदेश के जिला शिमला में जहां औसतन 129 सेंटीमीटर बर्फबारी होती थी, वहीं 2010 से 2020 के दौरान यह घटकर 80 सेंटीमीटर रह गई। पिछले 3 वर्षों में तो हिमपात का यह आंकड़ा दहाई के अंक को भी नहीं छू पाया, जो इस क्षेत्र के लिए असामान्य और चिंताजनक विषय है। यह चिंता केवल शिमला तक ही सीमित नहीं रहती, अपितु राज्य के दूसरे जिलों में भी स्थिति ठीक इसी प्रकार की ही दिखती है। राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र और स्पेस एप्लिकेशन सेंटर, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नदी बेसिनों में कुल बर्फ क्षेत्र का लगभग 18.5 प्रतिशत तक सिकुड़ जाना भविष्य के जल संकट का स्पष्ट संकेत है। प्रदेश में बर्फबारी में कमी का सबसे गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियरों पर भी पड़ना स्वाभाविक है। आंकड़े ग्लेशियरों के क्षेत्रफल में 20 से 25 प्रतिशत तक की कमी को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1984 से 2023 के बीच हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर झीलों की संख्या और क्षेत्रफल में 27 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। यह स्थिति ग्लेशियर झील विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आशंका को बढ़ा रही है, जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकती हैं। ग्लेशियरों के सिकुड़ने और बर्फ कवर में गिरावट का सीधा असर हिमाचल की प्रमुख नदियों पर पड़ता भी दिख रहा है। ये नदियां हिमपात और ग्लेशियरों से मिलने वाले जल पर निर्भर हैं। सतलुज बेसिन में बर्फ कवर, ब्यास नदी का जल प्रवाह तथा रावी बेसिन में बर्फ क्षेत्र की कमी दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश में निकट भविष्य में जल आपूर्ति अनियमित होने की संभावना में दिखती प्रतीत होती है। इन नदियों का महत्व केवल हिमाचल तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों की जल सुरक्षा भी इन्हीं पर निर्भर करती है। हिमपात में कमी होने से न केवल जल संकट की स्थिति बल्कि प्रदेश की कृषि और बागवानी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बागवानी में ठंडे क्षेत्रों की फसलों को पर्याप्त ठंड (चिलिंग आवर) न मिलने से उत्पादन और गुणवता प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिक तन्त्र, जैव विविधता पर भी नकारात्मक प्रभाव हुआ है, प्रदेश की कई वनस्पतियां व जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवास को खो चुके हैं। निकट भविष्य में जहां शीतकालीन पर्यटन, स्कीइंग व बर्फ से जुड़ी पर्यटन गतिविधियों को मुख्य आधार माना जा सकता है, उसमें निश्चित रूप से कमी देखने हो मिल रही है, जो प्रदेश में रोजगार एवं स्वरोजगार की संभावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है।

हिमपात में कमी जलवायु परिवर्तन को और तेज करती है, जिससे भविष्य में तापमान बढ़ने और मौसम के असामान्य व्यवहार की आशंका भी बढ़ जाती है। अनियमित वर्षा, भूस्खलन, बादल फटना और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है, जिसके उदाहरण पिछले तीन वर्षों में हमें प्रदेश में देखने को मिले हैं। इसके पीछे कारणों को खोजें तो जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, वनों की कटाई एवं आग, पश्चिमी विक्षोभ में अनियमितता, आधुनिकीकरण तथा पर्यावरण प्रदूषण विद्यमान हैं। जलवायु परिवर्तन यद्यपि यह एक वैश्विक चुनौती है, फिर भी स्थानीय स्तर पर प्रभावी उपाय करने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर वनरोपण और उससे भी कहीं अधिक वनों का संरक्षण, वर्षा जल संचयन, कृत्रिम ग्लेशियरों का निर्माण जरूरी है। प्रकृति के संरक्षण में ही प्रदेश तथा देश की भलाई है।

> हिमपात में कमी जलवायु परिवर्तन को और तेज करती है, जिससे भविष्य में तापमान बढ़ने और मौसम के असामान्य व्यवहार की आशंका भी बढ़ जाती है। अनियमित वर्षा, भूस्खलन, की संभावना बढ़ जाती है...

प्रेरक कहानी

चार साधु और चोर

स्वामी श्रीरामसुखदास जी महाराज

चार साधु थे। वे शहर के पास एक जंगल में रहते थे और भगवान का भजन–स्मरण करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अलग–अलग एक निष्ठा थी। एक दिन वहां के राजा ने अपनी स्त्री से कहा कि हमें अपने लड़के को अच्छा संत बनाना है, फिर वह चाहे राज्य करे, चाहे साधु बन जाए। रानी बोली कि महाराज! जो संत बनना चाहता है, वही संत बन सकता है, दूसरे के बनाने से कैसे बन जाएगा। आपका और मेरा उद्योग थोड़े ही काम करेगा। राजा ने कहा कि इसका एक उपाय है– सत्संग! रानी बोली कि ऐसा कोई अच्छा संत है, जिसके पास लड़के को भेजें? राजा बोला कि यहां पास में ही जंगल में चार अच्छे संत रहते हैं। उनके पास लड़के को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी बातें कर रहे थे। रात्रि का समय था। दैवयोग से एक चोर, जो चोरी करने के उद्देश्य से वहां आया था, छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उस चोर के मन में आया कि चोरी करने से तो मैं फंस भी सकता हू, पर साधु बन जाऊं तो काम बन जाएगा! राजकुंअर आएगा और मेरा चेला बन जाएगा, फिर चोरी करने की क्या जरूरत है? चोर ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए और जंगल में चला गया। उसके मन में आया कि कोई पूछेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा! ऐसा सोचकर वह चार संतों में से पहले सन्त के पास गया और पूछा कि महाराज! कल्याण कैसे हो? संत ने कहा, भाई किसी का जी मत दुखाओ, किसी को दुःख मत दो। चोर दूसरे सन्त के पास पहुंचा और बोला कि महाराज! मैं कल्याण चाहता हूं, कोई उपाय बताओ। संत बोले, कभी किंचिन्मात्र भी झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य ही बोलना। अब वह चोर तीसरे संत के पास गया और बोला कि महाराज! मेरा कल्याण कैसे हो? संत बोले, सीधी–सादी बात है, रात–दिन राम–राम करो। अब वह चौथे सन्त के पास पहुंचा और बोला कि महाराज! कल्याण कैसे हो? सन्त बोले– भाई! एक भगवान के शरण हो जाओ। मन में यह बात अटल रहे कि मैं तो केवल भगवान का हूं। चोर ने चारों सन्तों से चार बातें सीख लीं और आगे जाकर बैठ गया। अब राजा आया। वह क्रमशः चारों सन्तों के पास गया। चारों ने एक–एक बात कह दी। राजा ने देखा कि आगे पांचवां साधु भी बैठा है! राजा उसके पास भी गया और प्रार्थना की कि महाराज! कृपा करके कल्याण की बात बताएं। वह साधुवेषधारी चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। राजा ने ज्यादा प्रार्थना की तो वह बोला– मैं जैसा बताऊंगा, वैसा करोगे? राजा ने कहा कि हां महाराज! वैसा ही करूंगा। वह बोला– किसी का जी मत दुखाओ। राजा बोला, और कोई बात? वह बोला– सदा सत्य बोलो। राजा बोला– दूसरी कोई बात? वह बोला– भगवान के नाम का जप करो। राजा बोला, और कुछ बताइये! वह बोला– भगवान के शरण हो जाओ। राजा बोला– महाराज! और कोई बात? वह बोला– सन्त जैसा कहे, वैसा कर दो। राजा ने मन में विचार किया कि यह सन्त ज्यादा ऊंचा है! अन्य सन्तों ने तो एक–एक बात कही, पर इन्होंने पांच बातें कह दीं! राजा बड़े सरल स्वभाव का था। उसको मालूम नहीं था कि सन्त की पहचान इस तरह नहीं होती। राजा लौटकर महल में आ गया। रात होने पर वह चोर फिर छिपकर महल में आया। जब राजा रानी के पास गया, तब वह चोर दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। रानी ने पूछा कि क्या बात हुई? राजा ने कहा कि मैं जंगल में सन्तों के दर्शन करके आया हूं। मैं तो चार ही सन्त समझता था, पर वहां पांच सन्त बैठे थे। रानी बोली– वहां जाकर आपने क्या कहा? राजा बोला– मैंने भगवत्प्राप्ति की बात पूछी तो उनमें से एक संत ने कहा कि किसी का जी मत दुखाओ, दूसरे ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तीसरे ने कहा कि नाम–जप करो, चौथे ने कहा कि भगवान के शरण हो जाओ। परंतु पांचवें सन्त ने उन चारों सन्तों की चार बातें भी बतायीं और साथ में पांचवीं बात यह बतायी कि सन्त की आज्ञा का पालन करो। राजा और रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि वह पांचवां सन्त ठीक है, अपने लड़के को उसी के पास भेजो। उनकी बातों का चोर पर बड़ा असर पड़ा कि अरे! मैंने तो नकली बात कही, उस पर भी राजा ने श्रद्धा कर ली। अगर सच्ची बात कहूं तो कितनी मौज हो जाए! राजा के सद्भाव के कारण चोर का हृदय बदल गया! बाद में उसी संत के पास राजकुंवर को भेजा गया।

पाठकों के पत्र

दोस्ती हो तो विवेकानंद और अजीत सिंह जैसी

12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद अक्सर कहते थे कि भारतवर्ष की उन्नति के लिए मैंने जो कुछ भी किया है, वह मैं नहीं कर पाता यदि राजा अजीत सिंह मुझे नहीं मिलते। इस कथन से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि विवेकानंद के जीवन में खेतड़ी के राजा अजीत सिंह का क्या स्थान था। विवेकानंद राजपूताने की खेतड़ी रियासत के राजा अजीत सिंह को अपना सच्चा दोस्त और सहयोगी मानते थे। उन्होंने जीवन भर अजीत सिंह से रिश्ता निभाया और उनसे मदद ली। अजीत सिंह को विविदिशानंद नाम उच्चारण में सही नहीं लगा, तो उन्होंने विवेकानंद कहकर बुलाया। विवेकानंद नाम से पूरी दुनिया में मशहूर होने के बाद इस बात से पर्दा उठा कि उनका यह नाम खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के सुझाव पर ही रखा गया।

–अमित बैजनाथ गर्ग, जयपुर

किसी भी जगह हो रहा अन्याय, हर जगह के न्याय के लिए गंभीर खतरा होता है।
– मार्टिन लूथर किंग

उम्मीद के आंकड़े

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के नए आंकड़ों से स्पष्ट है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक, भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.4 फीसद की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसमें विनिर्माण, सेवाएं और सरकारी व्यय वृद्धि को गति मिलेगी। जाहिर है, इसका असर नौकरी, महंगाई, आमदनी, कर्ज, कर और सरकारी सुविधाओं पर पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों में कृषि से जुड़े रोजगार में बढ़ोतरी हो सकती है। सात फीसद या उससे अधिक दर का मतलब यही है। दूसरी ओर, तेज जीडीपी से मांग बढ़ती है, जिससे यदा-कदा महंगाई का दबाव बनता है। अगर विकास दर संतुलित रहे तो आपूर्ति बढ़ने से महंगाई काबू में रहती है। कहा जा सकता है कि आम आदमी के लिए बहुत तेज विकास दर का मतलब महंगाई का खतरा होता है, वहीं इसकी धीमी रफ्तार से आमदनी प्रभावित होती है। लिहाजा, मध्यम और स्थिर विकास आंकड़ा सबसे अच्छा माना जाता है।

कर संग्रह और राजकोषीय घाटे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। व्यापक अर्थव्यवस्था और आगामी केंद्रीय बजट दोनों के दृष्टिकोण से यह अच्छी बात है। जीडीपी दर के समांतर महंगाई काबू में रहे तो केंद्रीय रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटा सकता है, जिसका सीधा असर कर्ज की किस्त पर पड़ सकता है। साथ ही, सरकार को मिलने वाला कर राजस्व बढ़ सकता है, जिससे ढांचागत और समाज कल्याण की योजनाओं पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। शेयर बाजार में तेजी से म्यूचुअल फंड, भविष्य निधि आदि पर सकारात्मक असर हो सकता है। जीडीपी की दर 2024-25 में 6.5 फीसद की तुलना में अधिक है, और यह मुख्य रूप से विनिर्माण और सेवाओं में वृद्धि के सुधार का नतीजा है।

दूसरी ओर, नवीनतम आंकड़ों को लेकर चर्चा में कई पहलुओं की अनदेखी हो रही है। कुछ महीने बाद आने वाले जीडीपी के अनंतिम आंकड़े उनसे प्रभावित दिखेंगे। जीडीपी के आंकड़ों में अवैतनिक श्रम (जैसे घरेलू काम), पर्यावरणीय क्षति, आय असमानता और गैर-बाजार लेनदेन (जैसे स्वयंसेवा) जैसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं को नहीं गिना जाता। जीडीपी देश की औसत आय बताता है, लेकिन यह नहीं दिखाता कि धन का वितरण कितना असमान है। उच्च जीडीपी के बावजूद समाज के एक बड़े हिस्से का जीवन स्तर निम्न हो सकता है। यह उन वस्तुओं और सेवाओं (जैसे निजी खपत के लिए उत्पादित वस्तुएं, स्वयंसेवा) को शामिल नहीं करता जिनका बाजार में लेन-देन नहीं होता, और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार को नहीं दर्शाता। आपदाओं या खराब परिस्थितियों से बचने के लिए किया गया खर्च (जैसे प्रदूषण मास्क खरीदना, मरम्मत कार्य) भी जीडीपी बढ़ाता है, जबकि यह असल में समाज के कल्याण में कमी को दर्शाता है। ऐसे में जीडीपी के आंकड़ों को सतत विकास का संकेतक नहीं माना जाता। यह भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में नहीं रखता। बावजूद इन तर्कों के, जीडीपी के आंकड़ों से उम्मीद तो बढ़ी है। जरूरत इस बात की है कि अर्थव्यवस्था की ठोस मजबूती के लिए उन पहलुओं पर भी गौर किया जाए, जिनकी अनदेखी हो रही है।

नोटिस और विवाद

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को नोटिस भेजे जाने पर पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में है। गौरतलब है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना था। आरोप लग रहे हैं कि इसमें मतदाताओं को ही उलझा दिया गया है। अब न तो मानवीय संवेदना का ध्यान रखा जा रहा है और न ही मर्यादा का। यहां तक कि प्रशासनिक जवाबदेही तक नजर नहीं आती। कुछ समय पहले एसआइआर से संबंधित सुनवाई के लिए बीमार और बुजुर्ग मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा गया। जब इसकी शिकायत होने लगी, तो जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग मतदाताओं को सुनवाई के लिए न बुलाया जाए और उनके आवास पर ही सत्यापन किया जाए। मतदाता सूची को दुरुस्त करने के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई गई उससे मतदाताओं को खासी परेशानी हुई।

यह सिलसिला थमा ही था कि अब चुनाव आयोग ने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को नोटिस जारी कर दिया। कहा गया कि सेन की ओर से प्रस्तुत प्रपत्र में विसंगतियां पाई गई हैं। आयोग का तर्क है कि उनके और उनकी माता अमिता सेन की उम्र में 15 साल से भी कम अंतर है- ऐसा कैसे संभव है। सवाल यह है कि पर्यवेक्षण के दौरान भरे गए उनके प्रपत्र में आखिर किस स्तर पर गलती हुई। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2002 की मतदाता सूची को आधार बनाया गया है। उस सूची में अमिता सेन की उम्र 88 वर्ष दर्ज है। इस बार की मसविदा सूची में अमर्त्य सेन की उम्र 92 वर्ष लिखी गई है। आशय यह कि वे 2002 में 69 साल के थे। इस नाते उनकी और उनकी मां की उम्र में 19 साल का फर्क है। सवाल यह है कि 2002 की सूची से इतर आंकड़ा किस स्तर पर प्रपत्र में भरा गया? अमेरिका में रह रहे अमर्त्य सेन को शांति निकेतन स्थित उनके आवास पर नोटिस भेजा गया है। उन्हें अब अपनी मां से संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे, ताकि मतदाता सूची में उनका नाम बरकरार रह सके। अगर वैश्विक पहचान रखने वाले अमर्त्य सेन के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, तो फिर आम मतदाताओं की कौन सुनेगा?

वैश्विक परिवेश में व्यवसाय की सुगमता

देश के तेज आर्थिक विकास के लिए व्यवसाय सुगमता जरूरी है। इसलिए कारोबार शुरू करने, चलाने और बंद करने की प्रक्रियाओं को सरल और कुशल बनाया जाना चाहिए, ताकि प्रशासनिक जटिलताओं और बाधाओं को कम किया जा सके।

अजय जोशी

किसी भी देश के तेज आर्थिक विकास के लिए वहां व्यवसाय सुगमता जरूरी है। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय शुरू करने, चलाने और बंद करने की प्रक्रियाओं को सरल, कुशल तथा लागत-प्रभावी बनाया जाए, ताकि नियामकीय जटिलताओं तथा प्रशासनिक बाधाओं को कम किया जा सके और निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। साथ ही आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिले। विश्व बैंक का 'व्यवसाय सुगमता सूचकांक' देशों की व्यवसाय सुगमता को मापता है। इसके लिए वह व्यवसाय शुरू करने, अनुमति पत्र प्राप्त करने, बिजली-पानी की सुविधा, कर भुगतान, ऋण उपलब्धता, अनुबंध लागू करने और सीमा-पार व्यापार जैसे मानकों के आधार जांच करके उन देशों को वर्गीकृत करता है। व्यवसाय सुगमता सूचकांक में भारत को इस वर्ष 190 देशों में से 63वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष यह 77वें स्थान पर था। इस वर्ष चौदहवें स्थान के सुधार के साथ उसका स्कोर 71 हो गया है।

व्यवसाय सुगमता का उद्देश्य कारोबार के लिए पूरे जीवनकाल में नियमों, परमिट और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता तथा समय को कम करने के साथ ही अनुकूल विनियामक वातावरण बनाना है, जो संपत्ति अधिकारों को स्पष्ट करे और विवादों को सुलझाने की लागत कम करे। इसका उद्देश्य एकल इलेक्ट्रानिक मंच बनाना, कागज रहित व्यवस्था करना और डिजिटल कर प्रणाली के माध्यम से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। उच्च रैंकिंग देश की छवि को सुधारती है, निवेश आकर्षित करती है और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देती है। व्यवसाय की सुगमता वर्तमान वैश्विक परिवेश को देखते हुए बहुत जरूरी है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों, नियामक संस्थाओं, व्यवसायिक संगठनों और व्यवसायियों के साझा प्रयास जरूरी हैं। देश में अधिकांश व्यावसयिक गतिविधियों का संचालन कंपनी स्वरूप में होता है। इनमें भी छोटी कंपनियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यवसाय सुगमता छोटी कंपनियों के लिए और जरूरी हो जाती है, ताकि वे कम से कम कानूनी औपचारिकताओं के साथ अपना कार्य संचालन कर देश की अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान कर सकें।

हाल में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने छोटी कंपनियों के लिए अनुपालन का बोझ कम करने के उद्देश्य से एक दिसंबर 2025 से कई उपाय किए हैं। छोटी कंपनियों के लिए चुकता पूंजी का मानदंड चार करोड़ रुपए से बढ़ा कर दस करोड़ रुपए और कारोबार का मानदंड चालीस करोड़ रुपए से बढ़ा कर सौ करोड़ रुपए कर दिया है। इससे अपेक्षाकृत अधिक पूंजी वाली कंपनियां भी छोटी कंपनी की श्रेणी में आ जाएंगी और उन पर भी अनुपालन का बोझ कम हो सकेगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का कार्य अधिनियम में संशोधन के माध्यम से दो चरणों में किया गया है। इस तरह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 51 प्रकार के मामलों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसके अलावा सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2021 के अंतर्गत 12 प्रकार के मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इस संशोधन से अदालतों और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण पर इस तरह के मामलों का बोझ

कम करने में सहायता मिलेगी और व्यवसायी भी तनावमुक्त होकर अपने व्यवसाय का कुशल संचालन कर सकेगा। व्यवसाय सुगमता की दृष्टि से छोटे-छोटे उपक्रमों का आपस में विलय भी होता रहता है, इनके त्वरित विलय के दायरे को फरवरी 2021 में विस्तारित किया गया, ताकि एक नवउद्यम का अन्य

> **छोटे स्तर पर शुरू किए जाने वाले व्यवसायों के पंजीकरण और अन्य क्रियाकलापों का सरलीकरण करने की दृष्टि से एकल विंडो प्रणाली लागू की जा सकती है, जिससे व्यापारियों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं मिल सकें। व्यापारिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और ई-गवर्नेंस लागू करने जैसे उपाय भी आवश्यक हैं, ताकि व्यापारियों को आनलाइन सेवाएं मिल सकें। व्यापारिक नियमों और विनियमों को सरल एवं स्पष्ट बनाया जाना चाहिए। छोटे स्तर पर व्यापार करने वालों को या तो पूरी तरह से कर मुक्त किया जाए या फिर उन पर बहुत कम कर लगाया जाए।**

लघु कंपनियों के साथ विलय आसानी से हो सके। सितंबर 2025 में इस दायरे को और विस्तृत किया गया, ताकि ज्यादा कंपनियां इस आपसी विलय के साथ सुगमता पूर्वक अपने कार्य का संचालन कर सकें। इसके अलावा, समयबद्ध तरीके से अनुमोदन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से त्वरित विलय के लिए 'मानित अनुमोदन' की व्यवस्था शुरू की गई है। इसके अंतर्गत शर्तें पूरी होने पर दो या अधिक उपक्रमों का स्वतः विलय मान लिया जाता है। व्यवसाय सुगमता के लिए राहें इसीलिए आसान की गई हैं।

भारतीय सार्वजनिक कंपनियों द्वारा स्वीकृत विदेशी क्षेत्राधिकारों में प्रतिभूतियों को सीधे सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी गई है। इससे उत्पादों को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलता है और पूंजी का वैकल्पिक स्रोत प्राप्त होता है तथा निवेशक आधार को व्यापक बनाने में मदद मिलती है। यदि कोई छोटी कंपनी अपने कंपनी स्वरूप से बाहर निकलना चाहे, तो इसके लिए त्वरित कारपोरेट निकासी प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना मई 2023 में की गई। इसका उद्देश्य हितधारकों को उनकी कंपनियों और सीमित दायित्व साझेदारी के नामों को रजिस्टर से समय पर और प्रक्रियाबद्ध तरीके से हटाने के लिए परेशानी मुक्त 'फाइलिंग' प्रदान करना और उन्हें सक्षम बनाना है।

व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, अनुपालन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और 'कारपोरेट फाइलिंग' को सुव्यवस्थित करने के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। अब सभी फाइलिंग इसी प्रणाली के माध्यम से की जा रही हैं, जो पहले से भरे हुए 'मास्टर डेटा' के साथ वास्तविक समय पर सत्यापन प्रदान करता है। इससे मानवीय त्रुटियां और अनुपालन की समय सीमा कम हो जाती हैं। हितधारकों को मार्गदर्शन के लिए नियमित रूप से वेबिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पोर्टल पर 'वीडियो ट्यूटोरियल', 'चैटबाट' और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उपलब्ध हैं, जो उपयोगकर्ताओं को रिटर्न दाखिल करने में सहायता करते हैं। यह पोर्टल एक 'डैशबोर्ड' की सुविधा प्रदान करता है, जो हितधारकों को भुगतान में सक्षम बनाता है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है। पोर्टल से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। व्यवसाय सुगमता कंपनी प्रारूप के अतिरिक्त अन्य प्रारूपों में संचालित होने वाले उपक्रमों के लिए भी जरूरी है। इस दृष्टि से भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

छोटे स्तर पर शुरू किए जाने वाले व्यवसायों के पंजीकरण और अन्य क्रियाकलापों का सरलीकरण करने की दृष्टि से एकल विंडो प्रणाली लागू की जा सकती है, जिससे व्यापारियों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं मिल सकें। व्यापारिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और ई-गवर्नेंस लागू करने जैसे उपाय भी आवश्यक हैं, ताकि व्यापारियों को आनलाइन सेवाएं मिल सकें। व्यावसायिक नियमों और विनियमों को सरल तथा स्पष्ट बनाया जाना चाहिए। छोटे स्तर पर व्यापार करने वालों को या तो पूरी तरह से कर मुक्त किया जाए या उन पर बहुत कम कर बोझ हो, साथ ही कर प्रणाली को सरल बनाया जाए, ताकि व्यापारियों को आसानी हो। जिन व्यवसायों में किसी प्रकार के लाइसेंस या परमिट की व्यवस्था है, वहां इस प्रक्रिया को या तो समाप्त कर दिया जाए या उनको सरल बनाया जाए, ताकि व्यापारियों को जल्दी से जल्दी लाइसेंस एवं परमिट मिल सकें। जो व्यवसाय आनलाइन माध्यम से संभव हों उनके लिए आभासी व्यापार मंच बनाए जाएं, जिससे व्यापारियों को परस्पर आनलाइन व्यापार करने में आसानी हो। ऐसे बहुत से व्यवसाय हैं, जिनमें व्यापारियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की जरूरत रहती है। लिहाजा उनके लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि वे अपना कारोबार और बेहतर ढंग से चला सकें।

जीवन और त्याग

प्रभात कुमार

हम जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाहते, उन्हें कोई दूसरा उपयोग कर सकता है। हमारी कोई चीज किसी को अच्छी लग रही हो, बेहद पसंद आ रही हो, हमें यह अंदाजा हो जाए और हम वह चीज किसी को भेंट कर दें, तो वह व्यक्ति खुश हो सकता है। हम लकीर के बहुत पुराने फकीर है, लेकिन त्याग के नए अर्थ गढ़ रहे हैं। खुद त्याग करें, न करें, मगर दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे स्वार्थी न बनें। त्याग करें, बलिदान दें, समर्पण करें। अब तो मानवीय रिश्ते भी वस्तुओं की मानिंद हो गए हैं। एक-दूसरे पर, चीजों और संपत्ति पर नजर रखी जा रही है। काफी कुछ जैसे-तैसे हासिल करने की कोशिश की जा रही है। न मिले तो मारना-पीटना तो कम है, मनमानी हरकत भी की जा रही है। क्रूर शैली में जान तक ली जा रही है। विवाह नामक पारंपरिक, सांस्कृतिक संस्था जोखिम में है। ऐसा लगता है कि वचनों की मर्यादा जैसे जिंदगी की भूल-भुलैया में भटक रही है।

बदलाव सकारात्मक हो, मानवीय हो, तो इससे अच्छा क्या होगा। मगर बाजार की गिरफ्त में फंसी दुनिया में आए बदलावों ने सबसे ज्यादा परेशान मानवीय रिश्तों को किया है। किसी को नहीं पता कि विवाह के बंधन में उलझे इंसानी रिश्ते, कब तक कौन-सा रूप बनाए रखेंगे, कब अचानक बदल जाएंगे। यह नए तरह के विकास की ही 'मेहरबानी' है कि पति-पत्नी के रिश्तों के आयाम बदल रहे हैं और उनके बीच नई अपेक्षाएं पैदा हो रही हैं। फिल्में भी ऐसे रिश्ते-नातों के उतार-चढ़ावों को आकर्षक बना कर पेश कर रही हैं। अनेक धारावाहिक भी ऐसे सुलझते, उलझते रिश्तों के कारण खूब पसंद किए जा रहे हैं और वे सफल भी हो रहे हैं। यह समाज में आ रहे बदलाव से निर्मित स्वीकृति है।

दुनिया मेरे आगे

> **बदलाव सकारात्मक और मानवीय हो, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मगर बाजार की गिरफ्त में फंसी दुनिया में आए बदलावों ने सबसे ज्यादा परेशान मानवीय रिश्तों को किया है। किसी को नहीं पता कि विवाह के बंधन में उलझे इंसानी रिश्ते, कब तक कौन-सा रूप बनाए रखेंगे।**

विकास के एक मानक माने जा रहे मोबाइल के जरिए बनते वीडियो और तस्वीरों की दुनिया ने खूब मनोरंजन किया है, संप्रेषण को खूब बढ़ावा दिया है, सूचनाओं की अति कर दी है। डिजिटल संपर्क इतना हो गया है कि माहौल का मौसम संक्रमित हो गया। इस क्रम में संवाद की बार-बार हत्या होने लगी है। जीवन की आचार संहिता और मूल्यों के नुकसान का ग्राफ बढ़ता गया है। भौतिकता इंसानी रिश्तों में बहुत गहरे घुसपैठ कर चुकी है। मानवीय रिश्तों से दिल दुखाता स्वार्थ लगातार रिसने लगा है। फिल्मों की कहानी जैसी अविश्वसनीय बातें आंखों के सामने घटनाएं बनने लगीं। कभी फिल्में सामाजिक घटनाओं और सच्चाइयों का आईना होती थीं, इंसान को उचित राह पर लौटने के लिए प्रेरित करती थीं। मगर ऐसा लगता है कि अब फिल्में सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाई जा रही हैं और उनमें परोसी जा रही हिंसा, क्रूरता, नफरत और चापलूसी देखने का असर दिमाग पर हो रहा है।

बदलते वातावरण का प्रभाव युवाओं से लेकर बच्चों और महिलाओं पर बहुत दिख रहा है। यह माहौल यही चाहता है कि महिलाएं नौकरी करे, पैसा कमाए, लेकिन साथ-साथ सुबह घर से निकलने से पहले या घर पर काम करते समय समूचे घर-परिवार का ध्यान रखे। इसके बाद फिर शाम को लौट कर घरेलू काम संभाले और सारी दुनियादारी भी निभाए। यानी दूसरों के लिए सुविधा बनी रहे। निरंतर त्याग करती रहे। मगर अब महिलाएं भी बदल रही हैं। दबी-छिपी इच्छाओं की गली से निकल रही हैं। नौकरी या व्यवसाय करना चाहती हैं। अपने पांव पर खड़ी होकर रिश्तों के अपने चुनाव के रास्ते पर चल रही हैं। विवाह उनकी एकमात्र या आखिरी मंजिल नहीं। किसी दबाव या अन्य कारणों से शादी करती हैं, तो अपनी सुविधा के मुताबिक संतान प्राप्त करने का समय तय करती हैं।

प्रेम विवाह, सप्रेम न चल रहा हो, तो परिस्थिति अनुसार मानसिक रूप से अलग रहने लगती हैं। उसी पुरानी छत के नीचे नई छत बना लेती हैं। यानी त्याग का सूत्र वहां भी काम करता है, फिर चाहे वहां कई अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़े। जीवन में कलुष को पीछे छोड़ नई राह पर निकलने के सामाजिक, व्यक्तिगत और पारिवारिक खतरे भी रहते हैं। पसंदीदा और संवेदनशील व्यक्ति मिल जाए और जब तक समझ बनी रहे, तब तक आपसी समन्वय को जिंदगी संवारने, व्यक्तित्व सुधारने के नजरिए से देखा-समझा जा सकता है।

इस तरह का व्यवहार समाज में किसी की ओर से संभव है। कभी-कभी तो यह काफी हद तक खालिस व्यावसायिक भी हो सकता है। यहां भी विचारों का त्याग काम आता है। जिंदगी में वैचारिक उकताहट बढ़ जाए, तो त्याग का सूत्र कामयाब नहीं होता। नई छत का निर्माण नहीं, पुराना फर्श भी छोड़ने को तैयार रहना पड़ता है। त्याग दरअसल नफरत, बड़प्पन, प्रतिशोध संभालता कई स्वादों वाला व्यंजन है। यह वियोग का उत्सव मनाने की तरह है, जिसमें आने वाले समय में मनचाही स्वतंत्रता के साथ, अकेले या किसी के संपर्क में रहना है। त्याग करना यानी जिंदगी से गैरजरूरी हटाना अपनी गुस्ताखियां कम करने जैसा है। इसे ही आजकल जीवन का सकारात्मक रास्ता माना जा रहा है। एक बार मिली जिंदगी में कुछ ऐसा ही किया जाए, जिससे मन को कुछ संतुष्टि और शांति का एहसास हो।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

मनमानी कार्रवाई

'दोहरे मापदंड' (संपादकीय, पांच जनवरी) पढ़ा। मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप लगा कर तथा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की नीतियों के कारण अवैध रूप से घुसपैठ को आधार बना कर अमेरिकी सेना ने पिछले दिनों वेनेजुएला पर हमला किया। इसके बाद राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया। यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। वर्ष 2003 में राष्ट्रपति जार्ज बुश ने भी इराक में परमाणु हथियारों का जखीरा होने को आधार बना कर सैन्य कार्रवाई की थी और राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल कर दिया था। मगर आज तक यह सटीक प्रमाण नहीं मिला कि इराक के पास रसायनिक हथियारों का कोई जखीरा था। असल में इन दोनों देशों पर हमले का उद्देश्य इनके विशाल तेल भंडार तथा बहुमूल्य खनिजों पर कब्जा करना है। वेनेजुएला पर कार्रवाई अमेरिका की मनमानी है। उस पर हमला करके उसने बची-खुची नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अराजकता की ओर धकेल दिया है। हालांकि भारत ने इस मसले को बातचीत से सुलझाने और शांति कायम रखने पर जोर दिया है।

– वेद प्रकाश, गुरुग्राम

लापरवाही की हद

जल ही जीवन है। इस कथन से सभी वाकिफ हैं। देश के सबसे साफ-सुथरे शहर का खिताब पा चुके इंदौर में दूषित जल आपूर्ति से लोगों की मौत चिंता का विषय है। इससे शर्मनाक बात सरकार के लिए और क्या हो सकती है? शहर के भागीरथपुरा से लिए गए पानी के नमूनों की जांच रपट में यह सामने आया है कि शहरवासी जो पानी पी रहे थे, वह दूषित था। पानी में खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। दूषित पानी पीने से एक और महिला की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़ गई गई है। भागीरथपुरा इलाके में अब भी भय का माहौल है। लोग पानी पीने से भी डर रहे हैं। गलियां सुनसान पड़ी हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अस्पतालों में हैं। ऐसे में सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो।

– युगल किशोर राही, छपरा

खिलौने में बचपन

बच्चों के जीवन में खिलौनों का विशेष महत्त्व होता है। खिलौनों के माध्यम से ही बच्चों का पहला संवाद संसार से स्थापित होता है। वे न केवल मनोरंजन का साधन होते हैं, बल्कि कल्पनाशक्ति, भावनात्मक अभिव्यक्ति और सीखने की प्रक्रिया का भी अहम हिस्सा होते हैं। इसी तरह 'बाबलहेड' एक प्रकार की सिर हिलाने वाली गुड़िया है, जो बच्चों की हर बात पर सिर हिला कर मानो अपनी सहमति जताती है। यह सरल-सा हावभाव बच्चों को आनंदित करता है और उनमें अपनापन और संवाद का भाव पैदा करता है। 'बाबलहेड' जैसे खिलौनों के महत्त्व और उनकी प्रासंगिकता को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष सात जनवरी को 'राष्ट्रीय बाबलहेड दिवस' मनाया जाता है। यह दिवस याद दिलाता है कि बच्चों के लिए खिलौने केवल खेल की वस्तु नहीं, बल्कि बचपन की स्मृतियों और सीखने की नींव होते हैं, जिसे कायम रखना चाहिए।

– हिमांशु शेखर, गयाजी

राजनीति और संस्थान

आज देश भर के शिक्षण संस्थान राजनीति के अखाड़े बनते जा रहे हैं। शिक्षक और शिक्षण संस्थान विशुद्ध रूप से समाज एवं देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं और रहने भी चाहिए। मगर आज यह गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है कि शिक्षण संस्थानों में छात्रों और शिक्षकों द्वारा अकादमिक तथा सामाजिक व्यवहार राजनीति से प्रेरित होता जा रहा है। छात्रों का शिक्षकों से और शिक्षकों का छात्रों के साथ अकादमिक संबंध नहीं रहे। इसके बजाय आपसी भेद करने वाली भावना ज्यादा बलवती होती जा रही है। शिक्षकों को समान दृष्टि रखनी चाहिए और बेहतर सोच के साथ ज्ञान देना चाहिए, जबकि वे राजनीतिक खांचों के आधार पर स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं। शिक्षण महज पैसा कमाने का धंधा नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों के साथ बेहतर समाज बनाने का कार्य है।

– मुकेश कुमार, द्वारका, दिल्ली

अमृत विचार

शुक्रवार, 9 जनवरी 2026

आगे बढ़ने का रहस्य शुरुआत करना है।
मार्क ट्वेन, अमेरिकी लेखक

श्वान संकट का समाधान

श्वान और इंसान का संबंध हजारों वर्षों पुराना है। सुरक्षा, सहचर्य, प्रेम और वफादारी का यह रिश्ता आज एक विद्रूप सामाजिक संकट बनकर अदालत के कठघरे तक पहुंच गया है। सवाल यह है कि इस स्थिति का दोषी कौन है- आम आदमी, व्यवस्था या कुत्ता? तो जवाब होगा कि वह सभी जिसने इस संकट को यहां तक आने दिया। कुत्ता स्वभाव से आक्रामक नहीं होता; उसे ऐसा बनाता है अव्यवस्थित शहरीकरण, लापरवाह पालतू-पालन, कमजोर नगर प्रशासन और नीति-क्रियान्वयन की लगातार विफलता। सुप्रीम कोर्ट की चिंता पूरी तरह जायज है। पालक के नियंत्रण से बाहर कुत्ते केवल रेबीज का खतरा ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं, बच्चों-बुजुर्गों पर हमलों, स्थायी अपंगता और मौत का कारण भी बन रहे हैंस लेकिन करोड़ों आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान न तो क्रूर हो सकता है, न ही भावुक, इसके लिए वैज्ञानिक, मानवीय और दीर्घकालिक नीति चाहिए।

उत्तर प्रदेश ने आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाने, दोबारा काटने पर आजीवन शेल्टर में भेजने जैसे कई नियम बनाए, लेकिन डॉग-बाइट और रेबीज से होने वाली मौतें अभी भी बहुत हैं। यूपी की पहल ठीक है, लेकिन अधिकांश राज्यों की गंभीरता सवालों के घेरे में है। नवंबर में जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया, तो कोई उपस्थित नहीं हुआ। हलफनामा मांगा गया- मात्र 10 राज्यों ने दिया। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब जैसे बड़े राज्यों की चुप्पी प्रशासनिक उदासीनता को ही दर्शाती है। केंद्र और राज्यों ने पिछले दो दशकों में एनीमल बर्थ कंट्रोल और एंटी-रेबीज कार्यक्रमों के नियम तो बनाए, पर क्रियान्वयन बेहद कमजोर रहा। देशभर में महज 66 एबीसी केंद्र प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, जबकि कुत्तों की आबादी बेकाबू है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पांच-पांच लाख, गुजरात और कर्नाटक में लगभग चार-चार लाख लोगों को कुत्तों ने काटा। इसके बावजूद इसके लिए बजट, प्रशिक्षित मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे का उचित प्रबंध नहीं हुआ। संस्थानों को 'कुत्ता-मुक्त' रखने के लिए फेंसिंग का आदेश व्यावहारिक नहीं। रेलवे स्टेशन बहु-दिशात्मक खुले परिसर हैं, तो 16 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में से अनेक के पास बिजली-पानी तक का बजट नहीं— वे बाड़बंदी कैसे करें? कुत्तों को शेल्टर होम में रखना भी अव्यावहारिक है। अनुमानित एक लाख शेल्टर होम पर लगभग 30,000 करोड़ की पूंजी, चिकित्सा-खानपान पर सालाना भारी खर्च और बीमारियों का जोखिम। सीएसवीआर मॉडल यानी पकड़ो, नसबंदी करो, वैक्सीन लगाओ और जहां से लाए वहीं छोड़ो— वैज्ञानिक रूप उचित लगता है, बशर्ते इसे बड़े पैमाने, पर्याप्त बजट, सटीक डेटा और कड़ी निगरानी के साथ लागू किया जाए। इसके साथ पालतू कुत्तों के अनिवार्य पंजीकरण, लापरवाही पर जुर्माना, उचित कचरा निस्तारण और समुदाय-स्तरीय जागरूकता अनिवार्य है।

दुनिया के कई देशों— जैसे जापान, नीदरलैंड्स और सिंगापुर ने कड़े पंजीकरण, व्यापक नसबंदी, जिम्मेदार पालतू-पालन और सख्त नगर प्रबंधन से इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया है। भारत, जहां रेबीज से सबसे अधिक मौतें होती हैं, इन अनुभवों से सीख लेनी होगी।

प्रसंगवश

2030 तक रैबीज खत्म करने का लक्ष्य

भारत में रेबीज वायरस एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बना हुआ है। हर साल लाखों एनिमल बाइट्स (ज्यादातर कुत्तों के काटने) के मामले दर्ज होते हैं और इससे हजारों मौतें होने का अनुमान है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में लगभग 5,700 मौतें रेबीज के कारण हुईं, लेकिन पिछले दशकों की तुलना में यह संख्या कम रही है, जो सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है।

भारत में रेबीज मुख्य रूप से आवारा कुत्तों के काटने या खरोंचने से फैलती है। वायरस संक्रमित जानवर की लार या थूक के माध्यम से मनुष्य में प्रवेश करता है। भारत में रेबीज के अधिकांश मामले कुत्तों से ही जुड़े होते हैं, हालांकि रेबीज वायरस कुत्ते के अलावा बिल्ली, बंदर और अन्य जानवरों से भी फैल सकता है। जागरूकता की कमी ने भारत में आवारा कुत्तों के प्रति नफरत और डर को काफी बढ़ा दिया है, खासकर 2025-2026 के दौरान जब कुत्तों के काटने के मामले और रेबीज से मौतों की खबरें तेजी से फैलीं। सभी आवारा कुत्ते भी रेबीज से संक्रमित नहीं होते। ज्यादातर काटने की घटना भूख, डर, या क्षेत्र की रक्षा के कारण होते हैं। देश में कुत्तों की छह करोड़ से अधिक संख्या, अपर्याप्त नसबंदी एवं टीकाकरण साथ ही नियमित भोजन न मिलने से भी आक्रामकता बढ़ती है।

अंबिका अंबी
लेखिका

रेबीज वायरस किसी भी कुत्ते के शरीर में जन्मजात पैदा नहीं होता या मां से बच्चे में जन्म से नहीं मिलता। रेबीज एक संक्रामक वायरस है, जो संक्रमित जानवर से दूसरे में फैलता है। प्रकृति में रेबीज वायरस का सबसे पुराना और मूल रिजर्वायर चमगादड़ हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, लगभग सभी लिसावायरस चमगादड़ों से शुरू हुए और समय के साथ यह वायरस अन्य जानवरों में फैला। भारत में आवारा कुत्ते ही सबसे बड़ा स्रोत हैं। ज्यादातर कुत्ते दूसरे संक्रमित कुत्तों के काटने से रेबीज ग्रस्त होते हैं और फिर वे और कुत्तों या मनुष्यों को संक्रमित करते हैं। वायरस कुत्तों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी) को प्रभावित करती है।

इंसानों में भी वायरस संक्रमण मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। यह मुख्य रूप से संक्रमित जानवर कुत्ते या बिल्ली के काटने, खरोंचने या लार के संपर्क से फैलता है। लक्षण दिखने के बाद यह लगभग शत्-प्रतिशत जानलेवा होता है, लेकिन संपर्क के तुरंत बाद घाव की सफाई, एंटी-रेबीज वैक्सीन और पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस से इसे पूरी तरह रोका जा सकता है।

रेबीज वायरस को रोकने के लिए जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, यदि समय पर सही कदम उठाए जाए तो वायरस को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। आवारा कुत्तों में अधिक से अधिक टीकाकरण कवरेज से रेबीज का चेन टूट सकता है। भारत में पशु जन्म नियंत्रण अधिनियम 2023 के तहत कैप्चर-स्टेरिलाइज़- वैक्सिनेट- रिलीज़ मॉडल अपनाया जा रहा है। पेट डॉग्स (पालतू कुत्ते) को सालाना रेबीज वैक्सीन और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए। नगर निगम वैक्सीन लगाने की सरकारी नीतियों का पालन अनिवार्यता से करे। चूंकि भारत में रेबीज का मुख्य स्रोत आवारा कुत्ते हैं और पिछले कुछ वर्षों में सरकार, विश्व स्वास्थ संगठन और विभिन्न संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। 2030 तक भारत को डॉग-मीडिएटेड ह्यूमन रेबीज से मुक्त करने का लक्ष्य है। अपवाहों और मिथकों से डरने के बजाय, उन्हें समझकर और जिम्मेदारी से संभालकर हम रेबीज को खत्म कर सकते हैं।

क्या धरती को निगल सकता है ब्लैक होल!

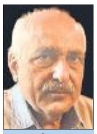

रणबीर सिंह
विज्ञान लेखक

> ब्लैक होल्स की जबरदस्त ताकत देखकर एक अहसास का जन्म होता है कि भविष्य में पृथ्वी या हमारा सौर मंडल क्या कभी एक ब्लैक होल द्वारा निगला जा सकता है? ऐसा न हो इसके लिए हमें एक ब्लैक होल से कितना दूर होना चाहिए?

ब्लैक होल्स की जबरदस्त ताकत को देखकर पृथ्वी वासियों में एक अहसास का जन्म होता है कि भविष्य में पृथ्वी या हमारा सौर मंडल क्या कभी एक ब्लैक होल द्वारा निगला जा सकता है? ऐसा न हो इसके लिए हमें एक ब्लैक होल से कितना दूर होना चाहिए? क्या एक ब्लैक होल हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर सकता है? ब्लैक होल तब बनता है, जब हमारे सूर्य के द्रव्यमान से कहीं अधिक द्रव्यमान वाले तारे का सारा हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाए और अत्यधिक गुरुत्व बल उत्पन्न होने से वह एक ब्लैक होल बन जाए। चूंकि सूर्य का द्रव्यमान उस तारे की अपेक्षा 20 गुणा छोटा है, जो एक ब्लैक होल बन सकता है, इसलिए इसके एक ब्लैक होल बनकर धरती को निगलने की संभावना न्यूनतम है।

सूरज लगभग पांच अरब साल बाद अपना हाइड्रोजन फ्यूल खत्म कर देगा और एक रेड जायंट बन जाएगा और शायद बुध और शुक्र को निगल लेगा। रेड जायंट फेज लगभग 10 करोड़ साल तक चलेगा, जिसके बाद सूरज अपनी बाहरी परतें हटा देगा और एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। फिर भी एक विशाल ब्लैक होल से पृथ्वी के लिए न्यूनतम सुरक्षित दूरी घटना क्षितिज अर्थात इवेंट होराइजन से लगभग 70 लाख किलोमीटर होनी चाहिए। इससे कम दूरी होने पर चुंबकीय-ज्वारीय बल मानव शरीर के लिए खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो जाते हैं। एक ब्लैक होल की ताकत का प्रभाव बहुत होता है। इससे बचने के लिए एक वस्तु को इससे दूरी बनाए रखने के लिए पलायन वेग या एस्केप विलोसिटी प्रकाश की गति के बराबर तो होनी ही चाहिए।

निकटतम ब्लैक होल गेया-1 हमसे 1560 प्रकाश वर्ष और गेया-2 पृथ्वी से 3800 प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं। वे हमारे दरवाजे पर नहीं खड़े हैं। अंतरिक्ष में पिंडों के वजूद में आने की प्रक्रिया के समय एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बना कर रखने का गुण गति, गुरुत्व बल और चुंबकत्व जैसी खगोलीय शक्तियों से तय हुआ होगा। ब्लैक होल के बॉर्डर एरिया को अस्थिर माना जाता है। इस ज़ोन में फ्लेयर्स, जेट्स और विकिरण के उफान का खतरा रहता है। इन डायनामिक घटनाओं का अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि टेढ़े-मेढ़े अथवा कर्व्ड स्पेस और ब्लैक होल के आस-पास की अंतरिक्ष भौतिकी के बारे में सटीक गणितीय ब्योरा जुटाना चुनौती है।

मसलन, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के मामले में, इवेंट होराइजन एक ऐसी सीमा है, जिसके इस पार की घटनाएं दूसरी ओर मौजूद ऑब्ज़र्वर को प्रभावित नहीं कर सकतीं। यह वह पॉइंट है, जहां ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल असर इतना मज़बूत होता है कि रोशनी भी उससे बच नहीं सकती। यह सीमा कोई फिजिकल सतह नहीं है, बल्कि एक मैथमेटिकल निशान है, जो उस पॉइंट को मार्क करता है, जहां से वापस नहीं आया जा सकता। एक बार जब कोई चीज़ इवेंट होराइजन को पार करके ब्लैक होल की तरफ खिंचती चली जाती है, तो वह हर हाल में ब्लैक होल के सेंटर की ओर जाती है। होराइजन के अंदर पैदा होने वाला कोई भी रेडिएशन कभी भी उससे बाहर नहीं निकल सकता। इवेंट होराइजन शांत, अदृश्य और बेरहम होता है। पकड़ में आने के बाद वस्तु का इससे बचना नामुमकिन है। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन स्पेसटाइम की ज्योमेट्री में एक ऐसे पॉइंट को परिभाषित करता है, जहां एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति के बराबर होती है।

अमरीका में फ्लैटिरॉन इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च टीम द्वारा प्रस्तुत एक नई मॉडलिंग स्टडी सामने आई है, जिसमें अब तक के सबसे डिटेल्ड सिमुलेशन करके, अर्थात ब्लैक होल के निकट की असल स्थितियों के डाटा को सुपरकंप्यूटर में फीड करके देखा गया कि एकल तारे से बने ब्लैक होल अलग-अलग रेट पर मैटर को कैसे निगलते और उगलते हैं। ब्लैक होल को कल्पना में काले भंवर जैसा दिखाया जाता है, लेकिन उसके पार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों होता है, इसके बारे में सिर्फ कच्चे अनुमान ही मौजूद हैं।

खास बात यह है कि फ्लैटिरॉन इंस्टीट्यूट की स्टडी पहले के मॉडल्स में इस्तेमाल किए गए सिंपलिफिकेशन पर निर्भर नहीं थी। पहले के प्रयासों के अंतर्गत की जाने वाली कैलकुलेशन से निष्कर्षों को मुमकिन बनाने के लिए शॉर्टकट्स की ज़रूरत होती थी, लेकिन इस नवीनतम सिमुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा को आधार बनाया गया। ब्लैक होल एक्रीशन फ्लो के सर्वे ऑब्ज़र्वेशन को उनके स्पिन और मैग्नेटिक फील्ड के मेज़र के साथ मिलाकर, दो पावरफुल सुपरकंप्यूटर का इस्तेमाल करके, टीम ने जो नया मॉडल पेश किया, उससे सूर्य से थोड़े बड़े द्रव्यमान वाले तारे से बने हुए ब्लैक होल के चारों ओर गैस, लाइट और मैग्नेटिज़्म की मूवमेंट के बारे में पता चला है।

मैग्नेटिक फील्ड में मेजर से अर्थ है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक करंट के साथ इनका इंटरेक्शन और अलग-अलग फील्ड में इनके एप्लीकेशन्स आदि। ब्लैक होल एक्रीशन फ्लो वह प्रोसेस है, जिससे गैस, धूल और दूसरे तरह के पदार्थ जो ब्लैक होल के बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल खिंचाव से उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। इस प्रोसेस से एक्रीशन डिस्क बनती है और अंदर आने वाली धारा भी।

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखी जाने वाली हाई-एनर्जी उत्सर्जन पैदा करने के लिए यह बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं। जिस एफिशिएंसी से गर्म गैस अपनी थर्मल एनर्जी रेडिएट करती हैं, वह एक्रीशन फ्लो की ज्योमेट्री और डायनामिक्स पर बहुत ज़्यादा असर डालती है, जिससे रेडिएटिव रूप से एफिशिएंट पतली डिस्क और रेडिएटिव रूप से इनएफिशिएंट मोटी डिस्क, दोनों देखी जाती हैं। एक्रीशन प्रोसेस ब्लैक होल फिजिक्स का एक बेसिक पहलू है और गैलेक्टिक इवोल्यूशन और फीडबैक मैकेनिज्म में अहम भूमिका निभाता है।

आमने सामने

कांग्रेस की गलत मंशा के चलते मनरेगा के तहत किए गए अधिकांश कार्य गांवों की समग्र विकास योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। नए वीबी-जी-राम जी कानून में इन सभी कमियों को दूर किया गया है। अब सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।

-भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री, राजस्थान

'वीबी-जी-राम जी' योजना ग्रामीण लोकतंत्र और मनरेगा के खिलाफ है। जिस पंचायती राज व्यवस्था से मुख्यमंत्री ने अपनी राजनीतिक पहचान बनाई, आज उसी को कमजोर करने के लिए वे केंद्र सरकार के ब्रांड एंबेसडर बने हुए हैं। योजना को नई व्यवस्था से खत्म करने की कोशिश की जा रही है।

-टीकाराम जूली
नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान

दूसरे देशों में जबरन घुसपैठ अमेरिकी फितरत

डॉ. शिवम भारद्वाज
असिस्टेंट प्रोफेसर

> 1945 के बाद अमेरिका द्वारा उठाया गया लगभग हर बड़ा सैन्य कदम किसी न किसी रणनीतिक, आर्थिक या शक्ति-संतुलन से जुड़े उद्देश्य से प्रेरित रहा है।

अमेरिकी हितों, प्राथमिकताओं और स्वार्थों को समझे बिना न तो इतिहास की सही व्याख्या संभव है और न ही वर्तमान वैश्विक राजनीति की। वस्तुतः, 1945 के बाद अमेरिका द्वारा उठाया गया लगभग हर बड़ा सैन्य कदम किसी न किसी रणनीतिक, आर्थिक, वैचारिक या शक्ति-संतुलन से जुड़े उद्देश्य से प्रेरित रहा है। इन उद्देश्यों को सामने लाने से ही यह स्पष्ट होता है कि अमेरिकी विदेश नीति आदर्शों से अधिक हितों द्वारा संचालित रही है।

1940 के दशक के उत्तरार्द्ध में चीन और ग्रीस में अमेरिकी हस्तक्षेप इसी सोच की उपज थे। चीन के गृहयुद्ध में अमेरिका की चिंता लोकतंत्र की रक्षा नहीं, बल्कि यह थी कि कहीं एशिया का एक विशाल भूभाग सोवियत प्रभाव क्षेत्र में न चला जाए। ग्रीस में भी अमेरिकी सहायता का लक्ष्य किसी आंतरिक राजनीतिक समाधान को प्रोत्साहित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि भूमध्यसागर क्षेत्र में साम्यवादी प्रभाव न फैले। यहीं से यह मानसिकता विकसित हुई, जिसे बाद में 'डोमिनो थ्योरी' कहा गया। यह आशंका कि यदि एक देश हाथ से निकल गया तो पूरा क्षेत्र क्रमशः अमेरिका के प्रभाव से बाहर हो जाएगा।

1950 का दशक इस नीति का औपचारिक विस्तार था। कोरियाई युद्ध में अमेरिका का हित केवल दक्षिण कोरिया की सुरक्षा तक सीमित नहीं था। एशिया में अपनी सैन्य विश्वसनीयता स्थापित करना और यह संदेश देना कि अमेरिका अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए युद्ध करने को तैयार है, इस हस्तक्षेप का केंद्रीय उद्देश्य था। इसी दशक में ईरान और ग्वाटेमाला में हुए तख्तापलट अमेरिकी हितों की और भी स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं।

1960 का दशक आते-आते अमेरिकी हस्तक्षेप और अधिक आक्रामक हो गए। क्यूबा में बे ऑफ पिग्स का असफल अभियान इस बात का प्रमाण था कि अमेरिका अपने प्रभाव क्षेत्र में किसी समाजवादी सरकार के अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसके बाद वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में हुआ हस्तक्षेप केवल युद्ध नहीं था, बल्कि एक पूरे क्षेत्र को वैचारिक प्रतिस्पर्धा का मैदान बना देना था। उद्देश्य स्पष्ट था- दक्षिण-पूर्व एशिया को सोवियत और चीनी प्रभाव से बचाना, चाहे इसकी कीमत तमाम नागरिकों की जान ही क्यों न हो। डोमिनिकन रिपब्लिक में प्रत्यक्ष आक्रमण और कंबोडिया में व्यापक बमबारी इस भय से प्रेरित थीं कि कहीं क्षेत्रीय सत्ता-संतुलन अमेरिका के नियंत्रण से बाहर न चला जाए। इन हस्तक्षेपों ने यह दिखा दिया कि अमेरिका के लिए क्षेत्रीय प्रभुत्व, मानवीय लागत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था।

1970 के दशक में अमेरिकी स्वार्थों का स्वरूप कुछ बदला, लेकिन मूल तर्क वही रहा। चिली में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का पतन इस कारण हुआ कि वह अमेरिकी आर्थिक और वैचारिक ढांचे को चुनौती दे रही थी। अंगोला में प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय प्रॉक्सी हस्तक्षेप अपनाया गया, ताकि अफ्रीका में सोवियत प्रभाव को सीमित किया जा सके, बिना अमेरिकी सैनिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी के। अमेरिका ने यह सीख ली थी कि परोक्ष हस्तक्षेप न केवल सस्ता पड़ता है, बल्कि घरेलू राजनीतिक असहमति भी कम पैदा करता है।

1980 का दशक मध्य अमेरिका और पश्चिम एशिया में अमेरिकी रणनीतिक हितों का दशक था। एल साल्वाडोर और निकारागुआ में हस्तक्षेप 'कम्युनिज़्म विरोध' के नाम पर किया गया, लेकिन इसके पीछे पनामा नहर जैसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक हितों की सुरक्षा और क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव बनाए रखना प्रमुख कारण थे। लेबनान, ग्रेनेडा और पनामा में सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य यह संदेश देना था कि अमेरिका अपने निकट और रणनीतिक क्षेत्रों में किसी भी चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा। लीबिया पर हवाई हमले भी केवल तत्काल प्रतिक्रिया नहीं थे, बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी दबदबे का प्रदर्शन थे।

शीतयुद्ध समाप्त होने के बाद यह उम्मीद की गई थी कि अमेरिकी हस्तक्षेपों का दौर समाप्त होगा, लेकिन 1990 का दशक इस भ्रम को तोड़ता है। खाड़ी युद्ध में ईराक के खिलाफ कार्रवाई का केंद्रीय कारण था— तेल आपूर्ति की सुरक्षा और खाड़ी क्षेत्र में शक्ति-संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखना। सोमालिया, बोस्निया और कोसोवो में किए गए हस्तक्षेपों को मानवीय कहा गया, लेकिन इनके पीछे नाटो की प्रासंगिकता बनाए रखना और यूरोप में अमेरिकी नेतृत्व को मजबूत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था।

इक्कीसवीं सदी में आतंकवाद अमेरिकी हस्तक्षेपों का प्रमुख औचित्य बन गया। अफगानिस्तान में युद्ध का उद्देश्य केवल अल-कायदा को खत्म करना नहीं था, बल्कि मध्य एशिया में दीर्घकालिक सैन्य उपस्थिति स्थापित करना और क्षेत्रीय भू-राजनीति को प्रभावित करना भी था। 2003 में ईराक पर किया गया आक्रमण कथित विनाशकारी हथियारों के नाम पर हुआ, लेकिन इसके पीछे पश्चिम एशिया में सत्ता-संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ने और ऊर्जा संसाधनों पर प्रभाव बनाए रखने की इच्छा भी स्पष्ट थी।

सोशल फोरम

गोवा में भारतीय कार्रवाई पर खामोश रहा था नाटो

आज जब अमरीका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है, जो एक नाटो सदस्य देश का अंग है, तो ऐसी एक घटना पर ध्यान देना चाहिए जो भारत से जुड़ी है

प्रवीण झा
लेखक

1961 में जब भारत ने गोवा, दमन और दीव पर सैन्य कार्रवाई कर, उन्हें पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया, उस समय पुर्तगाल नाटो (NATO) का सदस्य था। इसके बावजूद नाटो ने भारत के विरुद्ध कोई सामूहिक सैन्य कार्रवाई नहीं की। यह तथ्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं और नाटो की वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद करता है।

सबसे पहला कारण यह था कि नाटो एक सामूहिक रक्षा संगठन है, आक्रामक युद्धों में हस्तक्षेप करने वाला वैश्विक पुलिस बल नहीं। नाटो की संधि का अनुच्छेद-5 तभी लागू होता है, जब किसी सदस्य देश पर उसके अपने क्षेत्र में सशस्त्र हमला हो। गोवा उस समय यूरोप में स्थित पुर्तगाल का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक उपनिवेश था। कई नाटो देशों की नजर में उपनिवेशों की रक्षा को अनुच्छेद 5 के अंतर्गत लाना कानूनी रूप से स्पष्ट नहीं था।

दूसरा महत्वपूर्ण कारण था, औपनिवेशिक व्यवस्था का पतन। 1960 के दशक तक विश्व समुदाय में उपनिवेशवाद के विरुद्ध माहौल बन चुका था। भारत की कार्रवाई को कई देशों ने औपनिवेशिक शासन के अंत के रूप में देखा, न कि एक संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण के रूप में। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे नाटो के प्रभावशाली सदस्य भारत को शीत युद्ध के संदर्भ में पूरी तरह विरोधी खेमे में धकेलना नहीं चाहते थे।

तीसरा कारण था रणनीतिक यथार्थवाद। भारत एक बड़ा, स्थिर और क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण देश था। गोवा के लिए भारत से युद्ध करना न तो व्यावहारिक था और न ही नाटो के दीर्घकालिक हितों में।

इस प्रकार, कानूनी सीमाओं, बदलते वैश्विक नैतिक दृष्टिकोण और रणनीतिक हितों के कारण नाटो ने पुर्तगाल का साथ देकर युद्ध में उतरने से परहेज़ किया। यह घटना दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन भी हमेशा अपने घोषित सिद्धांतों से नहीं, बल्कि परिस्थितियों और हितों से संचालित होते हैं।

-फेसबुक वाल से

सामयिकी

महिला सशक्तिकरण की राह खोलेगी पीरियड लीव

हाल ही में कर्नाटक ने महिला कर्मचारियों को पीरियड लीव देने का फैसला किया है। इसके बाद एक बार फिर इस विषय पर बहस छिड़ गई है कि महिलाओं को पीरियड लीव मिलनी चाहिए या नहीं? असल में आधुनिक भारत में जहां महिलाएं अंतरिक्ष से लेकर सीमा सुरक्षा तक हर मोर्चे पर नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन वे अपने 'उन दिनों' की परेशानी को लेकर मौन हैं। उनकी एक जैविक प्रक्रिया होती है मासिक धर्म। इसे लेकर आज भी देश और प्रदेश में महिला कर्मचारी कार्यस्थलों पर मौन रहती हैं और अपने इस मौन के कारण पीड़ा को झेलती रहती हैं।

भले ही भारत के केंदीय कानून में इसे जगह नहीं मिल पाई है, लेकिन हाल के वर्षों में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए पीरियड लीव की मांग जोर पकड़ गई है। इस पर बहस भी प्रारंभ हो गई है कि यह अवकाश महिलाओं का अधिकार है। यह केवल एक अवकाश की मांग नहीं है, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण कार्य परिवेश की दिशा में एक बड़ा कदम है। कर्नाटक से पहले बिहार और केरल जैसे राज्यों और कई निजी कंपनियों ने इसे लागू कर रखा है।

डॉ. मोनिका शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार

चिकित्सकों के अनुसार, मासिक धर्म केवल रक्तस्राव की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शरीर में होने वाले तीव्र हार्मोनल बदलावों का समय होता है। एक कामकाजी महिला को इस दौरान कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें गर्भाशय में संकुचन के कारण पेट के निचले हिस्से और पीठ में असहनीय दर्द होता है। कई महिलाओं के लिए यह दर्द इतना तीव्र होता है कि सामान्य रूप से खड़ा होना या बैठना भी मुश्किल हो जाता है। भारी रक्तस्राव के कारण शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर में अस्थायी गिरावट होती है। इससे महिलाओं को कमजोरी महसूस होती है। कई महिलाएं प्री-मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का शिकार रहती हैं। ऐसी महिलाओं में चिड़चिड़ापन, एंग्जायटी, और डिप्रेशन जैसी स्थिति पैदा होती है।

वहीं काम के भारी दबाव के बीच मासिक धर्म का दर्द उनकी एकाग्रता में कमी लाता है, जो उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। इसके अलावा जी मिचलाना, उल्टी, सिर दर्द और पाचन संबंधी समस्याएं भी पैदा होती हैं। सरकारी कार्यालयों में अक्सर काम का निश्चित समय होता है, इसलिए पीरियड लीव एक जरूरत है। इसके पीछे कई ठोस वजह हैं। जब एक महिला कर्मचारी शारीरिक पीड़ा में होती है, तो उसकी उत्पादकता स्वतः कम हो जाती है। एक या दो दिन का विश्राम उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से पुनर्जीवित करता है, जिससे वे बाद में अधिक ऊर्जा के साथ काम कर पाती हैं।

दरअसल कार्यस्थल को महिलाओं के अनुकूल बनाने का अर्थ है, उनकी जैविक वास्तविकताओं को स्वीकार करना। पीरियड लीव देना भेदभाव नहीं, बल्कि समान अवसर प्रदान करने का एक हिस्सा है। कई पुराने सरकारी कार्यालयों में आज भी महिलाओं के लिए स्वच्छ शौचालय और सैनिटरी पैड डिस्पोजल की उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में दर्द के साथ काम करना उनके संक्रमण के जोखिम को बढ़ा देता है। इस दौरान महिला कर्मचारी अपनी आकस्मिक छुट्टी (सीएल) या मेडिकल लीव (एमएल) का उपयोग करती हैं, जो कि काफी नहीं है।

भारत में पीरियड लीव (मासिक धर्म अवकाश) को लेकर कोई केंद्रीय कानून नहीं है, लेकिन 'पेड पीरियड लीव' और 'मुफ्त सैनिटरी उत्पाद' के लिए एक विधेयक साल 2022 में पेश किया गया था जो कानून नहीं बन सका। इस पर कर्नाटक और बिहार जैसे कुछ राज्यों और कई निजी कंपनियों ने अपनी नीतियां बनाई हैं।

स्वामी-रुहेलखंड इंटरप्राइजेज के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक हरि ओम गुप्ता द्वारा अमृत विचार प्रकाशन, नवादा जोगियान, चक रोड, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के सामने, बरेली (उ.प्र.), पिन कोड-243006 से मुद्रित एवं 932 कटरा चांद खां, भारत पेट्रोल पंप के सामने पीलीभीत बाईपास रोड बरेली (उ.प्र.) पिन कोड-243005 से प्रकाशित। **संपादक- राजेश श्रीनेत, स्थानीय संपादक- नवीन गुप्ता*** 0581-4000222 (कार्यालय), ईमेल- editorschoice@amritvichar.com, आर.एन.आई नं0-UPHIN/2019/78502, *इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी। (नोट-सभी विवादों का न्यायक्षेत्र बरेली होगा)।

भारत की भलाई गुटनिरपेक्ष नीतियों में

समकालीन रमणीक जनतांत्रिक दुनिया अमेरिकी वर्चस्व और उसकी समर्थित हिंसक हस्तक्षेपवादी राजनीति से तभी ज्यादा महफ़ूज़ हो सकती है, जब शक्ति-संतुलन बहुध्रुवीय होगा, अंतरराष्ट्रीय क़ानून को वास्तविक दाँत मिलेंगे, और वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ के देश परस्पर मिलकर वैकल्पिक संस्थागत ढांचे खड़े करेंगे। ऐसा इसलिए कि केवल नैतिक अपील या यूएनओ की प्रतीकात्मक निंदा से, जैसा कि यूक्रेन, गाजा और वेनेजुएला पर हालिया हमले में उसका गैरजिम्मेदाराना रोल दिखा, स्थितियाँ नहीं बदलेंगी। इसलिए यक्ष प्रश्न है कि आखिरकार अमेरिका की हस्तक्षेपवादी राजनीति से कैसे सुरक्षित रहेंगे उसके प्रतिद्वंद्वी देश? इसलिए खतरे की असल प्रकृति को समझना पड़ेगा, फिर रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, उत्तर कोरिया, कम्बोडिया, क्यूबा, मेक्सिको आदि देशों को परस्पर मिलकर अमेरिकी आपराधिक प्रवृति को हतोत्साहित करना होगा। इस निमित्त चीन को भी अपनी विस्तारवादी नीति और ईरान को इस्लामिक पूर्वाग्रही नीति से तौबा करना पड़ेगा। अन्यथा तटस्थ देश भारत का सहयोग ग्लोबल साउथ को नहीं मिल पायेगा और वह मजबूरी में अमेरिका-इजरायल-जापान खेमे से सहयोग लेते रहने को अभिशप्त हो जाएगा। हालांकि, रूसी-चीनी मित्रता से और भारत-चीन की शत्रुता से भारत हमेशा सावधान रहता है और अमेरिका-यूरोप के प्रति भी सहानुभूति रखता है। लेकिन पश्चिमी देशों की दोगली नीति के चलते भारत की भलाई गुटनिरपेक्ष नीतियों में ही है। यह स्थिति भारत-रूसी मित्रता की प्रगाढ़ता के लिए भी अच्छी नहीं होगी। क्योंकि अमेरिका, रूस और चीन को आर्थिक व सैन्य दृष्टि से तेजी से मजबूत बनते भारत को रोकने का स्वांग रच कर उसको आंख दिखाने वाले विकासशील देशों पर अनैतिक कार्रवाई करके उन्हें अपने काबू में ले रहा है। दुनिया ने देखा कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर "ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व" के तहत राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ़्तार कर बाहर ले जाकर "देश चलाने" तक की बात कही, जो संप्रभुता पर सीधा हमला और पुराने मॉनरो सिद्धांत की वापसी है। ऐसा करके उसने इराक की तरह ही तेल और दुर्लभ खनिज संपदा का खेल शुरू कर दिया है। साथ ही कम्बोडिया, मेक्सिको, क्यूबा, ग्रीनलैंड, ईरान आदि को लेकर डॉनल्ड ट्रंफ ने जो धमकी दी है, वह हैरतअंगेज पर काबिलेगौर है। वहीं, बेनेज़ुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति से उन्होंने अपेक्षा जताई है कि वह रूस, चीन, ईरान और क्यूबा से अपने सम्बन्धों को न्यूनतम करें ताकि अमेरिका को रणनीतिक खतरों से बचाया जा सके। अभी तक का जो अमेरिकी इतिहास है, उसके दृष्टिगत लक्षित देश इराक, लीबिया, सीरिया, फिलिस्तीन, वियतनाम आदि की तरह बर्बाद हुए हैं। सच कहा जाए तो बेनेज़ुएला के तरह के एकतरफ़ा सैन्य ऑपरेशन को अंतरराष्ट्रीय क़ानून और यूएन चार्टर के उल्लंघन के रूप में कई विशेषज्ञों व देशों ने देखा, लेकिन स्थायी सदस्यों की राजनीति के कारण कोई ठोस दंडात्मक क़दम नहीं उठ पाया। स्पष्ट है कि रूस को यूक्रेन सहित पश्चिमी यूरोप से, भारत को पाकिस्तान-बंगलादेश समेत अन्य पड़ोसी देशों से और चीन को ताइवान सहित दक्षिण चीन सागर में उलझाने के बाद अब उसने नए सिरे से अमेरिकी विस्तारवाद का बिगुल फूंक दिया है। जिसका मकसद साफ है कि अमेरिका अब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में रूस, चीन, भारत, ब्राजील की दाल नहीं गलने देगा ताकि समय रहते ही ब्रिक्स की हवा निकल जाए। यह मुनरो सिद्धांत की वापसी है ताकि पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका अपराजेय बन जाए। कूटनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक, अब तक अमेरिका की रणनीति रही कि यूरोप में रूस, चीन, भारत की दाल नहीं गले। लेकिन जब उसने महसूस कर लिया कि जी-सेवन के अन्य यूरोपीय व एशियाई देश चीन, भारत, रूस व अरब देशों से सम्बन्ध प्रगाढ़ बना रहे हैं और अमेरिका से मदद लेकर यह सबकुछ कर रहे हैं तो डॉनल्ड ट्रंफ ने इनकी आर्थिक नकेल कसनी शुरू कर दी। साथ ही खुद को पश्चिमी गोलार्द्ध यानी उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका में मजबूत करने का संकल्प लिया और बेनेज़ुएला से अमल प्रारंभ कर दिया और भावी इरादे भी स्पष्ट कर दिए। इससे भविष्य में अमेरिका का प्रतियोगी बनने की चाहत रखने वाले सभी देशों में हड़कंप मचा हुआ है। कल तक जो डॉलर को रिप्लेस करने का स्वप्न पाले हुए थे, वो अब अपने समर्थकों को भी अमेरिका के खूनी पंजों से बचा नहीं पा रहे हैं। वहीं, हैरत की बात है कि अब तक इस्लामिक देशों के आतंकवादियों के मार्फ़त अपनी दादागिरी चलाने वाला अमेरिका अब खुद ही सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर उतर आया है जो ब्रिक्स देशों को खुली चुनौती है कि जोर है तो रोक लो। शायद इसलिए अमेरिका रूस, चीन, भारत से एक एक करके अपने रिश्ते तो मजबूत रखना चाहता है, लेकिन इन्हें परस्पर भिड़ाये रखना भी चाहता है ताकि ये तीनों देश कभी एक न हो पाएं और अमेरिका की दादागिरी उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक चलती रहे। यही वजह है कि वैश्विक ढांचे में सुधार की जरूरत है। इसमें भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, जापान और जर्मनी जैसे देशों को शामिल करने की आवश्यकता है। क्योंकि दुनिया ने देखा कि यूएन सुरक्षा परिषद में पी-5 वीटो की असीमित शक्ति ने यूक्रेन, गाज़ा और वेनेज़ुएला जैसे मामलों में पक्षपात और पंगुता साबित की है, इसलिए प्रस्ताव है कि नरसंहार, युद्ध अपराध जैसे मुद्दों पर वीटो पर थीमैटिक प्रतिबंध लगे और उसकी सार्वजनिक जवाबदेही तय हो। "यूनाइटिंग फॉर पीस" और 2022 की Veto Initiative जैसे उपायों के ज़रिये जनरल असेंबली को ज़्यादा सक्रिय भूमिका देने की दिशा उभर रही है, जिससे एकतरफ़ा दखल पर सामूहिक राजनीतिक लागत बढ़े। इसलिए बहुध्रुवीय शक्ति-संतुलन जरूरी है। BRICS और BRICS+ का विस्तार 2025 के बाद से पश्चिमी प्रभुत्व के मुकाबले एक वैकल्पिक आर्थिक-राजनीतिक धुरी बना रहा है, जहाँ "फेयर एंड रिप्रेज़ेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर" का लक्ष्य रखा गया है।

कटाक्ष | सुरेश मिश्र

ट्रंप तुम्हारे कर्म से जग में है हड़कंप
दुश्मन भी कर रहे हैं,मेढक जैसा जंप
मेढक जैसा जंप,मादुरो को ले भागे
बचना मियां मुनीर,अगर मोदी जी जागे
कह सुरेश कविराय, खल को कर देंगे डंप
पुतिन करो तुम भी वही, जो करते हैं ट्रंप

भारत बनेगा ब्लू इकोनॉमी का पावर हाउस

वैश्विक स्तर पर जहाज निर्माण में चीन, दक्षिण कोरिया और जापान का दबदबा है, जबकि भारत इस रैंकिंग में 20वें स्थान के आसपास है। वैश्विक स्तर पर जहाज निर्माण में भारत का हिस्सा सिर्फ 0.1 प्रतिशत से भी कम है, लेकिन अब मोदी सरकार इसे बदलना चाहती है। इसलिए सरकार ब्लू इकोनॉमी को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है।

भारत एक ऐसा देश है जिसकी 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और तीन तरफ से समुद्र घिरा हुआ है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में समुद्री व्यापार की बड़ी भूमिका है। लगभग 95 प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। लेकिन अब तक भारत जहाज निर्माण में बहुत पीछे रहा है। इसे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने 44700 करोड़ खर्च करने की तैयारी कर ली है। वैश्विक स्तर पर जहाज निर्माण में चीन, दक्षिण कोरिया और जापान का दबदबा है और ये तीन देश मिलकर 95 प्रतिशत से ज्यादा जहाज बनाते हैं। भारत का हिस्सा सिर्फ 0.1 प्रतिशत से भी कम है और वैश्विक रैंकिंग में 20वें स्थान के आसपास है। वैश्विक स्तर पर जहाज निर्माण में भारत का हिस्सा सिर्फ 0.1 प्रतिशत से भी कम है और वैश्विक रैंकिंग में 20वें स्थान के आसपास है। मोदी सरकार इसे बदलना चाहती है। अब सरकार ब्लू इकोनॉमी को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है समुद्र के संसाधनों का टिकाऊ इस्तेमाल। जैसे मछली पकड़ना, बंदरगाह, जहाजरानी, समुद्री ऊर्जा, पर्यटन और जहाज निर्माण। इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, रोजगार बनेगा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत जहाज निर्माण में विश्व के टॉप-5 देशों में शामिल हो जाए। इसके लिए हाल ही में दो बड़ी योजनाओं के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, 1- शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम और दूसरा - शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम। इन पर कुल 44,700 करोड़ रुपए खर्च

होंगे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जहाज निर्माण क्षेत्र को नई नीति मिली है। ये दिशानिर्देश पारदर्शी और स्थिर ढाँचा बनाएँगे, जिससे घरेलू जहाज निर्माण फिर से जीवित होगा। इससे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा, बड़े निवेश आएँगे और विश्व स्तरीय क्षमता बनेगी। भारत विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की राह पर एक बड़ी समुद्री राष्ट्र बनेगा।" जानकारी के अनुसार मोदी सरकार की शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम और शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम योजनाएँ सितंबर 2025 में कैबिनेट से मंजूर 69,725 करोड़ रुपए के पैकेज का हिस्सा हैं। दिसंबर 2025 में इनके ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी हुए। दोनों योजनाएँ 31 मार्च 2036 तक चलेंगी और 2047 तक बढ़ाई जा सकती हैं। शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम का बजट 24,736 करोड़ रुपये है। इसमें भारतीय जहाज निर्माण कंपनियों को हर जहाज पर 15 से 25 प्रतिशत तक वित्तीय मदद मिलेगी। यह मदद जहाज के प्रकार पर निर्भर करेगी, जिसमें छोटे सामान्य जहाज, बड़े सामान्य या विशेष जहाज होंगे। सरकार की ओर से मदद चरणबद्ध तरीके से मिलेगी, स्टेप-दर-स्टेप काम पूरा होने के आधार पर। इसके साथ ही सीरीज ऑर्डर पर अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। एक नई सुविधा है शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट। अगर कोई पुराना जहाज भारतीय यार्ड में तोड़ा जाता है, तो मालिक को स्क्रैप वैल्यू का 40 प्रतिशत क्रेडिट मिलेगा। इसे नए जहाज बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और पुराने जहाज से नए बनेंगे। जानकारी के अनुसार अगले दशक में यह योजना 96,000 करोड़ रुपए के जहाज निर्माण प्रोजेक्ट सपोर्ट करेगी। इससे घरेलू विनिर्माण बढ़ेगा और लाखों रोजगार बनेंगे। शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम - मोदी सरकार की इस योजना का बजट 19,989 करोड़ रुपये है। यह लंबे समय की क्षमता बनाने पर फोकस करती है। इसमें नए ग्रीनफील्ड जहाज निर्माण क्लस्टर बनेंगे। केंद्र और राज्य मिलकर 50रू50 स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाएँगे, जो सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 प्रतिशत पूँजी मदद देगा। पुराने ब्राउनफील्ड याड्र्स को आधुनिकीकरण के लिए 25 प्रतिशत मदद मिलेगी, जैसे ड्राई डॉक, शिपलिफ्ट, फैब्रिकेशन सुविधाएँ और ऑटोमेशन अपनाने पर। क्रेडिट रिस्क कवरेज फ्रेमवर्क से प्री-शिपमेंट, पोस्ट-शिपमेंट और वेंडर डिफॉल्ट रिस्क पर सरकारी इंश्योरेंस मिलेगा। इससे प्रोजेक्ट आसानी से फाइनेंस हो सकेंगे। इन योजनाओं से 2047 तक भारत की व्यावसायिक जहाज निर्माण क्षमता 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज प्रति वर्ष हो जाएगी। इससे रोजगार बढ़ेगा, स्वदेशी तकनीक विकसित होगी और समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी। जानकारों के अनुसार ब्लू इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिलहाल यह जीडीपी में 4 प्रतिशत योगदान देती है, लेकिन संभावना बहुत ज्यादा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक यह 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचे। सागरमाला प्रोजेक्ट इसके केंद्र में है। सागरमाला से बंदरगाह आधुनिक हो रहे हैं, तटीय आर्थिक जोन बन रहे हैं और लॉजिस्टिक्स लागत कम हो रही है। अब तक 839 प्रोजेक्ट्स की पहचान हुई है, जिनकी लागत 5.8 लाख करोड़ रुपए है। मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृत काल विजन 2047 में जहाज निर्माण को प्रमुख स्थान दिया गया है। विजन 2030 में 150 से ज्यादा पहल हैं, जिन पर 3-3.5 लाख करोड़ निवेश होगा। अमृत काल विजन 2047 में 80 लाख करोड़ निवेश का प्लान है। इससे भारत टॉप-10 से टॉप-5 जहाज निर्माण देश बनेगा। विश्व में जहाज निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। 2025 में ग्लोबल मार्केट 155 अरब डॉलर का है। चीन अकेला 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा रखता है, उसके बाद दक्षिण कोरिया और जापान। ये देश सब्सिडी, आधुनिक तकनीक और बड़े क्लस्टर से आगे हैं। भारत अब उसी रास्ते पर है- क्लस्टर बनाकर, फाइनेंशियल मदद देकर और रिस्क कवर देकर। पहले भारत की क्षमता बहुत कम थी, सिर्फ 0.1 मिलियन ग्रॉस टनेज प्रति वर्ष। कोचिन शिपयार्ड और हिंदुस्तान शिपयार्ड जैसे सार्वजनिक यार्ड मुख्य थे, लेकिन व्यावसायिक जहाज कम बनते थे। अब निजी क्षेत्र भी सक्रिय हो रहा है। जानकारों की माने तो भारत के लिए इस राह में आगे बढ़ने को लेकर काफी चुनौतियाँ हैं, जिसमें लागत ज्यादा होना, पुरानी तकनीकी, स्किल की कमी और महँगा फाइनेंस, लेकिन मोदी सरकार की योजनाएँ इन समस्याओं को दूर करेंगी। इस काम में नेशनल शिपबिल्डिंग मिशन समन्वय करेगा। स्वतंत्र मूल्यांकन और मीलस्टोन बेस्ड पेमेंट से पारदर्शिता आएगी। सरकार का विजन स्पष्ट है कि आत्मनिर्भर भारत में समुद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सागरमाला, डीप ओशन मिशन और पीएम मत्स्य संपदा योजना से ब्लू इकोनॉमी मजबूत हो रही है। जहाज निर्माण इसमें केंद्र है। अंत में ये योजनाएं सिर्फ जहाज बनाने की नहीं, बल्कि भारत को समुद्री महाशक्ति बनाने की हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था बुलंद होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश सुरक्षित रहेगा। 2047 तक विकसित भारत का सपना समुद्र से भी पूरा होगा।

■ रामस्वरूप रावतसरे

विकास को मापने का सही पैमाना क्या?

किसी भी देश की प्रगति, नीति- निर्माण और भविष्य की दिशा तय करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है कि विकास को मापने के लिए सही संकेतकों का चयन किया जाए। आर्थिक इतिहास में लंबे समय तक जीडीपी को विकास का सबसे प्रमुख और लगभग सर्वमान्य पैमाना माना गया। सरकारें, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और निवेशक सभी जीडीपी के आँकड़ों के आधार पर किसी देश की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करते रहे हैं। लेकिन समय के साथ-साथ यह प्रश्न गहराता गया कि क्या केवल उत्पादन, आय और बाजार गतिविधियाँ ही विकास का वास्तविक माप हो सकती हैं? क्या बढ़ती अर्थव्यवस्था अपने-आप नागरिकों के जीवन को बेहतर, सुखी और सुरक्षित बना देती है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की प्रक्रिया में एनडीपी मतलब नेट घरेलू उत्पाद और आगे चलकर जीएनएच सकल राष्ट्रीय खुशी जैसे वैकल्पिक और अधिक व्यापक संकेतक सामने आए। यह लेख जीडीपी, एनडीपी और जीएनएच तीनों की अवधारणा, उनकी उपयोगिता, सीमाओं और परस्पर तुलना को सरल रूप से प्रस्तुत करता है तथा ढूंढता है कि कि आज के समय में विकास को मापने का सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। जीडीपी की बात करें तो विकास मापने का यह पश्चिम द्वारा विकसित पारंपरिक पैमाना है. यह किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि, सामान्यतः एक वर्ष में, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। यह कृषि, उद्योग और सेवा तीनों क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को एक संख्या में समेट देता है। इसे विकास का पैमाना इसलिए माना गया क्योंकि यह आर्थिक गतिविधि और उत्पादन क्षमता का एक स्पष्ट संकेत देता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग सभी देशों द्वारा इसे अपनाए जाने के कारण देशों के बीच तुलना भी आसान हो जाती है। निवेशक यह समझ पाते हैं कि कौन-सी अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है, सरकारें कर-संग्रह और रोजगार सृजन का अनुमान लगा पाती हैं और नीति-निर्माताओं को विकास दर का एक त्वरित संकेत मिल जाता है। लेकिन जीडीपी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह मात्रा को महत्व देता है, गुणवत्ता को नहीं। यह यह नहीं बताता कि आय का वितरण समाज में कितना समान या असमान है। यदि जीडीपी बढ़ रहा है, तो भी हो सकता है कि उसका लाभ केवल सीमित वर्ग तक सिमट जाए। पर्यावरणीय क्षति, प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को जीडीपी विकास मान लेता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, मानसिक संतोष और जीवन-स्तर की गुणवत्ता जैसे मानवीय पहलुओं को यह नज़रअंदाज़ करता है। वास्तव में जीडीपी यह तो बताता है कि "कितना उत्पादन हुआ" पर यह नहीं बताता कि उस उत्पादन से लोगों का जीवन कितना बेहतर, सुरक्षित और सुखद हुआ। इसके अलावा, विध्वंस और विकास दोनों प्रकार की गतिविधियाँ जीडीपी की गणना में शामिल हो जाती हैं। किसी प्राकृतिक आपदा के बाद पुनर्निर्माण से भी जीडीपी बढ़ सकता है, जबकि वास्तविकता में समाज को भारी नुकसान हुआ होता है। इस दृष्टि से जीडीपी सस्टेनेबिलिटी आधारित अर्थव्यवस्था के लिए एक अपूर्ण माप है। वहीं एनडीपी नेट घरेलु उत्पाद जीडीपी का अधिक यथार्थवादी रूप है. नेट घरेलू उत्पाद, जीडीपी की कुछ प्रमुख सीमाओं को सुधारने का प्रयास करता है, जैसे कि एनडीपी की गणना में जीडीपी से मूल्यह्रास घटा दिया जाता है। मूल्यह्रास मतलब मशीनों, भवनों, कारखानों, संसाधनों और अन्य पूंजीगत संपत्तियों की समय के साथ होने वाली टूट-फूट और क्षरण। इस दृष्टि से एनडीपी यह दर्शाता है कि उत्पादन प्रक्रिया में लगी पूंजी को बनाए रखने के बाद देश ने वास्तव में कितना नया मूल्य सृजित किया। इसलिए इसे जीडीपी की तुलना में अधिक यथार्थवादी माना जाता है। यह दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता का बेहतर संकेत देता है और यह नीति-निर्माताओं को यह समझने में मदद करता है कि विकास टिकाऊ है या केवल संसाधनों के क्षरण पर आधारित है। हालांकि, एनडीपी भी विकास की संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता। यह भी मानव कल्याण, सामाजिक संतुष्टि और खुशहाली को सीधे मापने में असमर्थ है।पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक न्याय और जीवन की गुणवत्ता जैसे तत्व इसमें शामिल नहीं होते। इस प्रकार, एनडीपी आर्थिक दृष्टि से जीडीपी से बेहतर अवश्य है, लेकिन यह भी विकास के मानवीय और नैतिक पक्ष को पूरी तरह नहीं समेट पाता। यह बताता है कि अर्थव्यवस्था कितनी स्वस्थ है, पर यह नहीं बताता कि आम नागरिक का जीवन अनुभव कैसा है। अब आते हैं जीएनएच पर विकास के मानवीय और सनातन दृष्टिकोण का. जीएनएच मतलब सकल राष्ट्रीय खुशी। जीएनएच की अवधारणा विकास को केवल धन, उत्पादन और उपभोग से नहीं जोड़ती, बल्कि इसे मानव सुख-समृद्धि और उसकी सततता से मापती है। यह मानती है कि अर्थव्यवस्था का अंतिम उद्देश्य केवल वस्तुओं का उत्पादन नहीं, बल्कि मनुष्य को सुखी, संतुलित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। जीएनएच के अनुसार खुशहाली का आधार सुख है, और सुख ही विकास का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसके प्रमुख घटक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, शिक्षा की गुणवत्ता और समान अवसर, पर्यावरणीय संतुलन और प्रकृति के साथ सामंजस्य, सुशासन, पारदर्शिता और सामाजिक विश्वास, कार्य-जीवन संतुलन और सामुदायिक संबंध, सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक समरसता है। जीएनएच का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह विकास को मानव-केंद्रित बनाता है। यह नीति-निर्माताओं को याद दिलाता है कि आर्थिक वृद्धि साध्य नहीं, बल्कि साधन है। हालाँकि, जीएनएच की भी अपनी चुनौतियाँ हैं। जैसे खुशी और संतोष को मापना स्वभावतः कठिन है। यह अधिकतर गुणात्मक आकलन पर आधारित होता है। वैश्विक स्तर पर इसके व्यापक रूप से न अपनाए जाने के कारण अंतरराष्ट्रीय तुलना जटिल हो जाती है। त्वरित नीतिगत निर्णयों में इसे सीधे लागू करना आसान नहीं है। इसके बावजूद, आधुनिक समय में जब मानसिक तनाव, सामाजिक विघटन और पर्यावरण संकट बढ़ रहे हैं, जीएनएच का दृष्टिकोण अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। अब आते हैं कौन-सा पैमाना बेहतर है? इस प्रश्न का उत्तर एक शब्द या एक संकेतक में नहीं दिया जा सकता। जीडीपी आवश्यक है एक आंकड़े के रूप में क्योंकि बिना आंकड़े के कोई भी देश शिक्षा, स्वास्थ्य या सामाजिक सुरक्षा में निवेश नहीं कर सकता लेकिन इसे विकास का अंतिम पैमाना नहीं माना जा सकता।

■ पंकज जायसवाल

प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा

दुनिया एक बार फिर उसी पुराने और ख़तरनाक सवाल के सामने खड़ी है कि क्या अंतरराष्ट्रीय कानून सिर्फ़ कमज़ोर देशों के लिए है? क्या अमेरिका को यह अधिकार है कि वह तय करे कि कौन वैध राष्ट्रपति है, कौन अपराधी, और किस देश में किसकी सत्ता रहेगी? वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप और वहां के राष्ट्रपति को पकड़कर मुकदमे चलाना कोई अचानक घटित घटना नहीं अपितु यह उस नीति की अगली कड़ी है, जिसे अमेरिका दशकों से अलग-अलग नामों से लागू करता आया है । कभी "लोकतंत्र की रक्षा", कभी "ड्रग्स के खिलाफ युद्ध", और कभी "मानवाधिकार"। नाम बदलते रहे, इरादा वही रहा ताक़त के दम पर दूसरे देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने एवं वहां अपनी मनपसंद के शासक बैठाने राजनीति। अमेरिका यह कहकर अपने कदमों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है कि वेनेज़ुएला "नार्को-स्टेट" बन चुका था। सवाल यह है कि अगर किसी देश में अपराध है, तो क्या इसका फ़ैसला वाशिंगटन करेगा? और सज़ा भी वही देगा? और यदि ऐसा होता है तो फिर वहां की सरकार शासन एवं प्रशासन की क्या भूमिका रह जाएगी? हो सकता है नई पीढ़ी या जैन जी को लगे कि वेनेजुएला जैसी घटना पहली बार घटित हुई है लेकिन ऐसा नहीं है अमेरिका पहले भी एक बार नहीं अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग जगह पर कई बार ऐसा कर चुका है थोड़े बहुत अंतर के साथ। उदाहरण के लिए पनामा के मैनुएल नोरीएगा को याद कीजिए जिसे पहले अमेरिका ने पाल-पोसकर सत्ता में रखा और फिर जब वह 'अनुपयोगी' हो गया, और मनमानी करने लगा तो 1989 में पनामा के इस सर्व शक्तिशाली सेना अध्यक्ष को पहले तो अपहरण कर अमेरिका लाया गया और फिर वहीं मुकदमा चलाया और उसे 30 वर्ष जेल में रखा गया। तब भी संयुक्त राष्ट्र ने निंदा तो की, लेकिन अमेरिका बेपरवाह रहा। यही पैटर्न आज वेनेजुएला में दोहराया जा रहा है। सच बात तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद जैसे संगठनों पर पूर्ण तरीके से अमेरिका का कब्जा है और यदि वह अमेरिका के ख़िलाफ़ जाना भी चाहते हैं तो उनके पास इतनी ताकत नहीं है। 2 जनवरी की रात को दुनिया को हतप्रभ कर देने वाली राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण की घटना के साथ भी सब कुछ खत्म होता नहीं दिख रहा है बल्कि वेनेज़ुएला के बाद मेक्सिको और कोलंबिया को लेकर अमेरिकी चेतावनियाँ बताती हैं कि यह मामला एक देश तक सीमित रहने वाला नहीं है। ड्रग तस्करी और सीमा सुरक्षा की आड़ में सैन्य कार्रवाई की भाषा दरअसल पुराने औपनिवेशिक दृष्टिकोण की वापसी है, जिसमें लैटिन अमेरिका को अमेरिका का प्रभाव-क्षेत्र माना जाता था। यह वही इलाक़ा है जिसने अमेरिकी हस्तक्षेपों की सबसे भारी कीमत चुकाई है, कभी तख़्तापलट,कभी गृहयुद्ध, और कभी आर्थिक तबाही की मार लैटिन अमेरिकी देशों ने बार-बार सही है। 'अमेरिका फर्स्ट' के नारे के साथ सत्ता में लौटे डोनाल्ड ट्रंप लैटिन अमेरिकी देशों की सीमा एवं परिधि से बाहर भी यदि ऐसी कार्रवाई करने तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अमेरिकी मनमानी के एक नहीं कई उदाहरण हैं. 1980 के दशक में अमेरिका ने इराक पर रासायनिक हथियार रखने का आरोप लगाकर भीषण हमला किया बाद में यह आरोप झूठे निकले तब संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि इराक युद्ध अवैध था।

■ घनश्याम बादल

आज का कार्टून

साभार

तलवार की धार पर भारत की विदेश नीति!

अमेरिका की 'दादागीरी' और दबंगई पुरानी है। यह दुनिया भर में कम से कम सवा सौ साल से चल रही है। इस अवधि में और आक्रामकता आयी है। इसी दौरान दो बार विश्व युद्ध हुए। सोवियत संघ के रूप में दुनिया में दूसरी महाशक्ति बनी तथा उसका पराभव हुआ। कालान्तर में चीन बड़ी ताकत बना और वह अब भी ऐसा लगता है। बावजूद इसके, दुनिया बहुध्रुवीय हो गयी है जहाँ समय-समय पर अनेक गुट बनते, बढ़ते, बदलते और बिगड़ते रहते हैं; फिर भी अमेरिका को चुनौती देने की ताकत किसी एक क्या, कई देशों के समूहों तक में नहीं दिखती। वजह इन सबके निहित स्वार्थ हैं। नतीजतन, अमेरिका अब धौंस के साथ दुनिया का 'खौफनाक दरोगा' हो गया है। वह जब, जहाँ, जिस तरीके से चाहता है मनमानी करता है। ताजा मामला वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अपहरण और गिरफ्तारी का है। अचरज यह है कि अमेरिका यह सब लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा के नाम पर करता है! ऐसी स्थिति में भारत का मौन बहुध्रुवीय दुनिया की कसौटी पर है। यह ठीक है कि इस वक्त हमारा भारत "बड़ी आर्थिक शक्ति" बनने को अग्रसर है और इसके मद्देनज़र 'सुरक्षात्मक नीति' (डिफेंसिव पालिसी) आवश्यक होती है लेकिन चाहे वेनेजुएला की बात हो या, पड़ोसी बाँग्लादेश में हिन्दुओं की हत्या का मामला, भारत का मुखर होकर आगे न आना अनेक लोगों को खलता है और गरचे ऐसा न हो, तो हैरान अवश्य करता है क्योंकि भारत सदा से विश्व शान्ति का पक्षधर रहा है। दुनिया आज दिखने में तो भले बहुध्रुवीय हो चुकी है, लेकिन शक्ति सन्तुलन की असल तस्वीर बहुत असमान है। एक ओर अमेरिका है जो अपने हित में किसी भी देश की सत्ता–संरचना को पलट देने से कभी नहीं हिचकता, दूसरी ओर चीन–रूस–ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया जैसे देश हैं जो इस वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के देश अमूमन अमेरिका के पिछलग्गू हैं। ऐसे समय में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और तेज़ी से उभरती चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, पर अभी उसकी आवाज़ उतनी 'मुखर' नहीं दिखती। इसके कारणों पर विशेषज्ञों के दृष्टिकोण भिन्न हैं। हाँ, ज्यादातर का यह अवश्य मानना है कि भारत किसी को मौक़ा देने की चूक नहीं करना चाहता। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को अपना मित्र कहते जरूर हैं परन्तु यह उनके 'तंज' जैसा ही है। असल में ट्रम्प भारत से खार खाये बैठे हैं। उन्होंने सोचा होगा कि भारत भी उनके पिछलग्गुओं की जमात में शामिल हो जाएगा किन्तु भारत ने मौजूदा नेतृत्व की स्पष्ट नीति से यह बता दिया है कि यह अब अपनी पुरानी नीति को तिलाञ्जलि दे चुका है। इससे ट्रम्प की बहाने की तलाश के साथ कूटनयिक कोशिशें और साज़िशें भले जारी हों, उन्हें भारत पर सीधे कोई कार्रवाई की कल्पना भी नहीं हो सकती। वजह साफ है कि भारत अब बड़ी आबादी वाला देश और बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं, एक बड़ा बाजार है जिसके पेटे में पूरा चीन, अमेरिका जैसे चार और जनसंख्या में रूस की तरह 10 से अधिक देश समा जाएँगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को 3 जनवरी (2026) की रात अमेरिकी विशेष बलों ने 'डेल्टा फोर्स' की अगुवाई में गुप्त अभियान के तहत राजधानी काराकस के एक सैन्य ठिकाने से पकड़ लिया और अमेरिकी जहाज़ पर ले जाकर उन्हें अपने यहाँ मुक़दमे के लिए बन्दी बना लिया। अमेरिका इसके पहले कम से कम चार बार विभिन्न देशों में ऐसी हरकत को अंजाम दे चुका है। 1901 में 23 मार्च को पहली बार उसने फिलीपींस के तत्कालीन राष्ट्रपति एमिलियो एगुइनाल्डो को एक सैनिक कार्रवाई में इसी प्रकार बन्दी बनाया था। उसके कोई 89 वर्ष बाद उसने 1990 में पनामा के मैनुएल नोरिएगा, 2003 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन और इसके अगले ही साल 2004 में हैती के राष्ट्रपति जीन बर्टेण्ड एरिस्टाइड को गिरफ्तार कर लिया। ये सारी कार्रवाइयाँ सम्बन्धित देशों की सम्प्रभुता के खिलाफ जाते हुए की गयीं। उनकी वजह कुछ भी बतायी गयी हो, मकसद केवल अमेरिकी कारोबार का विस्तार तथा उसके व्यावसायिक हितों को साधना रहा है। इसी तरह इस बार वेनेज़ुएला में भी हुआ है जहाँ निशाने पर उसका विशालतम पेट्रोलियम 'तेल रिजर्व' है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है।

■ डॉ. मत्स्येन्द्र प्रभाकर

अपने आप पर विजय प्राप्त करना ही आपकी महानतम विजय होती है : प्लेटो

'ऑपरेशन सिंदूर' से भयभीत हो गया था पाकिस्तान

'ऑपरेशन सिंदूर' से पाकिस्तान के अस्तित्व की बुनियाद हिल गई थी। अमेरिका के 'फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट' के दस्तावेजों से यह बात एक बार फिर सामने आ गई है कि भारत के हमले से बचाने के लिए पाकिस्तान अमेरिका के सामने बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था। हाल ही में सार्वजनिक हुए दस्तावेज गवाह हैं कि पिछले साल अप्रैल में जब भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, तो पाकिस्तान की सामरिक हेकड़ी किस तरह हवा हो गई थी। 45 करोड़ रुपये, 60 बैठकें और 6 लॉबिंग फर्मों का सहारा—ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान भारत के सामने सैन्य मुकाबला करने की नहीं, बल्कि महाशक्तियों के पीछे छिपकर जान बचाने की स्थिति में है। मीडिया रिपोर्ट्स और फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के खुलासे से स्पष्ट है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसने पाकिस्तान के रक्षा तंत्र में गहरा मनोवैज्ञानिक भय पैदा कर दिया था। चार दिनों तक चले इस ऑपरेशन के दौरान, पाकिस्तानी राजनयिकों द्वारा अमेरिकी प्रशासन, पेंटागन और सांसदों के साथ संपर्क साधने की आपाधापी यह सिद्ध करती है कि इस्लामाबाद को अपनी सेना से ज्यादा भरोसा वाशिंगटन की 'लॉबिंग' पर था। ट्रम्प प्रशासन तक पहुँच बनाने के लिए करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाना पाकिस्तान की हताशा का परिचायक है, न कि उसकी कूटनीतिक कुशलता का। उस समय पाकिस्तान के सामने एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी करके भारत के हमले से बचा जाए। भारत से दुश्मनी मोल लेने और करोड़ों रुपये बर्बाद करने की अपेक्षा पाकिस्तान को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि कूटनीतिक बैसाखियां उसे कुछ समय के लिए सहारा तो दे सकती हैं, लेकिन उसके आंतरिक संकटों और आतंकवाद को पनाह देने की नीति का समाधान नहीं कर सकतीं। वहीं, 'ऑपरेशन सिंदूर' ने यह स्थापित कर दिया है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमा पार कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा और न ही किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुकेगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के सामने एक ही विकल्प बचता है कि वह भारत से नफरत छोड़कर एक सभ्य पड़ोसी के रूप में स्वयं को स्थापित करने का प्रयास करे। बहरहाल, अमेरिका के एफएआरए के दस्तावेजों से सामने आई जानकारी ने भारत के विपक्षी राजनीतिक दलों को भी आईना देखने के लिए मजबूर कर दिया है। एक प्रकार से यह जानकारी विपक्षी दलों के उस प्रोपेगेंडा को भी विफल करती है, जिसके तहत बार-बार भारत सरकार और भारतीय सेना को कमजोर दिखाने के प्रयास किए जा रहे थे। विशेषकर, कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। अमेरिका के दबाव में भारत ने युद्ध विराम किया। जबकि वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान बार-बार अमेरिका में गुहार लगाता रहा, लेकिन भारतीय सेना ने तब तक अपनी कार्रवाई नहीं रोकी, जब तक पाकिस्तान ने सीधे हमसे प्रार्थना नहीं की। भारत ऐसे मामलों में अपनी संप्रभुता का सम्मान करना जानता है। यह नया भारत है, जिसकी ताकत का अंदाजा पाकिस्तान सहित समूचे विश्व को 'ऑपरेशन सिंदूर' में हो चुका है।

'ऑपरेशन सिंदूर' से पाकिस्तान के अस्तित्व की बुनियाद हिल गई थी। अमेरिका के 'फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट' के दस्तावेजों से यह बात एक बार फिर सामने आ गई है कि भारत के हमले से बचाने के लिए पाकिस्तान अमेरिका के सामने बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था। हाल ही में सार्वजनिक हुए दस्तावेज गवाह हैं कि पिछले साल अप्रैल में जब भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, तो पाकिस्तान की सामरिक हेकड़ी किस तरह हवा हो गई थी।

अमृत कलश

जीवन में नयापन लाएं

उपनिषद् में कहा गया है कि वास्तव में समय नहीं बीतता, हम बीत जाते हैं। हम इस नए वर्ष में नए गुण, नई सोच, नई विधा, नया चिंतन और अच्छे कर्म अपने जीवन में ले आएं। किसी नादान की तरह नहीं जिएं। जिएं तो एक जाग्रत व्यक्ति की तरह जिएं। जब हम जाग्रत होकर जिएंगे, तो बाहर-अंदर सब कुछ नया होगा। आइए हम जाग्रत जीवन जीने का संकल्प लें और अपने जीवन में नयापन लाएं। मैं आपको कुछ संकल्प करने को कहूंगी, तो उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो। जब आप खुद संकल्प करोगे कि मैं यह करूंगा, तो आप उसे खुशी से कर लोगे। आपका अहंकार और अपने प्रति प्यार आपको उस संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूर करेगा।

अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का यही सही समय है। शुरुआत इस चिंतन से करें कि अब तक आपने कितनी साधना की है? मन के कितने दोष दूर किए हैं? मन का कितना अज्ञान दूर किया है? बीते समय में क्या किया? पिछला साल तो यही सोचते निकल गया कि साधना आज शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे।

मन को अच्छी बातों से जोड़ें : नए साल में संकल्प करने की परंपरा है। बहुत-से लोग बहुत प्रकार के संकल्प करते हैं, जैसे- वजन कम करेंगे, मीठा नहीं खाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसे संकल्प करना भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे भी आपके मन की शक्ति बढ़ जाती है और मन की कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत-से लोग संकल्प तो करते हैं, परंतु उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन बेईमान हो जाता है। जरूरी है कि हम अपने मन पर नियंत्रण करें। उसके गुलाम नहीं बनें। यह कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। इसके लिए जरूरी है ईमानदारीपूर्वक निरंतर प्रयास करने की।

जैसे पानी के लिए नीचे गिरना आसान और सहज होता है, परंतु अगर उसे ऊपर उठाना हो, तो मोटरपंप की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे मन के लिए नीचे गिरना आसान और सहज है। मन को ऊंचा उठाना बहुत मुश्किल है। मन के लिए अच्छी बातों से जुड़ना बहुत मुश्किल है, उनको छोड़ देना सहज है।

कल की नहीं, आज की करें चिंता : मन की आदतें ऐसी होती हैं कि उन्हीं आदतों में मन को सुविधा महसूस होने लगती है। हमारा मन कुछ आदतों को पाल लेता है और उन्हीं में खुश रहता है। अगर आप अपनी दिनचर्या में साधना को बढ़ाने का संकल्प करते हैं, तो उसको बिना किसी अटकाव के सालभर चलाते रहना बहुत जरूरी है। भूतकाल बीत चुका है, परंतु वर्तमान आपके हाथ में है, इसलिए आनेवाले कल में क्या होगा, यह आपके आज पर निर्भर करता है।

● सृष्टि चौबे

क्या असहमति की आड़ में राष्ट्र-विरोध, हिंसा और सशस्त्र संघर्ष का समर्थन दिया जा सकता है?

भारत में वामपंथी वैचारिकी, विश्वविद्यालयी आंदोलन और नक्सली समर्थन

कैलाश चंद्र
सामाजिक कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ स्तंभकार

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सीएए-एनआरसी आंदोलन के बाद तो 'प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स' का एक नया मॉडल विकसित हुआ-जहाँ सड़क, सोशल मीडिया और विश्वविद्यालय परिसर मिलकर ऐसा नैरेटिव गढ़ते हैं जिसमें अल्पसंख्यक अधिकार, राज्य दमन और उदार-वामपंथी विमर्श एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं।

भारत का लोकतंत्र अपनी विविधता, मतभिन्नता और खुली बहस की परंपरा के कारण विश्व में विशिष्ट रहा है। किंतु पिछले दो दशकों में एक ऐसी वैचारिक धारा विकसित हुई है, जिसने विश्वविद्यालयों, वामपंथी छात्र संगठनों, शहरी बुद्धिजीवी समूहों और माओवादी हिंसा को एक व्यापक वैचारिक सूत्र में पिरो दिया है। यह विमर्श केवल छात्र-राजनीति या असहमति तक सीमित नहीं, यह राज्य-विरोध, पहचान की राजनीति, 'क्रांतिकारी प्रतिरोध' की संस्कृति और अंततः माओवादी सशस्त्र संघर्ष तक फैला एक सुनियोजित नैरेटिव बन चुका है।

सबसे स्पष्ट उदाहरण दिल्ली के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय - जेएनयू और जामिया मिल्लिया इस्लामिया, तथा हैदराबाद और कलकत्ता विश्वविद्यालय हैं, जहां विमर्श का झुकाव धीरे-धीरे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हटकर एक प्रकार के वैचारिक अराजकवाद की ओर दिखाई देता है। जेएनयू में एसएफआई, एआईएसएफ, डीएसएफ, डीएसयू जैसे वामपंथी छात्र संगठनों ने बीते वर्षों में न केवल वर्ग-संघर्ष के अपने पुराने नारे को पुनर्जीवित किया, बल्कि राज्य, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खुलेआम चुनौती देने वाले आंदोलन खड़े किए।

2016 में अफजल गुरु की फांसी के विरोध में लगे 'भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी' और 'पाकिस्तान जिंदाबाद' जैसे नारे विश्वविद्यालयी राजनीति को निर्णायक मोड़ देने वाले सिद्ध हुए। यह सिर्फ एक छात्र-प्रदर्शन भर नहीं था, यह राष्ट्र-राज्य और न्यायिक संरचना को अवैध ठहराने वाले वैचारिक उभार का संकेत था, जिसमें अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के प्रति सहानुभूति जताई गई, और भारतीय न्याय व्यवस्था को 'कातिल' बताने की मुहिम चली।

इसी क्रम की अगली कड़ी जनवरी 2026 में तब उभरी, जब उमर खालिद और शरजील इमाम की

जमानत याचिकाएं खारिज होने पर जेएनयू में 'मोदी–शाह की कब्र खुदेगी' जैसे हिंसक-उन्मादी नारे लगे। ये नारे लोकतांत्रिक असहमति से कहीं आगे बढ़कर हिंसक क्रांति की विचारधारा को वैधता प्रदान करते दिखे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा अन्य समूहों द्वारा इसे राष्ट्र-विरोधी गतिविधि बताया जाना स्वाभाविक था, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज करने से यह स्पष्ट हुआ कि परिसर केवल बहस के मंच नहीं रह गए, बल्कि वैचारिक युद्धभूमि में बदल रहे हैं।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सीएए-एनआरसी आंदोलन के बाद तो 'प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स' का एक नया मॉडल विकसित हुआ-जहां सड़क, सोशल मीडिया और विश्वविद्यालय परिसर मिलकर ऐसा नैरेटिव गढ़ते हैं जिसमें अल्पसंख्यक अधिकार, राज्य दमन और उदार-वामपंथी विमर्श एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। यहां भी वही तर्क-फासीवाद, पुलिस-राज, राज्य-आतंक-प्रमुखता से उभरे, जो माओवादी अपने हिंसक संघर्ष को उचित ठहराने के लिए दशकों से उपयोग करते आए हैं।

यही वैचारिक साम्यता भारत के आदिवासी अंचलों में फैली माओवादी हिंसा को विश्वविद्यालयी विमर्श से जोड़ती है। 2010 के दंतेवाड़ा नरसंहार, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान मारे गए, पर कुछ वामपंथी बुद्धिजीवियों ने इसे "ऑपरेशन ग्रीन हंट का प्रतिकार" कहकर उचित ठहराने का प्रयास किया। इसी प्रकार 2021 में सुकमा-बीजापुर में 22 जवानों की हत्या और इन घटनाओं में माओवादी कमांडर मदवी हिड़मा की भूमिका यह प्रमाण है कि विचार जब हथियारों के साथ घुल-मिल जाते हैं, तो वह राष्ट्र और उसके रक्षकों पर प्रहार के रूप में सामने आते हैं।

2025 में हिड़मा और बसवराजू जैसे शीर्ष माओवादी नेताओं के मारे जाने के बाद भी शहरी नक्सली नेटवर्क सक्रिय रहा। उसी वर्ष दिल्ली के प्रदूषण-विरोधी प्रदर्शनों में 'मदवी हिड़मा अमर रहे' जैसे नारे और बिरसा मुंडा की छवि के साथ हिड़मा के पोस्टर लगाना यह दर्शाता है कि शहरी नेटवर्क न केवल ग्रामीण हिंसा का समर्थन करते हैं, बल्कि आदिवासी प्रतीकों को माओवादी हिंसा के औचित्य के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति अपनाते हैं।

इन घटनाओं से स्पष्ट है कि भारत में वामपंथी छात्र राजनीति अब सिर्फ परिसर-गत मुद्दों का विस्तार नहीं रह गई; यह राष्ट्रीय राजनीति से लेकर सशस्त्र माओवादी संघर्ष तक फैला एक बड़ा वैचारिक मोर्चा है। न्यायपालिका के निर्णयों- अफजल गुरु, बुरहान वानी आदि - के विरुद्ध जिस आक्रोश और 'प्रतिरोध' का नैरेटिव खड़ा किया गया, वह वही समूह कर रहे हैं जो लगातार राज्य की नैतिक वैधता को ही संदेह के घेरे में रखते हैं।

'भारत तेरे टुकड़े होंगे' और प्रधानमंत्री–गृहमंत्री के लिए खुलेआम हिंसक धमकियां, लोकतांत्रिक असहमति नहीं बल्कि अराजकता की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं। इस वैचारिक तंत्र के भीतर मार्क्सवादी समूहों, इस्लामी कट्टरपंथी धाराओं, माओवादी नेटवर्क और कुछ विदेशी मिशनरी संगठनों की गतिविधियों का घालमेल एक प्रकार के वैचारिक 'कॉकटेल मॉडल' के रूप में उभर रहा है-जिसका लक्ष्य भारत की एकता को कमजोर करना, समाज में विभाजन पैदा करना और राज्य-व्यवस्था को चुनौती देना है।

पूर्वोत्तर भारत को 'चिकन नेक' क्षेत्र में विभाजित कर अलग करने की खुली वकालत करने वाले समूहों को भी लंबे समय से विश्वविद्यालय परिसर वैचारिक ऊर्जा प्रदान करते रहे हैं। यदि ऐसे शैक्षणिक केंद्र और शहरी नेटवर्क अनियंत्रित रहे, तो आने वाले समय में यही संस्थान वैश्विक मंच पर भारत की पहचान को अराजकता, हिंसा और पत्थरबाज़ी के प्रतीकों में बदल सकते हैं।

अंततः प्रश्न यह नहीं कि असहमति होनी चाहिए या नहीं - असहमति लोकतंत्र की आत्मा है। प्रश्न यह है कि क्या असहमति की आड़ में राष्ट्र-विरोध, हिंसा और सशस्त्र संघर्ष का समर्थन दिया जा सकता है? क्या विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र बने रहेंगे या राजनीतिक रणभूमि बन जाएंगे? क्या भारतीय वामपंथ माओवादी हिंसा से स्वयं को स्पष्ट रूप से अलग कर अपनी वैधानिक भूमिका सिद्ध करेगा? और क्या भारत अपनी शिक्षा संस्थाओं को विदेशी हस्तक्षेप, वैचारिक प्रदूषण, और उग्रवाद के बढ़ते प्रभाव से सुरक्षित रख सकेगा?

भारत का भविष्य इन्हीं निर्णायक प्रश्नों के उत्तरों में निहित है।

यह लेखक के निजी विचार है

मिथ्या चेतना का दर्शनशास्त्र

हरदीप एस पुरी
भारत सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

भारत में 2026 के आरंभ में सार्वजनिक बहस नववर्ष के अनुशासन के साथ शुरू होनी चाहिए। हमें पड़ताल और तीखी आलोचनाओं का भी स्वागत करना चाहिए। लेकिन इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि बहस के साथ जवाबदेही शामिल हो। कुल 1.4 अरब की आबादी वाले गणराज्य को निराशावाद से नहीं सुधारा जा सकता। रोजगार, उत्पादकता, निर्यात और समावेशन सबसे अच्छे समय में भी आसान नहीं होते। प्रगति डिजाइन, क्रियान्वयन, सुधार और परिमापन के नीरस मेल से आती है। नया साल निराशावाद को संशयवाद से अलग करने का भी क्षण है।

फ्रेडरिक नीत्शे ने 'बेयांड गुड एंड ईवल' में लिखा हैः 'दार्शनिक को सिर्फ आलोचक या दर्शक होने के बजाय मूल्यों का सर्जक होना चाहिए। उसे तत्वचिंतन जीवन के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके नजरिए से करना चाहिए।' लोकनीति में इसी तरह के दृष्टिकोण की दरकार है। आलोचनाओं का स्वागत है। मगर ये साक्ष्य तथा एक जटिल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र का शासन चलाने की ज्वलंत बाधाओं से आबद्ध होनी चाहिए। जब संशयवाद एक भंगिमा बन जाए तो यह सुधार संभव बनाने वाली संस्थाओं में विश्वास को खत्म करता है।

पिछले वर्षों में टिप्पणी की एक नई विधा सामने आई है। यह संदेह को सुसंस्करण के तौर पर पेश करती है। यह सुधार के कार्य को मजाक में तब्दील कर देती है। यह हर अपूर्ण परिवर्तन को स्थाई नाकामी के सबूत के तौर पर लेती है। यह एक चिरपरिचित सांत्वना पेश करती हैः भारत कदाचित अपने ही नीति निर्माताओं से अभिशप्त है। इस दृष्टिकोण के अपने नतीजे हैं। यह आंकड़ों और बाजारों में विश्वास को घटाता है। यह उद्यमियों और निवेशकों में नियतिवाद को प्रोत्साहित करता है। साथ ही यह बाहरी ताकतों को वार्ताओं में भारत को दबाव में लाने के लिए तैयार कथानक भी प्रदान करता है। विशेषज्ञता को तथ्यों के प्रति जवाबदेह बने रहना चाहिए।

मजबूत पेशेवर और शैक्षिक पृष्ठभूमि का दंभ भरने वाले कुछ टिप्पणीकारों का इस तरह की भंगिमा का सहारा लेना चिंता की बात है। इनमें से कुछ ऐसे टिप्पणीकारों को मैं जानता हूं जिनकी पहचान और विश्वसनीयता भारत पर आधारित है। लेकिन वे संभवतः ध्यानाकर्षण या अब सरकार का हिस्सा नहीं होने के बावजूद प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए देश के खिलाफ अनाप-शनाप बोल कर अपना करियर बनाने की कोशिश में लगे हैं।

वित्तीय अनुशासन में सुधार के प्रभाव अब दिखाई देने लगे हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैरनिष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) 2018 में 11.2 प्रतिशत से घट कर 2025 में 2.1 प्रतिशत रह गई है। यह सिर्फ खयाली पुलाव बनाने से नहीं हुआ। यह बैलेंस शीट्स की लगातार सफाई, सख्त निगरानी और एक ऐसे तंत्र को प्रतिबिंबित करता है जिसने सदाबहार ऋण और गुप्त हानियों की गुंजाइश को समय के साथ घटाया है। जब आलोचक कहते हैं कि

शासन सुधार नहीं कर सकता तो यह आडंबरहीन कायाकल्प उनके लिए पहला जवाब है।

कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में कमियां गिनाना और यह मान लेना आसान है कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अब नीति का रुख बदल गया है। अब सरकार का ध्यान सीधे तौर पर मदद पहुंचाने और ऐसी संपदा बनाने पर है, जो उत्पादकता और सम्मान दोनों बढ़ाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जल जीवन मिशन है, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 12.5 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल से पानी का कनेक्शन पहुंचाया गया है। इससे न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बल्कि परिवारों पर पानी भरने के बोझ कम हुआ है और समय की बर्बादी भी कम हुई है।

विकास के लाभ सब तक पहुंचने की कहानी स्वास्थ्य, आवास और ऊर्जा के क्षेत्र में भी दिखाई देती है। आयुष्मान भारत ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 42 करोड़ से ज़्यादा कार्ड जारी किए हैं, जिससे परिवारों को गंभीर बीमारियों के भारी खर्च नहीं करने पर आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ घर बनकर तैयार हो चुके हैं, जिससे परिवारों को न केवल अपनी संपत्ति मिली है बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का एक ठोस आधार भी दिया है। इसी तरह, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे उन घरों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचा है जो कभी धुएं और कठिन परिश्रम के जाल में फंसे थे। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह वह व्यावहारिक आधार है जिस पर लोगों की आकांक्षाएं और उनकी कार्यक्षमता टिकी है।

सबसे ज़्यादा निराशा अक्सर राज्यों की स्थिति को लेकर जताई जाती है जैसे कि एक अरब से ज़्यादा लोगों के देश को एक ही तरीके से चलाया जा सकता हो। भारत का संघीय ढांचा थोड़ा शोर-शराबे वाला ज़रूर है, लेकिन यह वक्त के साथ बदलना भी जानता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे कई राज्यों ने यह दिखा दिया है कि बेहतर कानून-व्यवस्था, परियोजनाओं की शीघ्र मंज़ूरी और अवसंरचना के निर्माण में निरंतर काम से निवेश और बेहतर नौकरियां मिल सकती हैं। केंद्र सरकार ने इस प्रतिस्पर्धी संघवाद को और मज़बूत किया है। इसके लिए ऐसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जिनसे राज्य जुड़ सकते हैं, ऐसा फंड बनाया है जो बेहतर काम करने पर इनाम के तौर पर दिया जाता है और सुधारों के आंकड़ों को इतना पारदर्शी बना दिया है कि जनता खुद सरकार के काम का फैसला कर सके।

भारत की प्रगति की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, इस पर हमेशा बहस होती रहेगी। सवाल यह है कि नए साल की शुरुआत में हम किस तरह की बहस चुनते हैं। जब बड़े-बड़े पेशेवर लोग केवल अनुमानों या इशारों को ही 'गहन विश्लेषण' मान लेते हैं, तो वे उन संस्थाओं को कमज़ोर करते हैं जो सुधारों को मुमकिन बनाती हैं। यहां नीत्शे की बात याद करना जरूरी है - एक गंभीर विचारक ऐसे मूल्य पैदा करता है जो समाज को जीने और बेहतर बनने में मदद करें। भारत ने काम करके दिखाने का कठिन रास्ता चुना है। ये नतीजे ही हैं, जो आंकड़ों में भी दिखते हैं और महसूस भी किए जाते हैं। यह किसी भी तरह की निराशा पर भारी पड़ेंगे और लंबे समय तक बने रहेंगे। साल 2026 में, भारत को ऐसी आलोचना की मांग करनी चाहिए जो नीतियों को बेहतर बनाए, न कि ऐसी टिप्पणियों की जो केवल वाहवाही लूटने के लिए देश के आत्मविश्वास को कमज़ोर करती हों। यह वह मानक हैं जो देश के भीतर सुधारों, निवेश और लोकतांत्रिक विकल्प की रक्षा करते हैं।

'दिल्ली दंगा', साजिश मामला

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और न्यायिक संतुलन की कसौटी

डॉ विश्वास चौहान
प्राध्यापक विधि, शास. स्टेट लॉ कालेज भोपाल

हम सब जानते हैं कि फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा कथित 'बड़ी साजिश' प्रकरण लंबे समय से भारतीय न्यायिक और सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में रहा है। यह मामला केवल दंगों की आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967), यूएपीए के अंतर्गत जमानत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सुरक्षा और न्यायिक विवेक के बीच संतुलन जैसे बुनियादी प्रश्नों को सामने रखा।

दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 36 मुस्लिम और 15 हिंदू थे, जबकि 200 से अधिक घायल हुए, ये आंकड़े राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विभिन्न रिपोर्ट्स से लिए गए हैं, जो अक्सर अनछुए रह जाते हैं।

अभी 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश इसी संदर्भ में निर्णायक महत्व रखता है, क्योंकि इसमें अदालत ने कुछ आरोपियों को जमानत दी और कुछ को नहीं, और ऐसा करते हुए अपने निर्णय के कारणों को केंद्र में रखा।

सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्षः जमानत पर आरोपी-विशेष दृष्टिकोण

सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि अभियोजन की सामग्री से उनके विरुद्ध यूएपीए के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है और उनकी भूमिका 'केंद्रीय तथा निर्णायक' प्रतीत होती है। यह फैसला एफआईआर 59/2020 के तहत आता है, जिसमें कुल 18 आरोपी हैं और ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हुआ। सभी आरोपी पुलिस हिरासत में हैं।

यूएपीए की कसौटीः प्रथम दृष्टया सत्य का परीक्षण

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए की धारा 43डी(5) को लागू करते हुए स्पष्ट किया कि जमानत के स्तर पर अदालत का दायित्व साक्ष्यों की गहन जाँच करना नहीं, बल्कि यह देखना है कि अभियोजन की सामग्री प्रथम दृष्टया विश्वसनीय प्रतीत होती है या नहीं। यह दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट के पूर्ववर्ती निर्णयों के ही अनुरूप है और यह स्थापित करता है कि यूएपीए मामलों में सामान्य आपराधिक कानून की जमानत-नीति लागू नहीं होती।

बड़ी साजिश बनाम व्यक्तिगत भूमिकाः न्यायिक द्वंद्व

जमानत के कठोर प्रावधानों के बाद भी जमानत होना, यहीं से इस निर्णय की सबसे गंभीर आलोचनात्मक कसौटी सामने आती है। जब अभियोजन यानी सरकारी पक्ष स्वयं पूरे घटनाक्रम को भारत के विरुद्ध 'बड़ी साजिश' कहता है, जिसमें विरोध प्रदर्शनों को हिंसा में बदलने की योजना शामिल है, तब सुप्रीम कोर्ट का, जमानत के स्तर पर आरोपियों की भूमिका को इस प्रकार अलग-अलग काटकर देखना, क्या आपराधिक कानून की सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ पूरी तरह सामंजस्य रखता है?

भारतीय न्याय संहिता में सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य और षड्यंत्र जैसे सिद्धान्त सामूहिकता की धारणा पर आधारित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी रूप से सही कहा कि जमानत के स्तर पर दोषसिद्धि नहीं होती, परंतु 'केंद्रीय और निर्णायक भूमिका' जैसी भाषा ट्रायल से पहले ही एक आंशिक निष्कर्ष का आभास देती है। जबकि चार्जशीट में उल्लेखित अनुसार दंगों के पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में कई संदेशों का आदान प्रदान सामूहिक रूप से हुआ था, जो अपराध के पूर्व मस्तिष्क मिलन या सामान्य आशय बताता है, कोर्ट ने इस सन्दर्भ का संज्ञान या तो नही लिया या अनदेखा कर दिया।

ट्रायल में देरी और संवैधानिक प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यूएपीए मामलों में ट्रायल में देरी अपने-आप जमानत का आधार नहीं बनती, हालांकि ट्रायल कोर्ट को सुनवाई तेज़ करने का निर्देश दिया गया। यह दृष्टिकोण विधिक रूप से सुसंगत है, परंतु यह प्रश्न बना रहता है कि क्या संरक्षित गवाहों और जटिल साक्ष्य-प्रक्रिया वाले मामलों में यह निर्देश व्यवहारिक रूप से पर्याप्त है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएंः निर्णय के बाद का नैरेटिव

निर्णय के बाद कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा पांच आरोपियों को जमानत मिलने को 'न्याय की जीत' बताना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आंतरिक प्रक्रियाओं पर की गई टिप्पणियों की चर्चा फिर उभरना स्वाभाविक राजनीतिक घटनाक्रम है।

न्यायिक दृष्टि से ये प्रतिक्रियाएं निर्णय को प्रभावित करने वाली नहीं हैं, किंतु यह अपेक्षा बनी रहती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की तर्क-प्रक्रिया इतनी स्पष्ट हो कि किसी भी प्रकार के दबाव या प्रभाव की आशंका स्वतः समाप्त हो जाए, दुर्भाग्य से इस केस में सुप्रीम कोर्ट इस अपेक्षा पर खरा नही उतरा।

मोदी सरकार का वीबी-ग्राम जी अधिनियम : विकसित भारत में ग्रामीण भागीदारी का स्वरूप

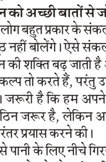

डॉ. आलोक कुमार द्विवेदी
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में पीएचडी हैं। वर्तमान में वह केएसएएस, लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं।

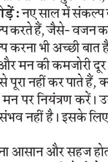

तुहिन सिन्हा
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एक प्रसिद्ध लेखक हैं। उन्होंने जनजाति योद्धाओं और नॉर्थ – ईस्ट के विकास पर आधारित महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी

विकसित भारत–2047 की परिकल्पना को केवल महानगरों की चमक या शहरी बुनियादी ढांचे के विस्तार तक सीमित नहीं किया जा सकता। भारत आज भी मूलतः एक ग्रामीण समाज है, जहां देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनयापन करती है। इन क्षेत्रों की उत्पादकता, उनकी आय और संकटों से जूझने की क्षमता ही यह निर्धारित करेगी कि भारत का विकास वास्तव में समावेशी होगा या केवल आंकड़ों तक सिमटकर रह जाएगा। इसी संदर्भ में मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुतविकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण), अर्थात वीबी-ग्राम जी अधिनियम, 2025, को किसी पारंपरिक कल्याणकारी योजना के संशोधन मात्र के रूप में देखना इसकी मूलभावना के साथ अन्याय होगा। यह अधिनियम सुशासन को प्रभावी करने हेतु एक ऐसा प्रयास है जो ग्रामीण भारत को नीति के हाशिये से निकालकर राष्ट्रीय विकास के केंद्र में स्थापित करता है।

इस अधिनियम ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का स्थान लिया है।

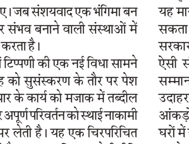

जो कानून वर्ष 2005 की आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, वह 2020 के दशक के भारत की बदलती वैश्विक संरचना, बढ़ती आकांक्षाओं और जटिल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरी तरह से आगे बढ़ाने की दिशा में पर्याप्त नहीं प्रतीत हो रहा था। आज का ग्रामीण भारत केवल जीविका नहीं, बल्कि निरंतर रोजगार, कौशल आधारित कार्य और बेहतर भविष्य की संभावना पर विचार करता है। यह केवल एक नीति परिवर्तन नहीं, बल्कि भारत के शासन दृष्टिकोण में आया एक गुणात्मक बदलाव का स्वरूप है, जिसकी पूर्व पीठिका है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब उसका ग्रामीण आधार सशक्त, सक्षम और सम्मानजनक आजीविका से युक्त होगा।

ग्रामीण रोजगारः जीविका की सुरक्षा से विकास के संवाहक तक

भारत में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों की भूमिका कभी एकांगी नहीं रही। उनसे हमेशा यह अपेक्षा की गई कि वे एक ओर अनियमित मौसम के संकट, कृषि की अनिश्चितताओं और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को जीविका की सुरक्षा प्रदान करें, तो दूसरी ओर इस बात को भी ध्यान दें कि उन पर किया जा रहा सार्वजनिक व्यय ग्रामीण उत्पादकता और उसकी आत्मनिर्भरता को स्थायी करने की दिशा में भी पर्याप्त प्रगति कर रहा है। अपने प्रारंभिक वर्षों में, विशेष रूप से कृषि संकटों और सूखे के दौर में, एमजीएनआरईजीए ने इस पहली जिम्मेदारी को निभाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। परंतु समय के साथ यह योजना धीरे-धीरे 'रोजगार मात्र के लिए रोजगार' की सीमित अवधारणा में सिमटती चली गई। इस बीच ग्रामीण भारत की वास्तविकता पूरी तरह बदल चुकी थी। कृषि में मशीनीकरण बढ़ा, ग्रामीण सड़कें सुधरी, बाजार तक पहुंच बढ़ीं, डिजिटल तकनीक और विद्युतीकरण ने जीवन और काम करने के तरीकों को बदला, और सबसे बढ़कर - ग्रामीण समाज की आकांक्षाएं कहीं अधिक ऊंची हो गईं।

कुत्तों पर सुनवाई

आवारा कुत्ते क्या वास्तव में इंसानों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह आवारा कुत्तों को लेकर सुनवाई हो रही है, उससे तो यही लगता है कि मामला वास्तव में गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। गुरुवार को जोकि लगातार सुनवाई का दूसरा दिन था, कुत्तों के पक्ष और विपक्ष में अदालत के सामने दलीलें रखी गई। जोकि काफी मजेदार भी रही। ढाई घंटे तक चली बहस में जस्टिस नाथ का कहना था कि कुत्ते इंसानों का डर पहचान लेते हैं, इसलिए काटते हैं। हालांकि जज की इस बात पर जो कुत्तों का फेवर करने वाले अधिवक्ता ने इन्कार किया। इस पर जस्टिस नाथ यह कहने से नहीं चूके कि अपना सिर मत हिलाइए, यह बात वह पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं।

वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने यह दलील दी कि राज्यों ने जो आंकड़े दिए हैं, उसमें किसी ने यह नहीं बताया कि नगरपालिका की तरफ से कितने शेल्टर चलाए जाते हैं। उनके अनुसार देश में सिर्फ 5 शेल्टर हैं और इनमें प्रत्येक में मात्र 100 कुत्ते रह सकते हैं। ऐसे में इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। वहीं एनिमल वेलफेयर की तरफ से दलील दे रहे एडवोकेट सीयू सिंह ने कुत्तों को हटाने या शेल्टर होम भेजने पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि कुत्ते हटाने से चूहों की आबादी बढ़ेगी। इस पर कोर्ट ने भी मजाकिया अंदाज में कह डाला कि क्या इसके लिए बिल्लियां ले आएं। इस पूरे मामले पर सात महीनों से कोर्ट में छह बार सुनवाई हो चुकी है और पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, स्पोट्स कॉम्प्लैक्स और रेलवे स्टेशन से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था। आदेश देते समय कोर्ट ने यह भी कहा था कि इन कुत्तों को तय शेल्टर में ट्रांसफर किया जाए।

याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि अदालत का आदेश सिर्फ संस्थानों तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि उसे रिहायशी इलाकों पर भी लागू किया जाना चाहिए। अधिवक्ता की यह भी दलील थी कि कुत्तों को समझाना संभव नहीं है, लेकिन कुत्तों की देखभाल करने वाले मालिक को समझाया जा सकता है। याचिकाकर्ता के वकील ने हर डॉग लवर और एनजीओ की याचिका लगाने में जो एक तय राशि जमा करनी होती है, उसको हटाने की मांग की है। कोर्ट ने भी उसी लहजे में जवाब दिया कि अगर हमने यह शर्त नहीं रखी होती तो यहां पंडाल लगाना पड़ता। जज महोदय का यह कहना सही है कि कुत्तों की मॉनिटरिंग के लिए पहले उनकी गिनती जरूरी है। उन्होंने आखिरी बार हुई 2009 में गिनती का हवाला भी दिया और कहा कि सिर्फ दिल्ली में ही 5 लाख 60 हजार कुत्ते थे। जाहिर है, आज के संदर्भ में यह संख्या कई गुना बढ़ी हो सकती है। इसमें कोई दोराय नहीं कि कुत्तों को लेकर आए दिन बड़ी दुखदायी खबरें सामने आती रहती हैं। कई मामलों में तो जान तक चली जाती है, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित होते हैं।

एक भी वोट न कटने पाए

वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने की साजिश को हर हाल में नाकाम किया जाए, तमाम प्रयासों के बावजूद पीडीए समाज के करोड़ों मतदाताओं के नाम अब तक मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं, एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए के संकल्प के साथ सभी को फिर से संगठित होना होगा, मतदाता सूची में नाम होना नागरिक होने की पहचान है, अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटता है, तो आने वाले समय में उसी आधार पर राशन कार्ड, सरकारी योजनाओं, जाति प्रमाणपत्र, आरक्षण, नौकरी, बैंक खाते, बीमा, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बिजली-पानी कनेक्शन, खेत-जमीन और घर- मकान तक पर संकट आ सकता है।

-अखिलेश यादव, अध्यक्ष,समाजवादी पार्टी

पक्षियों की जिंदगी और ध्वनि प्रदूषण

आज की तेजी से विकसित होती दुनिया में, शोर प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन गई है। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, और जनसंख्या वृद्धि के कारण शोर स्तर बढ़ता जा रहा है। इस शोर प्रदूषण का न केवल मनुष्यों पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह पक्षियों और अन्य जीवों के जीवन को भी प्रभावित करता है। इस लेख में हम यह समझेंगे कि शोर प्रदूषण किस प्रकार पक्षियों के जीवन, उनके व्यवहार, और उनके प्रजनन पर प्रभाव डालता है।

शोर प्रदूषण क्या है?

शोर प्रदूषण उन सभी अवांछित ध्वनियों को संदर्भित करता है जो मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती हैं। यह ध्वनियां ट्रैफिक, औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण कार्य और सार्वजनिक कार्यक्रमों से उत्पन्न होती हैं। शोर प्रदूषण को मापने के लिए डेसीबल का प्रयोग किया जाता है। 85 dB से अधिक के स्तर को शोर प्रदूषण माना जाता है।

पक्षियों की संवेदनशीलता

पक्षी अपनी सुनने की क्षमता और संवेदी तंत्र के लिए जाने जाते हैं। उनका अधिकांश संचार स्वर और आवाज के माध्यम से होता है। पक्षियों की अनेक प्रजातियां आवाज को अपने शिकार, साथी, और दुश्मनों के पहचानने के लिए उपयोग करती हैं। इसलिए, शोर प्रदूषण पक्षियों की जीविका के लिए एक गंभीर खतरा है।

शोर प्रदूषण के प्रभाव

1. व्यवहार में परिवर्तन

शोर प्रदूषण पक्षियों के व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है। विभिन्न अध्ययन दर्शाते हैं कि जब पक्षियों को उच्च स्तर के शोर के संपर्क में लाया जाता है, तो उनके गाने की आवृत्ति और ध्वनि स्तर में बदलाव होता है। इससे उनकी संचार क्षमता प्रभावित होती है, और वे साथी को आकर्षित करने में कठिनाई महसूस करते हैं।

2. प्रजनन पर प्रभाव

शोर प्रदूषण का प्रजनन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई प्रजातियों में यह देखा गया है कि शोर के कारण अंडों की संख्या में कमी, अंडों के फटने में देरी, और शिशुओं की मृत्यु दर में वृद्धि होती है। जब माता-पिता शोर से परेशान होते हैं, तो वे अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हो सकते हैं।

3. भोजन की उपलब्धता

शोर प्रदूषण से पक्षियों की भोजन खोजने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। जब शोर स्तर बढ़ता है, तो पक्षियों को अपने शिकार या भोजन को पहचानने में कठिनाई होती है। इससे उनकी ऊर्जा खर्च होती है, जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।

4. स्वास्थ्य पर प्रभाव

शोर प्रदूषण के कारण पक्षियों में तनाव स्तर बढ़ जाता है। यह तनाव विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे कि हृदय रोग, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, और सामान्य स्वास्थ्य में गिरावट। तनावग्रस्त पक्षियों का जीवन काल भी प्रभावित हो सकता है।

अध्ययन और शोध

विभिन्न शोधों ने शोर प्रदूषण के पक्षियों पर प्रभाव की पुष्टि की है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में यह पाया गया कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाली चिड़ियों की प्रजातियों की प्रजनन दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम थी। इसके अलावा, कई शोधकर्ताओं ने पाया है कि शोर प्रदूषण से प्रभावित पक्षियों में मानसिक तनाव और चिंता के लक्षण अधिक देखे गए हैं।

समाधान और संरक्षण

1. शोर स्तर को नियंत्रित करना

सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों को शोर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय करने चाहिए। जैसे कि ट्रैफिक को नियंत्रित करना, निर्माण कार्यों के समय को सीमित करना, और औद्योगिक ध्वनियों को कम करना।

2. संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना

विशेष संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना से पक्षियों को सुरक्षित स्थान प्रदान किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में शोर प्रदूषण को कम किया जा सकता है, जिससे पक्षियों को उनकी प्राकृतिक स्थिति में रहने का अवसर मिलेगा।

3. जन जागरूकता

लोगों को शोर प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। इसके लिए शैक्षिक कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन किया जा सकता है।

4. अनुसंधान और विकास

शोर प्रदूषण के प्रभावों को समझने के लिए और अनुसंधान की आवश्यकता है। यह शोध न केवल पक्षियों, बल्कि अन्य जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

निष्कर्ष

शोर प्रदूषण केवल मानव जीवन को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह पक्षियों और अन्य जीवों के लिए भी एक गंभीर समस्या है। हमें इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें और पक्षियों को उनके प्राकृतिक निवास में रहने का अवसर प्रदान कर सकें। हमें समझना होगा कि प्रकृति का संरक्षण हमारे अपने भविष्य के लिए भी आवश्यक है।

यदि हम इस समस्या के प्रति जागरूक रहें और इसे हल करने की दिशा में प्रयास करें, तो हम न केवल पक्षियों को बल्कि पूरी पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रख सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति की रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण सुनिश्चित करें।

विलुप्त हो रहे पक्षियों की संख्या

हालांकि ध्वनि प्रदूषण के कारण कई पक्षियों की प्रजातियां प्रभावित हो रही हैं, विशेष रूप से उनके संचार और प्रजनन पर प्रभाव डालने के कारण, कोई सटीक संख्या बताना मुश्किल है। विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में कई पक्षी प्रजातियां शोर के कारण अपने आवासों से बाहर जा चुकी हैं।

टॉड के पक्षी

इन पक्षियों का प्रजनन स्थान शोरगुल वाले क्षेत्रों में होने के कारण प्रभावित हुआ है, जिससे उनकी संख्या में कमी आई है।

संगीत पक्षी

जो अपने सुंदर गीतों के लिए जाने जाते हैं, वे ध्वनि प्रदूषण के कारण अन्य पक्षियों के साथ संवाद नहीं कर पा रहे हैं।

विलुप्त होती प्रजातियां

शोधकर्ताओं का मानना है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। उदाहरण के लिए, एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में कुछ प्रजातियां जैसे कि श्हेम्पस्टरश और इबिस तेजी से घट रही हैं।

मनुष्य के विकास में दूध के सेवन का संबंध

कुछ उत्परिवर्तनों से वयस्कों में भी लैक्टेस एंजाइम का उत्पादन होने लगा, जो दूध में उपस्थित लैक्टोस शर्करा को पचाने में मदद करता है। वयस्क अवस्था में भी इस एंजाइम के बने रहने को लैक्टेस निरंतरता कहते हैं। आधुनिक अफ्रीका की बड़ी जनसंख्या में लैक्टेस निरंतरता के लिए चार उत्परिवर्तन हुए हैं जबकि यूरोपीय लोग सिर्फ एक ऐसे उत्परिवर्तन पर निर्भर हैं। फिर भी यह उत्परिवर्तन काफी तेजी से फैल गए जिससे लगता है कि ये काफी फायदेमंद रहे होंगे। दूध सेवन के इतिहास को और गहराई से समझने के लिए शोधकर्ताओं ने अफ्रीका का अध्ययन किया, जहां का समाज पिछले 8000 वर्षों से गाय, भेड़ और बकरी पालन करता आ रहा है।

मनुष्यों द्वारा दूध के सेवन का इतिहास मुर्गी और अंडा की पहेली जैसा है। मनुष्य दूध का सेवन तब से करते आ रहे हैं जब उनमें इसे पचाने की व्यवस्था भी नहीं थी, लेकिन डीएनए में उपयुक्त परिवर्तन के लिए जरूरी था कि वे दूध का सेवन करें। तो सवाल है कि क्या दूध पीने की शुरुआत पहले हुई या दूध पचाने के लिए जरूरी उत्परिवर्तन? ताजा अध्ययनों के अनुसार आधुनिक केन्या और सूडान के लोग कम से कम 6000 वर्षों से दुग्ध उत्पादों का सेवन कर रहे हैं यानि वे दूध को पचाने वाले जीन के अस्तित्व में आने से भी पहले से दूध का सेवन करते आ रहे हैं। गौरतलब है कि सभी मनुष्य बचपन में दूध पचाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन लगता है कि वयस्कों में यह क्षमता पिछले 6000 वर्षों में ही विक. सित हुई है।

कुछ उत्परिवर्तनों से वयस्कों में भी लैक्टेस एंजाइम का उत्पादन होने लगा, जो दूध में उपस्थित लैक्टोस शर्करा को पचाने में मदद करता है। वयस्क अवस्था में भी इस एंजाइम के बने रहने को लैक्टेस निरंतरता कहते हैं। आधुनिक अफ्रीका की बड़ी जनसंख्या में लैक्टेस निरंतरता के लिए चार उत्परिवर्तन हुए हैं जबकि यूरोपीय लोग सिर्फ एक ऐसे उत्परिवर्तन पर निर्भर हैं। फिर भी यह उत्परिवर्तन काफी तेजी से फैल गए जिससे लगता है कि ये काफी फायदेमंद रहे होंगे। दूध सेवन के इतिहास को और गहराई से समझने के लिए शोधकर्ताओं ने अफ्रीका का अध्ययन किया, जहां का समाज पिछले 8000 वर्षों से गाय, भेड़ और बकरी पालन करता आ रहा है। वैज्ञानिकों ने खुदाई में मिले सूडान और केन्या के 2000 से 6000 वर्ष पुराने 8 कंकालों के दांतों की कठोर परतों में दुग्ध-संबंधी प्रोटीन की उपस्थिति देखी, जिससे लगता है कि ये लोग लगभग 6000 वर्ष पहले से डेयरी उत्पादों का सेवन कर रहे थे। नेचर कम्युनिकेशन्स में प्रकाशित यह अध्ययन अफ्रीका और विशेष रूप से विश्व की डेयरी खपत का प्राचीनतम प्रमाण है। अध्ययन से यह भी पता चला है कि अफ्रीका में डेयरी उद्योग यूरोप के डेयरी उद्योग जितना या उससे भी अधिक पुराना है और तो और, 2020 में कुछ अफ्रीकी कंकालों के डीएनए के अध्ययन के अनुसार प्राचीन अफ्रीकी लोगों में उस समय दूध को पचाने वाले किसी जीन का विकास भी नहीं हुआ था। वे लोग लैक्टेस निरंतरता से पहले से ही दूध का सेवन करते आ रहे थे। कंकालों में मिला प्रोटीन दूध, पनीर या दही जैसे किण्वित उत्पादों से आया होगा। कई संस्कृतियों में किण्वन का उपयोग दूध का सेवन करने से पहले उसकी शर्करा को तोड़ने के लिए किया जाता रहा है ताकि लैक्टेस की अनुपस्थिति में भी दूध उत्पादों का सेवन कर सकें। अंततः वह उत्परिवर्तन हुआ होगा, जिसने लोगों को दूध से अधिक से अधिक पोषण प्राप्त करने में मदद की।

वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की पुरातत्वविद फियोना मार्शल के अनुसार, जिन अफ्रीकी लोगों में लैक्टेस की निरंतरता अधिक थी वे लोग अधिक समय तक जीवित रहते थे और उनके बच्चे भी ज्यादा होते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि लैक्टेस निरंतरता के चयन का कारण पर्यावरणीय भी हो सकता है। गौरतलब है कि दूध मुश्किल परिस्थितियों में आबादी का प्रबंधन करने का एक बढ़िया तरीका है जिसमें चरवाहे जानवरों की हत्या किए बिना ही उनसे पोषण प्राप्त कर सकते थे। सूखे के समय में भी ये चौपाए उनके लिए पानी के फिल्टर और भंडारण का काम किया करते थे। जब तक ये जीव जिंदा रहते थे, तरल, प्रोटीन और पोषण का स्रोत हुआ करते थे।

...स्रोत फीचर्स

सबकुछ जानकर भी नहीं छूट पा रही सोशल मीडिया की लत

सोशल मीडिया का आगमन पिछले एक दशक में हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफार्मों ने न केवल हमारी संवाद शैली को बदल दिया है, बल्कि हमारी मानसिकता, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाला है। हालांकि, इस तकनीकी प्रगति के साथ-साथ, सोशल मीडिया की लत भी एक गंभीर समस्या बन गई है। इस लेख में हम सोशल मीडिया की लत के स्वास्थ्य पर प्रभावों की गहराई से चर्चा करेंगे।

सोशल मीडिया की लत: एक परिचय

सोशल मीडिया की लत को किसी व्यक्ति के सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो उनके दैनिक जीवन, कार्यक्षमता, और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह लत व्यक्तियों को अपने वास्तविक जीवन से दूर कर देती है और उन्हें एक आभासी दुनिया में सीमित कर देती है।

सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग

1. जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्ग में प्रभाव

आजकल के युवा और बच्चे सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिता रहे हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि औसतन एक व्यक्ति दिन में लगभग 2-3 घंटे सोशल मीडिया का उपयोग करता है। यह समय न केवल संचार के लिए, बल्कि मनोरंजन, समाचार, और अन्य जानकारी के लिए भी उपयोग किया जाता है।

2. सोशल मीडिया का व्यावसायिक उपयोग

सोशल मीडिया का उपयोग व्यवसायों में भी बढ़ रहा है। कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग कर रही हैं। हालांकि, इस व्यावसायिक उपयोग के साथ-साथ, व्यक्तिगत उपयोग भी बढ़ रहा है।

अवसाद और चिंता

सोशल मीडिया की लत से अवसाद और चिंता की समस्याएं बढ़ सकती हैं। जब व्यक्ति दूसरों के जीवन को देखकर अपनी स्थिति की तुलना करते हैं, तो उन्हें असुरक्षा का अनुभव होता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

आत्म-सम्मान में कमी

सोशल मीडिया पर ष्लाइकष और ष्फॉलोअरष की संख्या से व्यक्ति का आत्म-सम्मान प्रभावित होता है। जब व्यक्ति को अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो उनकी आत्मछवि पर बुरा असर पड़ता है।

शारीरिक स्वास्थ्य

सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग रात में नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। स्क्रीन की नीली रोशनी और लगातार सूचनाओं के कारण व्यक्ति सोने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं।

शारीरिक गतिविधियों की कमी

सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने से शारीरिक गतिविधियों की कमी होती है। यह वजन बढ़ने, हृदय रोग, और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

व्यक्तिगत संबंधों में कमी

सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने से व्यक्ति अपने वास्तविक संबंधों की उपेक्षा करने लगता है। इससे पारिवारिक और मित्रता संबंध कमजोर हो सकते हैं।

सामाजिक अलगाव

जब व्यक्ति केवल ऑनलाइन बातचीत में ही उलझा रहता है, तो वे वास्तविक दुनिया से अलगाव का अनुभव कर सकते हैं। यह सामाजिक जीवन में कमी का कारण बनता है।

प्रभावी शोध और अध्ययन

अनेक शोधों ने सोशल मीडिया के उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित किया है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि जिन व्यक्तियों ने रोजाना अधिक समय सोशल मीडिया पर बिताया, उनमें अवसाद और चिंता के लक्षण अधिक देखे गए।

डेटा का विश्लेषण

एक अन्य अध्ययन में, 18 से 24 वर्ष के युवाओं में सोशल मीडिया के उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध को स्थापित किया गया। यह पाया गया कि जिन युवाओं ने अपने आत्म-सम्मान को सोशल मीडिया पर आधारित किया, उनमें अवसाद की संभावना अधिक थी।

समाधान और उपाय

सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित करना एक प्रभावी उपाय हो सकता है। व्यक्ति को अपनी स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करना चाहिए और इसे केवल आवश्यकतानुसार उपयोग करना चाहिए।

डिजिटल डिटॉक्स

डिजिटल डिटॉक्स का अर्थ है कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाना। इससे व्यक्ति को अपने मानसिक स्वास्थ्य को पुनः सुधारने और वास्तविक जीवन में जुड़ने का अवसर मिलता है।

जागरूकता कार्यक्रम

लोगों को सोशल मीडिया के प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। व्यक्ति को अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए पेशेवर मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए।

निष्कर्ष

सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसकी लत गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। मानसिक, शारीरिक, और सामाजिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें इसे समझदारी से उपयोग करने की आवश्यकता है, ताकि हम इसके फायदों का लाभ उठा सकें और इसके हानिकारक प्रभावों से बच सकें। इस दिशा में उठाए गए कदम न केवल हमारे लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए हमें सोशल

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

विश्व पटल पर बालिकाओं का नवयुग: बदली सोच, उभरी शक्ति

(लेखक- ललित गर्ग)

दुनिया के कई देशों में महिलाएँ अब राजनीति, प्रशासन और कॉरपोरेट नेतृत्व में अग्रिम पंक्ति में हैं। वे राष्ट्राध्यक्ष हैं, सेनाओं का नेतृत्व कर रही हैं, वैज्ञानिक खोजों की अगुआई कर रही हैं और वैश्विक संस्थानों में नीति-निर्धारण का हिस्सा हैं। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि अवसर मिलने पर प्रतिभा लिंग नहीं देखती। गैलप इंटरनेशनल के सर्वे में उभरी उदासीनता कि संतान का लिंग मायने नहीं रखता, दरअसल इसी विश्वास का सामाजिक विस्तार है कि लड़कियाँ भी उतनी ही सक्षम हैं।

एक समय था जब दुनिया के बड़े हिस्से में बेटी का जन्म बोझ समझा जाता था। गर्भ में ही उसके जीवन का अंत कर दिया जाता, या जन्म के बाद भेदभाव, उपेक्षा और वंचना उसका भाग्य बनती। सदियों तक चली इस दकियानूसी एवं पुरानपंथी सोच ने समाज, सभ्यता और प्रकृति-तीनों को गहरे घाव दिए। किंतु आज उसी दुनिया में सोच के स्तर पर एक निर्णायक मोड़ दिखाई दे रहा है, एक नयी सोच का उदय हो रहा है। गैलप इंटरनेशनल जैसे वैश्विक सर्वे यह संकेत देते हैं कि 44 देशों में माता-पिता की बड़ी संख्या अब संतान के लिंग को लेकर उदासीन हो रही है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा लड़का है या लड़की। यह बदलाव केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि मानव चेतना में घटित एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। बालिकाओं को लेकर बदल रही यह सोच मानवीयता का दर्शन करा रही है। यह सच है कि तस्वीर का एक पक्ष उजला है तो दूसरा अब भी चिंताजनक। पिछले 25 वर्षों में दुनिया ने लगभग 70 लाख बच्चियों को बचाया है, यह मानवीय प्रगति का बड़ा प्रमाण है। परंतु यह भी उतना ही कड़वा सत्य है कि आज भी हर साल दस लाख से अधिक बच्चियां गर्भ में ही खत्म कर दी जाती हैं और बीते 45 वर्षों में यह संख्या पाँच करोड़ से अधिक रही है। यानी लड़का-लड़की के भेद का राक्षस अभी पूरी तरह पराजित नहीं हुआ है। इसके बावजूद, उम्मीद की किरण इसलिए प्रबल है क्योंकि अब यह भेद सामाजिक स्वीकृति खो रहा है, और यही किसी भी क्रांति की सबसे ठोस बुनियाद होती है।

भारत में यह संघर्ष और भी जटिल रहा है। कम शिक्षा, रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक सोच, अंधविश्वास और सामाजिक भ्रांतियों ने लंबे समय तक बालिकाओं के अस्तित्व पर संकट बनाए रखा। लेकिन हाल के वर्षों में स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दिखता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, भारत में बेटों की चाहत 1999 के 33 प्रतिशत से घटकर अब 15 प्रतिशत रह गई है। यह गिरावट केवल सांख्यिकीय नहीं, बल्कि मानसिकता में आए बदलाव का संकेत है। फिर भी, 15 प्रतिशत भी कम नहीं क्योंकि इसका सीधा असर लिंगानुपात पर पड़ता है। आज देश में लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 943 लड़कियों का है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार जन्म के समय लड़के-लड़कियों का प्राकृतिक अनुपात लगभग 105ः 100 होता है, जो पाँच वर्ष की आयु तक बराबर हो जाना चाहिए। यदि पाँच साल के बाद भी 1000 लड़कों पर 57 लड़कियाँ कम हैं, तो स्पष्ट है कि प्रकृति नहीं, समाज हस्तक्षेप कर रहा है। 57 बड़ा अंतर है। सुधार की जो गति चल रही है, उस हिसाब से इस अंतर को पाटने में पच्चीस साल से ज्यादा लग जाएंगे। ये बच्चियां दुनिया में कदम रखें और अच्छी तरह से खुशगवार जिंदगी जिएं, इसके लिए उन्हें बचाने के उपाय, उनकी व्यापकता और गति सब बढ़ाने होंगे। सृष्टि के संतुलन के लिए भी यह जरूरी है। समाज की विडम्बनापूर्ण सोच ही वह 卐बाहरी शक्ति卐 है-भेदभाव, उपेक्षा, असमान पोषण, स्वास्थ्य और अवसर जो संतुलन को बिगाड़ रही है। मौजूदा सुधार की गति से इस अंतर को पाटने में पच्चीस वर्ष से अधिक लग सकते हैं। इसलिए उपायों की व्यापकता और गति दोनों को बढ़ाना अनिवार्य है।

इस बदलाव के पीछे शिक्षा सबसे बड़ा कारक बनकर उभरी है। जब-जब लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर मिले, उन्होंने न केवल अपनी क्षमताएँ सिद्ध कीं, बल्कि समाज की दिशा भी बदली। भारत सहित कई देशों में बालिका शिक्षा, छात्रवृत्ति, डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं ने लड़कियों के जीवन-पथ को नया आयाम दिया है। आज ग्रामीण क्षेत्रों तक स्कूल नामांकन में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ी है, उच्च शिक्षा में उनकी उपस्थिति मजबूत हुई है और विज्ञान, तकनीक, खेल, प्रशासन तथा उद्यमिता-हर क्षेत्र में वे अपनी पहचान बना रही हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि अब नीतियाँ केवल संरक्षण तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि सशक्तिकरण की ओर बढ़ी हैं। शिक्षा के साथ-साथ पोषण, मातृत्व स्वास्थ्य, सुरक्षित परिवहन, डिजिटल पहुँच और नेतृत्व प्रशिक्षण, इन सभी ने मिलकर बालिकाओं के आत्मविश्वास को पंख दिए हैं। यह समग्र दृष्टि ही भविष्य की महिलाओं को 卐सहायता पाने वाली卐 नहीं, बल्कि 卐निर्णय लेने वाली卐 बनाती है।

दुनिया के कई देशों में महिलाएँ अब राजनीति, प्रशासन और कॉरपोरेट नेतृत्व में अग्रिम पंक्ति में हैं। वे राष्ट्राध्यक्ष हैं, सेनाओं का नेतृत्व कर रही हैं, वैज्ञानिक खोजों की अगुआई कर रही हैं और वैश्विक संस्थानों में नीति-निर्धारण का हिस्सा हैं। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि अवसर मिलने पर प्रतिभा लिंग नहीं देखती। गैलप इंटरनेशनल के सर्वे में उभरी उदासीनता कि संतान का लिंग मायने नहीं रखता, दरअसल इसी विश्वास का सामाजिक विस्तार है कि लड़कियाँ भी उतनी ही सक्षम हैं। पहली बार दुनिया के स्तर पर बालिकाओं को लेकर एक सकारात्मक परिदृश्य उभरा है, इन बालिकाओं को लेकर बदली सोच एवं उभरी शक्ति के परिदृश्यों के बीच यह समय बालिकाओं-महिलाओं पर हो रहे अपराध, शोषण, बलात्कार, भेदभाव के त्रासद एवं क्रूर स्थितियों पर आत्म-मंथन करने का है, क्योंकि बालिकाओं एवं महिलाओं के समावेश, न्याय व सुरक्षा की स्थिति को बताने वाले वैश्विक शांति व सुरक्षा सूचकांक के 177 देशों में भारत का 128वां स्थान है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के विरूद्ध अपराध में राष्ट्रीय औसत 66.4 है। राजधानी दिल्ली का स्थान 144.4 अंकों के साथ सर्वोच्च है।

माना जाता है कि 90 प्रतिशत यौन उत्पीड़न जान-पहचान के व्यक्ति ही करते हैं। यानी बालिकाएं अपने ही घर या परिचितों के बीच सबसे ज्यादा असुरक्षित है। कानून और योजनाएँ आवश्यक हैं, पर पर्याप्त नहीं। असली परिवर्तन संस्कृति में होता है-घर के भीतर, भाषा में, परंपराओं में। जब परिवार बेटी के जन्म को उत्सव मानता है, उसकी शिक्षा में निवेश करता है, उसे निर्णयों में भागीदार बनाता है-तभी लिंगानुपात के आँकड़े स्थायी रूप से सुधरते हैं। मीडिया, साहित्य और सिनेमा की भूमिका भी यहाँ निर्णायक है; वे या तो रूढ़ियों को पोषित करते हैं या नई दृष्टि गढ़ते हैं। आज सकारात्मक प्रस्तुतियाँ बढ़ रही हैं, जो लड़कियों को आत्मनिर्भर, साहसी और नेतृत्वकारी रूप में दिखाती हैं यह सांस्कृतिक परिवर्तन का संकेत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत का लक्ष्य भी बालिका लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना है।

भविष्य की दिशा स्पष्ट है-समानता केवल अधिकारों की सूची नहीं, बल्कि अवसरों की वास्तविक उपलब्धता है। बालिकाओं को बचाना पहला कदम था; अब उन्हें बढ़ने, उड़ने और नेतृत्व करने देना अगला चरण है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार, संपत्ति अधिकार, डिजिटल अवसर और निर्णय-निर्माण में हिस्सेदारी-ये सभी समानता के स्तंभ हैं। यदि इन पर निरंतर और समन्वित कार्य हुआ, तो आने वाले वर्षों में लिंगानुपात केवल सुधरेगा ही नहीं, बल्कि समाज अधिक संतुलित, संवेदनशील और उत्पादक बनेगा। एक समय था जब बालिका को कोख में ही समाप्त कर दिया जाता था; आज वही दुनिया उसके जन्म पर प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। यह बदलाव अधूरा है, पर निर्णायक है। भारत में बेटों की चाहत का घटता ग्राफ, दुनिया भर में लिंग-उदासीनता की बढ़ती प्रवृत्ति और महिलाओं के लिए विस्तृत होती शिक्षा-सशक्तिकरण योजनाएँ-सब मिलकर संकेत देते हैं कि आने वाला समय वास्तव में महिलाओं का समय है। यदि यह गति बनी रही, तो देश की बालिकाएँ न केवल अपना परचम फहराएँगी, बल्कि मानव सभ्यता को अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित दिशा भी देंगी। यही सृष्टि का स्वाभाविक और आवश्यक संतुलन है।

संपादकीय

पंजाब में बढ़ते अपराध

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि पंजाब में सरेआम की जा रही लक्षित हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुस्साहसी हत्यारे अपने मंसूबों को अंजाम देकर साफ निकल जाते हैं। यह विडंबना ही है कि पंजाब में नये साल की शुरुआत दिनदहाड़े हुई हत्याओं की एक श्रृंखला के साथ हुई है। अब चाहे लुधियाना जिले में एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी की निर्मम हत्या हो या अमृतसर के मैरिज रिसॉर्ट में एक विधायक के करीबी सरपंच की गोली मारकर बेरहमी से हत्या, इनसे पता चलता है कि पंजाब के अपराधियों में कानून का भय नहीं रह गया। निश्चित रूप से ये घटनाएं पंजाब में गंभीर चुनौती बनती एक जटिल समस्या की ओर इशारा करती हैं। इस चिंताजनक होती स्थिति की वजह लगातार अपराधी गिरोहों के नेटवर्क का मजबूत होना, घातक हथियारों की सहज उपलब्धता और पुलिस बल पर लगातार बढ़ता दबाव भी है। दूसरी ओर विपक्षी दल आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला चलाए रहते हैं और राजनीतिक लक्ष्यों के लिये मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग करते रहते हैं। वहीं सरकार इस संकट को अपने पूर्ववर्तियों द्वारा विरासत में छोड़ा गया बताते हैं। लेकिन एक हकीकत है कि इन बयानबाजियों से नागरिकों की असुरक्षा कम नहीं होती है। वहीं पंजाब के शीर्ष पुलिस अधिकारियों की दलील होती है कि पंजाब में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। लेकिन राज्य में बढ़ते अपराधों के संकट को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से जब हत्याएं राज्य के भीड़भाड़ वाले इलाकों में होती हैं तो लोगों का कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। वहीं दूसरी ओर राज्य के पुलिस महानिदेशक की दलील है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ड्रोन के जरिये हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थ भेजकर सीमांत राज्य पंजाब के खिलाफ परोक्ष युद्ध छेड़े हुए है। निश्चय ही यह बात इस सीमावर्ती राज्य के लिये गंभीर चिंता का विषय है। इसमें दो राय नहीं कि पंजाब के डीजीपी का पाक से अपराधियों को प्रश्रय देने वाला बयान चिंता बढ़ाने वाला है। खासकर उस राज्य के लिये, जिसने एक दशक तक उग्रवाद का सामना किया हो। लेकिन पंजाब के अपराध संकट के लिये केवल बाहरी कारकों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह पुलिस विभाग की शिथिलता व खुफिया तंत्र की नाकामी के साथ सामाजिक विद्रूपताओं से भी उपजा संकट है। निस्संदेह, राज्य में अधिक बेरोजगारी है। बंदूक संस्कृति का महिमामंडन भी गंभीर चुनौती है। वहीं दूसरी ओर युवाओं में रातों-रात धनवान बनने का लालच भी स्थानीय व क्षेत्रीय गिरोहों के पनपने की गंभीर वजह है। इसके अलावा पुलिस विभाग की संरचना की भी कुछ विसंगतियां सामने आती हैं। मसलन पुलिस व्यवस्था में उच्च अधिकारियों की तो अधिकता है मगर फील्ड स्टाफ पर काम का बोझ जरूरत से ज्यादा है। इसके अलावा पुलिस के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप के भी आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस, हासिल कुछ सफलताओं के बावजूद जनता का विश्वास जीतने के लिये संघर्ष कर रही है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजियों से इतर राज्य सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव लाकर धरातल पर गंभीर प्रयास करने होंगे। मौजूदा हालात में बहुआयामी रणनीति बनाने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। इसके अंतर्गत पुलिस सुधार भी प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की जरूरत है, ताकि हाइटैक अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके। इसके साथ ही अपराध नियंत्रण में केंद्रीय एजेंसियों से बेहतर तालमेल करने की भी जरूरत है।

अदृश्य रफ्तार: क्यों जरूरी है पृथ्वी की निरंतर धुरी पर दौड़?

(लेखक- दिलीप कुमार पाठक)

(08 जनवरी पृथ्वी घूर्णन दिवस)

पृथ्वी घूर्णन दिवस हर साल 8 जनवरी को मनाया जाता है, जो हमें हमारे ग्रह की उस निरंतर गति की याद दिलाता है जिसे हम महसूस तो नहीं कर पाते, लेकिन जिसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

यह दिन वैज्ञानिक जिज्ञासा और सत्य की खोज का प्रतीक है, जो सदियों के अंधविश्वास को तोड़कर वैज्ञानिक तथ्यों की स्थापना को समर्पित है। सदियों पहले तक मनुष्य का यह मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य सहित सभी खगोलीय पिंड इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन विज्ञान की प्रगति के साथ यह स्पष्ट हुआ कि हमारी पृथ्वी न केवल सूर्य की परिक्रमा करती है, बल्कि अपनी धुरी पर भी निरंतर घूमती रहती है। इसी घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र चलता है, जो जीवन की लय को निर्धारित करता है। इस वैज्ञानिक सत्य की गहराई में जाएं तो हम पाते हैं कि पृथ्वी की यह घूर्णन गति केवल समय का मापदंड नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का आधार भी है। आज के आधुनिक युग में जब हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं, विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि पृथ्वी लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। इतनी तीव्र गति के बावजूद हमें झटका महसूस नहीं होता, क्योंकि हम और हमारा वायुमंडल भी इसी गति का हिस्सा हैं। यह घूर्णन ही है जो समुद्र के जल स्तर को संतुलित रखता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ तालमेल बिठाकर हमें धरातल पर टिकाए रखता है। इसके बिना पृथ्वी का आकार भी वैसा नहीं होता जैसा आज हम देखते हैं, क्योंकि घूर्णन के कारण ही यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है।

इस विशेष दिवस का इतिहास फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फौकॉल्ट से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने 1851 में एक ऐतिहासिक प्रयोग के माध्यम से पृथ्वी के घूमने के प्रमाण प्रस्तुत किए थे। फौकॉल्ट ने पेरिस के पेंथियन की छत से एक लंबा पेंडुलम लटकाया था और दुनिया को यह दिखाया कि समय के साथ पेंडुलम के दोलन की दिशा बदल रही है। यह बदलाव पेंडुलम के कारण नहीं, बल्कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण हो रहा था। उनके इस सफल प्रदर्शन ने खगोल विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी और आम जनमानस के लिए इस सत्य को स्वीकार करना आसान बना दिया। आज फौकॉल्ट पेंडुलम दुनिया भर के कई विज्ञान संग्रहालयों में देखा जा सकता है, जो हमें निरंतर पृथ्वी की गति का स्मरण कराता रहता है।

पृथ्वी की घूर्णन गति हमारे अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह न केवल दिन-रात का निर्माण करती है, बल्कि पृथ्वी के तापमान को भी संतुलित रखती है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, तो इसके एक हिस्से में हमेशा चिलचिलाती गर्मी और दूसरे हिस्से में जमा देने वाली ठंड होगी, जिससे जीवन का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। इसके अलावा, पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न होने वाला कोरियोलिस प्रभाव समुद्र की लहरों और वायुमंडल में हवाओं की दिशा को नियंत्रित करता है। मौसम का बदलना, बादलों की गति और महासागरीय धाराओं का प्रवाह, ये सभी पृथ्वी के निरंतर घूमने का ही परिणाम हैं। यह घूर्णन ही पृथ्वी के चारों ओर उस चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, जो हमें सूर्य की हानिकारक विकिरणों से बचाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, यह दिवस हमें जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के बदलते स्वरूप पर भी विचार करने के लिए मजबूर करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों का पिघलना पृथ्वी के द्रव्यमान वितरण को बदल रहा है, जिससे इसकी घूर्णन गति पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ सकता है। यह सूक्ष्म बदलाव भविष्य में हमारे सटीक समय मापन और उपग्रह संचार प्रणालियों के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है। अत:, पृथ्वी घूर्णन दिवस केवल एक खगोलीय घटना का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे पारिस्थितिक तंत्र की संवेदनशीलता को समझने का भी दिन है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति की हर क्रिया एक निश्चित गणित और संतुलन पर आधारित है, जिसे बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

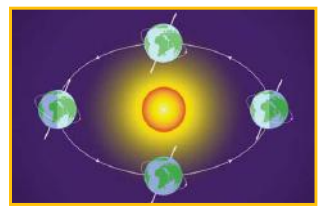

आज के आधुनिक युग में पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाने का उद्देश्य नई पीढ़ी को विज्ञान के प्रति जागरूक करना और उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भले ही हम अपने पैरों के नीचे की जमीन को स्थिर महसूस करते हों, लेकिन हम वास्तव में अंतरिक्ष में एक अविश्वसनीय गति से यात्रा कर रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों में इस दिन छात्रों को खगोल भौतिकी के बारे में बताया जाता है और महान वैज्ञानिकों के संघर्षपूर्ण योगदान को याद किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो, यह दिवस कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है कि हमारी पृथ्वी सही गति और सही झुकाव के साथ घूम रही है, जिससे जीवन फलता-फूलता रहे। हमें इस दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे और अपनी पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षित रखने में योगदान देंगे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इस अद्भुत ग्रह की गति का आनंद ले सकें।

(लेखक पत्रकार हैं)

प्रयश्चित ही कर्म फल से मुक्ति का आधार है

यह ठीक है कि जिस व्यक्ति के साथ अनाचार बरता गया अब उस घटना को बिना हुई नहीं बनाया जा सकता। सम्भव है कि वह व्यक्ति अन्यत्र चला गया हो। ऐसी दशा में उसी आहत व्यक्ति की उसी रूप में क्षति पूर्ति करना सम्भव नहीं। किन्तु दूसरा मार्ग खुला है। हर व्यक्ति समाज का अंग है। व्यक्ति को पहुँचाई गई क्षति वस्तुतः प्रकारान्तर से समाज की ही क्षति है। उस व्यक्ति को हमने दुष्कर्मों से जितनी क्षति पहुँचाई है उसकी पूर्ति तभी होगी जब हम उतने ही वजन के सत्कर्म करके समाज को लाभ पहुँचाये। समाज को इस प्रकार हानि और लाभ का बैलेन्स जब बराबर हो जायेगा तभी यह कहा जायेगा कि पाप का प्रायश्चित हो गया और आत्मग्लानि एवं आत्मप्रताड़ना से छुटकारा पाने की स्थिति बन गई। सस्ते मूल्य के कर्मकाण्ड करके पापों के फल से छुटकारा पा सकना सर्वथा असम्भव है। स्वाध्याय, सत्संग, कथा, कीर्तन, तीर्थ, व्रत आदि से चित्त में शुद्धता की वृद्धि होना और भविष्य में पाप वृत्तियों पर अंकुश लगाने की बात समझ में आती है। धर्म कृत्यों से पाप नाश के जो माहात्म्य शास्त्रों में बताये गये हैं उनका तात्पर्य इतना ही है कि मनोभूमि का शोधन होने से भविष्य में बन सकने वाले पापों की सम्भावना का नाश हो जाये। ईश्वरीय कठोर न्याय व्यवस्था में ऐसा ही विधान है कि पाप परिणामों की आग में जल मरने से जिन्हें बचना हो वे समाज की उत्कृष्टता बढ़ाने की सेवा-साधना में संलग्न हों और लदे हुए भार से छुटकारा प्राप्त कर शान्ति एवं पवित्रता की स्थिति उपलब्ध कर लें।

विचार मंथन

भारत की वैश्विक परीक्षा का समय

(लेखक- सनत जैन)

साल 2026 की शुरूआत के साथ ही भारत उम्मीदों और आकांक्षाओं के पंख फैलाकर विकास की निर्बाध उड़ान उडना चाहता है। लेकिन वैश्विक चुनौतियां उसकी राह में बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो गई हैं। ऐसे में यह समय भारत के लिए फूंक-फूंककर कर कदम बढ़ाने की जरूरत है। यह भी तभी संभव है, जब भारत की कूटनीति और विदेश नीति सही दिशा में हो। विश्व राजनीति इस समय जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, वह भविष्य में और भी जटिल, संघर्षपूर्ण और विकट होने जा रही है। अमेरिका अपनी वैश्विक प्रभुता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। चाहे वह यूरोप की सत्ता समीकरणों के माध्यम से हो या दक्षिण एशिया में रणनीतिक हस्तक्षेप के जरिए। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि अब वह एकध्रुवीय विश्व का युग समाप्त हो चुका है। आज की दुनिया बहुध्रुवीय है, जहां भारत, चीन, रूस, और यूरोपीय संघ जैसे केंद्र अपनी स्वतंत्र और निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका की कोशिश है कि दक्षिण एशिया में वह अपनी पकड़ बनाए रखे, ताकि चीन को घेरा जा सके और भारत को अपने पाले में रखा जा सके। इसके लिए वह ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, और फिलीपींस जैसे देशों के माध्यम से चीन पर रणनीतिक दबाव बना रहा है। किंतु भारत के लिए यह रास्ता उतना सरल नहीं है जितना दिखाई देता है। यदि भारत ताइवान के साथ मित्रता के सूत्रों को सार्वजनिक रूप से मजबूत करता है, तो निस्संदेह चीन भारत के विरुद्ध अप्रत्यक्ष मोर्चा खोल देगा। साल 2026 की शुरुआत भारत के पड़ोसी देशों के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाली है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल तीनों देश गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहे हैं। कहीं चुनाव व्यवस्था सवालों के घेरे में है, कहीं सेना का वर्चस्व बढ़ रहा है और कहीं बेरोजगार और गुस्साई युवा पीढ़ी सडकों पर है। इन तीनों देशों की अस्थिरता का असर सिर्फ इनके भीतर नहीं, बल्कि सीधे भारत की सुरक्षा, कूटनीति और क्षेत्रीय भूमिका पर पड़ सकता है। ऐसे में भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी नीति अब तक की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरने वाली है। बड़ा सवाल यह है कि भारत के तमाम सहयोग और राहत की नीतियों के बावजूद ये देश चीन और पाकिस्तान की तरफ क्यों झुके जाते हैं, जिनकी नीतियों की वजह से कर्ज और जिहादी आतंक के संकटों से घिर जाते हैं? चीन के अलावा अब ट्रंप और सऊदी का समर्थन मिलने से इतराए पाकिस्तान का उपाय करने के साथ-साथ इस सवाल का हल खोजना शायद भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती होगी। कहने को तो एक साल ही बदला है, पर डोनाल्ड ट्रंप ने जैसी उथल-पुथल मचाई है, उससे लगता है मानो एक युग बदल गया है। नए साल की शुरुआत में ही उन्होंने वेनेजुएला पर धावा बोल दिया। ट्रंप की दुनिया में किसी स्थापित कूटनीतिक परंपरा और अंतरराष्ट्रीय कायदे-कानून की कोई गारंटी नहीं है। यह द्वितीय महायुद्ध के बाद बनी नियमबद्ध व्यवस्था वाली दुनिया से नितांत भिन्न है, जिसके आधार पर भारत की विदेश और व्यापार नीति टिकी है। जिस गुटबाजी से भारत को परहेज था, वह सोवियत संघ के विघटन से टूटी और दुनिया एकध्रुवीय बन गई। भारत ने गुटनिरपेक्षता की जगह हितसापेक्ष स्वायत्तता की नीति अपनाई और खेमेबाजी से दूर रहते हुए अपनी सामरिक एवं आर्थिक शक्ति के विकास के लिए अमेरिका का रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार बन गया। भारत से पहले चीन ने भी गुटबाजी छोड़कर अपने सामरिक हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका के साथ व्यापारिक साझेदारी की, जिसकी बदौलत आज वह अमेरिका को हर क्षेत्र में चुनौती देने की स्थिति में आ गया है। ट्रंप खुद चीन को जी-2 का दूसरा जी यानी दूसरी महाशक्ति मान चुके हैं। रूस को वे सामरिक महाशक्ति मानते हैं, लेकिन वह वैश्विक शक्ति संतुलन की तीसरी धुरी बनने की स्थिति में नहीं है। यूक्रेन युद्ध और आर्थिक प्रतिबंधों ने उसे चीन के खेमे में पहुंचा दिया है। यानी दुनिया एक बार फिर दो खेमों में बंटती दिख रही है, जबकि भारत बहुपक्षीय व्यवस्था चाहता है। ट्रंप के यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु संधि जैसी वैश्विक संस्थाओं और संधियों से हाथ खींच लेने के कारण उभरती शक्तियों के लिए विश्व मंच पर कुछ जगह जरूर बनी है। हालांकि नियमबद्ध व्यवस्था का स्थान महाशक्तियों की मनमानी ने ले लिया है। अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति मादुरो को बंधक बनाना, ईरान और नाइजीरिया पर हवाई हमले और ताइवान को डराने के लिए चीन के सैनिक अभ्यास इसके ताजा उदाहरण हैं। महाशक्तियों की मनमानी भारत के लिए चिंताजनक है। भारत चाहता जरूर है कि वैश्विक संस्थाएं अमेरिका और यूरोप के नियंत्रण से मुक्त हों, पर नियमबद्धता की कीमत पर नहीं। वह चाहता है कि वैश्विक संस्थाओं में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसी शक्तियों को भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिले। महाशक्तियों की मनमानी वाली अव्यवस्था में यदि भारत को सुरक्षा परिषद और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में उचित स्थान मिल भी जाए तो उसकी व्यावहारिक उपादेयता क्या रह जाएगी? हकीकत यह है कि भारत को इसी व्यवस्था के भीतर अपनी विदेश नीति के कौशल से अपनी जगह बनानी है। इस साल उसे ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता करनी है, जहां उसे दक्षिणी देशों का नेतृत्व करने का अवसर तो मिलेगा, मगर उसके लिए उसे चीन का सामना भी करना पड़ेगा।

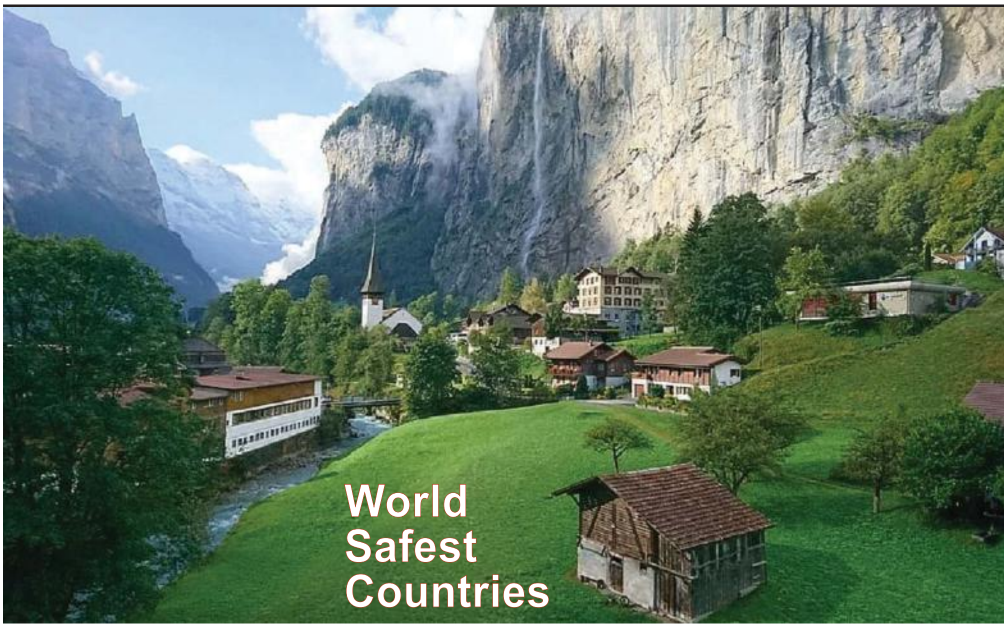

इन देशों में सुरक्षा की नहीं होगी चिंता, बेफिक्र होकर बनाएं घूमने का प्लान

कई लोग विदेश घूमने की इच्छा रखते हैं। विदेश घूमने के लिहाज से अधिकतर देश शानदार हैं। हालांकि विदेशों की खूबसूरती किसी भी टूरिस्ट के मन को आसानी से भा सकती है। लेकिन जब भी विदेश घूमने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आता है कि क्या वह जगह सुरक्षा के लिहाज से सही है। क्योंकि सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायॉरिटी होती है। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आपको सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आइए जानते हैं कि वह कौन-कौन से देश हैं, जहां पर आप बेफिक्र होकर घूम सकते हैं।

आइसलैंड

आइसलैंड की आबादी 3,72,295 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार, यह दुनिया का सबसे सुरक्षित देश हैं। बता दें कि यहां पर क्राइम रेट काफी कम है। इसके साथ ही यह हाई-सिक्योरिटी वाला देश भी है। सभी तरह के अपराधों के प्रति यहां के नागरिकों का एक मजबूत सामाजिक दृष्टिकोण है। यह देश धार्मिक स्वतंत्रता देने के साथ ही महिलाओम और पुरुषों को समान अधिकार देता है। अगर आप भी विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आइसलैंड सुरक्षित देश है।

न्यूजीलैंड

आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की जनसंख्या 5,124,100 के आसपास है। यह देश भी घूमने और रहने के लिहाज से सुरक्षित है। यहां पर आप बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। न्यूजीलैंड का भी क्राइम रेट कम है। हालांकि साल 2019 में क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों पर हुए आतंकवादी हमले के कारण यहां का क्राइम स्कोर थोड़ा कम हो गया है। यह पर आप सुरक्षा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड में शांति वाले इलाके में पुलिस अपने पास हथियार भी नहीं रखती है।

पुर्तगाल

साल 2014 के अनुसार, पुर्तगाल दुनिया का 18वां सबसे सुरक्षित देश है। ऐसे में आप बिना सुरक्षा की चिंता किए बगैर यहां पर घूम सकते हैं। 10,270,865 के करीब आबादी वाला यह देश विभिन्न कारणों से सबसे सुरक्षित देशों में शीर्ष 5वां स्थान अर्जित किया है। बता दें कि आर्थिक विकास के कारण इस देश की बेरोजगारी दर 17 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक कम हो गई है।

आस्ट्रिया

26,177,413 के करीब जनसंख्या वाला देश आस्ट्रिया भी सुरक्षित देशों की गिनती में आता है। यहां पर भी अपराध दर काफी कम है। लेकिन यहां पर घूमने आने वाले टूरिस्टों और यहां पर रहने वाले स्थानीय निवासियों को जेबकतरों और पर्स-स्नैचर्स आदि घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप भी यहां पर घूमने आना चाहते हैं तो

आपको जेबकतरों से सावधान रहने की जरूरत होगी।

डेनमार्क

डेनमार्क 5,896,026 आबादी वाला देश है। बता दें कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार, यह दुनिया का 5वां सबसे सुरक्षित देश है। इस देश में अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और कम भ्रष्टाचार होने के साथ ही कुशल सुरक्षाबन मिलेगा। इसके अलावा यहां की हेल्थ सुविधाएं भी काफी बेहतर हैं। इस देश में लोग आरामदायक तरीके से अपनी जीवन व्यतीत करते हैं।

कनाडा

कनाडा की कुल आबादी 37,742,154 के करीब है। आबादी के लिहाज से कनाडा काफी छोटा देश है। यहां का अधिकतर हिस्सा बंजर जंगल है और यह बंजर जंगल हजारों मीलों तक फैला हुआ है। लेकिन घूमने के लिहाज से यह काफी सुरक्षित देश है। इस देश का अपराध दर भी काफी कम है।

सिंगापुर

सिंगापुर 59,43,546 के करीब आबादी वाला है। सिंगापुर में छोटी-मोटी चोरी और अन्य अपराधों के खिलाफ कुछ सख्त कानून हैं। जिसके कारण इसकी गिनती दुनिया के सुरक्षित देशों में होती है। हालांकि सिंगापुर को शहर-राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि यह दुनिया के दूसरे नंबर का सबसे सुरक्षित राज्य है।

जापान

जापान की जनसंख्या 125.93 मिलियन के आसपास है। सुरक्षा के लिहाज से यह सबसे सुरक्षित देश है। चीन और उत्तर कोरिया के करीब होने के बाद भी जापान एशियाई महाद्वीप का एक सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्थिर देश है। वैश्विक शांति सूचकांक में जापान हमेशा हाई स्कोर हासिल करता है।

चेक गणराज्य

चेक गणराज्य की आबादी 10,512,397 के करीब है। यहां पर हर वर्ष अपराध दर घटता प्रतीत होता है। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में चेक गणराज्य सुरक्षित देशों में से एक है। यहां पर आप सुरक्षा की परवाह किए बिना आराम से घूम-फिर सकते हैं।

स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड घूमने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट वहां पहुंचते हैं। बता दें कि यहां की आबादी 8.6 मिलियन के आसपास है। रहने और घूमने के लिहाज से यह देश सबसे ज्यादा बेस्ट है। फूड सिक्योरिटी के मामले में भी स्विट्जरलैंड दुनिया भर में चौथे स्थान पर है।

इन टिप्स को फॉलो कर हॉलिडे को बनाएं शानदार, ऐसे करें पैसों की बचत

कई लोगों को घूमना काफी पसंद होता है। कई बार लगातार ट्रैवल करने के बाद भी छकान नहीं होती है। लेकिन घूमने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है। ऐसे में सेविंग्स का होना जरूरी होता है। घूमने के दौरान कई बार ज्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से घूमने की प्लानिंग करें तो आप पैसों की बचत कर सकते हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ट्रैवल के कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं। जिनकी मदद से आप ट्रैवल भी कर लेंगे और पैसों की सेविंग भी कर लेंगे।

हॉलिडे की योजना

अगर आप भी छुट्टी पर जाने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले यह डिसाइड करें की आप रिलैक्सिंग हॉलिडे के लिए समुद्र तट पर चाहते हैं या एडवेंचर्स करना चाहते हैं। जब आपको यह पता होता है कि आप घूमने के लिए कहां जाने वाले हैं तो वहां होने वाले खर्चे और यात्रा कार्यक्रम की योजना पहले से बना लें। इस दौरान आपके लिए रियलिस्टिक बजट बनाना आसान हो जाएगा।

रियलिस्टिक बजट

घूमने जाने की शुरूआत हॉलिडे रीयलिस्टिक बजट तय करने से शुरू होती है। आप कहीं भी घूमने जा रहे हों। कोई भी स्मार्ट ट्रैवलर यह बात काफी अच्छे से जानता है कि शानदार छुट्टियां बिताने के लिए एक रियलिस्टिक बजट की जरूरत होती है। जिसे आप आसानी से पहले ही बना सकते हैं।

ट्रैवल और खरीदारी

घूमने जाने के दौरान बुकिंग या खरीदारी पर कैशबैक कमा सकते हैं। इससे आपकी ट्रैवलिंग आसान हो जाती है। कई बार खरीददारी करने पर या बुकिंग करने के दौरान आपको कैशबैक मिलता है। इसलिए हमेशा इस ऑप्शन को ओपेन रखना चाहिए।

ऑफ सीजन में यात्रा

इस सीक्रेट को सभी स्मार्ट ट्रैवलर्स अपनाते हैं। अधिकतर ट्रैवल करने वाले ऑफ सीजन में यात्रा कर बड़ी बचत करते हैं। इस दौरान उनका ज्यादा खर्च नहीं होता है। क्योंकि वह ऑफ-पीक हॉलिडे सीजन में ट्रैवल करते हैं। ऑफ सीजन में ट्रैवल करने से फ्लाइट्स, होटल आदि सस्ते और आसानी से मिल जाते हैं।

फ्लाइट्स चुनते समय फ्लेक्सिबल

पर्यटकों की आवाजाही सप्ताह के कुछ दिनों में कम होती है। इस समय यात्रा करने पर आपको सस्ती उड़ान भरने का मौका मिल सकता है। फ्लाइट की कीमत के आधार पर आप अपनी छुट्टियों को प्लान कर सकते हैं। इससे भी आप अच्छी खासी सेविंग कर लेंगे।

हॉस्पिटैलिटी कंपनी

आपको बता दें कि अपने नियमित ग्राहकों के लिए कई प्रमुख होटल चेंस और एयरलाइंस बहुत कम या बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के लॉयल्टी प्रोग्राम्स पेश करती हैं। इस दौरान आपको होटल चेंस और एयरलाइंस के जरिए स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड

क्रेडिट या डेबिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट अर्जित कर सकते हैं। यह पॉइंट अर्जित करने का एक क्विक और आसान तरीका है। जिसके बदले कई प्रमुख बैंक गिफ्ट्स और सर्विस के बदले में आपको रिवार्ड पॉइंट प्रदान करते हैं। जिन्हें किसी भी समय रिडीम किया जा सकता है।

सस्ता विकल्प खोजें

अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप उन विकल्पों को पता करें। जिनमें यात्रा सस्ती होने के साथ ही आने-जाने से लेकर रहने तक हर चीज के लिए काफी सारे विकल्प होते हैं। इस दौरान हॉलिडे प्लान करने के दौरान शानदार अनुभवों के लिए फ्लाइट्स के स्थान पर ट्रेनों की खोज करें।

सिक्किम घूमने का बना रहे हैं प्लान तो...

इन खूबसूरत जगहों को करें एक्सप्लोर, जन्नत में आने का होगा एहसास

देश की टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन्स में नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों का नाम गिना जाता है। नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप प्लान करने वाले अधिकतर लोग सिक्किम घूमना नहीं भूलते हैं। वैसे तो सिकिम्म में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं। ऐसे में अगर आप भी सिक्किम घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को एक्सप्लोर करना न भूलें। इन खूबसूरत जगहों पर घूमने के बाद आपका वापस आने का दिल नहीं करेगा। हिमालय की गोद में बसा सिक्किम भले ही एक छोटा सा राज्य है। लेकिन यहां की खूबसूरत वादियों से लेकर नेचर की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको सिक्किम की कुछ शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में...

त्सोमगो झील की सैर

अगर आप सिक्किम में किसी रोमांटिक जगह पर घूमना चाहते हैं तो त्सोमगो लेक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। त्सोमगो लेक सिक्किम की राजधानी गंगटोक से महज 40 किलोमीटर दूर है। यह लेक 12,400 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इस लेक को चांगु झील के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि सर्दियों में यह लेक पूरी तरह से जम जाती है। वहीं बसंत ऋतु के मौके पर इस लेक की सुंदरता कई खूबसूरत फूलों से खिल उठती है।

जुलुक का दीदार

जुलुक का दीदार करने के लिए सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 3 घंटे का सफर तय करना होता है। इस दौरान रास्ते में 32 हेयरपिन मोड़ आपकी यात्रा को अधिक शानदार बना सकते हैं। वैसे तो जुलुक सिक्किम का एक छोटा सा और काफी खूबसूरत गांव है। लेकिन यहां से 11 फीट की ऊंचाई पर स्थित थुंबी व्यू प्वाइंट कंचनजंघा चोटी अपने खूबसूरत नजारों के लिए फेमस है। जुलुक की ट्रिप के दौरान कपुप लेक या हाथी झील का भी दीदार कर सकते हैं।

पेलिंग की ट्रिप

गंगटोक से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पेलिंग भी घूमने के लिए बेस्ट जगह है। यह जगह रोमांच के लिए फेमस है। पेलिंग का सफर एडवेंचर लवर्स के लिए बेस्ट हो सकता है। यहां पर एडवेंचर के शौकीन लोग रॉक क्लाइंबिग, ट्रेकिंग, कयाकिंग, माउंटेन बाइकिंग, रिवर राफ्टिंग जैसी कई एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा सांगचोएलिंग मठ रिम्बी वॉटरफॉल स्काई वॉक और सेवारो रॉक गार्डन का दीदार कर अपने सफर को शानदार और रोमांचक बना सकते हैं।

रंवगला

रंवगला सिक्किम का खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय पर्वतों से घिरा रंवगला मैनम और तेंडोंग हिल्स टॉप पर मौजूद है। बता दें कि रंवगला गंगटोक से लगभग 63 किलोमीटर की दूर स्थित है। नेचर लवर्स के लिए रंवगला की सैर बेस्ट हो सकती है। यहां से आप ग्रेटर हिमालय के मनमोहक नजारों को बेहद नजदीक से देख सकते हैं।

अवैध कब्जे और बेघर होता भारतः एक अंतहीन राष्ट्रीय संकट

ललित गर्ग

सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण की समस्या भारत में न तो नई है और न ही किसी एक क्षेत्र तक सीमित। यह एक ऐसी जटिल और बहुआयामी चुनौती है, जो शहरीकरण, पलायन, राजनीतिक स्वार्थ, प्रशासनिक लापरवाही और सामाजिक मजबूरियों के सम्मिलित परिणाम के रूप में सामने आती है। देश के लगभग हर राज्य, हर बड़े शहर और अनेक कस्बों में सरकारी जमीन पर मकान, दुकानें, झुग्गियां, गोदाम, यहां तक कि बड़े-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान और संस्थान खड़े मिल जाते हैं। वर्षों तक यह सब कुछ खुलेआम होता रहता है, लेकिन जिम्मेदार तंत्र या तो आंखें मूंदे रहता है या जानबूझकर चुप्पी साधे रहता है।

सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण की समस्या भारत में न तो नई है और न ही किसी एक क्षेत्र तक सीमित। यह एक ऐसी जटिल और बहुआयामी चुनौती है, जो शहरीकरण, पलायन, राजनीतिक स्वार्थ, प्रशासनिक लापरवाही और सामाजिक मजबूरियों के सम्मिलित परिणाम के रूप में सामने आती है। देश के लगभग हर राज्य, हर बड़े शहर और अनेक कस्बों में सरकारी जमीन पर मकान, दुकानें, झुग्गियां, गोदाम, यहां तक कि बड़े-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान और संस्थान खड़े मिल जाते हैं। वर्षों तक यह सब कुछ खुलेआम होता रहता है, लेकिन जिम्मेदार तंत्र या तो आंखें मूंदे रहता है या जानबूझकर चुप्पी साधे रहता है। जब अचानक विकास परियोजनाओं, सड़क चौड़ीकरण, रेलवे, मेट्रो, औद्योगिक गलियारों या स्मार्ट सिटी योजनाओं की जरूरत सामने आती है, तब सरकार की नींद खुलती है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होती है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा संकट उन लोगों पर टूटता है, जो वर्षों से वहां रह रहे होते हैं और जिनका जीवन, आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य उसी जमीन से जुड़ चुका होता है। हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क जैसे संगठनों के आंकड़े इस समस्या की भयावहता को उजागर करते हैं। वर्ष 2017 से 2023 के बीच साढ़े तीन लाख से अधिक मकानों पर बुलडोजर चलाए गए और करीब सोलह लाख लोग बेघर हुए। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आने वाले समय में लगभग 1.7 करोड़ लोग ऐसे दायरे में हैं, जिनके घर विकास परियोजनाओं या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के कारण टूट सकते हैं। इनमें से बड़ी संख्या उन लोगों की है, जिन्होंने अपनी जीवनभर की पूंजी लगाकर घर बनाए, बच्चों को स्कूल में डाला, आसपास रोजगार तलाशा और एक स्थायी जीवन की कल्पना की। जब ये घर टूटते हैं तो केवल दीवारें नहीं गिरतीं, बल्कि पूरे परिवार की सामाजिक और आर्थिक संरचना ढह जाती है।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को प्रायः एक आवश्यक प्रशासनिक कदम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसके मानवीय पक्ष को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बेघर होना केवल सिर से छत छिनने की समस्या नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की संभावनाओं पर सीधा प्रहार है। बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है, महिलाएं असुरक्षा और अस्थिरता के भय में जीने लगती हैं, बुजुर्ग इलाज और सहारे से वंचित हो जाते हैं और पुरुष वर्ग बेरोजगारी तथा मानसिक तनाव से जूझने लगता है। पुनर्वास योजनाएं कागजों पर तो आकर्षक लगती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में वे या तो अधूरी होती हैं या इतनी दूरस्थ जगहों पर लागू की जाती हैं कि वहां रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है। इस पूरी समस्या का एक कड़वा सच यह भी है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एक दिन या एक रात में नहीं हो जाता। यह एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें प्रशासनिक उदासीनता, स्थानीय स्तर पर मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण की बड़ी भूमिका होती है। जब गांवों से पलायन कर गरीब परिवार शहरों की ओर आते हैं, तो उन्हें सबसे पहले सस्ती या खाली जमीन की तलाश होती है। सरकारी जमीन इस दृष्टि से सबसे आसान निशाना बनती है। पहले अस्थायी झोपड़ियां खड़ी होती हैं, फिर धीरे-धीरे पक्के मकान, दुकानें और अन्य निर्माण होने लगते हैं। सरकारी एजेंसियां एवं जिम्मेदार तो तब ही हरकत में आते हैं जब या तो कोई हादसा होता है या फिर विकास कार्यों के दौर में इन्हें हटाने की जरूरत पड़ती है। महज सात साल में 16 लाख लोगों के बेघर होने का आंकड़ा छोटा नहीं है। इनमें भी 58 प्रतिशत से ज्यादा के बेघर होने की वजह अतिक्रमण ही है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों की मिलीभगत से अनदेखी होती है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। बिजली, पानी, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसी सुविधाएं भी किसी न किसी रास्ते से मिल जाती हैं, जिससे यह अतिक्रमण धीरे-धीरे वैधता का भ्रम पैदा करने लगता है।

इस पूरी प्रक्रिया में भू-माफिया की भूमिका भी बेहद खतरनाक है। वे सरकारी जमीनों की पहचान कर गरीबों को वहां बसाते हैं, उनसे पैसे वसूलते हैं और बाद में राजनीतिक संरक्षण के जरिए उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। चुनाव आते ही ये बस्तियां वोट बैंक में बदल जाती हैं। इस राजनीतिक खेल में न तो कानून की प्रतिष्ठा बचती है और न ही आम नागरिकों का भविष्य सुरक्षित रहता है। अतिक्रमण हटाने के बाद होने वाले नुकसान को यदि समग्र रूप से देखा जाए तो यह केवल प्रभावित परिवारों का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे देश का नुकसान है। एक ओर लोग अपने सीमित संसाधनों से घर बनाते हैं, दूसरी ओर सरकार अतिक्रमण हटाने पर भारी खर्च करती है। यदि शुरूआत में ही सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिि त की जाए, समय पर निगरानी हो और अवैध कब्जे को बढ़ने से रोका जाए, तो यह दोहरा नुकसान टाला जा सकता है। दुर्भाग्य से हमारे यहां किसी परियोजना की घोषणा और उसके क्रियान्वयन के बीच लंबा अंतराल रहता है, जिसका फायदा अतिक्रमणकारी उठाते हैं। वर्षों तक जमीन खाली पड़ी रहती है और देखते ही देखते वहां एक पूरी बस्ती खड़ी हो जाती है।

विकास के लिए कई बार राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए विध्वंस की कार्रवाई जरूरी हो जाती है। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए केवल बुलडोजर चलाना पर्याप्त नहीं है। जरूरत एक ऐसी दूरदर्शी नीति की है, जिसमें अतिक्रमण रोकने की व्यवस्था शुरूआत से ही सख्त और प्रभावी हो। सरकारी जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड, नियमित सर्वेक्षण, स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही और दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई इस दिशा में जरूरी कदम हो सकते हैं। साथ ही शहरी गरीबों के लिए सस्ती आवास योजनाओं को वास्तविक जरूरतों के अनुरूप और रोजगार के करीब लागू करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि वे मजबूरी में अवैध कब्जे की ओर न जाएं। राजनीतिक दलों को भी इस मुद्दे पर ईमानदार आत्ममंथन करना होगा। वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध अतिक्रमण को संरक्षण देना अंततः समाज और शासन दोनों के लिए घातक सिद्ध होता है। यदि कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से हो और अवैध कब्जे को किसी भी स्तर पर समर्थन न मिले, तो ऐसी स्थितियां स्वतः कम होंगी। सरकारी भूमि जनता की साझा संपत्ति है और इसका उपयोग योजनाबद्ध विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए होना चाहिए, न कि अव्यवस्था और अवैध कब्जों के लिए। अंततः सवाल यही है कि क्या हम समस्या के मूल कारणों पर गंभीरता से विचार करेंगे या हर बार बुलडोजर के बाद कुछ दिनों की संवेदना दिखाकर आगे बढ़ जाएंगे। यदि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की प्रवृत्ति को समय रहते नहीं रोका गया, तो आने वाले वर्षों में बेघर होने वालों की संख्या और बढ़ेगी, सामाजिक असंतोष गहराएगा और विकास का दावा खोखला साबित होगा। जरूरत इस बात की है कि सरकार, प्रशासन, राजनीतिक दल और समाज मिलकर इस जटिल समस्या का मानवीय, न्यायपूर्ण और दूरगामी समाधान तलाशें, ताकि विकास भी हो और किसी का जीवन उजड़ने से भी बच सके।

समुचित देश एवं विभिन्न प्रांतो में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके लोगों ने न केवल अपने मकान बने कुछ भी खड़े कर लिए हैं कुछ व्यापारिक संस्थान और कुछ संस्थाएं भी संचालित हो रही है जब सरकार की नींद खुलती है तो इन सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके बनाए गए मकान में रहने वाले लोगों को बेघर किया जाता है या उन्हें अन्यत्र बसाने की योजनाएं लागू की जाती है जिससे इन परिवारों और उनके सदस्यों की न केवल बेघर होने की समस्या खड़ी होती है बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी खड़ी होती है इन गतिविधियों को संचालित करने में विभिन्न राजनीतिक दलों को अपना वोट वोट बैंक दिखाई देता है और यह राजनीतिक दल ही ऐसी सरकारी भूमि पर लोगों को बचाने के षड्यंत्र करते हैं फिर उन्हें विस्थापित होने पर आंदोलन खड़े किए जाते हैं और अन्यत्र बसाने की मांग की जाती है यह भारत की एक जटिल समस्या है। क्यों नहीं सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा होने की स्थितियों को सरकार पहले से ही गंभीरता से लेती?

संपादकीय

एक बेतुका आदेश

हाल के दिनों में देश की शीर्ष अदालत से लेकर आम विमर्श तक में आवारा कुत्तों का मामला सुर्खियों में रहा है। इस संवेदनशील, जटिल व विवादास्पद मुद्दे से जुड़े कई तरह के अंतर्विरोध सामने आ रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में बिहार के एक नगर निगम के बेतुके फरमान को लेकर आलोचना की जा रही है। यह निर्णय न केवल बेतुका है बल्कि हास्यास्पद भी है। बिहार के सासाराम के नगर निगम ने शिक्षकों से सड़कों में घूमने वाले आवारा कुत्तों की गिनती करने को कहा है। दरअसल, अदालत के निदेशों के अनुरूप स्थानीय निकायों की इस बाबत जवाबदेही तय की गई है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों व गिरते परीक्षा परिणाम के बावजूद शिक्षकों को गैर-शिक्षण कार्यों में लगाना दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। वहीं दूसरी ओर हर छोटे-बड़े सरकारी अभियान में शिक्षकों की जिम्मेदारी लगाना प्रशासनिक विफलता को भी उजागर करता है। कभी जनगणना, कभी चुनावी ड्यूटी तो कभी आपदा सर्वेक्षण, और अब कुत्तों की गिनती का बेतुका काम शिक्षकों के जिम्मे लगा दिया गया है। दरअसल, बिहार के शिक्षक विषम परिस्थितियों के चलते पहले ही अत्यधिक दबाव में हैं। जिसके कारण वे शैक्षणिक जिम्मेदारियों व गैर-शिक्षण दायित्वों के लगातार बढ़ते बोझ के बीच संतुलन बनाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि हर इस तरह का व्यवधान कक्षा के समय, पाठ योजना और छात्रों की सहभागिता को गहरे तक प्रभावित करता है। निि त रूप से प्राथमिक शिक्षा बच्चे के विकास की नींव रखती है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहद निराशाजनक रहता है। वर्षों से पेश की जा रही एएसईआर रिपोर्टों में कई बार उजागर किया गया है कि बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम देश में सबसे कमजोर रहा है। जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में जब पहले ही बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम निराशाजनक रहता है तो शिक्षकों को एक और गैर-शैक्षणिक कार्य के लिये कक्षाओं से बाहर निकालना, निस्संदेह शिक्षा व्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम ही कहा जाएगा। इससे भी बुरी बात यह है कि यह आदेश कई वास्तविक खतरों से भरा है। आवारा कुत्तों की गिनती करना शिक्षण के कागजी कार्य के समान सहज नहीं है। निि त रूप से अनेक शिक्षक ऐसे होंगे जो कुत्तों से डरते भी होंगे। खासकर शिक्षिकाओं के लिये यह कार्य खासा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ लोग इस गणना प्रक्रिया में वास्तविक खतरे का सामना भी कर सकते हैं। इस बात का संकेत शीर्ष अदालत की टिप्पणी में भी मिलता है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि किसी कुत्ते के मन को पढ़ना या यह अनुमान लगाना असंभव है कि कोई जानवर कब आक्रामक हो जाएगा। निि त रूप से अप्रशिक्षित शिक्षकों को ऐसे कार्य करने के लिए कहना, उनकी सुरक्षा के लिये भी चुनौती होगी।

चिंतन-मनन

प्रेम और दया से ही प्रसन्न होंगे ईश्वर

ईश्वर को खुश करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। मंत्र साधक लाखों बार मंत्र जप करते हैं, भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोग मंदिर जाकर ईश्वर की पूजा करते हैं। धूप-दीप आरती से भगवान को प्रसन्न करने की भी कोशिश करते हैं। इतना करने के बाद भी यह पता नहीं होता कि ईश्वर हमें प्यार करता है या नहीं। प्रेम में सफलता तभी मिलती है जब हमें जिसे प्यार करते हैं वह हमें प्यार करे। इसलिए हमेशा ऐसा काम करें जिससे ईश्वर आपको प्यार करे। यह काम पूजा-पाठ और मंत्र जप से भी आसान है। सभी धर्म एक बात पर सहमत है कि प्रेम और दया यह दो ऐसे साधन है जिसकी बदलौत हम ईश्वर को मजबूर कर सकते हैं कि वह हमें प्यार करे। प्रेम और दया ऐसी चीज है जिसके लिए न तो धन की जरूरत पड़ती है और न ही किसी दूसरे साधनों की। यह अपने आप में पूर्ण और पवित्र है। हम किसी के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं तो बदले में हमें भी प्रेम मिलता है। इसका कारण यह है कि जिसके प्रति हम प्रेम दशार्ते हैं उसके हृदय में मौजूद आत्मा जो ईश्वर का स्वरूप होता है वह प्रसन्न होता है और बदले में हमें अपने प्रेम की अनुभूति कराता है। गीता, कुरान अथवा बाइबल सभी में दया को ईश्वर को पाने का माध्यम बताया गया है। ईश्वर को फूल, फल अथवा मंत्र से ध्यान करने का उद्देश्य भी यही है कि हमारा मन निर्मल हो और मन में दया की भावना बढ़े। जिसने दया करना सीख लिया वह ईश्वर का पुत्र हो जाता है। ईसा मसीह, भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, साईं सभी ने अपने जीवन में दया का अनुपम परिचय दिया। अपने इसी गुण के कारण ईश्वर ने इन्हें प्यार किया और ईश्वरीय शक्ति इनमें समाहित हो गयी।

वेनेजुएला पर ट्रंप की सख्ती- नया वैश्विक टकराव

सनत जैन

वेनेजुएला को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया आक्रामक कार्रवाई ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति एवं सामरिक तनाव को तेज कर दिया है। प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना, समुद्री मार्गों पर निगरानी बढ़ाना और कथित तौर पर रूस से जुड़े जहाज की जप्ती जैसे कदम केवल वेनेजुएला तक सीमित नहीं हैं। इनके दूरगामी अंतरराष्ट्रीय प्रभाव जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। यह घटनाक्रम स्पष्ट संकेत देता है, अमेरिका, लैटिन अमेरिका क्षेत्र में अपने वर्चस्व को आर्थिक एवं सामरिक दृष्टिकोण अपनाते हुए ट्रम्प कब्जा करना चाहते हैं। भले ही इसके लिए रूस और चीन के साथ सीधा टकराव लेने की ट्रंप की सोच है। अमेरिका और वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी और अर्थव्यवस्था पर जो संकट देखने को मिल रहे हैं उसके बाद यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, आने वाले दिनों में अमेरिका अपनी डॉलर मुद्रा तथा वैश्विक व्यापार के वर्चस्वको बनाए रखना चाहता है। उसके लिए ट्रंप अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्रम्प ने टेरिफ के बहाने जो नया खेल खेला था। उसमें वह असफल हो गए है। अमेरिका में मंहगाई और आर्थिक स्थिति पर इसके दुष्परिणाम दिखने लगे है। इससे बचने के लिये अब ट्रम्प ने वेनेजुएला का मुद्दा खड़ा करके अमेरिका में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते है? वेनेजुएला लंबे समय से रूस और चीन का रणनीतिक साझेदार है। रूस ने वहां ऊर्जा, हथियार और सैन्य सहयोग किया है। जबकि चीन ने कर्ज, बुनियादी ढांचा और तेल समझौतों के जरिए अपनी गहरी पैठ बनाई है। रूस और चीन के हथियार भी वेनेजुएला में है। ऐसे में किसी रूसी जहाज की जप्ति केवल एक कानूनी या तकनीकी कार्रवाई के रूप में नहीं देखी जा सकती है। इस कार्रवाई को रूस के प्रभाव को खुली चुनौती के रूप में ही देखा जाएगा। मॉस्को ट्रंप की इस कार्रवाई को अपनी संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्रता पर हमला बताकर कूटनीतिक विरोध, जवाबी प्रतिबंध या समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने जैसे कदम उठा सकता है। हालांकि रूस सीधे सैन्य टकराव से बचता हुआ दिख रहा है। समय आने पर इसकी प्रतिक्रिया बड़े रूप में हो सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दुनिया के देशों में अमेरिका, विरोधी मंचों पर इस मुद्दे का जोर-शोर से उठना तय है। चीन का रुख अपेक्षाकृत संतुलित होते हुए भी व्यापारिक दृष्टिकोण से दीर्घकालिक होगा। बीजिंग आमतौर पर प्रत्यक्ष टकराव से बचते हुए अंतरराष्ट्रीय कानून, बहुपक्षवाद और संप्रभुता के सिद्धांतों की बात करते हुये इस समस्या के समाधान की कोशिश करेगा, ऐसी संभावना देखने को मिलती है। अमेरिका की कार्रवाई को चीन एकतरफा दबाव नीति करार देकर वैश्विक मंच पर अमेरिका को अलग-थलग करने की कोशिश करेगा। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों तथा वैश्विक व्यापार संधिकरण की नीति को लेकर अपना विरोध दर्ज करा सकता है। इसके साथ चीन वेनेजुएला में अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों, गुप्त या अप्रत्यक्ष रूप से वेनेजुएला की मदद रूस के साथ तालमेल कर ट्रंप की दादागिरी को चुनौती देने का काम कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का वैश्विक प्रभाव तेल बाजारों,समुद्री व्यापार, वैश्विक व्यापार और विकासशील देशों की आर्थिक एवं विदेश नीति पर पड़ना तय है। वह देश जो अमेरिकी प्रतिबंधों से असहमत हैं। वह चीन-रूस खेमे की नीतियों की और झुक सकते हैं। अमेरिका समर्थक देश भी ट्रंप की इस तरह की कार्यवाही के खुले समर्थक नहीं है। इसका असर नाटो देश और यूरोपियन संगठन में भी देखने को मिल रहा है। वह ट्रंप की इन नीतियों का कितना समर्थन करेंगे, वर्तमान में कहना मुश्किल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की नीतियां आ रही हैं। उसके बाद दुनिया एक बार फिर आर्थिक एवं सामरिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। विकासशील देश एवं वेनेजुएला जैसे देश

महाशक्तियों की रस्साकशी का मैदान बन रहे हैं। यह स्थिति वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सारी दुनिया के सामने है। अमेरिका की इस कार्रवाई से वैश्विक व्यापार संधि के बाद जो आर्थिक परिवर्तन सारी दुनिया के देशों में देखने को मिला था। निि त रूप से वह तेजी के साथ सिमटने लगेगा। जिसका दुष्प्रभाव आर्थिक मंदी के रूप में जल्द ही सामने आ सकता है। इसको लेकर तरह-तरह की वैश्विक चिंताएं सामने आने लगी हैं।

सुप्रीम कोर्ट का उपद्रवियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नजरिया

मनोज कुमार अग्रवाल

दिल्ली के दंगाइयों को शीर्ष अदालत ने राहत देने से सीधा इंकार कर दिया यह अदालत की अराजकता से निबटने की जीरो टॉलरेंस को नीति का हवाला देता है। उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से साफ इंकार करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने साथ ही उमर खालिद और शरजील इमाम पर इस मामले में एक साल तक जमानत याचिका दाखिल करने पर भी रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की बैंच ने हालांकि इस मामले में अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाय अहमद को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है।

इस मामले में बैंच ने कहा, अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से याचिकाकताओं उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होते हैं। इन याचिकाकताओं के संबंध में वैधानिक कसौटी लागू होती है। कार्यवाही के इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। अदालत ने कहा कि जिन लोगों को जमानत मिली है, उनकी भूमिका सीमित और परिस्थितिजन्य मानी गई है, जबकि उमर खालिद और शरजील इमाम पर दंगों की साजिश रचने, भीड़ को भड़काने और सुनियोजित तरीके से हिंसा को दिशा देने के गंभीर आरोप हैं। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। देखा जाये तो उच्चतम न्यायालय का यह फैसला केवल दो व्यक्तियों की जमानत याचिका का निपटारा नहीं है, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय संकल्प का स्पष्ट संदेश है।

आपको पता रहे उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे लोग कोई साधारण आरोपी नहीं हैं। ये वह चेहरे हैं जिन्होंने विचारधारा की आड़ में सड़कों पर आग लगाने की मानसिकता को खाद पानी दिया। यह साबित हो चुका है कि दिल्ली दंगे अचानक नहीं भड़के थे। उनके पीछे शब्दों के बारूद, भाषणों की चिंगारी और योजनाबद्ध उकसावे की लंबी तैयारी थी। ऐसे मामलों में यदि अदालत नरमी दिखाती, तो यह न केवल न्याय के साथ अन्याय होता बल्कि समाज के लिए एक खतरनाक संकेत भी जाता। अदालत ने सही कहा कि इन दोनों की स्थिति अन्य आरोपियों से अलग है। यह अंतर केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक भी है। दंगा केवल पत्थर फेंकने से नहीं होता, दंगा उस सोच से पैदा होता है जो समाज को बांटने का काम करती है। जब किसी मंच से यह कहा जाए कि सड़कों पर उतर कर व्यवस्था को जाम कर दो, तब वही शब्द बाद में आग वन जाते हैं। जमानत खारिज करने का फैसला उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो खुद को एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी बताकर कानून को ठेंगा दिखाना चाहते हैं। यह फैसला बताता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अराजकता फैलाने की छूट नहीं है। मुकदमे में देरी को लेकर अदालत की टिप्पणी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वर्षों से एक तर्क गढ़ लिया गया था कि अगर मुकदमा लंबा चल रहा है, तो आरोपी को स्वतः राहत मिलनी चाहिए। यह सोच न्याय व्यवस्था को कमजोर करती है। अगर गंभीर साजिशों में केवल समय के आधार पर जमानत मिलने लगे, तो हर देश विरोधी ताकत समय को हथियार बना लेगी। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उपद्रवी और दंगाई मानसिकता वाले लोगों पर पड़ेगा। अब यह भ्रम टूटेगा कि लंबी कानूनी प्रक्रिया अंततः उन्हें बचा लेगी। देखा जाये तो अदालत का सख्त रुख भारत की आतंकवाद के खिलाफ चल रही लढाई को मजबूत करता है।

आपको बता दें यह फैसला उन आम नागरिकों के लिए भी भरोसे का आधार है जिन्होंने दंगों में अपने घर, दुकानें और परिजन खोए। उनके लिए न्याय केवल सजा नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि सिस्टम उनके साथ खड़ा है। कुछ लोग इसे कठोरता कहेंगे, लेकिन सच यह है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कठोर फैसले जरूरी होते हैं। उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत खारिज होना इस बात का प्रमाण है कि भारत की न्यायपालिका आज भी राष्ट्र की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और संविधान की मूल भावना को समझती है। यह फैसला आने वाले समय में न केवल कानूनी मिसाल बनेगा, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी भी होगा जो भारत को भीतर से तोड़ने का सपना देखती हैं। यह निर्णय बताता है कि भारत कमजोर नहीं है, भारत चुप नहीं है और भारत अब दंगों की राजनीति को वर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हालिया कानूनी घटनाक्रमों और न्यायिक टिप्पणियों के अनुसार, खुद को एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी बताकर कानून से ऊपर समझने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्ती बढ़ी है। अदालतों ने स्पष्ट किया है कि एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी होने का लेबल किसी व्यक्ति को आपराधिक जांच या कानूनी प्रक्रिया से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं। पिछले कुछ वर्षों में भीमा कोरेगांव और दिली दंगों जैसे मामलों में कई चर्चित चेहरों की गिरफ्तारियों और अदालतों द्वारा उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज किए जाने को इस दिशा में एक बड़ा झटका माना गया है। जांच एजेंसियों ने इन पर अर्बन नक्सल या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। यूएपीए जैसे कड़े कानूनों के तहत की गई कार्रवाई और अदालतों द्वारा साक्ष्यों के आधार पर दी गई कड़ी टिप्पणियों ने यह संदेश दिया है कि वैचारिक स्वतंत्रता की आड़ में हिंसा या अस्थिरता को बढ़ावा देना स्वीकार्य नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में कहा है कि विरोध का अधिकार मौलिक है, लेकिन यह कानून के शासन के उल्लंघन का अधिकार किसी को नहीं देता है।

जाहिर है कि कानून का शासन बनाए रखने के लिए अदालत का भी सख्त रुख होना अत्यंत महत्वपूर्ण है इसके बिना सामूहिक गुंडई अराजकता फैलाने और भीड़ तंत्र कायम करने के षडयंत्रों पर नकेल डालना संभव नहीं होगा।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

बाजार में अमानक दवाएं कर रहीं मरीजों से खिलवाड़

किसी भी बीमारी के लिए दवा लेने वाले को यदि बाद में यह पता चले कि वह अमानक दवाओं की श्रेणी में है तो सेहत को लेकर मरीज की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। हैरत इसी बात की है कि बाजार में आने के बाद दवाओं के बारे में मुनादी होती है कि ये अमानक हैं इसलिए इनका सेवन नहीं किया जाए। सीधे तौर पर अमानक दवाओं के साथ, इनकी निगरानी करने वाले सिस्टम की नाकामी से मरीजों की जान संकट में आने लगी है। हाल में राजस्थान में दर्द निवारक, खांसी-जुकाम, पेट दर्द और कैल्शियम की दस दवाएं जांच में फेल पाई गईं। केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि समूचे देश में अमानक दवाएं मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं।

अमानक दवाएं आमतौर पर तब मानी जाती है जब उनके रैपर पर अंकित साल्ट की मात्रा तय मापदंडों के अनुसार नहीं होती। मुद्दे की बात यह कि पिछले साल 3100 से अधिक दवाएं अमानक और 245 नकली पाई गईं। कार्रवाई के नाम पर 961 मुकदमे चले, लेकिन ज्यादातर कंपनियां बच निकलीं। जांच में 905 इकाइयों पर कार्रवाई हुई, मगर उत्पादन रोकने या लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्ती नजर नहीं आई। पिछले पांच सालों में अमानक दवाओं से सैकड़ों मौतें हुईं। कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतें तो गहरा जख्म देकर गई हैं। कोई दवा कब मानक श्रेणी से हटा ली जाए इसका भी किसी को अंदाज नहीं होता। खास बात यह है कि कड़े परीक्षण के दौर से गुजरने के बाद ही किसी दवा को बाजार में उतारा जाता है। इसके बावजूद जांच में कोई दवा अमानक पाई जाती है तो मिलीभगत के बिना ऐसा होना आसान नहीं लगता। सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के चलते अमानक दवाएं पहुंचती हैं। बच्चे कफ सिरप से मरते हैं, लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता। जांच की खामियां कई बार दोषियों को बचाने का काम भी करती हैं। कम सजा और भ्रष्टाचार दोनों ही नकली दवा के कारोबारियों के रक्षा कवच बन जाते हैं। दुनिया के दूसरे कई देशों में नकली दवाओं को लेकर सख्त कानून हैं। अमरीका में दस साल की सजा और लाखों का जुर्माना है। यूरोपीय संघ में दवा ट्रैकिंग सिस्टम से नकली दवाएं रोकी जाती हैं, जहां उल्लंघन पर आजीवन कारावास तक सजा है। चीन में तो मौत की सजा तक का प्रावधान है। लेकिन भारत में इस दिशा में काफी काम करना बाकी है।

अमानक दवा से किसी की भी मौत होती है तो इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। इन पर लगाम लगाने के लिए जांच तंत्र की मजबूती के साथ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करना जरूरी है। साथ ही दवा का गुणवत्ता प्रमाणन अनिवार्य करना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ग्लोबल सर्विलांस मॉडल इस दिशा में उपयोगी हो सकता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग से दवाओं की निगरानी होती है। समूचे सिस्टम में सुधार की जरूरत है तभी जाकर लोगों को सेहतमंद रखा जा सकेगा।

वेनेजुएला संकट: अमरीका का वेनेजुएला पर सीधा कब्जा न करने के पीछे इराक का कड़वा अनुभव भी एक कारण है

संसाधनों पर कब्जा, रणनीति और सत्ता की राजनीति

वाप्पला बालचंद्रन
लेखक कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव रहे हैं
(द बिलियन प्रेस)
@patrika.com

वेनेजुएला का 'आर्को मिनेरो डेल ओरिनोको' क्षेत्र चांदी, सोना व दुर्लभ धातुओं से समृद्ध बताया जाता है। इनका रणनीतिक महत्व तेल से कम नहीं है। इन पर नियंत्रण यूएस को यूरोपीय संघ व अन्य देशों पर भू-राजनीतिक बढ़त दिला सकता है।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण का आदेश देने और संसाधन-संपन्न इस लैटिन अमरीकी देश पर हमले के पीछे डॉनल्ड ट्रंप की मंशा को समझाने के लिए कई सिद्धांत सामने आए हैं। क्या यह तेल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की एक छिपी कोशिश है या फिर पश्चिमी गोलार्ध में अमरीका द्वारा अतीत में अपनाए गए सिद्धांत-आधारित हस्तक्षेपवाद यानी 1823 के मुनरो सिद्धांत की ओर वापसी का प्रयास? पहला सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि मादुरो के सत्ता से हटने के बाद अमरीकी बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों को प्रवेश देकर वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। तेल से भी गहरा कारण चांदी और अन्य रणनीतिक धातुओं से जुड़ा माना जा रहा है। वेनेजुएला का 'आर्को मिनेरो डेल ओरिनोको' क्षेत्र, (जहां एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक के अप्रयुक्त संसाधन होने का अनुमान है) चांदी, सोना और दुर्लभ धातुओं से समृद्ध बताया जाता है। ये धातुएं अमरीकी सैन्य प्रणालियों, रक्षा आपूर्ति शृंखलाओं व उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए महत्वपूर्ण हैं।

वैश्विक कमी के दौर में इनका रणनीतिक महत्व तेल से कम नहीं है। इन पर नियंत्रण अमरीका को यूरोपीय संघ व अन्य देशों पर भू-राजनीतिक बढ़त दिला सकता है। दूसरा कारण अमरीका की वह पारंपरिक दलील है, जिसे वह 'लोकतंत्र की बहाली' कहता है। इस बार संदर्भ वेनेजुएला के 2024 के कथित 'धांधली भरे' चुनाव हैं, जिनमें विपक्षी उम्मीदवार एडमुनदो गोंजालेज उरुतिया- जो पूर्व-चुनावी सर्वेक्षणों में आगे थे, को 44.2 प्रतिशत वोट मिले, जबकि मादुरो को 51.2 प्रतिशत वोट मिलने की पुष्टि की गई। यह स्थिति दिसंबर 1989 के माल्टा शिखर सम्मेलन की याद दिलाती है, जब अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश ने सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव से पनामा के मैनुअल नोरेगा का जिक्र करते हुए कहा था कि अमरीका उनके खिलाफ 'मजबूत अभियोग' तैयार कर रहा है और पनामा में 'लोकतंत्र' लाने जा रहा है।

स्पेन के दैनिक 'एल पाइस' के अनुसार तीसरा कारण ट्रंप की नई सुरक्षा नीति है, जिसमें लैटिन अमरीका को अमरीका की कई गंभीर समस्याओं जैसे अवैध प्रवासन, नशीले पदार्थों का निर्यात, अंतरराष्ट्रीय अपराध और बढ़ते चीनी निवेश का स्रोत माना गया है। ट्रंप इसे सद्भावना और दबाव, दोनों के माध्यम से हल करना चाहते हैं। ट्रंप की इस दोहरी रणनीति में अल सल्वाडोर, अर्जेंटीना, इक्वाडोर और बोलीविया की दक्षिणपंथी सरकारों को पुरस्कृत करना, होंडुरास में दक्षिणपंथी उम्मीदवार नासरी असफुरा का समर्थन और नशीले पदार्थों की तस्करी में दोषी ठहराए गए पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को माफी देना शामिल है। इन देशों को बिना सार्वजनिक निविदा के अमरीकी कंपनियों को ठेके दिए जाएंगे। मित्र देशों पर चीनी कंपनियों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से बाहर करने का दबाव होगा, जबकि वेनेजुएला, कोलंबिया और चिली जैसे 'अड़ियल' देशों को सैन्य बल की 'लक्षित तैनाती' से नरम करने की योजना है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार, चौथा कारण अमरीका के भीतर के महंगाई संकट और एपस्टीन फाइलों जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है। 'टाइम' पत्रिका के अनुसार, इस घटनाक्रम ने वहन-क्षमता के संकट, स्वास्थ्य बीमा से वंचित होते लाखों लोगों और एपस्टीन फाइलों से ध्यान हटाकर वेनेजुएला पर केंद्रित कर दिया। 'एशिया टाइम्स' ने दो जनवरी 2026 को इसमें यह जोड़ा कि वित्त वर्ष 2025 के अंत तक अमरीकी कर्ज जीडीपी के 100 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। 2020 में जहां ब्याज भुगतान 345 अरब डॉलर था, वह अब बढ़कर लगभग 970 अरब डॉलर हो चुका है।

हालांकि, इन कारणों में से कुछ जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। अमरीकी आर्थिक और तकनीकी प्रकाशनों के अनुसार, अमरीकी तेल उद्योग को वेनेजुएला की पुरानी ड्रिलिंग और रिफाइनिंग प्रणालियों में निवेश कर वहां के चिपचिपे 'हेवी ऑयल' का दोहन करने में खास रुचि नहीं है, क्योंकि इसे निकालना और ढोना कठिन है। 'एल पाइस' ने चिली के पूर्व मंत्री और राजदूत जॉर्ज हाइन के हवाले से लिखा कि ट्रंप दक्षिण अमरीका को 'वफादार राज्य' की तरह देखना चाहते हैं। हाइन के अनुसार, अमरीकी कंपनियां वहां बड़े प्रोजेक्ट्स को लाभकारी नहीं मानतीं और लैटिन अमरीका में चीन की मौजूदगी अब अपरिवर्तनीय है। उन्होंने कहा कि आधुनिक 'डोनरो सिद्धांत' के तहत बल प्रयोग की धमकियों से दक्षिण अमरीकी देश डरने वाले नहीं हैं। अब तक अमरीका की ओर से वेनेजुएला पर सीधा कब्जा न करने के पीछे इराक का कड़वा अनुभव भी एक कारण है। वर्तमान स्थिति में मादुरो का अपहरण अमरीकी कानून-व्यवस्था की कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो 1989 में तत्कालीन सहायक अटॉर्नी जनरल बिल बार की कानूनी राय पर आधारित है।

पनामा पर आक्रमण और 20 दिसंबर 1989 को पनामा के वास्तविक तानाशाह मैनुअल नोरेगा के अपहरण से छह महीने पहले जारी की गई इस राय में कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर अमरीकी एजेंसियों को घरेलू कानून लागू करने के लिए विदेशों में 'बलपूर्वक अपहरण' से नहीं रोकता। नोरेगा का मुद्दा दिसंबर 1989 के माल्टा शिखर सम्मेलन में भी उठा था, जो सोवियत क्रूज जहाज 'मैक्सिम गोर्की' पर आयोजित हुआ। इस पर गोर्बाचेव की तीखी टिप्पणी थी- 'क्या स्वतंत्र देशों में अमरीकी कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है? संयुक्त राज्य अमरीका खुद फैसला करता है और उसी फैसले को लागू भी करता है।' यह टिप्पणी खुद राष्ट्रपति बुश ने अपनी पुस्तक 'ए वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड' (1998) में दर्ज की है। इसी सम्मेलन में शीत युद्ध के अंत की घोषणा भी हुई थी।

प्रसंगवश

शहरों का मास्टर प्लान बनाना ही काफी नहीं, क्रियान्विति भी जरूरी

भू-उपयोग का एक बार निर्धारण हो जाए तो उसे बार-बार नहीं बदलना चाहिए

किसी भी शहर का मास्टर प्लान उसके विस्तार की संभावनाओं और आवश्यकताओं को देखकर बनाया जाता है। मास्टर प्लान बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य शहरों के बेतरतीब विकास को रोकना है, लेकिन पिछले सालों में राजस्थान में जयपुर समेत बड़े शहरों के लिए जो मास्टर प्लान बनाए गए उनका क्या हश्र हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। अब सरकार ने नवगठित निकायों का मास्टर प्लान बनाने की कवायद शुरू कर दी है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि मास्टर प्लान बनाने का काम सिर्फ कागजी खानापूर्ति बनकर नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए भी कि जो भी मास्टर प्लान बनता है वह अगले दो-तीन दशक की जरूरतों के हिसाब से बनाया जाता है। इसके लिए जरूरी भी है कि भू-उपयोग को इस तरह से सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में उसे किसी भी स्तर पर बदलने की नौबत नहीं आए। जिन निकायों के मास्टर प्लान बनाए जाने हैं वहां भी आबादी भी लगातार बढ़ रही है। भविष्य की जरूरतों का अभी से आकलन करना होगा। साथ ही बेतरतीब विस्तार को रोकना भी होगा।

मास्टर प्लान की मंशा भी तब ही पूरी हो सकेगी जब अभी से शहरों के बेतरतीब विस्तार को रोका जाए। शहरों का बेतरतीब विस्तार आगे चलकर मास्टर प्लान में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। मास्टर प्लान बनाने वाली एजेंसी कोई भी हो, उसमें ध्यान रखने की जरूरत यह है कि जहां सार्वजनिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सामुदायिक भवन, पार्क के लिए जगह चिह्नित की गई है, उसका उपयोग उसी कार्य के लिए हो। हां, और इस पर भी नजर रखने की जरूरत है कि कहीं निजी क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों को इसका लाभ तो नहीं मिल रहा है। कई बार मास्टर प्लान में स्कूल, कॉलेज या अस्पताल के लिए जगह तो आरक्षित की जाती है वहां निजी क्षेत्र के अस्पताल, स्कूल-कॉलेज अपने लिए जमीन आवंटित करवा लेते हैं। आमजन एवं जनप्रतिनिधियों से आपत्तियां एवं सुझाव लेने के साथ मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। पहाड़, जलाशय, हरियाली क्षेत्र को सुरक्षित भी रखना होगा।

- चन्द्रप्रकाश जोशी
cp.joshi@in.patrika.com

बुक इनसाइट

ओल्ड एज की दिलचस्प किताब

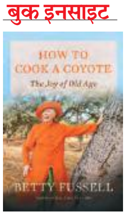

बेट्टी फस्सल की पुस्तक 'हाउ टू कुक ए कोयोट: द जॉय ऑफ ओल्ड एज' दिलचस्प और प्रेरणादायक रचना है। यह वृद्धावस्था को एक उत्सव के रूप में देखने की नई दृष्टि प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में फस्सल ने वृद्धावस्था के न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को भी छुआ है और इसे एक यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया है जो आनंद, संतोष और आत्म-समर्पण की ओर ले जाती है।

लेखिका इस किताब में अपने जीवन के अनुभवों को साझा करती हैं, जिसमें उन्होंने अपनी उम्र बढ़ने को एक चुनौती नहीं, बल्कि एक उपहार के रूप में स्वीकार किया। पुस्तक का शीर्षक एक रूपक है, जो जीवन की कठिनाइयों और जटिलताओं को समझाने के लिए उपयोग किया गया है। साथ ही यह इस बात को भी रेखांकित करता है कि हम जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, हम उनसे सीख सकते हैं। किताब में फस्सल ने अपने जीवन के अनुभवों और पुरानी यादों को साझा किया है, जो पाठकों को वृद्धावस्था को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती हैं।

फैक्ट फ्रंट

कैलिफोर्निया बटेर

कैलिफोर्निया बटेर एक अत्यंत आकर्षक और सुंदर पक्षी है, जो मुख्य रूप से अमरीका के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है।

यह पक्षी कैलिफोर्निया राज्य का आधिकारिक पक्षी भी है, इसलिए इसे वहां विशेष सम्मान प्राप्त है। इसकी सबसे अनोखी पहचान इसके सिर पर आगे की ओर झुकी हुई अल्पविराम जैसी कलगी है। यह कलगी वास्तव में छह पंखों का एक समूह होती है, जो नर में मादा की तुलना में अधिक लंबी और स्पष्ट दिखाई देती है। आकार में यह पक्षी लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा और 150 से 190 ग्राम वजनी होता है, जिसमें नर थोड़े भारी होते हैं। नर कैलिफोर्निया बटेर का रंग-रूप बहुत आकर्षक होता है। इसके चेहरे पर काला रंग और उस पर सफेद धारियां होती हैं, सिर पर भूरा मुकुट, सीना नीला-धूसर और पेट भूरा होता है। वहीं मादाएं अपेक्षाकृत सादे भूरे रंग की होती हैं। यह पक्षी अत्यंत सामाजिक स्वभाव का होता है और छोटे-छोटे झुंडों में रहता है।

पेयजल इंदौर में होने वाला हादसा एक सबक है

जलापूर्ति संस्थाओं और आमजन को सचेत रहना चाहिए

डॉ. प्रभात ओझा
वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार
@patrika.com

पिछले दिनों इंदौर शहर में दूषित पानी पीने से मौतें और लोगों के बीमार होने की खबर चिंताजनक है। यह तब हुआ है, जब मध्य प्रदेश का यह शहर स्वच्छता सर्वेक्षण के मुताबिक लगातार आठ वर्षों से देश में नंबर 1 पर बना हुआ है। देश के सबसे स्वच्छ शहर के माथे पर यह कलंक उसकी ही असावधानी से लगा है। सच यह है कि स्वच्छ पेयजल स्वच्छता का पहला मानक हुआ करता है। पानी जीवन के हर पड़ाव पर आवश्यक है। इसीलिए 'जल है तो जीवन है' का सूत्र वाक्य आमतौर पर प्रचलित है। वर्तमान केंद्र सरकार ने इसे ही ध्येय बनाकर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन कर देश में 'हर घर नल जल' मुहिम शुरू की। सरकार की संकल्पनिष्ठ मंशा का अंदाज इससे भी लगता है कि केंद्र में अलग से जलशक्ति मंत्रालय गठित किया गया है। कहा गया है कि वर्ष 2019 में जहां देश के 16.71 प्रतिशत ग्रामीण घरों में पानी के कनेक्शन थे, वह पिछले वर्ष के अक्टूबर तक 81 फीसदी से ज्यादा हो गए थे। इसके 93 प्रतिशत तक होने के भी दावे हैं।

स्वाभाविक है कि जलापूर्ति योजनाओं के तहत हर घर में पेयजल पहुंचाने का उद्देश्य लोगों को निरोग रखना ही है। इन योजनाओं के पानी से सबसे बड़ा लाभ पेयजल को आर्सेनिक और फ्लोराइड से मुक्त रखना है। दुखद है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके अनुसार भारत के एक करोड़ 96 लाख घरों में आर्सेनिक और फ्लोराइड की अधिकता वाला पानी मिलता है। पेयजल में यह अतिरिक्त आर्सेनिक सिर्फ पश्चिम बंगाल में करीब डेढ़ करोड़ लोगों को प्रभावित कर रहा है। फ्लोराइड की अधिकता देश के 19 राज्यों में करोड़ों लोगों को बीमार बनाती है।

कुछ दशकों में बोरिंग के अत्यधिक उपयोग से भूजल में कमी हो रही है। अनुमान के अनुसार देश में करीब 3 करोड़ भूजल आपूर्ति केंद्र हैं। इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की 85 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 48 प्रतिशत की आपूर्ति होती है। कुछ हद तक निश्चिंत हुआ जा सकता है कि 'हर घर नल जल' जैसी योजनाएं इस ओर से सचेत है। फिर 'स्वजल' जैसे कार्यक्रम में पेयजल की जांच के कई स्तर तय किए गए हैं। प्रश्न यह है कि देश की स्थानीय इकाइयां इस दिशा में कितना सावधान रहती हैं। सरकारें साधन ही उपलब्ध करा सकती हैं। आज स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता में कमी के कारण दुनियाभर में 260 अरब डॉलर का नुकसान होता है। भारत में यह नुकसान 42 अरब रुपए का आंका गया है। स्वाभाविक रूप से सरकारों के साथ- साथ स्थानीय इकाइयों और आम लोगों को भी स्वास्थ्य के मूल कारण पानी पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा।

विस्तार से पढ़ने के लिए **क्यूआर कोड स्कैन करें**

अर्जेंटीना में प्रकृति की कारीगरी बेसाल्ट स्तंभ

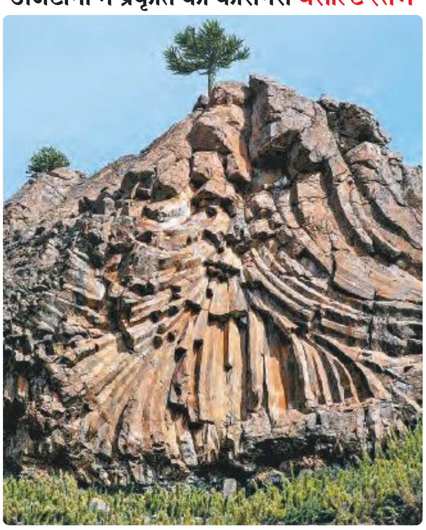

अर्जेंटीना *के न्युक्वेन प्रांत के पिनो हाचाडो क्षेत्र में स्थित बेसाल्ट स्तंभ प्रकृति की अद्‌भुत शिल्पकला का उदाहरण हैं। यह दृश्य ऐसे प्रतीत होता है मानो कुशल वास्तुकार ने ज्यामितीय नियमों के अनुसार पत्थरों को सजाया हो, जबकि वास्तविकता में यह संरचना लाखों वर्ष पहले हुए ज्वालामुखीय विस्फोटों की देन है।*

दृष्टिकोण छतें बनाई जा सकतीं जीवनदायी केंद्र

सोलर रूफटॉप और अर्बन फार्मिंग है आज की जरूरत

प्रो. हेमंत पारीक
महासचिव, आइएसएलएएस
@patrika.com

भारत तीव्र शहरीकरण के दौर से गुजर रहा है। शहरों की बढ़ती आबादी, सीमित भूमि, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं, खाद्य सुरक्षा की चिंता और पर्यावरणीय असंतुलन ने शहरी जीवन को जटिल बना दिया है। ऐसे समय में सतत विकास की अवधारणा केवल एक नीतिगत शब्द न रहकर व्यावहारिक समाधान की मांग करती है। इसी संदर्भ में अर्बन फार्मिंग (शहरी कृषि) और सोलर रूफटॉप प्रणाली का संयोजन भारत के शहरों के लिए अत्यंत प्रभावी और व्यावहारिक मॉडल के रूप में उभर रहा है।

शहरी कृषि का अर्थ है शहरों के भीतर उपलब्ध सीमित स्थानों- जैसे छत, बालकनी, आंगन, खाली भूखंड और सामुदायिक क्षेत्रों- में खाद्य फसलों, सब्जियों, फलों और औषधीय पौधों की खेती। यह न केवल ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराती है, बल्कि शहरों को अधिक आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। वहीं दूसरी ओर, सोलर रूफटॉप प्रणाली स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बनकर उभरी है। आज भारत के लाखों घरों में छतों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे बिजली उत्पादन तो हो रहा है, परंतु अधिकांश मामलों में छत का बड़ा भाग अनुपयोगी रह जाता है। यहीं पर शहरी कृषि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सोलर पैनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि उनके नीचे और आसपास पर्याप्त स्थान तथा आंशिक छाया बनी रहती है। यह छायादार क्षेत्र कई प्रकार की सब्जियों और पौधों के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। पालक, धनिया, मेथी, पुदीना, सलाद पत्तियां, अदरक, हल्दी तथा अनेक औषधीय पौधे ऐसी परिस्थितियों में अच्छी तरह पनपते हैं। इस प्रकार सोलर पैनल और शहरी खेती एक-दूसरे के पूरक बन जाते हैं और छत का अधिकतम, बहुउद्देशीय उपयोग संभव हो पाता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी मिशन और सरकारी नीतियों में सोलर रूफटॉप और शहरी कृषि को एकीकृत दृष्टिकोण से अपनाया जाए। प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और जन-जागरूकता के माध्यम से इसे जन-आंदोलन बनाया जा सकता है। अर्बन फार्मिंग और सोलर रूफटॉप का संयुक्त मॉडल केवल संसाधनों के बेहतर उपयोग का समाधान नहीं है, बल्कि यह भारत के शहरों को आत्मनिर्भर, स्वस्थ और सतत बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यदि इस दिशा में संगठित प्रयास किए जाएं, तो आने वाले समय में शहरी छतें केवल कंक्रीट की सतह नहीं रहेंगी, बल्कि ऊर्जा और हरियाली से भरपूर जीवनदायी केंद्र बन जाएंगी।

विस्तार से पढ़ने के लिए **क्यूआर कोड स्कैन करें**

आपकी बात

सड़क सुरक्षा शिक्षा अनिवार्य हो

बहुआयामी और व्यावहारिक कदम उठाना जरूरी है, ताकि जागरूकता केवल जानकारी तक सीमित न रहे बल्कि व्यवहार में भी उतरे। स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को अनिवार्य किया जाना चाहिए। **- डॉ. मुकेश भटनागर,** भिलाई

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें https://shorturl.at/SwiI0

समसामयिक विषयों पर पाठकों के विचार आमंत्रित हैं। चुनिंदा विचार प्रकाशित किए जाएंगे।
ईमेल करें: edit@epatrika.com

राजनीति बनाम खेल मुस्तफिजुर रहमान मामले में यह संदेश कि भारत मानवाधिकार उल्लंघन व धार्मिक हिंसा को नजरअंदाज नहीं करेगा

खेल भावना का अर्थ 'भावनाओं से खेलना' नहीं होना चाहिए

डॉ. सुभाष कुमार
प्रोफेसर, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय वडोदरा
@patrika.com

खेल को अक्सर 'राजनीति से परे' होना चाहिए, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ता है, उसका असर खेलों पर भी पड़ता है। हाल में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से रिलीज करने का बीसीसीआइ का निर्णय इसी जटिल रिश्ते का उदाहरण है। आइपीएल 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा, किंतु बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हालिया हमलों और भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव को देखते हुए बीसीसीआइ ने फ्रेंचाइजी को निर्देश दिया कि वे उन्हें टीम से रिलीज करें। इस पर बांग्लादेश की सरकार ने अपनी टीम के टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत न आने के फैसले और बांग्लादेश में आइपीएल के प्रसारण पर रोक लगाने की धमकी दे दी। मुस्तफिजुर रहमान के आइपीएल अनुबंध रद्द करने के निर्णय को खेल में राजनीतिक हस्तक्षेप बताकर इसकी आलोचना करने से पहले उन प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरणों को देखना समीचीन है जब खेलों में राजनीतिक हस्तक्षेप को अनिवार्य समझा गया था।

ओलंपिक बहिष्कार

1980 मॉस्को ओलंपिक: अमरीका और उसके सहयोगी देशों ने सोवियत संघ के अफगानिस्तान आक्रमण के विरोध में भाग नहीं लिया।

1984 लॉस एंजेलिस ओलंपिक: सोवियत संघ और पूर्वी ब्लॉक देशों ने अमरीका के खिलाफ बहिष्कार किया।

इन घटनाओं ने दिखाया कि ओलंपिक जैसे वैश्विक खेल का आयोजन भी राजनीतिक मुद्दों से अछूते नहीं हैं।

क्रिकेट और अपार्थेड

- **दक्षिण** अफ्रीका को नस्लभेदी अपार्थेड नीति के कारण दशकों तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर रखा गया।
- **यह** खेल जगत में सबसे बड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप था, जिसने खेल को सामाजिक न्याय का माध्यम बना दिया।

फुटबॉल और विश्व राजनीति

- फीफा विश्व कप कई बार राजनीतिक विवादों का केंद्र रहा है।
- 1978 का अर्जेंटीना विश्व कप सैन्य तानाशाही के बीच आयोजित हुआ, जिसे राजनीतिक प्रचार का साधन माना गया।

जो लोग खेल को राजनीति से अलग करने की बात करते हैं वे भूल जाते हैं कि चाहे 1971 का अमरीका और चीन के बीच 'पिंग-पोंग डिप्लोमेसी' हो (जिसके अंतर्गत टेबल टेनिस मैचों ने दोनों देशों के संबंध सुधारने में अहम भूमिका निभाई) या भारत में, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में क्रिकेट की लोकप्रियता को देखते हुए दो देशों के बीच के संबंध को बेहतर करने के लिए 'क्रिकेट डिप्लोमेसी' की बात होती रही है। राजनीतिक हस्तक्षेप हमेशा नकारात्मक नहीं होता बल्कि कभी-कभी यह शांति और सहयोग का मार्ग भी खोलता है, लेकिन इतना तो तय है कि खेलों में राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहा है। खेल समाज से अलग नहीं है, जब समाज प्रभावित होता है, तो खेल भी प्रभावित होता है। मुस्तफिजुर के आइपीएल फ्रेंचाइजी को रद्द करने के कई मायने हैं और यह केवल एक खेल संबंधी निर्णय नहीं था, बल्कि भारतीय दृष्टिकोण से यह एक बहुआयामी निर्णय था। रहमान को रिलीज करके भारत ने यह संदेश भी दिया है कि वह मानवाधिकार उल्लंघन व धार्मिक हिंसा को नजरअंदाज नहीं करेगा। रहमान मामले ने यह दिखाया कि खेल व राजनीति को पूरी तरह अलग रखना सरल नहीं है।

बीसीसीआइ का निर्णय इस बात का प्रमाण है कि जब समाज और राष्ट्रहित दांव पर हों, तो खेल में राजनीतिक हस्तक्षेप न केवल उचित बल्कि आवश्यक भी हो जाता है। खेल भावना के सम्मान की प्रक्रिया में सम्पूर्ण राष्ट्र की भावनाओं और सम्मान के साथ खेल नहीं होना चाहिए।

संपादकीय

महिला अपराधों पर समाज का दोहरा रवैया और चुनिंदा आक्रोश

हाल के दिनों में वर्ष भर की चर्चित राष्ट्रीय घटनाओं, दुर्घटनाओं की यादों की पुनरावृत्ति के क्रम में एक पति की हत्या करके ड्रम में डाल देने और हनीमून मनाने के क्रम में हत्या की बहुप्रचारित दो घटनाओं की खूब चर्चा की गई। ये भी कहा गया कि इन दोनों मामलों ने समाज में वैवाहिक रिश्तों की सुरक्षा, भरोसे और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। निश्चित रूप से ये दोनों घटनाएं भयावह थीं।इस अपराध में शामिल महिलाओं ने न सिर्फ दो निर्दोष लोगों की हत्या की, उनके माता-पिता और परिवार को जीवन भर का दर्द दिया, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक मान्यताओं को भी तार-तार किया। महत्त्वपूर्ण यह भी है कि जब उन्हें उक्त वैवाहिक बंधनों को निभाना नहीं था, तो विवाह नहीं करना चाहिए था। हालांकि जीवन और परिस्थितियों के अपने-अपने संदर्भ होते हैं और घटनाएं भी उसी मुताबिक संचालित होती रहती हैं। उसमें दूसरों की राय के लिए बहुत जगह नहीं होती। मगर इन बातों को आज के बिगड़ती सामाजिक बनावट, खराब माहौल, स्वतंत्रता की परिभाषा, मोबाइल और सोशल मीडिया के भयानक तरीके से जीवन में घुसपैठ, सांस्कृतिक क्षरण आदि के रूप में देखा जा सकता है। इस विषय पर बहुत सारी बातें हुई हैं। टीवी चैनलों ने बहस और चर्चा भी परोसी। महीनों तक हर तरफ घरों, मोहल्लों, चौक-चौराहों यही मुद्दा छाया रहा। पूरी महिला बिरादरी इसके लपेटे में आई और गाहे-बगाहे उन्हें तीखी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। जो हुआ, वह निश्चित तौर पर बुरा था और पूरे समाज ने इसके विरोध में जिस तरीके से एकजुटता दिखाई, वह गौरतलब थी।इसके समांतर कुछ महत्त्वपूर्ण सवाल, जो इन शोरगुल के बीच दबे रह गए या किसी ने उठाया भी तो लोगों को गौरतलब ही नहीं लगा, वह यह है कि क्या ये दोनों मामले 'वैवाहिक हत्याओं' के संदर्भ में इकलौते हैं? क्या कभी लड़कियों की दहेज, अवैध संबंध, झूठे सम्मान के नाम पर हत्या अन्य मुद्दों को लेकर ऐसी ही या इससे भी विद्रूप नृशंस हत्याएं नहीं की गई हैं?सामूहिक बलात्कार, तेजाबी हमले से मारी जाती, अपंग होती लड़कियों के मामलों पर कभी इतना शोर क्यों नहीं हुआ? कम या ज्यादा उम्र में बलात्कार का दंश भोगती, प्रताड़ित होती, मौत की ओर धकेली जाती अनगिनत महिलाओं के सच को जानकर भी समाज ने अब तक क्या किया है? हमारे इर्द-गिर्द हर रोज होती ऐसी घटनाएं और साल दर साल महिला उत्पीड़न के बढ़ते आंकड़ों का सच आखिर क्या है? प्रश्न यह भी कि चंद अपवादों की बात छोड दें, तो क्या दूसरा पक्ष भी परंपराओं, कट्टरता और आपराधिक प्रवृत्ति के त्रास तले उतना ही दंड भोग रहा है?ऐसे तमाम आपराधिक कृत्य हर रोज, हर तरफ होते हैं, तो फिर कुछ घटनाओं की तरह सामाजिक एकजुटता इन पर क्यों नहीं दिखाई जाती? संभव है, वैसी ही एकजुटता महिला उत्पीड़न के बढ़ते आंकड़ों की दर को कुछ कम कर देती। यहां आशय लैंगिक आधार पर अपराधों को कम या ज्यादा करके आंकना कतई नहीं है, क्योंकि अपराधी चाहे महिला हो या पुरुष, उसकी प्रवृत्ति सिर्फ अपराध करने की होती है। पीड़ित भी सिर्फ पीड़ित होता है। वर्ग या रसूख के आधार पर अन्याय तथा अनाचार का बंटवारा करना और न्याय का पलड़ा उसके अनुसार मोड़ना अपने आप में एक बड़ी खामी है।

विकसित भारत के सपने को हकीकत बनाने की आधारशिला

अतः इन दोनों पक्षों को सरकारी प्रयासों में भी प्रमुखता देनी होगी, लेकिन उसके लिए समाज तथा शिक्षा संस्थानों का योगदान सर्वोपरि होगा।भारत में अधिकांश अध्यापक बहु-जातीय और बहु-पंथिक कक्षाओं में पढ़ाते हैं तथा वे स्वयं भी ऐसी ही कक्षाओं में पढ़कर आए होते हैं। विविधता को साझा करने का ऐसा संजोग शायद ही कहीं और इतनी प्रचुरता से मिलता होगा

विकसित भारत की लक्ष्य-साधना निश्चित रूप से देश के हर नागरिक को प्रोत्साहित करेगी। आज के वैश्विक अस्थिरता के माहौल में ऐसा कौन होगा, जो भारत को विकसित होते न देखना चाहे! भारत के संविधान निर्माताओं ने उस समय चौदह साल तक के हर बच्चे को अगले दस वर्षों में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था। वे सभी देश की सामर्थ्य की वास्तविकता से अवगत थे, मगर यह भी जानते थे कि बड़े लक्ष्य जो प्रेरणा देते हैं, वे बहुत दूर तक ले जाते हैं।समय ने इसे सिद्ध किया है, हालांकि लक्ष्य अभी भी कहीं न कहीं अपनी दूरी दर्शाता है। लक्ष्य-साधना की सफलता के लिए यह मानकर ही चलना होगा कि इसके लिए सार्वभौमिक स्तर पर देश के प्रत्येक नागरिक का योगदान आवश्यक होगा। जो कमी दिखेगी, उस पर भी सामाजिक सद्भाव और पंथिक समरसता को और अधिक सशक्त बनाकर सफलता के द्वार खोले जा सकते हैं। अतः इन दोनों पक्षों को सरकारी प्रयासों में भी प्रमुखता देनी होगी, लेकिन उसके लिए समाज तथा शिक्षा संस्थानों का योगदान सर्वोपरि होगा।भारत में अधिकांश अध्यापक बहु-जातीय और बहु-पंथिक कक्षाओं में पढ़ाते हैं तथा वे स्वयं भी ऐसी ही कक्षाओं में पढ़कर आए होते हैं। विविधता को साझा करने का ऐसा संजोग शायद ही कहीं और इतनी प्रचुरता से मिलता होगा! भारत की प्राचीन ज्ञानार्जन परंपरा की गहराई, सूक्ष्मता और वैश्विकता में निहित 'सर्वभूत हिते रतः' की भावना का सम्मान भी सर्वत्र होता है। जहां पूर्वाग्रह बौद्धिकता को ढ़क लेते हैं, वहां ऐसा नहीं हो पाता है।

विश्व में हर प्रकार की विविधता के सम्मान की जो व्यावहारिक अवधारणा भारत में पनपी है, और जो आज भी जीवंत है, वैसी अन्य कहीं नहीं मिलेगी। स्वतंत्रता आंदोलन में देश ने अच्छी तरह समझ लिया था कि भारतीयों को बांटने, और अंततः देश का विभाजन करने में ब्रिटिश शासन ने कैसे-कैसे हथकंडे अपनाए थे। सबसे सशक्त साधन तो उनको 1835 में थामस बैबिंगटन मैकाले ने प्रदान किया था। उन्होंने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को बनाए रखने के लिए जो योजन बनाई, उसका लक्ष्य उनके लिए पूरी तरह स्पष्ट थाः 'हमें ऐसे लोग तैयार करने हैं, जो खून और रंग में भारतीय होंगे, मगर रुचि, राय, नैतिकता और बौद्धिकता में अंग्रेज होंगे।'

मैकाले की भारत, उसकी संस्कृति और वैश्विक ज्ञान भंडार में उसके योगदान के संबंध में जो राय थी, उसे याद करने से यह समझ में आ जाएगा कि भारतीयों को सूरत से भले ही न सही, दिल से अंग्रेज बना देने में अपनी सफलता के प्रति वह इतना आश्वस्त क्यों था! मैकाले ने भारत की सुव्यवस्थित ज्ञानार्जन प्रणाली और नए ज्ञान की जनहित में उपयोगिता के लिए शोध के प्रति समर्पण की परंपरा को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंपरागत स्कूलों और संस्थाओं को उसने यह कहकर नकार दिया कि उन पर सरकार को खर्च करना पड़ेगा, जबकि अंग्रेजी पढ़ाने वाले स्कूलों में लोग अच्छी-खासी फीस देकर आने को तैयार रहते हैं। ऐसा आज भी देश में हो रहा है, और यह लगातार बढ़ रहा है।

स्वतंत्रता के बाद तीन-चार दशकों में न जाने कितने बच्चों ने स्कूल कुछ वर्ष बाद केवल अंग्रेजी सीखने में असफल होने के कारण छोड़ दिए थे। धीरे-धीरे वह स्थिति बदली है, लेकिन आज भी अधिकांश सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है। कहा नहीं जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में मातृ भाषा पर दिए गए जोर के बावजूद स्थानीय स्तर पर भी नौकरियों में अंग्रेजी का प्रभाव भाषागत भेदभाव का कारण नहीं बनेगा! वैसे लोग अब घरों में रखे जाने वाले सहायक एवं सहायिकाओं से भी अपेक्षा करते हैं कि उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान हो, वे 'माल' से सामान मंगा सकें, उसमें मियाद की तारीख पढ़ सके! मैकाले की दूरदृष्टि और भविष्य के आकलन की क्षमता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है, क्योंकि वह भारतीयों को भारत से अलग करने में कितना सफल रहा, इसे हम आज भी देख रहे हैं। हम आजादी के बाद भी मैकाले के बिछाए जाल से नहीं निकाल पाए, तो इसमें दोष हमारा ही है!

वैसे भी अब समय मैकाले की आलोचना का नहीं, बल्कि भारतीयों को भारत से पुनः पूरी तरह जोड़ने का है। संभवतः ऐसे ही विचार सर्वोच्च स्तर पर नीति निर्धारकों के भी रहे होंगे, तभी तो देश को मैकाले के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त करने का आह्वान किया गया है। यह भी स्वीकारोक्ति है कि 1835 में मैकाले ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें जमाने के लिए जिस शिक्षा व्यवस्था को तत्कालीन स्वदेशी प्रणाली को नष्ट कर लागू किया, उसके प्रभाव से भारत आज भी मुक्त नहीं हो पाया है।

यह भी एक तथ्य है कि अनगिनत अवसरों पर संसद में चर्चाएं हुई थीं, आश्वासन दिए गए और प्रयास भी हुए, लेकिन बात बनी नहीं! इसका कारण अज्ञात नहीं है, मगर वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में उसका पुनः विश्लेषण आवश्यक हो गया है। इसके लिए फिर से अपनी जड़ों से जुड़ने की जरूरत को स्वीकार करना होगा। हावर्ड विश्वविद्यालय की ख्याति विश्वव्यापी है और उसे ज्ञान के प्रसार, प्रचार एवं संवर्धन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। यहां के दो पुराने छात्र हेनरी डेविड थोरो और राल्फ वाल्डो एमरसन अपने बौद्धिक ज्ञान और उसके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। एक बार दोनों अपनी पुरानी मातृ संस्था को लेकर चर्चा कर रहे थे।

एमरसन ने कहा कि अब इस विश्वविद्यालय में ज्ञान की सभी शाखाएं स्थापित हो चुकी है और प्रगति कर रहीं हैं। थोरो ने उत्तर दिया- शाखाओं की बात अति सुंदर है एवं उत्साहजनक है, लेकिन जड़े कैसी हैं, यह जानते रहना ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र की बौद्धिक संरचना को गति और मजबूती देने के लिए सबसे पहले उसकी नींव के टिकाऊ आधार-स्तंभों को जानना और समझना आवश्यक है, ताकि इनके ऊपर आगे की संरचना आधुनिक वैश्विक संदर्भ में निर्मित की जा सके। भारतीय दर्शन में शिक्षा प्रणाली में विद्या, ज्ञान, मेधा, बुद्धि का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है, जो नैतिक कसौटी पर भी पूरी तरह खरे उतरें।

भविष्य के भारत की शिक्षा नीतियां केवल ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण न करें, जो जीवन में सिर्फ धनार्जन और सुख सुविधाओं के संग्रहण को ही शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य मान ले या जिन्हें जीवन के उच्चतम लक्ष्यों और उससे प्राप्त होने वाले 'सत्, चित, आनंद' के संबंध में जानकारी न हो, और न ही इसे लेकर कभी कोई प्रेरणा मिली हो। बेहतर शिक्षा से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। शिक्षा में मानवीय मूल्यों का होना भी जरूरी है, तभी सामाजिक चेतना का निर्माण होता है।

प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति और संस्कारों की परंपरा व्यक्ति को उसकी आत्मा की उपस्थिति, गरिमा और उसकी विश्व व्यापकता का भान कराती है। यह पद्धति संस्कारों को जीवन-प्रगति के लिए एक आवश्यक तत्त्व मानती है। इसी से व्यक्ति में सत्य और अन्याय की समझ बढ़ती है तथा इसकी खोज में जीवन लगाने में आनंद का आभास होता है।

'समय ' और अन्य के बारे में सोचना

डॉ. विजय गर्ग

समय की कभी शुरुआत नहीं होती; समय का कभी अंत नहीं होता। फिर भी मानव मन समय को मापने में विश्वास रखता है। एक समय ऐसा था जब माप शुरू हुआ, और इसे मापने के लिए विभिन्न इकाइयां बनाई गईं। यह सब मानव निर्मित है। विभिन्न समुदायों ने समय का अलग-अलग माप विकसित किया है। यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न रहा है तथा तर्क के विभिन्न आधारों का अनुसरण करता रहा है। अधिकांशतः वे क्षेत्रीय विश्वासों या धारणाओं को प्रतिबिंबित करते हैं, जो विश्व की समझ में सहायक होते हैं।

अक्सर, समय का मापन सूर्य, चंद्रमा या किसी अन्य ग्रह की गति से जुड़ा हुआ है। यह सब मानव निर्मित है। इनमें से कोई भी सर्वोच्च अस्तित्व द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुष्य अपने व्यवहार और कार्यों को मापने और समझने के लिए ऐसा करता है।

इस विचारधारा के लिए तात्कालिक प्रोत्साहन तथाकथित 'नववर्ष' की चर्चा है। 2025 समाप्त हो गया है, और 2019 शुरू हो गया है। इसे, सर्वोत्तम रूप से, एक कैलेंडर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। वास्तव में, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ और कुछ भी शुरू नहीं हुआ।

एक लोकप्रिय धारणा है कि तथाकथित कैलेंडर, जिसका 2025/2026 भी हिस्सा होगा, पोप ग्रेगरी द्वारा बनाया गया था। उन्होंने समय की गणना इस प्रकार की कि यीशु मसीह के जन्म की तारीख तय हो गई। इसलिए, मसीह के जन्म से पहले के समय को Kristus Bago कहा गया था। माना जाता है कि मसीह का जन्म 0 ईसा पूर्व में हुआ था, और वहां से ई. कहा जाता है कि (एनो डोमिनी) युग शुरू हो गया है। इसलिए, अब हम 2025 के अंत और 2036 की शुरुआत के साथ जी रहे हैं।एक अन्य गणना से पता चलता है कि संबंधित तिथि में लगभग तीन वर्ष की त्रुटि है, तथा यीशु मसीह का जन्म 0 ईस्वी में नहीं, बल्कि 3 ईस्वी में हुआ था। यह गणना, जैसा कि अपेक्षित था, कुछ लोगों द्वारा प्रश्नांकित की गई है तथा अन्य लोगों द्वारा इसका बचाव किया गया है। यह इस बहस को सुलझाने का स्थान नहीं हो सकता। हालाँकि, बहस ही मुख्य बात नहीं है; मुख्य बात वह कैलेंडर है जिसका दुनिया का अधिकांश हिस्सा पालन करता है।

दुनिया के कुछ हिस्से अलग-अलग कैलेंडर का पालन करते हैं। भारत के कई भागों में विक्रम संवत कैलेंडर का पालन किया जाता है, तथा ईसा मसीह के बीच 50 वर्ष से अधिक का अंतर होता है। नामकरण और विक्रम संवत संदर्भ। यह एक और बहस है जिसका समाधान इस पाठ में नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, इस्लाम के अनुयायियों का अपना कैलेंडर है, जिसका संबंध पैगंबर मुहम्मद से है।दुनिया भर में कई कैलेंडरों की पहचान की जा सकती है। आम तौर पर, जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित आधिकारिक भारतीय कैलेंडर को कई लोग शक संवत मानते हैं।जाहिर है, इस पर बहस चल रही है और इसका समाधान करने के लिए कोई एकल ढांचा नहीं है। कानून ने आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिया है।इस विचारधारा को विस्तार के अन्य भागों में भी देखा जा सकता है और यदि विरोधाभासों पर प्रकाश नहीं डाला जाता, तो कम से कम ऐसे मापन की सीमाओं पर प्रकाश डालने के लिए इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए, सूर्य को सुबह उदय होना चाहिए और शाम को अस्त होना चाहिए। सच तो यह है कि सूर्य कभी उगता नहीं और सूर्यास्त भी नहीं होता। यह पृथ्वी है जो अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, और सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति सूर्योदय और सूर्यास्त का भ्रम पैदा करती है।

यह इस बात का एक और उदाहरण है कि किस प्रकार मानव मन की सीमा ने स्वयं को एक तथाकथित सार्वभौमिक नियम में बदल दिया है, जिसका हर कोई सहज रूप से या अन्यथा पालन करता है। उपरोक्त उदाहरण एक बहुत ही बुनियादी प्रश्न उठाते हैं: क्या समय को मापने, कैलेंडरों का वर्गीकरण करने, मौसमों को समझने आदि में कोई सुधार किया जा सकता है।

यह प्रश्न पूछा गया है, और समाधान में स्पष्ट रूप से समय, बहस आदि लगेगा। हालाँकि, यह एहसास महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव कथा का अधिकांश हिस्सा समय के आसपास होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से, होमो सेपियंस का औसत जीवनकाल 100 वर्ष से भी कम है। तदनुसार, एक 10वीं सदी का जीवन स्तर के लिए एक मानक बन गया है। हालांकि, यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि कई कोशिकाओं का जीवनकाल एक शताब्दी से भी अधिक होता है। इन कोशिकाओं में कुछ महत्वपूर्ण क्षमताएं भी होती हैं और वे प्रजनन करने में सक्षम होती हैं। यदि उनके बीच कोई भाषा है, तो उसे मनुष्यों द्वारा अभी तक समझा नहीं जा सका है। लेकिन मुद्दा यह नहीं है; मुद्दा यह है कि मनुष्य इस ग्रह पर हावी हैं, और उनकी सोच का तरीका माप निर्धारित करता है। साइबेरिया के बर्फीले रेगिस्तान में कोशिकाओं के एक निश्चित प्रकार के जीवन के चित्रण मौजूद हैं, जो वस्तुतः हजारों वर्षों से अस्तित्व में हैं।

चाहे कुछ भी हो, एक वर्ष का अंत और दूसरे वर्ष की शुरुआत उन चीजों पर विचार करने के लिए उपयुक्त समय है जिनका उपयोग मनुष्य मापने और रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। यह सब उनके आचरण और व्यवहार को प्रभावित करता है।

इसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। यहां उद्देश्य दोष ढूंढना या खामियों को उजागर करना नहीं है। यहां उद्देश्य कुछ बुनियादी मुद्दों पर चिंतन और विचार करना है जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं, और वास्तव में समय का तथाकथित माप भी। हो सकता है कि जैसे-जैसे मानव प्रजाति का विकास होगा, इनमें से कुछ चिंताओं को सुधारा जाएगा और उनका प्रबंधन किया जाएगा

यह बहस किस प्रकार आगे बढ़ेगी, यदि होगी भी तो केवल समय ही बता सकता है।

डॉ. विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद स्ट्रीट कौर चंद एमएच मलोट पंजाब

शादी विकल्प, जीवन मिशन : आज की लड़कियों की सोच

आज की लड़कियाँ पहले शिक्षा और करियर को महत्व देती हैं। शादी कई के लिए पहले प्राथमिकता नहीं रह गई है, बल्कि यह जीवन के कई संभावित विकल्पों में से एक बन गई है। विद्यार्थी खासकर उच्च शिक्षा पूरी करना, नौकरी में स्थापित होना, यात्रा और आत्मानुभव को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के तौर पर, भारत में युवतियाँ अविवाहित रहने को भी विकल्प मान रही हैं क्योंकि शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें पारंपरिक पथ से आगे बढ़ना सिखा रही है।

डॉ विजय गर्ग

आज के समय में लड़कियों का विवाह और जीवन-लक्ष्य को लेकर सोच में स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहा है। पारंपरिक रूढ़ियों के साथ आधुनिकता, शिक्षा, करियर और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कई नई प्रवृत्तियाँ उभर रही हैं—जो सिर्फ़ शादी को जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं मानतीं।

1. शिक्षा, करियर और व्यक्तिगत लक्ष्य अब प्राथमिकता

आज की लड़कियाँ पहले शिक्षा और करियर को महत्व देती हैं।

शादी कई के लिए पहले प्राथमिकता नहीं रह गई है, बल्कि यह जीवन के कई संभावित विकल्पों में से एक बन गई है। विद्यार्थी खासकर उच्च शिक्षा पूरी करना, नौकरी में स्थापित होना, यात्रा और आत्मानुभव को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के तौर पर, भारत में युवतियाँ अविवाहित रहने को भी विकल्प मान रही हैं क्योंकि शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें पारंपरिक पथ से आगे बढ़ना सिखा रही है।

2. शादी अब ज़रूरी 'लक्ष्य' नहीं—एक विकल्प है

परंपरागत समाज में 'शादी ही जीवन का उद्देश्य' जैसी सोच आज भी कहीं-न-कहीं मौजूद है, लेकिन इससे हटकर लड़कियाँ अब सवाल उठाती हैं:

'कब और क्यों शादी करनी है? ' 'क्या करियर पूरा होने के बाद ही रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए? ' 'क्या शादी ज़रूरी है या बस सामाजिक अपेक्षा?' युवा महिलाओं में यह समझ बढ़ रही है कि शादी सिर्फ एक सामाजिक संस्था है, न कि जीवन की अंतिम मंज़िल।

3. रिश्तों में बदलावः शादी के नए आयाम

शादी के प्रति सोच अब अधिक विवेकपूर्ण और चयनात्मक हो चुकी है:

स्वेच्छा से रिश्ता चुनना

लड़कियाँ अब लिव-इन रिलेशनशिप, साझा जीवन लक्ष्यों और समान सम्मान-आधारित रिश्तों पर भी विचार करती हैं—कुछ लोग इसे स्वतंत्रता और वैकल्पिक रिश्तों का संकेत मानते हैं।

व्यक्तिगत जोखिम और अनुभव

बॉलीवुड हस्तियों या सोशल मीडिया से सन्दर्भ में, कई महिलाओं ने बहुत कम उम्र में शादी न करने की सलाह दी है, ताकि पहले खुद को जान सकें और जीवन के अनुभव पा सकें।

4. सामाजिक दबाव ड्व्हृ. व्यक्तिगत फैसला

आज भी कुछ क्षेत्रों में परंपरागत सोच दबाव बनकर आती है—जैसे जल्दी शादी को प्राथमिकता देना या शादी को हर समस्या का समाधान मानना। लेकिन युवतियाँ अब खुद के फैसले पर ज़ोर देती हैं—चाहे वो शिक्षा हो, करियर हो, या शादी का निर्णय।

5. वैश्विक रुझानों की झलक

वैश्विक शोध और सर्वे भी यही संकेत देते हैं किः किशोरियों में अब शादी की अपेक्षा कम है—बहुत सारी लड़कियाँ शादी को भविष्य की प्राथमिकता के रूप में नहीं देखतीं। महिलाएँ (साथ) खोजती हैं न कि सिर्फ़ पारंपरिक बंधन।

निष्कर्ष

आज की लड़कियों की सोच बहुताधिक बहुआयामी हो गई हैः शादी अब ज़िंदगी का मात्र लक्ष्य नहीं, बल्कि स्वयं के फैसले, करियर, स्वतंत्रता और जीवन अनुभव का विकल्प है। शादी या अविवाहित रहना, दोनों को सम्मानजनक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ व्यक्ति स्वयं तय करता है कि उसका जीवन मिशन क्या है। समाज की अपेक्षाएँ बदल रही हैं, और लड़कियाँ उस परिवर्तन की नायिकाएँ हैं—जो अपने लक्ष्य खुद तय कर रही हैं।

पश्चिमी सिंहभूम में हाथी का हमला और वन विभाग की सुस्ती पर उठते सवाल

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिलेमें मंगलवार रात एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने सामने आई, जिसमें एक जंगली हाथी के हमले में छह लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हाथी पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में उत्पाद मचा रहा था। इस घटना के बाद वन कर्मी हरकत में आए और हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया

देश भर में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और वनों के घटते दायरे से मनुष्य और वन्यजीवों के बीच संघर्ष गहराता जा रहा है। जंगलों में मानव गतिविधियों की निरंतरता से सह-अस्तिव से जुड़े प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इसके नतीजतन भोजन की तलाश में वन्य जीव रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं और जिसकी कीमत न केवल फसलों के नुकसान के रूप में चुकानी पड़ रही है, बल्कि कई बार लोग उनकी आक्रामकता का भी शिकार हो जाते हैं।

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिलेमें मंगलवार रात एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने सामने आई, जिसमें एक जंगली हाथी के हमले में छह लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हाथी पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में उत्पाद मचा रहा था। इस घटना के बाद वन कर्मी हरकत में आए और हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया।

ऐसे में सवाल है कि वन विभाग ने समय रहते स्थिति की गंभीरता को क्यों नहीं समझा? इन लोगों की मौत के लिए

आखिर कौन जिम्मेदार है? यह गंभीर चिंता का विषय है कि न सिर्फ हाथी, बल्कि चीते और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर भी जंगलों से निकल कर अब इंसानी बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। दरअसल, जंगलों के नजदीक अतिक्रमण बढ़ रहा है।आसपास बसावट से हाथियों और अन्य वन्य प्राणियों की शांति भंग हो रही है। साथ ही वनों की कटाई से उनके लिए भोजन का संकट भी पैदा हो रहा है। नतीजा यह कि वे अपने ही आवास से बेदखल हो रहे हैं। जंगली हाथियों की बात की जाए तो उनके हमलों में हर वर्ष कई लोगों की जान जा रही है।

हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल और झारखंड से लेकर असम, तमिलनाडु और केरल तक कई राज्यों में हाथियों के हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। मानव से संघर्ष में हाथियों की भी मौत हो रही है। कई बार तो उनके मार्ग में आने वाली रेल पटरियां भी उनकी मौत का सबब बन जाती हैं। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसे सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू से देखना होगा। जब तक समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे, तब तक मनुष्य और वन्यजीवों के बीच टकराव खत्म नहीं होगा।

सम्पादकीय

पत्थरबाजों पर की जाए सख्त कानूनी कार्रवाई

दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में सैयद फैज इलाही मस्जिद के पास बुधवार को जो हुआ वह सच में खौफनाक मंजर था। अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान हिंसा भड़क गई। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने रामलीला मैदान इलाके में एक धार्मिक स्थल के निकट स्थित औषधालय सहित कुछ व्यावसायिक ढांचों को अतिक्रमण घोषित किया था उसी निर्देश के अनुपालन पर दिल्ली नगर निगम के अधिकारी मस्जिद से सटे इलाके और तुर्कमान गेट के पास के कब्रिस्तान पर बने अतिक्रमण को हटा रहे थे, तभी झड़पें शुरू हो गईं। सवाल यह है कि इस कार्रवाई से अगर कोई व्यक्ति या समूह किसी बात से सहमत नहीं था, तो वह अपना विरोध प्रकट कर सकता था। मगर इसका तरीका कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण और अहिंसक होना चाहिए था। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन यह अधिकार कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की अनुमति नहीं देता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में एक धार्मिक स्थल के निकट बुधवार तड़के अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान पथराव की घटना गंभीर चिंता पैदा करती है, जिसमें पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। सवाल है कि विरोध प्रदर्शन हिंसक कैसे हो गया? क्या वजह रही कि लोगों ने पुलिस कार्रवाई को रोकने के लिए ईंट-पत्थरों का सहारा लिया? दरअसल, सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों ने इस घटना को हिंसक रूप दे दिया, जिसमें दावा किया गया कि अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान एक धार्मिक स्थल को ध्वस्त किया जा रहा है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और पुलिस बल पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। गौरतलब है कि पत्थरबाजी की घटनाएं पहले कश्मीर में आए दिन देखी जाती थीं। कई बार तो आतंकियों को बचाने के लिए भी सुरक्षाबलों पर पथराव किया जाता था। यहां तक कि मुठभेड़ के दौरान भी सुरक्षा कर्मियों को रोकने के लिए पत्थरबाजी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि, सरकार और प्रशासन की सख्ती से हाल के वर्षों में घाटी में इस तरह की घटनाएं काफी कम हो गई हैं। मगर, विरोध प्रदर्शन के नाम पर इसी तरह के कृत्य अब दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा का प्रकरण भी काफी चर्चा में रहा है, जिसमें पुलिस बल पर जमकर पथराव किया गया था।अब दिल्ली में इसी तरह की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर भी नए सिरे से बहस जोर पकड़ने लगी है। यह अक्सर देखा गया है कि इस तरह के मामलों में लोगों को एक जगह एकत्रित करने और उन्हें हिंसा के लिए उकसाने में सोशल मीडिया पर अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं का सहारा लिया जाता है। पुलिस के मुताबिक, अदालत ने रामलीला मैदान इलाके में एक धार्मिक स्थल के निकट स्थित औषधालय सहित कुछ व्यावसायिक ढांचों को अतिक्रमण घोषित किया था और इसे हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम के कर्मी पुलिस बल के साथ मौके पर गए थे। इसी बीच, सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी गई कि इलाके में स्थित धार्मिक स्थल को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल है कि जब अदालत ने इन व्यावसायिक ढांचों को अतिक्रमण करार दिया था, तो लोग बिना सोचे-समझे इतने आक्रामक कैसे हो गए? जबकि जिस धार्मिक संरचना को गिराने की अफवाह फैलाई गई, वह पुलिस कार्रवाई का हिस्सा थी ही नहीं। पुलिस अब इस बात की जांच भी कर रही है कि पथराव की यह घटना अचानक हुई या फिर किसी पूर्व नियोजित साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया। यह आशंका इसलिए भी जताई जा रही है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई अदालत के फैसले के बाद की गई और अगर स्थानीय लोगों को कोई आपत्ति थी, तो वे समय रहते ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते थे। इस घटना में जो भी दोषी हैं, उन्हें न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए। साथ ही आगे भविष्य में इस तरह की घटनाओं से सामना न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को अपनी योजनाओं में बदलाव करना होगा। खासकर मुस्लिम इलाके में कार्रवाई से पहले सोशल मीडिया पर अफवाह रोकने के लिए प्रशासन को संबंधित इलाके का संचार नेटवर्क बंद करना चाहिए, ताकि अफवाह फैलाने वालों को माहौल बिगाड़ने का अवसर न मिल सके, साथ ही पत्थरबाजों को कानूनी दायरे लाया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए।

जब सहनशक्ति टूटती है, तब परिवर्तन जन्म लेता है

नितिन जैन
प्रस्तुति-अमर भारती

मनुष्य का जीवन केवल सुख की कहानी नहीं है। इसमें संघर्ष, अपमान, अन्याय और चुप्पी के लंबे दौर आते हैं। अक्सर लोग सहनशील व्यक्ति को कमजोर समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता इसके उलट होती है। जो व्यक्ति सहन करता है, वह डर के कारण नहीं बल्कि विवेक के कारण सहन करता है। वह टकराव से पहले समाधान खोजता है, क्रोध से पहले संयम चुनता है और बदले से पहले न्याय की प्रतीक्षा करता है। लेकिन सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। जब तक सहन है, तब तक मौन है, और जिस दिन सहन टूटता है, उस दिन परिवर्तन निश्चित हो जाता है।समाज में अनेक बार ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति शांत रहता है, उसे दबाने की कोशिश की जाती है। उसकी चुप्पी को उसकी सहमति मान लिया जाता है। धीरे-धीरे उस पर अन्याय बढ़ता जाता है, शोषण गहराता जाता है और अपेक्षा की जाती है कि वह हर बार समझौता ही करेगा। लेकिन यह समझ लेना भूल है कि सहनशीलता अनंत होती है। सहनशीलता शक्ति है, पर उसका टूटना चेतावनी होती है। जब सहन टूटता है, तब विनाश नहीं, बल्कि शुद्धि की प्रक्रिया शुरू होती है।यह प्रकृति का भी नियम है। आकाश में बादल तब तक शांत रहते हैं जब तक वे सहन कर सकते हैं, लेकिन जब सहन की सीमा पार होती है, तो बिजली चमकती है और वर्षा होती है। वही वर्षा सूखे को समाप्त करती है और नई फसल को जन्म देती है। इसी प्रकार समाज में भी जब सहन टूटता है, तब सच्चाई सामने आती है, अन्याय उजागर होता है और व्यवस्था को स्वयं को सुधारना पड़ता है।इसलिए सहनशील व्यक्ति को कमजोर आंकना सबसे बड़ी भूल है। उसका मौन डर नहीं, उसका धैर्य कायरता नहीं और उसकी शांति पराजय नहीं होती। वह भीतर से मजबूत होता है, परिस्थितियों को समझता है और सही समय की प्रतीक्षा करता है। लेकिन जिस दिन उसे यह आभास हो जाता है कि सहन अब अन्याय का साधन बन गया है, उस दिन उसका उठ खड़ा होना तय है। वह दिन केवल प्रतिक्रिया का नहीं, बल्कि परिवर्तन का दिन होता है।आज समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि सहनशीलता का सम्मान किया जाए, न कि उसका दुरुपयोग। क्योंकि जब सहन टूटता है, तब शब्द नहीं, कर्म बोलते हैं और फिर परिणाम भी उतने ही निर्णायक होते हैं।

एक जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और देश विरोधी गैंग सक्रिय

मृत्युंजय दीक्षित
प्रस्तुति-अमर भारती

माननीय सुप्रीमकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में फरवरी 2020 में उत्तर- पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मुख्य आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। इसी केस में उमर और शरजील के 5 साथियों को 12 कड़ी शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर और शरजील इमाम पर कड़ी टिप्पणियां करी हैं । अब ये दोनों अभियुक्त आने वाले एक साल में जमानत के लिए अपील भी नहीं कर पाएंगे। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगे अत्यंत वीभत्स दंगो में से एक थे। इस दंगे में मारे गए 53 निर्दोष लोगों में एक युवा आईबी अधिकारी अंकित शर्मा, पौढ़ी गढ़वाल से पांच महीने पहले आया गरीब माता का बेटा दिलबर नेगी और दो पुलिस कर्मी भी शामिल थे। ऐसे कुख्यात दंगों के अपराधियों को जमानत न मिलने पर सर्व साधारण में संतोष का भाव है किन्तु कुछ लोग इस पर भी तुष्टीकरण की रोटियां सेंकते हुए उमर खालिद और शरजील इमाम के लिए न केवल आंसू बहा रहे हैं वरन अनर्गल प्रलाप भी कर रहे हैं । शरजील इमाम केवल दिल्ली दंगों का ही अपराधी नहीं है वरन चिकन नेक तोड़कर पूर्वोत्तर भारत को देश से अलग करने कि बात करने वाला देशद्रोही है । शरजील इमाम भारत को खंड -खंड मे विभाजित देखना चाहता हैं। भारत के जो विपक्षी दलो ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत ण मिलने पर उसको सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं क्या वे इन विचारों से सहमत हैं? दरअसल उमर व शरजील के साथ खड़े लोग अपनी कुंठा और हताशा को ही जगजाहिर कर रहे हैं। इस कुंठित टोली मे कोई जमानत न मिलने को कायरता पूर्ण कार्रवाई कह रहा है तो कोई इसे बेतुका बता रहा है जबकि कोई इसे अत्याचार बता

रहा है । एक ने तो सारी लज्जा त्यागते हुए इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बता दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि 5 साल से अधिक बिना किसी दोष साबित हुए जेल में रखना बर्बरता बता दिया। यह बात भारतीय जनमानस के समझने योग्य है कि इन सेक्युलर नेताओं को सुप्रीम कोर्ट का फैसला बर्बर लग रहा है। अमेरिकी अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि जो अदालतों के अधिकार व उनके फैसलों को नकारता है वह राष्ट्र की नींव को नकारता है । इस तुष्टीकरण गैंग से पूछा जाना चाहिए कि आज देश में 4 लाख 34 हजार 302 विचाराधीन कैदी हैं जो सजा पाए बिना जेल में बंद हैं। करीब 26 हजार ऐसे कैदी हैं जो 3 से 5 साल तक जेल में बंद हैं और करीब साढ़े 11 हजार ऐसे कैदी हैं जो 5 वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद हैं । यह आंकड़े केवल 2020 तक के ही हैं । इंडिया जस्टिस रिपोर्ट- 2025 के अनुसार यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इसमें भी अधिकांश बंदी जन गरीब, दलित अल्पसंख्यक व महिला समाज के हैं । इन कैदियों के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थकों का मन कभी नहीं छटपटाता है। यह लोग उन उमर खलिद और शरजील इमाम के लिए रो रहे हैं जिनकी जमानत के फैसले से पूर्व ही न्यूयार्क के मेयर ममदानी का एक आपत्तिजनक पत्र सार्वजनिक हो गया था। ममदानी के पत्र से पता चलता है कि भारत के खिलाफ कितनी गहरी साजिशें रची जा रही हैं। यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया गया शरजील इमाम राष्ट्र द्रोही व घातक व्यक्ति है। चिंता का विषय है कि उमर खालिद और शरजील इमाम के बचाव में अदालत में जो लोग खड़े हुए हैं वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं अपितु देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इनमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, अश्विनी कुमार जैसे नाम शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस सरकार में बडे मंत्रालय संभाले। इसके अतिरिकत सिद्धार्थ दवे, सिद्धार्थ लूथरा, त्रिदीप पैइस भी इनके वकील रहे।प्रश्न यह उठता है कि 'क्या यह केवल कानूनी सहायता है' या 'किसी विशेष मानसिकता का स्पष्ट संकेत ?' यह सब चल ही रहा था तभी बीच में जेएनयू के ढपली वालों ने आकर ताल से ताल मिला दी। दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की जमीन से एक बार फिर देश के विरुद्ध आपतिजनक नारे लगे। दस साल पूर्व भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह -इंशा अल्लाह के नारे लगाए गए थे उसी जगह 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी , अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी खुदेगी' जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए। इस गैंग की नारेबाजी की वजह थी दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत की अर्जी का खारिज होना। कांग्रेस व उसके अन्य विरोधी दलों के नेताओं ने इस प्रदर्शन व नारेबाजी को गुस्से ,नाराजगी के प्रकटीकरण का तरीका बता दिया। दिल्ली दंगो से सम्बंधित एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय दिल्ली में आप मुखिया अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। दंगो की जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि हिंसा अचानक नहीं हुई थी आप पार्षद ताहिर हुसैन और विधायक अमानतुल्लाह खान की इसमें बड़ी भूमिका थी, इनकी जांच प्रगति पर है और अभी कोई बरी नहीं हुआ है। केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते सरकारी तौर पर इन तत्वों को बचाने का पूरा प्रयास किया गया और उन्हीं की वजह से आज भी वह जमानत पर घूम रहे हैं । जब तक दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे तब तक उनकी ओर से दिल्ली दंगो की जांच में कोई सहयोग नहीं किया जा रहा था। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में संभव है फरवरी 2020 के पीड़ितों को न्याय मिल जाए।

मरसलगंज गौरव

सुविचार

आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज

अन्तर्मना उवाच

सही कार्य करने के परिणाम हमेशा अच्छे ही आते हैं.. लेकिन सही कार्य वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो..!

एक शिष्य ने गुरू से पूछा - गुरुजी हम कैसे जीयें-? सन्त ने कहा - दो दिन साथ रहो, सब समझ जाओगे कि कैसे जीना है-? शिष्य गुरू चरणों में ठहर गया। एक भक्त आया और सन्त के चरणो में मीठाई का डिब्बा चढ़ा कर बैठ गया। सन्त ने डिब्बा उठाया और पीठ करके सारी मीठाई खा ली। वह भक्त गुस्सा होकर चला गया कि हमको सन्त ने प्रसाद भी नहीं दिया। कुछ देर में एक भक्त फल लेकर आया और सन्त के चरणों में चढ़ाकर बैठ गया। सन्त ने फल उठाये और फेंक दिये। वह भक्त सोचने लगा कि सन्त ने फल स्वीकार नहीं किया और पीछे फल फेंक दिये। फिर एक भक्त मीठाई और फल लेकर आया। सन्त ने सबको मीठाई और फल प्रसाद में बांट दिया, सब खुश हो गये।

सन्त ने शिष्य से कहा - समझ आ गया कैसे जीना चाहिए-? शिष्य बोला गुरुदेव कुछ भी समझ नहीं आया - कृपया आप ही इस रहस्य को बतायें-? सन्त ने कहा - जिस परमात्मा ने आप हमको सब कुछ दिया, तुमने उसको धन्यवाद तक नही दिया। ये अन्याय पूर्ण जीवन है। दूसरा - भक्त ने फल चढ़ाये और हमने वो फल फेंक दिये - यह मनुष्य जीवन परमात्मा प्रदत्त उपहार है जिसका हम उपहास उड़ा रहे और मूल्यवान जीवन को कामना वासना की आग में झुलसा रहे हैं। तीसरा - भक्त फल और मीठाई लेकर आया और हमने वह मीठाई और फल सबको प्रसाद में बांट दिया - मनुष्य जीवन परोपकार मय जीओ, और सबको जीने दो। हँसो और हसाओ, खुश रहो और दूसरों को खुश रहने दो, जीओ और सबको जीने दो। जिसने हमको सब कुछ दिया, उस परमात्मा को धन्यवाद दो।

मनुष्य जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। अहंकार, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच की प्रवृतियों ने हमारे अच्छे सुन्दर मानव जीवन को नष्ट नाबूत कर दिया। माता, पिता, गुरू और परमात्मा का आभार मानकर मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करो...!!!

अंतर्मना

भूख से मुक्ति का राष्ट्रीय संकल्प है अटल कैंटीन योजना

ललित गर्ग
प्रस्तुति-अमर भारती

भूख केवल एक शारीरिक पीड़ा नहीं है, वह सामाजिक असंतुलन, मानसिक कुंठा और नैतिक विचलन की जननी भी है। इतिहास साक्षी है कि जब पेट खाली होता है, तो विचार उग्र हो जाते हैं, व्यवस्था के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है और विद्रोह की भावना पनपती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे पहली जिम्मेदारी यह होती है कि उसका कोई भी नागरिक भूखा न रहे। इसी बुनियादी और मानवीय सोच के साथ दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार द्वारा शुरू की गई रुपये 5 में भोजन उपलब्ध कराने की 'अटल कैंटीन योजना' निस्संदेह एक दूरदर्शी, करुणामय, मानवीय और जनकल्याणकारी पहल है। इस योजना का उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट और मानवीय है कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। राजधानी जैसे महानगर में, जहाँ एक ओर समृद्धि और चमक-दमक है, वहीं दूसरी ओर असंगठित श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शाचालक, ठेला-पटरी वाले, घरेलू कामगार और बेघर लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। इनके लिए दो वक्त का सम्मानजनक और पौष्टिक भोजन आज भी एक चुनौती बना हुआ है। अटल कैंटीन योजना इन्हीं वर्गों के लिए जीवनरेखा बनकर सामने आई है, जो 'संकल्प से सिद्धि' के लक्ष्य को दर्शाता है और इसे देश में भोजन सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस योजना का शुभारंभ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर किया जाना केवल एक औपचारिक तिथि चयन नहीं, बल्कि एक वैचारिक निरंतरता का प्रतीक है। अटलजी का संपूर्ण राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन अंत्योदय अर्थात समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के विचार से प्रेरित रहा। वर्ष 2000 में शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अटलजी के लिए गरीब केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि नीति का केंद्र था। उस योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया गया, जिससे करोड़ों लोगों को भुखमरी से राहत मिली। अटल कैंटीन योजना उसी सोच का आधुनिक शहरी संस्करण है, जहाँ अनाज के बजाय तैयार, पौष्टिक और स्वच्छ भोजन सीधे थाली में परोसा जा रहा है। यह नीतिगत निरंतरता इस बात का प्रमाण है कि सुशासन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि संवेदनशील क्रियान्वयन

से साकार होता है। अटल कैंटीन में भोजन की कीमत रुपये 5 रखी गई है, जबकि सरकार प्रत्येक थाली पर रुपये 25 की सब्सिडी दे रही है। यह मूल्य निर्धारण अत्यंत सोच-समझकर किया गया है। भोजन पूरी तरह मुफ्त न देकर एक न्यूनतम राशि तय करने का उद्देश्य यह है कि भोजन की कद्र बनी रहे और लाभार्थी इसे भीख नहीं, बल्कि अधिकार और सम्मान के रूप में ग्रहण करे। यह नीति सामाजिक मनोविज्ञान को समझने का उत्कृष्ट उदाहरण है। रेखा गुप्ता सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए जिस संवेदनशीलता, निर्णय क्षमता और प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया है, वह उनके प्रभावी राजनीतिक नेतृत्व को रेखांकित करता है; अटल कैंटीन जैसी योजनाएँ बताती हैं कि वे शासन को सत्ता नहीं, सेवा का माध्यम मानती हैं। किंतु सर्दी के इस कठोर मौसम में दिल्ली की सड़कों, फुटपाथों और फ्लाईओवरों के नीचे ठिठुरती रातें काटने को विवश गरीब और बेघर लोगों के लिए केवल मौसमी रैन-बसेरे पर्याप्त नहीं हैं, आवश्यकता एक स्थायी, समन्वित और मानवीय शीत-रक्षा योजना की है, जिसमें अस्थायी आश्रय के साथ गरम वस्त्र, पौष्टिक भोजन, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा और पुनर्वास की स्पष्ट व्यवस्था हो, ताकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी की सड़कों पर कोई भी व्यक्ति सर्द रात में बेसहारा और अदृश्य न रहे; ऐसा कदम न केवल प्रशासनिक संवेदनशीलता का प्रमाण होगा, बल्कि लोकतंत्र की नैतिक जिम्मेदारी का भी सशक्त निर्वाह बनेगा। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि उपलब्ध कराया जा रहा भोजन पोषण मानकों के अनुरूप है। भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई मानकों का पालन किया जाता है, जिसमें प्रति थाली 700-800 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन होता है। डिजिटल टोकन, सीसीटीवी और निगरानी के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। प्रत्येक कैंटीन प्रतिदिन लगभग 1000 लोगों को भोजन परोसने की क्षमता रखी है, और 100 कैंटीन खोलने का लक्ष्य है। दाल, सब्जी, रोटी/चावल जैसे संतुलित आहार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें आरओ वाटर एवं अचार आदि भी परोसा जा रहा है ताकि यह योजना केवल पेट भरने तक सीमित न रहकर स्वास्थ्य सुधार में भी योगदान दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा गरीबों और निम्न आय वर्ग के लिए मुफ्त एवं रियायती अनाज योजनाएँ लगातार संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी पहलों ने संकट काल में करोड़ों परिवारों को राहत दी है। इन योजनाओं का मूल दर्शन यही है कि भूखा नागरिक न आत्मनिर्भर बन सकता है और न ही राष्ट्रनिर्माण में भागीदार। रेखा गुप्ता सरकार की अटल कैंटीन योजना इन राष्ट्रीय प्रयासों के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। यह दर्शाती है कि केंद्र और राज्य, यदि समान मानवीय दृष्टि से काम करें, तो सामाजिक समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से संभव है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों ही इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि भुखमरी और अपराध के बीच गहरा संबंध होता है। जब व्यक्ति की मूल आवश्यकताएँ पूरी नहीं होतीं, तो वह व्यवस्था के प्रति विद्रोही दृष्टिकोण अपनाने लगता है। यही कारण है कि अनेक महान नेताओं ने यह कहा है कि गरीब को पहले रोटी दो, उपदेश बाद में। भूखे को खिलाना किसी प्रकार का राजनीतिक प्रलोभन नहीं है। यह सच्ची राष्ट्रभक्ति, मानवीय कर्तव्य और सामाजिक सुरक्षा का आधार है। अटल कैंटीन जैसी योजनाएँ अपराध को नियंत्रित करने, सामाजिक असंतोष को कम करने और लोकतंत्र में विश्वास को मजबूत करने का कार्य करती हैं। हालाँकि, किसी भी जनकल्याणकारी योजना की सफलता केवल उसकी घोषणा से नहीं, बल्कि उसके पारदर्शी, निगरानी और ईमानदार क्रियान्वयन से तय होती है। यह अत्यंत आवश्यक है कि अटल कैंटीन योजना को भ्रष्टाचार, अपव्यय और लापरवाही से पूरी तरह मुक्त रखा जाए। खाद्य सामग्री की खरीद, भोजन की गुणवत्ता, लाभार्थियों की पहुँच, वित्तीय प्रबंधन और संचालन व्यवस्था-हर स्तर पर सख्त निगरानी, नियमित ऑडिट और सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि इस योजना में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार प्रवेश करता है, तो वह न केवल सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होगा, बल्कि गरीब के विश्वास के साथ भी विश्वासघात होगा।

आर्थिक मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ता भारत

डॉ. ओपी त्रिपाठी
प्रस्तुति-अमर भारती

भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती की राह पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। यदि 1990 के दशक में कोई कहता कि भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ सकती है, तो कोई भी उद्योगपति या अर्थशास्त्री इसे स्वीकार नहीं करता। तब जापान विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और भारत बहुत पीछे था। भारत ने अर्थव्यवस्था को खोलने और आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत ही की थी, लेकिन आज यथार्थ सामने है। आज भारत 4.187 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसने जापान को पीछे कर दिया है। भारत सबसे तेज गति वाली अर्थव्यवस्था है और वह दिन दूर नहीं है, जब भारत में कामगार आबादी 1 अरब होगी। फिलहाल भारत की कुल आबादी 1.47 अरब को पार कर चुकी है। राजनेता अपने आंकड़े सुधार लें। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और कई विख्यात रेटिंग एजेंसियां 2025-26 (31 मार्च, 2026 तक) वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर औसतन 7 फीसदी आंक रही हैं। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन इससे भी अधिक विकास दर को लेकर आशान्वित हैं। यकीनन भारत बदल रहा है और आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। जर्मनी 4.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ तीसरे स्थान पर है। यकीनन भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर है। ऐसी अनुकूल स्थिति के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने शीर्ष नौकरशाहों को यह सलाह क्यों दी है कि 'विनियमन प्रकोष्ठ' स्थापित किए जाएं। प्रधानमंत्री देश की बढ़ती आर्थिक ताकत के रास्ते में किसी भी नियम, कानून और प्रक्रिया को रोड़ा बनने के पक्षधर नहीं हैं। साफ है कि प्रधानमंत्री सुधारों को गति देना चाहते हैं। फालतू के नियम, कानून, प्रतिबंध और प्रक्रियाओं को समाप्त करना चाहते हैं, ताकि जिंदगी और व्यापार करना आसान हो सके। इसी बिंदु पर भारत जापान से बहुत अलग है। 2004 को याद करें, जब एक अनुबंध या ठेका प्राप्त करने में औसतन 425 दिन लगते थे। करीब 40 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। दिवालियापन के समाधान की प्रक्रिया आराम से 10 साल तक चलती थी। नीति आयोग ने 2017 की अपनी रपट में स्वीकार किया था कि भारत में एक दुकान स्थापित करने में औसतन 118 दिन लगते थे। असम में यह अवधि 248 दिन तक फैल जाती थी। बेशक आज स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फालतू के सैकड़ों कानूनों को खत्म किया है, लेकिन प्रक्रियाएं आज भी व्यापार, उद्योग के पहिये को अवरुद्ध कर रही हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री को 'विनियमन प्रकोष्ठ' स्थापित करने की बात कहनी पड़ी है। यदि भारत 2047 तक 'विकसित राष्ट्र' बनना चाहता है, तो ऐसी स्थितियां बनानी पड़ेगी, जिनमें कायदे-कानून और फालतू की प्रक्रियाएं 'शासन' न करती हों, बल्कि नियमन को सहज-सुगम बनाती हों। बेशक उससे भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। अब भारत ऐसा देश है, जिसमें 2025 में 1.95 लाख करोड़ रुपए के आईपीओ आए और डीमैट खातों की संख्या 21 करोड़ के पार चली गई। अभी तक 1350 स्टार्टअप में 25,320 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। आज भारत 159 प्रकार के गोला-बारूद, गोलियां, रॉकेट आदि का उत्पादन देश में ही कर रहा है। रक्षा- क्षेत्र करीब 91 फीसदी आत्मनिर्भर हो चुका है। 'मेक इन इंडिया' उत्पादों में ब्रह्मोस और पिनाका मिसाइलों की मांग बढ़ रही है। 2029 तक भारत ने 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा-निर्यात का लक्ष्य तय किया है। आधा तो हम हासिल कर चुके हैं। बहरहाल संसद में बजट पेश करते हुए राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य तय किया गया था, वह नियंत्रण में है। मुद्रास्फीति 0.7 फीसदी तक गिर गई है। चालू खाते का घाटा दोगुना हो सकता है, लेकिन यह जीडीपी के 1.2 फीसदी तक ही रहेगा, जो एक सहज स्थिति है। यह हमारी आर्थिक और बाजारी ताकत है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी विख्यात

बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में 67.5 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणाएं की हैं। इस निवेश का खास फोकस कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), आधारभूत ढांचे पर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से बुधवार को जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमानों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में देश की वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 7.4 फीसदी रहने का अनुमान है। यह वित्त वर्ष 2024-25 के 6.5 फीसदी के अनुमान से अधिक है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक गति बनी हुई है और आने वाले समय में विकास की रफ्तार और तेज हो सकती है। एनएसओ के अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी 201.90 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में इसका अनंतिम अनुमान 187.97 लाख करोड़ रुपये था। यह इशारा करता है कि अर्थव्यवस्था का आकार लगातार बढ़ रहा है। वहीं, नॉमिनल जीडीपी की बात करें, तो इसमें 8 फीसदी की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। चालू कीमतों पर नॉमिनलर जीडीपी के 2025-26 में बढ़कर 357.14 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जबकि 2024-25 में यह 330.68 लाख करोड़ रुपये रही थी। नॉमिनल जीडीपी में मुद्रास्फीति शामिल होती है, जबकि वास्तविक जीडीपी महंगाई के असर को हटाकर अर्थव्यवस्था की असली ग्रोथ दिखाती है। एनएसओ की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि की सबसे बड़ी ताकत इस समय सेवा क्षेत्र बना हुआ है। वित्तीय, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज के साथ-साथ सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में स्थिर कीमतों पर 9.9 फीसदी की मजबूत वृद्धि का अनुमान है। इसके अलावा व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण सेवाओं में भी 7.5 फीसदी की ग्रोथ का अनुमान जताया गया है। इससे साफ है कि घरेलू मांग, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल सेवाओं से जुड़े सेक्टर आगे भी विकास को सपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, द्वितीयक क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से भी समग्र विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025-26 में सेकेंडरी सेक्टर में 7.0 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च, निजी निवेश और रियल एस्टेट गतिविधियों में तेजी का असर कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर दिखाई दे रहा है। वहीं, मैन्युफैक्चरिंग में भी धीरे-धीरे रिकवरी और एक्सपोर्ट सपोर्ट के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, सभी सेक्टरों में समान गति नहीं दिख रही। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 2025-26 के दौरान 3.1 फीसदी की अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। मौसम पर निर्भरता, लागत में बढ़ोतरी और ग्रामीण मांग की स्थिति इस सेक्टर की ग्रोथ को प्रभावित कर सकती है। इसके बावजूद, सरकार की ओर से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई और ग्रामीण योजनाओं पर फोकस से आने वाले समय में इसमें सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। आज भारत महाशक्ति के जिस अवतार में है, उसमें बहुआयामी गरीबी, बेरोजगारी, किसानी, श्रम, पानी आदि को लेकर जो संकटग्रस्त स्थितियां हैं, वे बहुत बड़ा सवालिया निशान भी हैं। कमोबेश 2026 में उन पर प्राथमिकता के स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। भारत को आर्थिक क्षेत्र में अभी लंबा सफर तय करना है। चीन और अमेरिका की बराबरी के लिए अभी कई कुछ बाकी करना है। इन दोनों देशों से अभी हम बहुत पीछे हैं।

अमर भारती में प्रकाशित समाचार, विचार, लेख अथवा विज्ञापन से यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो कृपया स्पष्टीकरण एवं सुझाव समूह सम्पादक की ईमेल- editor@amarbharti.com पर प्रेषित करें अथवा 9311222595 पर व्हाट्सएप करें।